राष्ट्रीय संस्करण

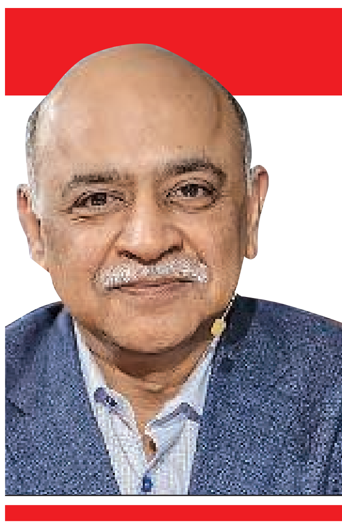

आइबीएम के सीईओ चुने गए अरविंद कृष्णा >>7

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 235

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 1 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

अगले दशक में देश की विकास गाथा का एजेंडा तय करेगा बजट

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का दूसरा बजट कुछ वैसा ही होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को जाना जाता है। यानी चुनौतियों को दरकिनार करते हुए पहले बड़ा लक्ष्य तय करना और फिर उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किया जाने वाला आम बजट 2020-21 अगले दशक में देश की विकास गाथा का पूरा रोडमैप पेश करने वाला होगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का संकेत है कि वित्तीय सुधारों को लेकर निर्भीक फैसला भी लिया जाएगा और एक दशक में हर हाथ को काम देने की दिशा में भी आगे बढ़ा जाएगा। यह भी तय है कि वित्त मंत्री राजकोषीय प्रबंधन को लेकर फिलहाल बहुत फिक्रमंद नहीं होंगी। वह निवेश, बचत और निर्यात को बढ़ाने वाला बजट पेश करेंगी, ताकि लंबे समय तक तेज आर्थिक विकास दर हासिल की जा सके।

शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर पांच फीसद पर सिमटने के बाद 2020-21 में छह से साढ़े छह फीसद रहेगी।

यह निश्चित तौर पर देश की आर्थिक सेहत के लिए थोड़ी बेहतर स्थिति होगी, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (फाइव ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए नाकाफी होगी। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगले पांच साल तक आठ फीसद की सालाना वृद्धि दर से ही सरकार यह लक्ष्य हासिल कर सकती है। हालांकि, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि यह दर कम से कम 10 फीसद होनी चाहिए।

विशेष पेज >> 10-11

6-6.5% अगले वित्त वर्ष में सुधार के साथ रह सकती है विकास दर

8% की विकास दर चाहिए अगले पांच साल तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए

3.3% से बढ़कर राजकोषीय घाटा 3.8 फीसद पर पहुंचने का अनुमान

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

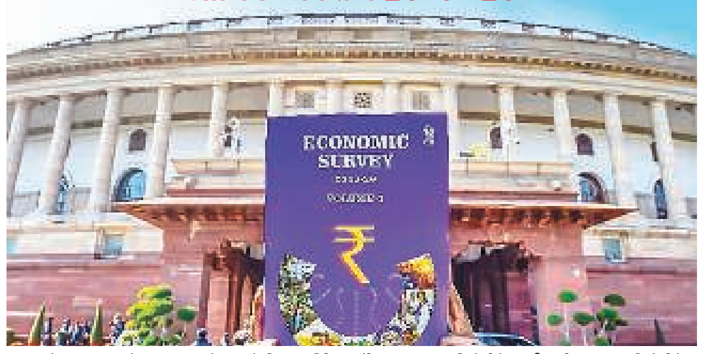

संसद में शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वे-2019-20 रिपोर्ट पेश की गई। यह इस रिपोर्ट के पहले खंड का कवर है ● प्रेट्र

क्या मिल रहे हैं संकेत?

- सुधारों को लेकर उठाए जा सकते हैं अप्रत्याशित कदम
- आजमाए जा सकते हैं बचत बढ़ाने के नए उपाय
- ग्रामीण विकास के लिए आवंटन में होगी भारी वृद्धि
- वानिकी, डेयरी व मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा
- निर्यात से रोजगार बढ़ाने को नई रणनीति का एलान संभव
- देश में कारोबार की राह सुगम बनाने की पहल होगी तेज
- एसएमई के लिए फंड का होगा इंतजाम
- मौजूदा जरूरत को देखते हुए खर्च बढ़ाने पर रहेगा जोर
- खाद्य सब्सिडी पर जारी बहस के बीच चल सकती है कैंची
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव भी संभव
- राजकोषीय प्रबंधन पर ज्यादा फिक्र नहीं करेगी सरकार

हर मोर्चे पर चुनौती

लंबे समय तक तेज विकास दर के लिए निवेश, बचत व निर्यात में लगातार वृद्धि बेहद जरूरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था उक्त तीनों मामलों में पिछड़ रही है। तीनों सेक्टरों में जान फूंकने के लिए सुधारों का नया डोज देना होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने कहा, निवेश व बचत को बढ़ाने की कोशिश सतत प्रक्रिया है। विकास दर में गिरावट निचले स्तर पर है और अब आगे इसमें सुधार ही होना है।

विनिवेश पर बढ़ेंगे आगे

इस वर्ष भले ही 1.05 लाख करोड़ का विनिवेश लक्ष्य हासिल होता नहीं दिख रहा हो, लेकिन अगले वित्त वर्ष में भी लक्ष्य बड़ा रखा जाएगा। सरकार मान रही है कि आर्थिक हालात सुधरने के साथ ही विनिवेश प्रक्रिया भी तेज होगी। आर्थिक सर्वेक्षण ने निर्यात के जरिये बेरोजगारी खत्म करने का नुस्खा बताया है। सरकारी बैंकों की स्थिति पर निराशा को देखते हुए बजट में इस दिशा में भी बड़े एलान की उम्मीद है।

2018-19 की विकास दर घटकर 6.1 फीसद हुई

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के संशोधित आंकड़ों में वित्त वर्ष 2018-19 की विकास दर को 6.8 फीसद से घटाकर 6.1 कर दिया गया है। यह संशोधन खनन, मैन्यूफैक्चरिंग व खेती के प्रदर्शन में कमी की वजह से किया गया है। एनएसओ ने बताया कि 2011-12 की कीमतों के आधार पर 2018-19 व 2017-18 में रीयल जीडीपी 139.81 लाख करोड़ और 131.75 लाख करोड़ रुपये रहा है। 2017-18 की विकास दर भी पुनः संशोधित करते हुए 7.2 से घटाकर सात परसेंट कर दी गई है।

सरोकार

गंगासागर पहुंच 'पुण्य' कमाते हैं डॉक्टर भाई-बहन

कोलकाता : सारे तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार! लोग आस्था के महापर्व मकर संक्रांति पर एक बार भी गंगासागर पहुंच जाने को सौभाग्य मानते हैं, वहीं यह डॉक्टर भाई-बहन 40 साल से हर बार यहां पहुंच सेवा कर पुण्य कमाते आ रहे हैं। (पेज-7)

जागरण विशेष

तकनीकी क्रांति ला सकता है एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा

भोपाल : एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा नामक 4डी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की गति को लाइव देखा जा सकता है। जर्मनी में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष गर्ग का आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, कंप्यूटिंग क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। (पेज-6)

सीएए पर मोदी सरकार के तेवर सख्त

रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं : प्रधानमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखें सदस्य
- कानून मुस्लिम विरोधी नहीं, दुष्प्रचार कर रहा विपक्ष

यह तय है कि बजट सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानों में घमासान देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को एकजुटता का सबसे बड़ा शस्त्र मानकर विरोध को और धारदार बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के अपने साथियों से स्पष्ट कहा है कि इस मुद्दे पर रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखना है।

बजट सत्र के लिए रणनीति तैयार करने के लिए आयोजित राजग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'विपक्ष सीएए को मुस्लिम विरोधी होने का दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारे लिए अल्पसंख्यक भी उतने ही अपने हैं, जितने अन्य दूसरे नागरिक।'

बैठक के बाद राजग की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर राजग पूरी तरह एकजुट है और चट्टान की तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले थोड़ा अलग रुख दिखा रहा शिरोमणि अकाली दल (बादल) अब पूरी तरह साथ आ गया है। वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अलग राग अलाप रहे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र के मौके पर राजग के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करते हुए। एएनआइ

प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पहले भी बार-बार कह चुके हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले निर्णय में इस पर रोक लगाने से साफ इन्कार कर दिया था। नैतिक आधार पर सरकार के साथ महात्मा गांधी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह तक के बयान हैं। ऐसे में वर्तमान सत्र में घमासान होना लाजिमी है।

नागरिकता कानून ऐतिहासिक : राष्ट्रपति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कहा, विरोध के नाम पर हिंसा की जगह नहीं
- कानून को गांधी जी की इच्छाओं के अनुरूप बताया

नागरिकता संशोधन कानून को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी साफ संदेश दे दिया कि विरोध प्रदर्शनों के दबाव में सरकार इस पर झुकने वाली नहीं है। साथ ही विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को खारिज करते हुए राष्ट्रपति ने दो टूक कहा कि बहस-चर्चा ही विवाद समाधान का रास्ता है। बजट सत्र की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे।

सीएए पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और विरोध के बीच अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून को महात्मा गांधी की इच्छा के अनुरूप बताते साफ कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार के मद्देनजर इस कानून का लाया जाना अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद बने माहौल में गांधीजी ने साफ कहा था कि 'पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं, उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है।' उन्होंने सीएए पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का अभिनंदन करते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बढ़ा है और ननकाना साहिब की घटना इसका ताजा प्रमाण है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह हम सभी का दायित्व है कि विश्व के

नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बजट सत्र से पहले दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधित करने के दौरान। प्रेट्र

सामने पाक के ऐसे कृत्यों को बेनकाब किया जाए। सीएए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किए बिना राष्ट्रपति ने कहा कि विरोध के नाम पर किसी तरह की हिंसा समाज और देश को कमजोर करती है। सरकार का मानना है कि चर्चा-बहस और वाद-विवाद ही लोकतंत्र को मजबूत करते हैं और समाधान का रास्ता निकालते हैं। सीएए पर राष्ट्रपति के इस नजरिए पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने जहां मेजें थपथपाईं वहीं, उत्तेजित विपक्षी सदस्यों ने भी जमकर नारेबाजी और शोर शराबा किया। (संबंधित खबरें पेज-3 पर)

निर्भया के दोषियों की फिर टली फांसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्या मामले में चारों दोषियों की फांसी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। दोषी पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह के अधिवक्ता एपी सिंह ने कानूनी विकल्प शेष होने का हवाला देते हुए डेथ वारंट पर रोक की अर्जी दायर की थी। चौथे दोषी मुकेश ने सभी उपाय इस्तेमाल कर लिए हैं। 17 जनवरी को एक फरवरी के लिए डेथ वारंट जारी हुआ था। शुक्रवार को इस अर्जी पर लंबी बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। करीब चार घंटे के इंतजार के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगाने का आदेश दिया। तिहाड़ जेल प्रशासन को आदेश दिया कि शनिवार को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे।

दोषियों की याचिका में कहा गया था कि फांसी पर अनिश्चित काल तक रोक लगा देनी चाहिए। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दोषी विनय को छोड़कर किसी की भी दया या अन्य कोई याचिका विचाराधीन नहीं है। लिहाजा तीन लोगों को शनिवार सुबह फांसी दी जा सकती है। मुकेश की अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने कहा, जब एक साथ डेथ वारंट जारी हुआ है तो अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती।

वकीलों की भूमिका पर उठाए सवाल पेज>>6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

घपले के आरोपित आइएएस अफसरों को राहत नहीं

रायपुर : छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए करीब एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपित सात आइएएस समेत 12 अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ सीबीआइ को मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, जिससे टॉप ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ब्रिटेन ने आधी रात यूरोपीय यूनियन को कहा बाय

लंदन : ब्रिटेन आधी रात को यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग हो गया। इसके साथ ही ईयू सदस्य देशों के साथ उसकी 47 साल पुरानी आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी एकजुटता खत्म हो गई। ईयू से अलग होने यानी ब्रेक्जिट पर शुक्रवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, 'यह नए युग की शुरुआत है।'

ड्रोन से रखी निगाह, फिर ढेर किए तीन आतंकी

राज्य ब्यूरो, जम्मू

- मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी व सीआरपीएफ के दो जवान घायल
- प्लास्टिक के पाउडर की बोरियों से लदे ट्रक में छिपे थे जैश आतंकी

बड़ी वारदात की मंशा से ट्रक में छिपकर कश्मीर जा रहे जैश-ए-मुहम्मद के तीन आतंकियों को सुरक्षाबलों ने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में नगरोटा के बन इलाके में मार गिराया। इनसे स्नाइपर राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार व अन्य सामान बरामद हुआ है। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए। ट्रक के चालक, सहचालक और एक सवार से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह के मुताबिक मारे गए आतंकी पाकिस्तानी हैं, जो कठुआ के हीरानगर सीमा से घुसे थे। ट्रक चालक उनका ओवर ग्राउंड वर्कर था। आतंकियों ने गुरुवार शाम इसी ट्रक में छिप कर रात गुजारी थी। सूत्रों के अनुसार आतंकी जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा संस्थानों को भी निशाना बनाने की ताक में थे।

जम्मू शहर से 28 किमी दूर बन टोल प्लाजा पर शुक्रवार सुबह पांच बजे पालीविनाइल क्लोराइड की बोरियों से लदा ट्रक (जेके03एफ-1478) रुका। चालक समीर और सह चालक आसिफ मलिक तलाशी से आनाकानी करने लगे तो शक हुआ। पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) जवान सामान की तलाशी लेने लगे।

ट्रक के बाईं तरफ छोटे दरवाजे को खुलवाया तो अंदर छिपे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, पुलिसकर्मी भूमराज सिंह के हाथ में गोली लगी। तब तक एक आतंकी ने बोरियां हटाकर बाहर निकलने की कोशिश की। वह कुछ कर पाता कि टोल प्लाजा कार्यालय की छत पर तैनात सीआरपीएफ जवान ने उसे मार गिराया। फायरिंग के बीच दो आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। इसके बाद स्मोक बम फेंका और धुएं की आड़ में साथ की खाई में कूद जंगल में भाग निकले। ग्रेनेड फटने से सीआरपीएफ जवान संजीव कुमार व पासवान घायल हो गए। करीब पौने छह बजे सेना, पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व सीआइएसएफ ने जंगल को घेर लिया। सेना ने हेलीकॉप्टरों व ड्रोन से आतंकियों की निगरानी शुरू की। करीब एक किलोमीटर जंगल में चले गए आतंकियों की सटीक लोकेशन उस समय पता चली जब उन्होंने एक ड्रोन को निशाना बनाया। मॉनिटर पर आतंकियों को देख सुरक्षाबलों ने उन्हें मार गिराया। अफसरों, के अनुसार, ट्रक चालक समीर डार, सह चालक आसिफ मलिक व एक अन्य सवार आसिफ अहमद को नगरोटा थाने ले जाया गया। आसिफ गाइड बताया जा रहा है।

आतंकियों के पास से ये हुई बरामदगी पेज>>6

भारत की लगातार दूसरी 'सुपर जीत'

वेलिंगटन, प्रेट्र : भारतीय टीम ने शुक्रवार को वेलिंगटन में चौथे टी-20 में न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी बार सुपर ओवर में हराकर पांच मैचों की सीरीज में 4-0 की बढ़त लेने के साथ ही क्लीन स्वीप की तरफ कदम बढ़ा दिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दो टीमों के बीच लगातार दो मैचों का निर्णय सुपर ओवर से हुआ।

वेस्ट पैक स्टेडियम में भारत ने 20 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम एक समय जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर के आखिरी ओवर की बदौलत मेजबान 20 ओवर में सात विकेट पर 165 रन ही बना सके। मैच टाई हुआ जिसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया। न्यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत के लिए 14 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने पांच गेंदों पर एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

भारत ने सुपर ओवर में लगातार दूसरा मैच जीतकर सीरीज में 4-0 की बढ़त ली

वेलिंगटन में जीत के बाद खुशी जाहिर करते विराट कोहली। प्रेट्र (पेज-14 भी देखें)

04 बार जसप्रीत बुमराह ने टी-20 क्रिकेट (आइपीएल भी शामिल) में सुपर ओवर फेंका और हर बार टीम जीती है। अंतरराष्ट्रीय टी-20 में बुमराह ने दोनों ही बार सुपर ओवर फेंका और टीम इंडिया जीती

06 बार साउथी ने सुपर ओवर में गेंदबाजी की जिसमें पांच बार न्यूजीलैंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने टी-20 में सात और वनडे में एक बार सुपर ओवर खेला है जिसमें उसे सिर्फ एक बार जीत मिली है

2006 में न्यूजीलैंड व वेस्टइंडीज के बीच खेला गया मैच टाई हुआ। यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहला टाई टी-20 मुकाबला था। वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड का मैच 126 के स्कोर पर टाई रहा। ऑकलैंड में हुए इस मैच को कीवी टीम ने बॉल आउट में 3-0 से जीता था।

थालीनॉमिक्स

जनता को बजटीय गणित समझाने के लिए सरकार ने नया तरीका खोजा है, सरकार ने सरल शब्दों में लोगों को बताया कि गत छह वर्षों में उसके खाने की थाली कितनी सस्ती हुई है

थाली का बजट सुधरा, शाकाहारी रहना हुआ ज्यादा सस्ता

नई दिल्ली, प्रेट्र : अर्थशास्त्र का लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ता है। बावजूद इसके कुछ सीधी-सपाट बातों के अलावा लोग इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं। कई बार सरकार का लाखों-करोड़ों का बजट लोगों को समझ से बाहर लगने लगता है। इस बार सरकार ने लोगों की इस परेशानी को दूर करने की दिशा में पहल की है। आर्थिक सर्वेक्षण में बाकायदा थालीनॉमिक्स का एक अध्याय जोड़ा गया है। इसमें सरकार ने यह समझाने की कोशिश की है कि पिछले पांच साल में उठाए गए कदमों से लोगों का खाना कितना सस्ता हुआ है।

थालीनॉमिक्स में यह समझाया गया है कि सरकार के कदमों ने पांच सदस्यों वाले परिवार की जेब में सालाना कितने रुपये बचाए हैं। इसके लिए 25 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के औद्योगिक कर्मियों के लिए महंगाई की दर का आकलन किया गया। थाली की कीमत जानने के लिए अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 तक की कीमतों को समाहित किया गया। थाली पर होने वाले खर्च की गणना करने के लिए आय में वृद्धि से लेकर अन्य सभी पैमानों का ध्यान रखा गया। इसमें देश के चारों हिस्सों उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम में एक थाली की एब्सोल्यूट कीमत का आकलन किया गया। चारों ही क्षेत्रों में 2015-16 से थाली की कीमतें कम हुई हैं। एक औसत औद्योगिक कर्मचारी की सालाना आय के हिसाब से गणना करें तो 2006-07 की तुलना में 2019-20 में शाकाहारी थाली की कीमत 29 फीसद कम हो गई है। वहीं इसी अवधि में मांसाहारी थाली की कीमत में 18 फीसद की कमी आई है।

- सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण में जोड़ा थालीनॉमिक्स का अध्याय
- सरकार के कदमों से 29 फीसद सस्ती हुई शाकाहारी थाली
- मांसाहारी थाली भी 18 फीसद सस्ती, जेब में बच रहे सालाना 11787 रुपये

प्रतीकात्मक

2015-16 से शुरू हुई गिरावट

थाली की कीमत में गिरावट का सिलसिला 2015-16 से शुरू हुआ। इससे पहले कीमतें लगातार बढ़ रही थीं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में 2014-15 में सरकार ने कई सुधारवादी कदम उठाए थे। साथ ही कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि बाजारों में भी प्रक्रियात्मक सुधार किए गए थे। इनका नतीजा भी सालभर बाद ही दिखने लगा और 2015-16 में कीमतों में गिरावट शुरू हो गई। 2019 में कीमतों में कुछ बढ़ोतरी के बाद भी प्रभावी तौर पर एक थाली की कीमत कम हुई है।

जेब में कितना बचा?

आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि यदि 2015-16 से पहले वाली तेजी बनी रहती हो आज की तारीख में शाकाहारी थाली पर पांच सदस्यों वाले एक परिवार को सालाना 10,887 रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते। यानी कीमतें कम होने से एक परिवार ने सालाना 10,887 रुपये बचाए हैं। इसी तरह मांसाहारी थाली पर सालाना 11,787 रुपये की बचत हुई है।

थाली मतलब क्या?

शाकाहारी थाली में सरकार ने अनाज, सब्जी और दाल को शामिल मानते हुए आकलन किया है। इसी तरह मांसाहारी थाली में अनाज, सब्जी और एक मांसाहारी भोजन शामिल है। इस प्रक्रिया में सरकार ने भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले नमक, मसाले व अन्य सभी घटकों को भी ध्यान में रखते हुए कीमत का आकलन किया है।

दिल्ली में दो रुपये किलो आटा व छात्राओं को स्कूटी देगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- भाजपा ने पेश किया दिल्ली के विकास का संकल्प पत्र

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा शुक्रवार को जारी संकल्प पत्र में विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन और दूषित पानी की समस्या से निजात दिलाने का वादा किया गया है। साथ ही गरीबों को दो रुपये किलो आटा और कॉलेज में जाने वाली गरीब बेटियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी और नौवीं की छात्रा को साइकिल देने का एलान किया है। गरीबों को पांच लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना व प्रधानमंत्री आवास योजना भी लागू करने की बात है।

भाजपा ने कहा है कि मेरी दिल्ली, मेरा सुझाव अभियान के तहत 11.65 लाख लोगों से मिले सुझाव के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ शहर बनाने की ताकत और सोच सिर्फ भाजपा के पास है। दिल्ली का भविष्य चीजें मुफ्त बांटने से नहीं दूरगामी योजना बनाकर अमल करने से होगा। संकल्प पत्र में इसका ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा, भाजपा नेताओं को जब भी मौका मिला है, उन्होंने देश का भविष्य बदलने का काम किया है। मोदी सरकार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या हल करने के लिए 55 हजार करोड़ की लागत से सड़कें बनाई गई हैं। ईस्टर्न व वेस्टर्न पेरिफेरल पर 16 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, इसे बनाने में दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए।

अप्रैल तक तैयार हो जाएगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पेज>>2

45.16 करोड़ के कीमती सामान, आभूषण, शराब, नशीले पदार्थ इत्यादि पकड़े हैं चुनाव आचार संहिता लगने के बाद से सभी संबंधित एजेंसियों ने अब तक।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 1 फरवरी 2020

घोषणा ▸ गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए उठाए जाएंगे कदम, युवा, महिला, व्यापारी व किसानों की समस्याएं दूर करने का भी एलान

संकल्प पत्र में हर वर्ग को साथ लेकर चलने का वादा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा के संकल्प पत्र में प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया है। गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कदम उठाने के साथ ही युवा, महिला, व्यापारी व किसानों की समस्याएं दूर करने का भी वादा किया गया है। सत्ता में आने पर पार्टी प्रदूषण, यमुना की स्वच्छता, बदहाल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सहित अन्य प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। ऐसे में संकल्प पत्र में हर वर्ग को साथ लेकर चलने का विजन तो है ही साथ ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का भी वादा किया गया है।

गरीबों से वादा : गरीबों के लिए दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गेहूं का आटा। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और किसान सम्मान निधि योजना दिल्ली में भी लागू होगी। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग और अति पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। रेहड़ी पटरी वालों को नियमित करने का वादा। नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों की बकाया राशि का केंद्र सरकार के सहयोग से भुगतान कराया जाएगा। दिव्यांग, विधवा, निराश्रित महिलाओं व बुजुर्गो की पेंशन राशि भी बढ़ाई जाएगी।

महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा : गरीब परिवार की पहली दो लड़कियों के जन्म के समय बैंक खाता खोलकर उसमें पैसे जमा किए जाएंगे। 21 वर्ष की उम्र में उसे दो लाख रुपये मिलेंगे। गरीब परिवार की कॉलेज जाने वाली छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी और 9वीं कक्षा में पहुंचने वाली छात्राओं को साइकिल देने का वादा। गरीब विधवा की बेटी की शादी के अवसर पर 51 हजार रुपये का उपहार मिलेगा। महिलाओं के विकास के लिए महिला सशक्तीकरण बोर्ड का गठन। महिला सुरक्षा के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सुरक्षा योजना, महिला संबंधी अपराधों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें शुरू की जाएंगी।

बुनियादी ढांचे का विकास : दस लाख रुपये के प्रावधान के साथ समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत दिल्ली में बेहतर सड़क, फ्लाईओवर आदि बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राथमिकता के तहत निर्धारित समय सीमा में करने की बात कही गई है। भीड़ भाड़ वाले चौराहे फ्लाईओवर से जोड़े जाएंगे। रेलवे क्रासिंग पर अंडरपास व ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में संकल्प पत्र जारी करते (बाएं से) सांसद रमेश बिधूड़ी, राज्यसभा सदस्य विजय गोयल, केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, प्रकाश जावेडकर, नितिन गडकरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी। ध्रुव कुमार

बेरोजगारों को मिलेगा काम : पांच वर्षों में दस लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा। दिल्ली सरकार के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को एक साल के अंदर भरने का वादा। दिल्ली के अस्पतालों, सरकारी स्कूलों अन्य विभागों में अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष तक नौकरी के लिए जॉब गारंटी का वादा। दिल्ली को स्टार्टअप सिटी के तौर पर विकासित किया जाएगा। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा। आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए दिल्ली को विश्वस्तरीय सर्विस हब के तौर पर विकसित किया जाएगा। आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी में शोध व मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने के लिए ग्रीन इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाया जाएगा।

सभी को आवास : अनधिकृत कॉलोनियों में 40 लाख लोगों को मालिकाना हक देने के बाद इन कॉलोनियों में विकास कार्य को गति देने के लिए विकास बोर्ड का गठन। पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वालों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा। जहां झुग्गी वहीं मकान के तहत झुग्गी वालों को पक्का मकान मिलेगा। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के पुराने फ्लैट के समुचित विकास के लिए एक नीति बनाई जाएगी। एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) फ्लैट में रहने वालों को भी इसी तरह की सुविधा दी जाएगी। किरायेदारों के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे।

व्यापारियों को राहत : दस लाख व्यापारियों की दुकानों व कार्यालयों की लीज को फ्री होल्ड करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाएगा। सीलिंग से परेशान व्यापारी और कारोबारियों को राहत देने के लिए नियम और कानून में बदलाव करेंगे।

शिक्षा : शिक्षा बजट में प्रत्येक वर्ष दस फीसद की वृद्धि। पांच वर्षों में कम से कम दस नए कॉलेज और दो सौ स्कूल बनाएंगे। झुग्गियों और नगर निगमों के सभी वार्डों में पुस्तकालय बनेंगे।

किफायती स्वास्थ्य सेवाएं : स्वास्थ्य बजट में प्रति वर्ष दस फीसद की वृद्धि। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रविवार को विशेष ओपीडी की व्यवस्था। आयुष्मान भारत योजना के तहत चार सौ स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। दिल्लीवासियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की सुविधा।

युवाओं का विकास : युवाओं के लिए युवा कल्याण बोर्ड का गठन। युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिभा खोज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार की फिट इंडिया और खेलो इंडिया की अवधारणा के अनुरूप दिल्ली में नई खेल नीति बनाने का वादा।

दूर होगी बसों की कमी : सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दस हजार हरित बसें खरीदने के साथ ही मेट्रो के काम में तेजी लाई जाएगी। सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ेगी और मल्टी स्टोरी पार्किंग की व्यवस्था होगी।

प्रदूषण पर वार : चौराहों पर वायु नामक उपकरण और दिल्ली में अलग-अलग स्थानों पर एयर प्यूरीफायर टॉवर लगाए जाएंगे। सार्वजनिक परिवहन बसों की छत पर हवा शुद्ध करने के लिए परियंत्र नामक उपकरण लगेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। कचरे के पहाड़ से मुक्ति दिलाई जाएगी।

अप्रैल तक तैयार हो जाएगा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस

पहले पेज का शेष

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अप्रैल तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो जाएगा। 1.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से विश्व का सबसे लंबा दिल्ली-मुंबई हाईवे बन रहा है। इससे दिल्ली के विकास में तेजी आएगी। यमुना की सफाई के लिए छह हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। इसी तरह से दिल्ली में पानी की समस्या हल करने के लिए भी छह हजार करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। वर्ष 2070 तक पानी की समस्या नहीं होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की बिजली-पानी सहित अन्य योजनाएं जारी रहेंगी। संकल्प पत्र में उन बातों का जिक्र है, जिसे सर्वश्रेष्ठ दिल्ली के निर्माण के लिए भाजपा सत्ता में आने पर काम करेगी। इस मौके पर संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, प्रदेश प्रभारी, श्याम जाजू सहित दिल्ली के सभी सांसद व वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

सीईओ ने किया शाहीन बाग में मतदान केंद्रों का निरीक्षण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) डॉ. रणबीर सिंह ने शुक्रवार को शाहीन बाग स्थित पांच मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ दक्षिणी-पूर्वी दिल्ली की डीएम हरलीन कौर, विशेष पुलिस आयुक्त (इंटेलिजेंस) व विधानसभा चुनाव में दिल्ली पुलिस के नोडल ऑफिसर प्रवीर रंजन, संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिणी परिक्षेत्र देवेश चंद्र श्रीवास्तव, दक्षिणी-पूर्वी जिले के पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल, एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश, एसडीएम चुनाव हरीश बजाज समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

सीईओ ने नॉर्थ ब्लॉक मेन रोड और हरी कोठी मार्ग स्थित मतदान केंद्रों तक जाने वाले सभी रास्तों का निरीक्षण किया। उन्होंने शाहीन बाग थाने जाकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से क्षेत्र के रास्तों, गलियों व सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। ज्यादातर मतदान केंद्र छोटी व संकरी गलियों में स्थित होने के कारण वहां के वोटरों को होने वाली संभावित असुविधाओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मतदान केंद्रों के समस्त अधिकारियों व अध्यापकों से बात की गई।

दिल्ली को बनाएंगे सबसे खूबसूरत राजधानी : शाह

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▸ केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर बोला हमला

पूर्व भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने पर दिल्ली को पांच सालों में दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी बना देंगे। दिल्ली का सर्वांगीण विकास ही भाजपा का लक्ष्य है। शाह शुक्रवार शाम शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी डॉ. एससी वत्स के समर्थन में पीतमपुरा में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में दो खेमे हैं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाक के आतंकियों को नेस्तनाबूद किया तो दूसरी तरफ शाहीन बाग को समर्थन करने वाली आप व कांग्रेस के लोग हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा के लिए फैसला जनता को करना है कि वह किसे चुनती है। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जीवन में ऐसी झूठ बोलने वाली सरकार नहीं देखी। यह सरकार झूठ बोलने में नंबर एक होगी, अगर कोई ऐसी कोई प्रतियोगिता हो। केंद्रीय मंत्री ने केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता के सवालों से बचने के लिए सभाओं के बदले रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि सभाओं में उन्हें जनता के सवालों का जबाव देना पड़ता।

गृह मंत्री शाह ने कहा कि केजरीवाल ने 500 स्कूल, 50 कॉलेज, 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, 5000 डीटीसी बसें, बसों में कमांडो रखने, आठ लाख युवाओं को रोजगार, अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने, यूरोप जैसी सड़क बनाने, यमुना को साफ करने जैसे वादे किए, लेकिन क्या ये वादे पूरे किए गए। केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद बंगला गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन सब कुछ ले लिया। केजरीवाल ने आयुष्मान भारत योजना से जनता को वंचित रखकर दिल्ली की जनता से धोखा किया है। दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन केजरीवाल हैं जो 800 करोड़ के घाटे में चला गया, जबकि यह 178 करोड़ के लाभ में था। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत कर दिल्ली की 50 लाख की आबादी को राहत दी।

भाजपा के संकल्प पत्र को आप ने बताया जुमला पत्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा के लिए जारी किए गए भाजपा के संकल्प पत्र को आम आदमी पार्टी (आप) ने जुमला-पत्र करार दिया है। राज्य सभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि शुक्रवार को भाजपा ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, दरअसल वह एक नया जुमला पत्र और झूठ का पुलिंदा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि इस संकल्प पत्र के साथ भाजपा ने साफ कर दिया कि वह दिल्ली में आप की सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाएं जैसे 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 20,000 लीटर मुफ्त पानी, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों की मुफ्त तीर्थ यात्रा, दुर्घटना पीड़ितों की फरिश्ते योजना आदि को बंद करना चाहती है। सही मायने में यह संकल्प पत्र नहीं, बल्कि दिल्ली वालों की बर्बादी का संकल्प है। सिंह ने कहा कि भाजपा कह रही है, हम दिल्ली से टैंकर माफिया का राज खत्म करेंगे, जबकि टैंकर माफिया का राज तो खुद भाजपा ने ही चला रखा है। भाजपा के मुंह से नए स्कूल खोलने की बात सुनकर हंसी आती है। भाजपा के राज में मध्य प्रदेश के अंदर हजारों स्कूल बंद किए गए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार ने पाठशाला को गोशाला बना दिया। हरियाणा में भाजपा सरकार ने नए स्कूल खोलने के बजाय सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद कर दिए।

सीलिंग के मामले पर उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा ही हास्यास्पद है। अपराधी खुद कह रहा है कि आपको मारेंगे नहीं, आपके साथ न्याय करेंगे। भाजपा कह रही है कि दिल्ली सरकार जो मुफ्त इलाज, दवाइयां दिल्ली की जनता को उपलब्ध करा रही है, वह सभी बंद कर देंगे व आयुष्मान योजना लागू करेंगे। इस योजना के नियम इतने कठोर हैं कि दिल्ली के एक भी व्यक्ति को इसका लाभ नहीं मिलेगा। स्वच्छता के मुद्दे पर कहा कि पिछले लगभग 13 साल से दिल्ली नगर निगम में भाजपा है। जिसकी जिम्मेदारी है, दिल्ली को साफ सुथरा रखना, वहां भाजपा की सरकार है। हरियाणा से आएं या उत्तर प्रदेश से दिल्ली में घुसते ही कूड़े का पहाड़ नजर आता है। आप कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। सर्विसेज डिपार्टमेंट तो पहले से ही आपके पास है, तो आज तक क्यों नहीं पक्का किया।

संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने संकल्प पत्र के नाम से जारी भाजपा के घोषणा पत्र को झांसा पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे, उनमे से एक भी पूरा नही किया और अपने ही वायदों को जुमला कहकर पल्ला झाड़ा लिया।

चोपड़ा ने कहा कि संकल्प पत्र में कहा गया है कि वे दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए नए नियम बनाएंगे जबकि दिल्ली में सीलिंग होती रही और छोटे उद्योग धंधे बंद होने के कारण लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। उस समय केंद्र व नगर निगम में बैठी भाजपा सरकार व आप की दिल्ली सरकार ने सीलिंग रुकवाने के लिए न तो नियमों में बदलाव किया और न ही सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा। आज भाजपा चुनाव के समय कह रही है कि वह सफाई कर्मचारियों के एरियर का भुगतान कर देंगे, परंतु सफाई कर्मचारियों को एरियर मिलना तो दूर मासिक वेतन लेने के लिए उनको बार-बार हड़ताल पर जाना पड़ता है। भाजपा दो साल में दिल्ली को कचरा मुक्त करने की बात कह रही है। शायद भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह भूल गया है कि दिल्ली नगर निगम में पिछले 13 वर्षों से भाजपा का ही शासन है और सफाई व्यवस्था जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निगम की होती है।

भाजपा की प्रदूषण के प्रति असंवेदनशीलता इस बात से जाहिर होती है कि उनके झांसा पत्र में प्रदूषण कम करने के ठोस उपायों के बारे में कोई चर्चा तक नही है, जबकि प्रदूषण दिल्ली की एक मुख्य समस्या है। इसके कारण दिल्लीवासियों को प्रतिवर्ष आपातकालीन स्थिति का सामना करते हुए दमघोटू प्रदूषण में जीना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संकल्प पत्र के सह-संयोजक के रूप में राजकुमार चौहान का नाम छपा है, जिससे इनके घोषणा पत्र की गंभीरता का पता चलता है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने कहा कि भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र दिल्ली के बेरोजगार नौजवानों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। भाजपा सरकार द्वारा दो करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने का नारा दिया गया था, लेकिन भाजपा के राज में देश में बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है।

केजरीवाल बोले- हम बच्चों को कलम दे रहे हैं, वे बंदूक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास गुरुवार को गोली चलने की घटना पर भाजपा पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने बच्चों को कंप्यूटर और उनके हाथों में कलम दी है, जबकि वे (भाजपा) उन्हें बंदूक और नफरत दे रहे हैं। दिल्ली सरकार के एक स्कूल के छात्र के आइटी-प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित करने वाले वीडियो को ट्वीट करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमने बच्चों के हाथों में कलम और कंप्यूटर दिए हैं और आंखों में उद्यमशीलता के सपने। वे बंदूक और नफरत दे रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि आप अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं? 8 फरवरी को बताइएगा। जामिया यूनिवर्सिटी में गुरुवार को तब तनाव व्याप्त हो गया, जब एक नाबालिग ने पिस्तौल से नागरिक संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह पर गोली चला दी। इस दौरान एक छात्र घायल हो गया था। आप ने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी दंगा जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है और 8 फरवरी के विधानसभा चुनाव को स्थगित कराना चाहती क्योंकि उसे हार का आभास हो गया है।

आप ने अनुराग ठाकुर के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत : भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने पुलिस आयुक्त को शिकायत दी है। इसमें कहा गया है कि अनुराग ठाकुर ने भड़काऊ बयान दिया था। उसके बाद जामिया नगर में गोली चलाने की घटना हुई है। इस मामले की जांच अनुराग ठाकुर से जोड़ की जाए।

चांदनी चौक विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते अरविंद केजरीवाल। जागरण

भाजपा के स्टिंग को बताया फर्जी : एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोहल्ला क्लीनिक पर भाजपा के हालिया स्टिंग के जवाब में कहा कि भाजपा ने एक बार फिर फर्जी वीडियो जारी कर दिल्ली के लोगों का मजाक उड़ाया। दिल्लीवालों ने मेहनत करके 450 वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लीनिक बनाए। पूरी दुनिया में दिल्ली का नाम रोशन किया। आज मीडिया की जांच में भाजपा का झूठ पकड़ा गया। दिल्ली के लोग मोहल्ला क्लीनिक से बेहद खुश हैं।

भाजपा को वोट दिया तो नहीं मिलेगा मुफ्त बिजली पानी का लाभ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी बिजली और पानी मुफ्त का जिक्र नहीं है। ऐसे में यदि लोग भाजपा को वोट देते हैं, तो बिजली और पानी मुफ्त नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आप सरकार है तब तक दिल्लीवासियों को बिजली और पानी मुफ्त मिलेगा।

मोदी को हराने की अपील पर पाक मंत्री को लताड़ा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने संबंधी पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर बरसे। उन्होंने पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मसलों में दखल न देने की नसीहत देने के साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं उनके भी प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने शुक्रवार को किए गए ट्वीट में सीएए पर प्रदर्शन, गिरती अर्थव्यवस्था और कश्मीर का जिक्र कर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इसके साथ ही दिल्ली चुनाव में उन्हें हराने की अपील भी की थी। पाकिस्तानी मंत्री का यह ट्वीट केजरीवाल को नागवार गुजरा और उन्होंने तत्काल पाकिस्तान को खरी-खरी सुना दी।

पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने लिखा कि 'नरेंद्र मोदी भारत के और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली का चुनाव भारत का आंतरिक मसला है और हमें आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जितनी कोशिश कर ले, इस देश की एकता पर प्रहार नहीं कर सकता।'

पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को कांग्रेस ने किया निलंबित

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : सियासी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने दिल्ली में अपने दिग्गज नेता महाबल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। पूर्व सांसद के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको की ओर से जारी बयान के मुताबिक मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि महाबल के बेटे विनय मिश्रा 13 जनवरी को आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए थे। वह द्वारका से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि मिश्रा बेटे को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। महाबल मिश्रा कांग्रेस के बड़े नेता हैं। वह पश्चिमी दिल्ली सीट से सांसद और द्वारका विधानसभा सीट से **विधायक भी रहे हैं। इससे पहले 1997 में वह निगम पार्षद भी रहे।** विनय मिश्रा भी यूथ कांग्रेस के नेता रहे हैं। विनय मिश्रा 2013 में विधायक का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए थे।

महाबल 2019 में लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बावजूद इसके अचानक उनके बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पहले कहा जा रहा था कि विनय मिश्रा ने पिता की जानकारी के बगैर आप में शामिल हुए हैं, लेकिन जैसे ही चुनावी सरगर्मियां तेज हुईं, महाबल बेटे के प्रचार में जुट गए।

नेशनल कैपिटल

पासपोर्ट न होने पर टीवी अभिनेता को आइजीआइ एयरपोर्ट पर रोका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

टीवी अभिनेता करणवीर बोहरा को आइजीआइ एयरपोर्ट पर पासपोर्ट न होने की वजह से बुधवार की रात नेपाल जाने से रोका गया। उनके पास केवल आधार कार्ड था। इसके कारण उन्हें नेपाल जाने की इजाजत नहीं दी गई। बाद में उनका कर्मी पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद उन्हें जाने की इजाजत मिली। करणवीर बोहरा ने शरारत, कसौटी जिंदगी की, नागिन जैसे टीवी धारावाहिकों में काम किया है। वह विग बॉस के प्रतिभागी भी रह चुके हैं। इस घटना पर करणवीर ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी। उन्होंने यात्रा से रोकने पर एयरपोर्ट प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी व्यक्त की।

एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक मुंबई से एयर इंडिया की उड़ान से करणवीर दिल्ली पहुंचे थे। बाद में उन्हें आइजीआइ एयरपोर्ट से नेपाल रवाना होना था। इस दौरान उनके पास सिर्फ आधार कार्ड था। इसके कारण उन्हें नेपाल जाने से रोक दिया गया। इसके कुछ घंटों के बाद उनका कर्मचारी मुंबई से उनका पासपोर्ट लेकर पहुंचा। इसके बाद वह नेपाल की यात्रा कर सके। ट्वीट के माध्यम से बोहरा ने कहा कि यदि नेपाल यात्रा के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं था तो उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर ही रोका जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने भी उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं दी। एक वर्ष पहले भी पासपोर्ट फटे होने के कारण करणवीर को मास्को एयरपोर्ट पर रोका गया था।

आइजीआइ पर 1.34 करोड़ की नगदी के साथ चार दबोचे : आइजीआइ एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों ने विदेशी मुद्रा की तस्करी में दो अफगानी सहित चार को दबोचा है। अलग-अलग तीन मामलों में धरे गए यात्रियों के पास से 1.34 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। आरोपितों की पहचान अब्दुल सबूर अमिरी, जफर मुहम्मद (दोनों अफगानी) सुरिंदर सिंह और हबिबुल्ला के रूप में हुई है। सुरिंदर सिंह और हबिबुल्ला भारतीय नागरिक हैं।

ठिठुरन बरकरार, 7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : मौसम में आए बदलाव के कारण न केवल दिल्ली में ठिठुरन बरकरार है, बल्कि न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी अगले दो दिन ऐसी ही ठंडक बनी रहेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान तो कम ही बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। पालम में दृश्यता का स्तर 100 मीटर तक रह गया। दोपहर तक ठंडी हवा चली, हालांकि दोपहर बाद निकली धूप से मौसम कुछ गर्म हुआ, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर बढ़ गई। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 7.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मौसम कुछ साफ होगा जिससे अधिकतम तापमान में वृद्धि की उम्मीद है।

हुमायूं के मकबरे में शिशु देखभाल कक्ष का शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हुमायूं के मकबरे में छोटे बच्चों के लिए शिशु देखभाल कक्ष खोला गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसका उद्घाटन किया। कक्ष के अंदर बच्चों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस मौके पर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि पर्यटक स्मारकों में दूध पीने वाले बच्चे को भी लेकर जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए। इसकी ताजमहल से शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि देश भर में 100 आदर्श स्मारकों की श्रेणी में पहले चरण में कम से कम यह व्यवस्था हो। जिन स्मारकों में साउंड एंड लाइट है वह रात नौ बजे तक खुलेंगे। उन्होंने हुमायूं का मकबरा परिसर के अलावा अब्दुल रहीम ए खाना में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इसके अलावा सुंदर नर्सरी में केंद्रीय मंत्री ने 'अब्दुर्रहीम खान ए खाना काव्य सौंदर्य और सार्थकता' पुस्तक का विमोचन भी किया।

लाइफस्टाइल

रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता अपनी फिटनेस का रखते हैं पूरा ख्याल

दिनचर्या को प्रभावित कर रहा डिजिटल मंच

प्रियंका दुबे मेहता, नई दिल्ली

इन दिनों नेताओं की लाइफस्टाइल में केवल भागदौड़ ही नहीं, बल्कि उनके लिए डिजिटल मंचों पर उपस्थिति भी अनिवार्य बनी हुई है। ऐसे में उनकी दिनचर्या पूरी तरह बिगड़ गई है। दिनभर काम के बाद मौका मिलने पर आराम करने के बजाय सोशल मीडिया पर उपस्थिति दिखाने और जनता से कनेक्ट बनाए रखने के लिए नेता घंटों समय दे रहे हैं। नेताओं की पल-पल की टिप्पणियों और संदेशों से इसका पता चलता है। रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी व विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता कहते हैं कि उनकी दिनचर्या इस चुनावी मौसम में पदयात्रा और रैलियों के अलावा डिजिटल दुनिया से प्रभावित हो रही है।

फिटनेस के लिए सैर : चुनावी माहौल में फिटनेस बैकसीट ले लेता है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता अपनी फिटनेस का पूरा-पूरा ख्याल रख रहे हैं। वह शाम को कम से कम पांच किलोमीटर की सैर जरूर करते हैं। उनका कहना है कि अगर यूथ के लिए प्रेरणा बनना है तो नेताओं के लिए फिट रहना पहली जरूरत बन जाती है। वह फिट रहने के लिए थोड़ी-बहुत कसरत भी कर लेते हैं लेकिन बेहद व्यस्तता के कारण फिलहाल केवल सैर से काम चला रहे हैं।

नाश्ते तक सीमित हुई डायट : विजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि सुबह का पहला भोजन पौष्टिक व ऊर्जादायक हो। ऐसे में स्प्राउट्स, ओट्स व फलों का सेवन करते हैं। वैसे आम दिनों में वह तीनों समय भोजन करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल में केवल एक समय ही ऐसा कर पा रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभाओं आदि में उन्हें जो तली-भुनी चीजें खाने को दी जाती है, उसे खाना पड़ता है। सामान्य दिनों में वह इसे नहीं खाते। वैसे वह फूडी हैं और दिल्ली से लेकर देश-विदेश के स्थानों पर जाकर डिशेज को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं।

कुर्ता-पायजामा है सुविधाजनक : विजेंद्र का कहना है कि फिटनेस के साथ-साथ फैशन को लेकर नेताओं में जागरूकता आई है। वह भी इस मामले में खुद को अपडेटेड रखते हैं। वह कुर्ता-पायजामा से लेकर पैंट कोट व शेरवानी तक पहनते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उन्हें कुर्ता-पायजामा सुविधाजनक लगता है। वह जूतों का चयन करते वक्त ध्यान रखते हैं कि वे हल्के और सुविधाजनक हों। इस समय ब्रांडेड स्पोर्ट्स शूज पहनना पसंद करते हैं। हालांकि उनका मानना है कि फैशन नहीं, बल्कि अंत में सादगी के साथ परफॉर्मेंस जरूरी है। यह भी मानते हैं कि अब नेताओं के फैशन को लेकर रूढ़ियां टूटी हैं। राजनीति में व्यक्तिगत पसंद व फैशन से समझौता करना जरूरी नहीं है।

शॉपिंग के लिए नहीं मिलता समय, होती है तकरार : विजेंद्र को शॉपिंग करना पसंद है लेकिन इसके लिए समय नहीं मिल पाता। इस चीज को लेकर पत्नी से अक्सर तकरार होती है। वह अक्सर फिल्में देखने के लिए रात के शो में जाते हैं। वह बताते हैं कि बच्चे उन्हें बिना बताए रात के शो की टिकट करवा देते हैं तो वे परिवार के साथ फिल्म देखने निकल जाते हैं।

फुर्सत के पल बिताते रोहिणी विधानसभा क्षेत्र से भापजा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता। सौजन्य : विजेंद्र गुप्ता

तनाव मुक्ति के लिए संगीत का सहारा : विजेंद्र कहते हैं कि इस समय नींद पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में समय मिलते ही सोने का प्रयास करते हैं। गाना सुनते हुए सोना थकान व तनाव से राहत देता है। इसके अलावा संगीत सुनना उन्हें तनाव मुक्ति का कारगर तरीका लगता है। इस भागदौड़ में करीब एक माह के पोते के लिए थोड़ा समय निकाल लेते हैं और उससे बहुत सुकून मिलता है।

1951-52 में हुआ पहला आम चुनाव। भारतीय संसद के दो सदन है-उच्च सदन-राज्यसभा और निम्न सदन-लोक सभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। जिसका विघटन कभी नहीं होता है। हर दो वर्ष में इसके एक-तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं।

मृत्युदंड मामले में पीड़ित और समाज केंद्रित दिशानिर्देश देने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सख्त रुख

- ताकि कानूनी पेंच का सहारा लेकर फांसी से न बचने पाएं दोषी
- केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट विचार को तैयार, नोटिस जारी

आने वाले दिनों में मृत्युदंड पाए दोषियों का कानूनी पेचीदगियों का सहारा लेकर मौत को धता बताना कठिन होगा। सुप्रीम कोर्ट मृत्युदंड के मामले में पीड़ित और समाज के पहलू को ध्यान में रखकर दिशा निर्देश जारी करने और फांसी की सजा देने की समयसीमा तय करने पर विचार करने को राजी हो गया है।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अर्जी पर विचार का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया। केंद्र ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 21 जनवरी 2014 में शत्रुघ्न चौहान के फैसले में मृत्युदंड के बारे में तय किए गए दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की है।

शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की पीठ के समक्ष आग्रह किया कि उस फैसले में कोर्ट ने दोषी के अधिकारों को केंद्र में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे। अब पीड़ित और समाज को केंद्र में रखते हुए दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने साफ किया कि शत्रुघ्न चौहान मामले में जिनके पक्ष में फैसला हुआ था वे प्रभावित नहीं होंगे।

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड व अन्य मामलों में फांसी की सजा पाए दोषियों के कानूनी प्रक्रिया का लाभ उठा कर मामला लटकाने की प्रवृत्ति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की है। केंद्र ने अर्जी में मांग की है कि कोर्ट आदेश दे कि फांसी की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन के भीतर डेथ वारंट जारी कर दिया जाएगा और उसके सात दिन के भीतर उन्हें फांसी दे दी जाएगी। इस पर उनके साथी सह अभियुक्तों की पुनर्विचार, क्यूरेटिव या दया याचिका लंबित रहने का असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने शत्रुघ्न चौहान फैसले में फांसी के लिए तय की गई 14 दिन की समय सीमा को घटा कर सात दिन करने का आग्रह किया है। केंद्र ने कहा, कोर्ट ने शत्रुघ्न मामले में कहा था कि दया याचिका खारिज होने के बाद अभियुक्त को 14 दिन का समय दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि फांसी की सजा पाए दोषी का मामला लटके रहना उस पर मानसिक अत्याचार है।

सरकार की मांग है कि कोर्ट आदेश दे कि पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय सीमा के भीतर ही दोषी को क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की इजाजत होगी। दोषी दया याचिका देना चाहता है तो उसे डेथ वारंट जारी होने के सात दिन के भीतर ही ऐसा करना होगा। सरकार की यह भी मांग है कि कोर्ट राज्य, जेल अथारिटी तथा अन्य को आदेश दे कि वे दया याचिका खारिज होने के बाद सात दिन में डेथ वारंट जारी करेंगे और फिर सात दिन में फांसी दे दी जाएगी।

स्पाइसजेट डाटा लीक से प्रभावित हुए 12 लाख यात्री!

- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने किया दावा
- विमानन कंपनी ने किया खंडन, कहा-हमारा सिस्टम बेहद सुरक्षित

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत की बड़ी निजी विमानन कंपनी स्पाइसजेट में डाटा लीक का मामला सामने आया है। इससे उसके करीब 12 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शोध करने वालों का दावा है कि स्पाइसजेट के डाटाबेस में आसानी से सेंध लगाई जा सकती है। इसके जरिये यात्रियों के नाम, फोन नंबर, ई-मेल आइडी और जन्मतिथि आदि जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। हालांकि, विमानन कंपनी ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसके सिस्टम में डाटा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

टेकक्रंच के अनुसार, पहली बार डाटा लीक मामले का पर्दाफाश करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया कि कोई भी बहुत ही आसानी से अनुमान लगाने वाले पासवर्ड के जरिये स्पाइसजेट के सिस्टम से डाटा हासिल कर सकता है। उनका कहना है कि एयरलाइन के डाटाबेस में कोई भी व्यक्ति आसानी से सेंध लगा सकता है, जो यह जानता हो कि उसे हासिल करने की सामान्य प्रक्रिया क्या है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने डाटा लीक के बारे में स्पाइसजेट को आगाह किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक प्रक्रिया नहीं आई है। इसके बाद उन्होंने भारत सरकार की इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम (सीईआरटी-आइइन) को इत्तला किया। हालांकि, सीईआरटी-आइइन ने क्या उपाय किए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है।

स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, 'हमारे यात्रियों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे सिस्टम पूरी तरह सक्षम और सुरक्षित हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। हम यात्रियों के डाटा की सुरक्षा के लिए हरसंभव उपाय करते हैं और आश्वस्त करते हैं कि डाटा की देखभाल उत्कृष्ट और सबसे सुरक्षित तरीके से की जा रही है।'

एनपीआर से माता-पिता के विवरण से जुड़ा सवाल हटाया जाए : जदयू

नई दिल्ली, प्रेट्र : जनता दल (यूनाइटेड) ने शुक्रवार को राजग घटक दलों की बैठक में सरकार से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एपीआर) की प्रश्नावली से माता-पिता के विवरण से जुड़े सवाल हटाए जाएं।

जदयू नेता ललन सिंह ने बताया कि राजग की बैठक में उन्होंने यह मुद्दा उठाया और गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया कि इस मसले पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस मसले पर शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने भी जदयू का समर्थन किया। शुक्रवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र में रणनीति पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई भाजपा व उसके सहयोगी दलों की इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर पहले ही कह चुके हैं कि एनपीआर की कवायद के दौरान लोग माता-पिता की जन्मतिथि या अन्य जानकारियां नहीं देने के लिए स्वतंत्र हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में एनपीआर की कवायद शुरू करने की घोषणा भी कर दी है।

अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाना ऐतिहासिक

अभिभाषण ▶ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास प्राथमिकता

अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लोगों के परिपक्व व्यवहार को सराहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास का रास्ता साफ हुआ है। उन्होंने अयोध्या मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों द्वारा दिखाई गई परिपक्वता की भी सराहना की और कहा कि इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जम्मू-कश्मीर व लद्दाख का तेज से विकास करना है। सरकार के ऐतिहासिक फैसले से इन दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को वह अधिकार मिले हैं जो देश के बाकी नागरिकों को हासिल हैं। इस फैसले पर उठाए जा रहे सवालों को राष्ट्रपति ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोकसभा में दिए बयान का हवाला देते हुए खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि संघीय व्यवस्था में एक राज्य के नागरिकों के मौलिक अधिकार दूसरे राज्य से अलग नहीं हो सकते। जम्मू-कश्मीर में हुए संवैधानिक बदलाव के बाद वहां केंद्रीय योजनाओं को लागू करने में आई तेजी की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा वहां के लिए लागू की गई तमाम बड़ी स्कीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पंचायती राज व्यवस्था की नई शुरुआत हुई है। 300 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव को भी उन्होने अहम कदम बताया।

राष्ट्रपति ने कहा कि रामजन्म भूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जिस तरह का भरोसा जताया है, उससे लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। फैसले पर लोगों का परिपक्व व्यवहार सराहनीय है।

भारत पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की राह पर : मोदी दो सरकार की अहम उपलब्धियां की फेहरिस्त में करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक करार दिया। वर्ल्ड बैंक की इज आफ डूइंग बिजनेस, विश्व इनोवेशन और दिवालियापन का समाधान निकालने में भारत की सुधरी विश्व रैंकिंग का हवाला देते हुए उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर सरकार के कदमों से हो रहे बदलाव का जिक्र किया। इन कदमों से भारत पांच ट्रिलियन डॉलर (350 लाख करोड़ रुपये) की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है।

सरकार की उपलब्धियां गिनाई : राष्ट्रपति ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सरकार के मूल मंत्र से नागरिकों के जीवन में हो रहे बड़े बदलावों की भी चर्चा की। आठ करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, दो करोड़ गरीबों को घर, लगभग 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खुलने, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 43 हजार करोड़ रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाने, 50 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज, 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा और ढाई करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाने के सरकार के कदमों को इसी मूल मंत्र का हिस्सा बताया।

भावी विकास की रूपरेखा पेश की : सरकार के विकास की भविष्य की रूपरेखा रखते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अगले पांच साल में नए हाइवेज, वाटरवेज, एयरवेज और आईवेज बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस पर 100 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा। गांवों की सड़कों को बेहतर कर मुख्य मार्गों से जोड़ने की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है। गांवों में सभी घरों को पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा जिस पर 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। डिजिटल युग में देश के गावों को विकास की गति से जोड़ने के लिए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की योजना से लेकर स्टार्ट अप इंडिया स्कीम की अहमियत की भी चर्चा की।

नई दिल्ली में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए जाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। साथ में सबसे आगे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उनके पीछे राष्ट्रपति कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

संयुक्त सत्र में ही दिख गई सीएए पर सियासी घमासान की झलक

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- सत्तापक्ष ने मेजें थपथपाकर तो विपक्ष ने नारेबाजी की गूंज से दिए संकेत
- 14 विपक्षी दलों के नेताओं ने काली पट्टी बांधी

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के साथ एनआरसी-एनपीआर पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच सियासी घमासान की झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान पहले ही दिन दिख गई। कांग्रेस समेत विपक्ष की 14 पार्टियों के सांसदों ने अभिभाषण के दौरान हाथ में काली पट्टी बांधकर आक्रामक विरोध जताया। सत्ता पक्ष ने मेजों की थपथपाहट से सेंट्रल हॉल में सीएए के मुखर समर्थन के सुर को गुंजायमान कर बैकफुट पर नहीं आने का साफ संदेश दिया। तो विपक्ष ने भी इस दौरान नारेबाजी और शोरगुल के सियासी विकल्प का इस्तेमाल कर सरकार से भिड़ने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।

सीएए-एनआरसी-एनपीआर पर बजट सत्र में सरकार की आक्रामक घेरेबंदी के विपक्ष के तेवरों का संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने दिख गया। कांग्रेस की अगुआई में 14 पार्टियों के नेताओं ने सरकार पर संविधान की अनदेखी कर सीएए लाने का आरोप लगाते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अभिभाषण के दौरान इन दलों के सांसदों ने सेंट्रल हॉल में भी काली पट्टी बांधे रखी। अपने कड़े विरोध का इजहार करने के लिए सोनिया गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी सरीखे नेता पहली पंक्ति की अपनी सीट पर नहीं बैठे। सोनिया और आजाद पीछे पांचवीं पंक्ति में अपने सांसदों के साथ बैठे। वहीं शरद पवार और मुलायम सिंह जैसे वरिष्ठ नेता तो सदन में आए ही नहीं थे। पूर्व प्रधानमंत्री के नाते मनमोहन सिंह के अलावा पहली पंक्ति में विपक्ष का कोई नेता बैठा ही नहीं।

अभिभाषण के क्रम में राष्ट्रपति ने सबसे पहले जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के कदमों का जिक्र किया तो सत्तापक्ष ने इस दौरान 10 बार मेजें थपथपाई। विपक्षी दलों के सदस्यों ने सत्ता पक्ष की इस धमाकेदार गूंज पर किसी तरह का विरोध नहीं किया। मगर जब सीएए लाने के सरकार के फैसले को राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक ठहराया तो सत्तापक्ष की यह गूंज गड़गड़ाहट में तब्दील हो गई। भाजपा-राजग के सांसद कुछ मिनटों तक इतनी जोर-जोर से मेज थपथपाते रहे कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति की बात सुनने के लिए कान में हेडफोन लगाना पड़ा। सत्ता पक्ष के इस उत्साह को देख विपक्षी सांसदों का धैर्य भी जवाब दे गया। सबसे पहले सपा के शफीकुर रहमान बर्क और असम के एक कांग्रेस सांसद ने उठकर विरोध की आवाज उठाई। इसके बाद तो सभी विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर अभिभाषण के दौरान 'शर्म करो' की नारेबाजी करने लगे। इसमें युवा सांसदों से लेकर वयोवृद्ध सदस्य मोतीलाल वोरा तक शामिल थे। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी तभी थमी जब सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेज थपथपाना बंद किया।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच झलक रही इस तनातनी के बावजूद इसके बाद राष्ट्रपति के संबोधन में नारेबाजी नहीं हुई। हालांकि अभिभाषण के 45वें मिनट के दौरान अचानक तृणमूल कांग्रेस के सांसद अपनी जेबों से उजले कपड़े पर लाल रंग से सीएए-एनआरसी और एनपीआर के विरोध में लिखे बैनर लिए खड़े हो गए। करीब पांच मिनट तक बिना शोरगुल किए तृणमूल कांग्रेस के सांसद बैनर और पोस्टर राष्ट्रपति के सामने लहराते रहे। पार्टी के एक सांसद ने मोबाइल से इसका वीडियो बनाने से भी गुरेज नहीं किया। हालांकि पक्ष-विपक्ष के बीच बैनर लहराने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और शांति बनी रही। तभी सेंट्रल हाल के ऊपरी झरोखे से एक अर्द्धसफेद कबूतर उड़ता हुआ अंदर आया और चुपचाप दूसरे झरोखे पर जाकर बैठ गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन प्रस्ताव लाएगा विपक्ष

अभिभाषण में सीएए को शामिल करने पर एतराज जाहिर करते हुए राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसे राष्ट्रपति के संबोधन का हिस्सा बनाना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति तो केवल कैबिनेट से पारित संबोधन पढ़ते हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि सरकार देश को विभाजित करने के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है जो बेहद खतरनाक है। विपक्षी दलों ने साफ संकेत दिए हैं कि अभिभाषण में सीएए के जिक्र पर विपक्षी दल राज्यसभा में संशोधन प्रस्ताव लाकर सरकार को मुश्किल में डालेंगे और इस पर दोनों के बीच घमासान होना तय है।

आरटीआइ एक्ट में संशोधन को चुनौती देने वाली अर्जी पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसियां : सूचना का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ व केएम जोसेफ की पीठ ने नोटिस पर केंद्र से चार हफ्ते में जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि संशोधनों के जरिये सूचना आयोग के अधिकारों में कमी की गई है।

पिछले साल कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि संस्था से बदला लेने के उद्देश्य से सरकार सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन ला रही है क्योंकि उसने सरकार के झूठे दावों को उजागर कर दिया था। सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान जयराम रमेश ने सरकार द्वारा अधिनियम को कमजोर करने के पीछे पांच कारण बताए थे।

कांग्रेस नेता का कहना था कि 2003 से 2013 के बीच गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री (नरेंद्र मोदी) को उनके राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति पर जवाब देने के लिए योजना आयोग में आने के लिए बाध्य किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपना बदला लिया और योजना आयोग को खत्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री पांच मामलों में अपना बदला ले रहे हैं क्योंकि इन मामलों में सूचना आयोग के आदेश से सरकार का झूठ उजागर हो गया। इनमें प्रधानमंत्री की शैक्षिक योग्यता, बोगस राशन कार्ड के मामले में प्रधानमंत्री का झूठा दावा, नोटबंदी पर रिजर्व बैंक की नामंजूरी को उजागर करना, तत्कालीन रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा टॉप एनपीए डिफॉल्टरों की सूची देना और विदेश से लाई गई कालेधन की राशि उजागर करना। ये सभी मामले सरकार को शर्मसार करने वाले हैं। लिहाजा संशोधन विधेयक लाने का असल मकसद सूचना आयोग को दंतविहीन और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर कार्य करने वाली संस्था बनाना है।

जयराम रमेश फाइल फोटो

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका

गुजरात में मां की जाति से भी बन सकेगा बच्चे का जाति प्रमाण पत्र

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- विधवा, तलाकशुदा व सिंगल मदर के मामलों पर राज्य सरकार का फैसला
- राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को इस संबंध में जारी किए गए आदेश

केंद्र की अधिसूचना के आधार पर गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग की विधवा और परित्यक्ता के बच्चों का प्रमाण पत्र मां की जाति के आधार पर बनाने का निर्देश जारी किया है।

गुजरात सरकार ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर (डीएम) व सामाजिक न्याय विभाग के निदेशकों को केंद्र सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग की अधिसूचना को अग्रसारित करते हुए कहा है कि विधवा, तलाकशुदा और अकेली रहने वाली माता की संतान का प्रमाण पत्र उसकी माता की जाति के अनुसार बनाया जाएगा। अभी तक आमतौर पर जाति प्रमाण पत्र पिता की जाति के आधार पर ही बनाए जाते रहे हैं।

केंद्र सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थिति, तलाकशुदा, परित्यक्ता व विधवा महिला के बच्चों के जाति प्रमाण उसकी माता की जाति समुदाय के आधार पर ही बनाए जाने चाहिए यदि बच्चों का लालन-पालन मां के सानिध्य में ही हुआ हो। बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव तथा केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को भी यह परिपत्र जारी कर इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे।

सरकार ने दो अदालतों के फैसलों को भी इसके साथ संलग्न किया है जिसमें से एक उच्चतम न्यायालय में महेश भाई नायक बनाम स्टेट ऑफ गुजरात तथा दूसरा दिल्ली हाईकोर्ट का रुमी चौधरी बनाम राजस्व विभाग एनसीटी- दिल्ली मामला का है जिनमें पिता की जाति के अलावा मां की जाति के आधार पर बनने वाले जाति प्रमाण पत्र को स्वीकार्यता दी गई है। उल्लेखनीय है कि यह नई व्यवस्था होगी।

निलंबित विधायक भूपेंद्र खांट को बंधी उम्मीद

गुजरात में ऐसे ही एक मामले में विधायक भूपेंद्र सिंह खांट की विधानसभा की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। पंचमहल जिले की मोरवा हडफ विधानसभा से 2017 में विधायक चुने गए भूपेंद्र की विधानसभा की सदस्यता मई 2019 में विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उनका प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। राज्य के आदिवासी विकास आयुक्त ने बताया कि खांट की माता अनुसूचित जनजाति से आती हैं जबकि पिता ओबीसी समुदाय के हैं, इसलिए भूपेंद्र खांट का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। भूपेंद्र सिंह बताते हैं कि पिता ने मां को छोड़ दिया था। उनका जन्म मां के पीहर में हुआ तथा लालन-पालन व स्कूली शिक्षा भी वहीं पर पूरी की। सरकार के नए परिपत्र ने भूपेंद्र की उम्मीद को जगा दिया है। फिलहाल उनका मामला गुजरात उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा 5 फरवरी को इस पर सुनवाई होनी है।

बड़ा फैसला

रेलवे बोर्ड ने कारोबारियों की मांग पर उठाया यह कदम, मालगाड़ियों से सामान उतारने या चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में मिलेगी मदद

मालगाड़ी में सामान की रक्षा करेंगे निजी सुरक्षाकर्मी

- पहली बार रेलवे बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ दी इजाजत
- पूर्वी जोन में छह महीने के लिए आज से प्रभावी होगी योजना

नई दिल्ली, प्रेट्र : मालगाड़ियों में सामान की सुरक्षा के लिए रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने पहली बार निजी एजेंसियों के सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को मालगाड़ियों में लदे सामान की देखभाल की इजाजत दे दी है। शुरुआती तौर पर पूर्वी जोन में यह आदेश एक फरवरी से लागू होगा और अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगा। मुफीद परिणाम आने पर दूसरे जोनों में भी योजना लागू की जाएगी।

रेलवे बोर्ड की तरफ से 29 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार, 'सक्षम प्राधिकार ने मालगाड़ियों में लदे सामान की निगरानी के लिए सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को यात्रा की इजाजत दी है। मालगाड़ी से सामान उतारने या चोरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए निजी सुरक्षाकर्मी ब्रेक वैन में मौजूद रहेंगे।' एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हालांकि, मालगाड़ियों से सामान उतारने या चोरी की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन कारोबारियों की मांग को देखते हुए हमने ऐसा निर्णय लिया है।'

आदेश के अनुसार, 'पूर्वी रेलवे को निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की गतिविधियों पर करीब से नजर रखनी चाहिए। खासकर सुरक्षा और ब्रेक वैन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों की दृष्टि से। इसके बाद उसे इस योजना को दूसरे जोनों में लागू करने के संबंध में रिपोर्ट देनी चाहिए।'

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में पहली बार निजी ग्राहकों के माल की सुरक्षा के लिए मालगाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की यात्रा को अनुमति दी गई थी। हालांकि, तब उन्हें हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी।

व्यवस्था होगी चाक-चौबंद तभी मिलेगी इजाजत : निजी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मालगाड़ियों में यात्रा के लिए शर्तें भी रखी गई हैं। रैक में माल की लदान से पहले उसे भेजने या पाने वाली कंपनी या कारोबारी की तरफ से सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की संख्या और उनकी सुरक्षा एजेंसी के नाम के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ब्रेक वैन में यात्रा करने वाले सशस्त्र सुरक्षाकर्मी केंद्र व राज्य के कानून तथा समस्त नियमों का अनुपालन करते हैं।

आदेश के अनुसार, 'निजी सुरक्षा एजेंसी को इसके बारे में रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस बल व पुलिस को एडवांस में सूचना देनी होगी। उन्हें निजी सुरक्षा एजेंसी के बारे में समस्त सूचनाएं और उपयुक्त दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। सुरक्षा एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों को ड्यूटी से पहले सुरक्षाकर्मियों को समस्त जानकारियां देनी होंगी।'

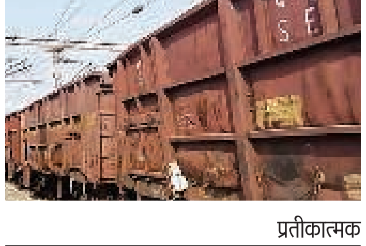

प्रतीकात्मक

अकाउंटेंट के घर सीबीआइ का छापा, 31 लाख नकद और गहने बरामद

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में छापेमारी के दौरान महालेखाकार के दफ्तर में तैनात वरिष्ठ अकाउंटेंट वाईएस मेइती के परिसरों से 31 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी, 18 लाख से ज्यादा के सोने के गहने तथा संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है।

अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने वाईएस मेइती के खिलाफ सेवा के दौरान 1.40 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है। मेइती के आवास व दफ्तर में छापेमारी के दौरान सीबीआइ ने नकदी व अन्य सामग्री जब्त की है। सीबीआइ को इस छापेमारी में इंफाल में स्थित दो बहुमंजिला इमारतों के दस्तावेज और एटीएम कार्ड के साथ 70 से अधिक पासबुक बरामद हुई हैं। ये पासबुक अलग-अलग लोगों के नाम पर हैं।

कह के रहेंगे माधव जोशी

4 फरवरी से संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की महानिदेशक ऑड्रे अजुले भारत के दो दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। वह यूनेस्को के माध्यम से विश्व को भारत का संभावित योगदान विषय पर चर्चा करेंगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 1 फरवरी 2020

हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसद आरक्षण की तैयारी

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

- मनोहर लाल कैबिनेट ने लिया सैद्धांतिक निर्णय
- उद्योगपतियों की सहमति से नई नीति बनाई जाएगी : मुख्यमंत्री

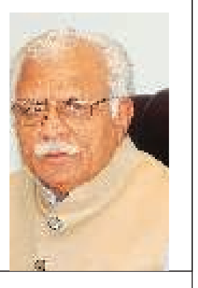

हरियाणा में लगे उद्यम व संस्थानों में राज्य के 75 फीसद युवाओं को रोजगार दिलाने की नीति बनाने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। अभी कानूनी राय मांगी गई है। राज्य के उद्यमियों की इस नीति के संदर्भ में सहमति बनाएगी ताकि उद्योगपतियों और रोजगार पाने वालों के बीच समन्वय रहे।
–मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

हरियाणा की भाजपा सरकार निजी क्षेत्र में राज्य के युवाओं के लिए 75 फीसद नौकरियां आरक्षित करेगी। सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी का यह चुनावी वादा था, जिसे पूरा करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को नई दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार उद्योगपतियों की सहमति से ऐसी नीति बनाएगी, जिससे उद्योग क्षेत्र सहित युवाओं के रोजगार के बीच समन्वय रहे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बताया कि यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन पालन नहीं हो रहा था। अब इसके अनुपालन के लिए नई नीति तैयार की जाएगी। संभवतः नई नीति बजट सत्र से पहले तैयार हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी सहायता और मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दाखिले में आरक्षण को बांटने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है।

इसके तहत पहले दिए जा रहे 20 फीसद आरक्षण को अब अनुसूचित जाति की ए और बी श्रेणी में दस-दस फीसद बांट दिया गया है। इससे दोनों श्रेणियों को बराबर का लाभ मिलेगा।

एक ही क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं होंगी नौकरियां : सरकार ध्यान रखेगी कि कहीं उद्योग जगत में इसका गलत संदेश न चला जाए। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया कि एक जिला या क्षेत्र के 75 फीसद युवा एक उद्योग में लगाने की बजाए पूरे हरियाणा के सभी जिलों में इस संख्या को विभक्त किए जाने का सुझाव भी आया है।

ममता सरकार के मंत्री के बिगड़े बोल, कहा–राज्यपाल को इलाज की जरूरत

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक ने शुक्रवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है। बैरकपुर की घटना पर उन्होंने कहा, 'राज्यपाल जो कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। उन्होंने मनोज वर्मा जैसे दक्ष पुलिस अधिकारी का जिस तरह सार्वजनिक तौर पर अपमान किया, वह सही नहीं था। राज्यपाल को उनसे माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, 'राज्यपाल खुद को ऐसी स्थिति में ले जा रहे हैं कि वे जहां भी जाएंगे, उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। अब तक विवि के छात्र-छात्राएं उनका रास्ता रोक रहे थे, अब जनता भी उनका रास्ता रोक देगी। इसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। ऐसे में उन्हें इलाज की जरूरत है। गौरतलब है कि गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक ड्यूटीरत पुलिसकर्मी को अखबार पढ़ता देखकर राज्यपाल ने बैरकपुर के पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा को फटकार लगाई थी।

आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी के कब्जे से मुक्त कराई गई 17 बीघा जमीन

जागरण संवाददाता, रामपुर

- ग्राम पंचायत के कब्जे में दी, 17 करोड़ों की जमीन पर कब्जा मुक्त करने के मिले थे आदेश

आजम खां फाइल

सांसद आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में चकरोड की पैमाइश का काम पूरा कर लिया गया है। यूनिवर्सिटी के कब्जे से 17 बीघा जमीन को मुक्त करा लिया गया है। राजस्व परिषद ने 11 चकरोड की 17 बीघा जमीन को खाली कराने के आदेश दिए थे। इसके अनुपालन में राजस्व टीम गुरुवार को यूनिवर्सिटी पहुंची थी और चार चकरोड की पैमाइश कर ली थी। बाकी चकरोड की पैमाइश के लिए तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में टीम शुक्रवार को यूनिवर्सिटी पहुंची। तहसीलदार ने बताया कि सभी चकरोड की पैमाइश कर ली गई है। एक चकरोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कालेज की दीवार बनी है, जबकि दूसरे में निर्माणाधीन इमारत आ रही है। तीसरा चकरोड उस जमीन पर है, जो अनुसूचित जाते के लोगों से बिना अनुमति खरीदी गई थी। चौथे चकरोड में वाइस चांसलर आवास का कुछ हिस्सा आ रहा है। भूमि पर ग्राम पंचायत को कब्जा दिला दिया गया है।

यह है पूरा मामला : आजम खां ने सपा शासनकाल में चकरोड की जमीन यूनिवर्सिटी परिसर में ले ली थी और इसके बदले दूसरी जमीन दी थी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस संबंध में शासन व प्रशासन में शिकायत की थी। आरोप लगाया कि सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते आजम खां ने नियम विरुद्ध तरीके से चकरोड की जमीन अभिलेखों में हेराफेरी कर अपनी यूनिवर्सिटी में मिला ली। शिकायत की जांच के बाद जिलाधिकारी ने राजस्व परिषद प्रयागराज में चार वाद दायर कराए थे। पिछले दिनों राजस्व परिषद प्रयागराज ने चकरोड की जमीन खाली कराने के आदेश दिए थे। इसी आदेश पर अमल करते हुए चकरोड की जमीन की पैमाइश कराई जा रही है।

बसपा सरकार में टूटी थी चकरोड पर बनी दीवारें : बसपा शासन काल में 2007 में चकरोड पर कब्जे की शिकायत पर विवि की दीवारों को तोड़ा गया था। इस बार भी विभागीय प्रक्रिया के बाद कब्जे को मुक्त किया जा सकता है। हालांकि अधिकारी अभी कुछ कहने से बच रहे हैं।

न्यूज गैलरी

राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

रांची : सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने धीरज प्रसाद साहू को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में हुई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 17 फरवरी मुकर्रर की है। दरअसल, प्रदीप सोंथालिया ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। बता दें कि पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट ने प्रदीप सोंथालिया की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्होंने अपनी याचिका में चुनाव आयोग को प्रतिवादी नहीं बनाया है। साथ ही राज्यसभा चुनाव की दोबारा मतगणना की मांग नहीं की है इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है। इसी आदेश के खिलाफ प्रदीप सोंथालिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। (राब्यू)

छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से एक अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराडे ने बताया कि सत्र में कुल 22 बैठकें होंगी। 25–26 फरवरी के सत्र के लिए प्रश्न की सूचना तीन फरवरी और 27–28 के लिए पांच और छह फरवरी तक सूचना दी जा सकती है। राज्य शासन ने सत्र की प्रारंभिक तैयारी पूरी कर ली है। सत्र में सरकार कुछ विधेयक भी पेश करेगी। इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित करेगी। केरल, पंजाब, राजस्थान और बंगाल की सरकार विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। भूपेश सरकार ने सीएए को देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बताया है। नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार करीब एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। सत्र की बैठक के पहले दिन कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सरकारी कामकाज के दिन तय किए जाएंगे। (नईदुनिया)

कोल इंडिया के सीएमडी बनेंगे प्रमोद अग्रवाल

भोपाल : 1991 बैच के आइएएस अधिकारी प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) होंगे। मप्र सरकार ने अग्रवाल को शुक्रवार को कार्यमुक्त किया। उनकी जगह 1994 बैच की अधिकारी दीपाली रस्तोगी को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। (नईदुनिया)

एक हजार करोड़ के घपले में आरोपित आइएएस अधिकारियों को राहत नहीं

झटका ▶ हाई कोर्ट ने खारिज की रिव्यू पिटीशन, कहा–यह वह बैंच नहीं जिसने फैसला सुनाया

सात आइएएस सहित फंसे हैं 12 अधिकारी, सता रहा है गिरफ्तारी का डर

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में भाजपा शासनकाल में हुए करीब एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपित सात आइएएस समेत 12 अधिकारियों को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ सीबीआइ को मुकदमा दर्ज करने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, जिससे टॉप ब्यूरोक्रेसी में खलबली मची है। अधिकारी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। उन्हें गिरफ्तारी का भय सता रहा है। गौरतलब है कि भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में सीबीआइ की जांच पर रोक लगा रखी है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ की राज्य में इंट्री और जांच सरकार के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है।

2013 से 2018 के बीच राज्य निःशक्तजन स्रोत संस्थान फिजिकल रेफरल रिहेब्लिटेशन सेंटर के नाम पर करीब एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। समाज कल्याण विभाग के राज्य निःशक्तजन स्रोत संस्थान में संविदा कर्मचारी के पद पर कार्यरत कुंदन सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आलाधिकारियों की मिलीभगत से चलाए जा रहे फर्जी विभाग के जरिये प्रति महीने लाखों रुपये के घोटाले की जांच की मांग की। इसके बाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। घपले में फंसे प्रदेश के सात आइएएस अफसर शुक्रवार को हाई कोर्ट पहुंचे।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस गौतम चौरड़िया की पीठ के समक्ष फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की। पीठ ने रिव्यू पिटीशन को स्वीकार करने से इन्कार करते हुए दो टूक कहा कि आप जहां आए है, वह जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की वह खंडपीठ नहीं है, जिसने आदेश दिया। जब वह खंडपीठ बैठेगी तब आप रिव्यू पिटीशन ला सकते हैं।

जस्टिस प्रशांत मिश्रा दोनों ही पीठों में शामिल हैं। कोर्ट ने जिन सात आइएएस पर जांच का निर्देश दिया है, उसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेका ढांड और सुनील कुजूर प्रमुख हैं। सुनील कुजूर प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्य सचिव कांग्रेस शासन में बनाए गए थे।

कांग्रेस सरकार ने इसकी जमकर ब्रांडिंग भी की थी। कुजूर को सेवानिवृत्ति के बाद सरकार ने राज्य सहकारिता निर्वाचन आयोग का चेयरमैन बनाया है। वहीं, विवेक ढांड रेरा के चेयरमैन बनाए गए हैं।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट फाइल

घोटाले पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 15 साल रमन सरकार का नारा रहा 'खाओ और खाने दो'। एनजीओ के माध्यम से प्रदेश के लाखों करोड़ रुपये सरकार ने लुटवा दिए। त्रिवेदी ने पूछा कि मंत्रीमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के चलते सरकार के मुखिया होने के नाते रमन सिंह इन घोटालों से अपना दामन कैसे बचा सकते हैं? पीएम मोदी, इस घोटाले का कब संज्ञान लेंगे? न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा छत्तीसगढ़ के लिए नहीं था क्या?

राज्य सरकार के रिव्यू को भी किया अस्वीकार

राज्य शासन की ओर से भी डिवीजन बेंच के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी। जस्टिस मिश्रा ने शासन के आवेदन को भी अस्वीकार कर दिया। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील देवर्षि ठाकुर ने डिवीजन बेंच के समक्ष दलील पेश की कि प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह ने शपथ पत्र पेश कर डिवीजन बेंच के समक्ष स्वीकार किया है कि 150 से 200 करोड़ की गड़बड़ी हुई है।

...तो सरकार की मजबूरी होगी

मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो अगर सीबीआइ उक्त अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करती है, तो उन्हें पद से हटाना सरकार की मजबूरी होगी। इसको लेकर सरकार भी विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। हालांकि, ब्यूरोक्रेसी में इस बात की भी चर्चा है कि कोर्ट में अपील का रास्ता खुला है। विधि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि एफआइआर होने तक सरकार को तय करना है कि अधिकारियों को पद से हटाए या नहीं। लेकिन, एफआइआर और गिरफ्तारी के बाद पद से हटाना ही पड़ेगा।

शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट मदरसा समिति की याचिका सुनने को तैयार

- याचिका में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को पूर्व में दिए बड़ी पीठ के फैसले के विपरीत बताया
- पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षकों की नियुक्ति का मौलिक अधिकार प्रदान किया था

नई दिल्ली, प्रेट्र : अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आयोग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति पर कानून को बरकरार रखने के अपने हालिया फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को बंगाल स्थित मदरसा प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया।

कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ द्वारा छह जनवरी को सुनाया गया फैसला उसकी 11 सदस्यीय पीठ द्वारा पूर्व में सुनाए गए फैसले के विपरीत है। इस फैसले में पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षकों की नियुक्ति का मौलिक अधिकार प्रदान किया था।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह मामले की सुनवाई करेगी और बंगाल व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिए। कोंताई रहमानिया उच्च मदरसा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन और सलमान खुर्शीद ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए राज्य की ओर से गठित वैधानिक बोर्ड का अनुपालन अनिवार्य है। इस पर पीठ ने कहा, उचित होगा कि याचिकाकर्ता राहत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट जाएं। धवन ने कहा कि समस्या यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही आना होगा।

इस पर पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट दो सदस्यीय पीठ के हालिया फैसले के बजाय 11 सदस्यीय पीठ के फैसले के मुताबिक सुनवाई करेगा। धवन ने कहा कि मामला राज्य द्वारा बोर्ड की नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इन संस्थानों द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के मौलिक अधिकार का व्यापक मसला शामिल है। उचित होगा कि यही अदालत मामले की सुनवाई करे और अस्पष्टता दूर करे।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

हार्दिक पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

- मोरबी जिले की एक अदालत ने जारी किया गैरजमानती वारंट

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें फिर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट से राजद्रोह मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मोरबी जिले के टंकारा की अदालत ने शुक्रवार को हार्दिक समेत चार लोगों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी की है।

पाटीदार आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल, कांग्रेस विधायक ललित वसोया व ललित कगथरा तथा अन्य पाटीदार नेताओं ने मोरबी जिले के टंकारा कस्बे में अप्रैल 2017 में जनसभा की थी। हालांकि, इसके लिए उन्होंने पुलिस से अनुमति नहीं ली थी। इस मामले में पुलिस ने हार्दिक समेत 34 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विधायक ललित कगथरा तथा अन्य आरोपित शुक्रवार को अदालत में हाजिर हुए, लेकिन हार्दिक पटेल, ललित वसोया, पाटीदार नेता अमित ठुमर व मनोज कालरिया पेश नहीं हुए। इस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट एसएन पुंजानी ने चारों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।

इससे पहले अहमदाबाद सत्र अदालत से हार्दिक के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद 18 जनवरी को उन्हें उनके गांव वीरमगाम से गिरफ्तार किया गया था। हार्दिक को 23 जनवरी को उस मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके तत्काल बाद उन्हें गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, उसी दिन उन्हें दूसरे मामले में भी जमानत मिल गई थी।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने गुरुवार को राजद्रोह मामले में हार्दिक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब टंकारा कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी होने के बाद हार्दिक पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है।

हार्दिक पटेल फाइल

डीजीपी को मिली राहत

अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने पाटीदार महारैली के दौरान लाठीचार्ज को लेकर गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शिवानंद झा तथा आइपीएस अधिकारी राजीव रंजन भगत के खिलाफ जांच की मांग को खारिज कर दिया है। पाटीदार समाज की ओर से अहमदाबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त शिवानंद झा तथा सेक्टर–1 के संयुक्त पुलिस आयुक्त राजीव रंजन भगत के खिलाफ जांच के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया था कि 25 अगस्त 2015 को अहमदाबाद में पाटीदार आरक्षण के लिए हुई महारैली में दोनों अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था।

जब मिले दिग्गज...

नई दिल्ली में शुक्रवार को शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल परिवार की ओर से एक लंच का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल समेत भाजपा और राकांपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान ट्रैक्टर पर कुछ इस अंदाज में तस्वीर खिंचवाते सुखबीर सिंह बादल, उनकी पत्नी और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले और भाजपा नेता किरण खेर। लंच में कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। प्रेट्र

सुधार

भिखारियों को कौशल विकास से जोड़ेगी केंद्र सरकार, उप्र में समाज कल्याण विभाग नोडल एजेंसी बनाई गई

भीख नहीं, मिलेगी रोजगार की सीख

अजय श्रीवास्तव, लखनऊ

भिखारियों को अब भीख नहीं, रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसके लिए देश के 10 शहरों को चिह्नित किया है, जहां भिक्षावृत्ति बढ़ रही है।

भीख मांगने वालों की भरमार किसी शहर की पहचान खराब करती है। विदेशी ऐसे भिखारियों से रूबरू होने पर शहर के प्रति गलत धारणा बनाते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने चुनिंदा शहरों में भिखारियों के पुनर्वास की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए समाज कल्याण विभाग नोडल एजेंसी नामित है। विभाग भिखारियों को केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के तहत कुशल बनाकर रोजगार से जोड़ेगा।

योजना के तहत चुने गए शहर

लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पटना और इंदौर। पहले भी हुई थी ऐसी पहल लखनऊ में पिछले दिनों भी भिखारियों को रोजगार से जोड़ने की कवायद की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई थी। तब सर्वे में अधिकांश भिखारी युवा पाए गए थे, जिनकी उम्र 19 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक थी। 541 भिखारियों में 30 के पास मोबाइल फोन थे। लालबत्ती पर खड़े वाहनों से भीख मांगने वालों में बच्चे अधिक पाए गए थे। इन्हें प्रथम चरण में हटाया जाना था, क्योंकि ये वाहन दुर्घटना का कारण बनते हैं।

कई भिखारी हाईटेक

लखनऊ के ग्रामीण इलाके पिपरसंड से आकर शहर में भीख मांगने वाली 23 वर्षीय संजो के पास मोबाइल फोन भी है। सर्वे में वह शारीरिक रूप से सामान्य भी पाई गई थी। 25 वर्षीय विकास फैजुल्लागंज क्षेत्र में भीख मांगता है, वह भी सामान्य पाया गया था। 31 वर्षीय लक्ष्मी हनुमान सेतु पर भीख मांगती है। 21 वर्षीय नारायन भी कैसरबाग में भीख मांगता है। 19 वर्षीय रुबीना और 28 वर्षीय अनीता टेढी पुलिया, तीस वर्षीय नीराजन घर–घर जाकर और तीस वर्षीय नहरूनिशा अमीनाबाद में भीख मांगती है। इन सबके पास मोबाइल फोन मिले थे।

समाज कल्याण विभाग को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नगर निगम को फिर से भिखारियों का सर्वे करने को कहा गया है। इसमें पुलिस विभाग भी सहयोग करेगा।
–अशोक सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम

अब रेलवे स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त भत्ता मिलेगा

प्रदीप चौरसिया, मुरादाबाद

- बेसिक वेतन का 10 फीसद लाभ जुलाई–2017 से देने का आदेश

ट्रेन के चालक व गार्ड को मिलने वाली रनिंग भत्ते की तरह रेलवे के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पढ़ाने का भत्ता मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने जुलाई-2017 से भत्ता देने का आदेश जारी किया है।

रेलवे चालक व गार्ड को काम करने का वेतन देने के साथ ही ट्रेन चलाने का भत्ता देता है, जिससे रनिंग एलाउंस कहा जाता है। रेल प्रबंधन रेल कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए ट्रेनिंग स्कूल और उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों का संचालन करता है। रेलवे ने वर्तमान में प्राइमरी स्कूलों को तो बंद कर दिया है, अब कुछ स्थानों पर माध्यमिक स्कूलों का संचालन किया जाता है। इनमें उत्तर रेलवे द्वारा देहरादून में ओक ग्रोव स्कूल है, जो देश का नामी स्कूल है, यहां बच्चों को प्रवेश के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। यहां 90 फीसद बच्चे रेलवे अधिकारियों व कर्मियों के पढ़ते हैं, दस फीसद बच्चे गैर रेल कर्मियों के होते हैं। रेल प्रबंधन माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को पढ़ाने का भत्ता देने जा रहा है। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक एनपी सिंह ने इस माह की शुरुआत में पत्र जारी कर निर्देश दिया कि शिक्षकों को बेसिक वेतन का 10 फीसद पढ़ाने का भत्ता दिया जाएगा। शिक्षकों को यह भत्ता एक जुलाई 2017 से मिलेगा लेकिन, यह भत्ता स्कूलों के प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति वित्त आयोग से भी मिल गई है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि बोर्ड ने शिक्षकों को पढ़ाने का भत्ता देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। रेलवे का एक स्कूल बरेली और एक मुरादाबाद में है।

उर्दू अकादमी से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो हटाईं, कर्मचारी पर केस

नईदुनिया, भोपाल : भोपाल में उर्दू अकादमी के कार्यालय में लगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने पर वहीं के एक कर्मचारी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह ने भी अपने समर्थकों के साथ उर्दू अकादमी पहुंचकर प्रदर्शन किया। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फोटो पूर्व की तरह फिर से अकादमी में लगा दी गई हैं।

दरअसल, कुछ दिन पहले ही पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी की नियुक्ति उर्दू अकादमी के अध्यक्ष पद पर की गई थी। कुरैशी अध्यक्ष पद संभालने के बाद अवकाश लेकर लखनऊ चले गए। इसी बीच अकादमी के कार्यालय में लगी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें हटने की खबरें आई तो मामले ने तूल पकड़ लिया। भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन किया।

261 प्रदर्शन नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में देशभर में हुए 11 दिसंबर से। फैक्ट-चेकिंग वेबसाइट प्रोटेस्ट मॉनिटर के मुताबिक, 230 प्रदर्शन सीएए के खिलाफ, जबकि 31 इसके पक्ष में थे।

केरल विधानसभा में पेश नहीं होगा राज्यपाल को वापस बुलाने का प्रस्ताव

बड़ा मामला ▶ आरिफ मुहम्मद को हटाने के प्रस्ताव के नोटिस को विस की कार्य मंत्रणा समिति ने किया खारिज

मंत्री एके बालन ने कहा-राज्य सरकार संविधान की भावना के विपरीत नहीं जाना चाहती

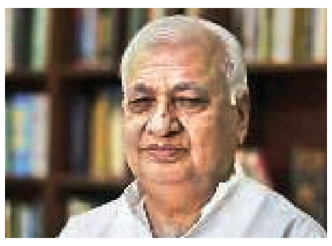
आरिफ मुहम्मद खान फाइल

तिरुअनंतपुरम, एजेंसियां : केरल विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान को वापस बुलाने की मांग की गई थी। अतः नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का समर्थन करने पर राज्यपाल के खिलाफ केरल विधानसभा में अब कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जाएगा।

विपक्ष के नेता और कांग्रेस सदस्य रमेश चेन्नीथला के लाए प्रस्ताव को राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाना था। दरअसल, राष्ट्रपति से ऐसी अपील करके ही किसी राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है। विपक्ष के इस प्रस्ताव में आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और सार्वजनिक रूप से विधायिका के सम्मान पर सवालिया निशान लगाया है। सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार के कानून मंत्री एके बालन ने इस फैसले के संबंध में संवाददाताओं को बताया कि राज्य सरकार केवल नियमों के अनुसार चलना चाहती है और वह संविधान की भावना के विपरीत नहीं जाना चाहती। इससे पहले, चेन्नीथला ने विगत 29 जनवरी को बजट सत्र में प्रस्ताव पेश करने को लेकर एक नोटिस विधानसभा अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन को सौंपा था। हालांकि, तब विधानसभा अध्यक्ष ने भी माना था कि नोटिस देना उचित है और इस पर अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा समिति ही लेगी। हालांकि, पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने इसका विरोध किया था, जबकि चेन्नीथला ने मीडिया से कहा कि उन्होंने विधानसभा के नियमों के तहत ही प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वह फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे। विधानसभा के सूत्रों के अनुसार, विपक्ष के इस प्रस्ताव की सामग्री पर चर्चा के लिए समय मांगा, लेकिन कार्य मंत्रणा समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विधानसभा के इस सत्र में समय कम होने के कारण चर्चा नहीं हो सकेगी। ध्यान रहे कि चेन्नीथला ने सीएए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने का विरोध किया था और केंद्र के इस कानून के खिलाफ बिना बताए सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी राज्यपाल के कड़ा ऐतराज जताते हुए अपना विरोध दर्ज किया था।

सीएए का विरोध हो, पर संविधान की लक्ष्मण रेखा के अंदर : टंडन

- मप्र के राज्यपाल ने कहा-संविधान ने मुझे भी दिए हैं कुछ अधिकार
- कानून संसद में बहुमत से पास हुआ, स्वीकारना राज्यों की बाध्यता

लालजी टंडन फाइल

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएए को लेकर कहा है कि विरोध हो, लेकिन संविधान की लक्ष्मण रेखा के भीतर। मर्यादा से हटकर काम होगा तो संविधान ने मुझे भी अधिकार दिए हैं। कोई कानून अथवा संशोधन संसद में दो तिहाई बहुमत से पास हो गया है तो उसे स्वीकार करना राज्यों की बाध्यता है। राज्यपाल टंडन ने यह टिप्पणी केरल में राज्यपाल और सरकार के बीच उत्पन्न विवाद से जुड़े एक सवाल पर की। वह राजभवन में प्रेस प्रकोष्ठ के शुभारंभ अवसर पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में किस दल की सरकार है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। सरकार ठीक से काम करे इसमें मेरा सहयोग और आशीर्वाद हमेशा रहेगा, लेकिन मर्यादा से हटकर यदि कोई काम होता है तो संविधान ने मुझे कुछ अधिकार दिए हैं और कर्तव्य बताए हैं। जहां हस्तक्षेप करना चाहिए, वहां मुझे किसी ने नहीं रोका।

कमलनाथ सरकार की तारीफ

टंडन बोले कि राज्य सरकार राम वनगमन पथ और श्रीलंका में सीता माता का मंदिर बनवा रही है। यह सब सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के काम हैं। इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। इस देश में भगवान राम के अस्तित्व का निर्धारण भी अदालत से तय हुआ है। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विचार से जुड़े सवाल पर वह बोले कि हमारे लोकतंत्र को गांधीजी से कभी अलग नहीं किया जा सकता। गांधीजी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई। उनकी त्याग-तपस्या और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। लोग गांधीवाद को भले ही भूल गए, लेकिन गांधी को नहीं भुला सकते।

किशोर बोला, गोली मारना नहीं सिर्फ डराना चाहता था

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- जामिया पर गोली चलाने वाले नाबालिग को सुधार गृह भेजा
- सीएए विरोधी प्रदर्शनों व हिंदूवादी नेताओं की हत्या से था गुस्से में

दिल्ली के जामिया इलाके में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में पैदल मार्च के दौरान गोली चलाने वाले किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 28 दिन के लिए सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग देशभर में सीएए विरोधी प्रदर्शनों और हिंदूवादी युवा नेताओं की हत्या से गुस्से में था। इसी बदले की भावना से 10 हजार रुपये में तमंचा खरीदा और दिल्ली आ गया। पूछताछ में बताया कि उसकी मंशा किसी को गोली मारने की नहीं थी। वह डराने के लिए हवा में गोली चलाना चाहता था, लेकिन फायर हो गया। हालांकि इसका उसे पछतावा नहीं दिखा।

नाबालिग से पूछताछ करने वाले क्राइम ब्रांच के अधिकारी उसकी बातों से हैरान हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे घटना के लिए किसी ने उकसाया तो नहीं था। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपित का कहना था कि सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के लिए समुदाय विशेष के लोग जिम्मेदार हैं। वह शरजील इमाम जैसे भाषण देने वालों और सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक उड़ाने वालों को विदेशी एजेंट मानता है। वह सोशल मीडिया पर लगातार कट्टरवादी वीडियो देखता था।

इन वजहों को लेकर था गुस्से में: 26 जनवरी 2018 को कासगंज में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन की हत्या और गत वर्ष अक्टूबर में लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या से खासा गुस्से में था। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से भी वह नाराज था।

17 साल 9 महीने 23 दिन का है आरोपित

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्वजनों द्वारा पेश आधार कार्ड और 10वीं के प्रमाणपत्र में उसकी उम्र 17 साल 9 महीने 23 दिन है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने जेजे बोर्ड के सामने उसकी सही उम्र का पता लगाने के लिए बोन ओसिफिकेशन (अस्थि परीक्षण) टेस्ट कराने का आग्रह किया है। यदि बोर्ड इसकी इजाजत देता है तो जांच होगी, नहीं तो दस्तावेज में दर्ज उम्र ही सही मानी जाएगा।

एक छात्र हुआ था घायल

जामिया इलाके में आरोपित नाबालिग द्वारा चलाई गई गोली से प्रदर्शन कर रहा जामिया का एक छात्र घायल हो गया था। वह ग्रेटर नोएडा के जेवर स्थित अपने घर से बहाना बनाकर बस से दिल्ली आया था। फिर ऑटो पकड़कर जामिया विश्वविद्यालय पहुंच गया। यहां पर वह प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ समय तक रहा था। एकाएक वह कट्टा निकाल कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच खड़ा हो गया। इसी दौरान गोली चल गई।

न्यूज गैलरी

ममता बनर्जी को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को बंगाल के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने की मांग करने वाली ममता बनर्जी को हटाने के लिए राज्यपाल जगदीप धनखड़ को निर्देश देने का आग्रह किया गया था। एक पत्रकार ने यह याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए पत्रकार वकाली को हाई कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। पीठ ने कहा, 'हम इससे इन्कार नहीं कर रहे हैं कि यह अहम नहीं है। आप हाई कोर्ट जाइए।' याचिका में कहा गया था कि भारत के संविधान की अनुसूची तीन के तहत पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री के लिए देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ बयान देने की मनाही है। ममता बनर्जी पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र या मानवाधिकार आयोग जैसी निष्पक्ष संस्था की निगरानी में सीएए पर जनमत संग्रह कराने की मांग की थी। (एएनआइ)

ड्रामे में पीएम के अपमान पर हेडमास्टर समेत दो गिरफ्तार

बेंगलुरु : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान पर हेड मास्टर व एक बच्ची की मां के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीएए व एनआरसी को लेकर स्कूल के ड्रामे में पीएम की अवमानना करने पर दोनों के खिलाफ शुक्रवार को यह कार्रवाई हुई। पुलिस ने यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता नीलेश रक्षयाल की शिकायत पर की है। कर्नाटक के बीदर शहर के शाहीन स्कूल में बीती 21 जनवरी को एक नाटक का मंचन किया गया था। नाटक में कक्षा चार, पांच व छह की बच्चियों ने भाग लिया था। कक्षा छह की एक बच्ची की मां ने नाटक की मूल पटकथा में बदलाव कर दिया। इसमें नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। सोशल मीडिया पर नाटक का वीडियो वायरल होने पर मामला तूल पकड़ गया। शिकायत दर्ज होने पर पुलिस ने हेड मास्टर व बच्ची की मां से गुरुवार को पूछताछ की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को पुलिस रिमांड में दे दिया। जांच अभी जारी है। (प्रेट्र)

सीएए का विरोध देश के साथ गद्दारी : इंद्रेश

देहरादून : देश में भय फैलाकर मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। सीएए, एनआरसी के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। इस कानून का विरोध करना देश के साथ गद्दारी है। यह कानून नागरिकता देने के लिए है न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। सरकार अल्पसंख्यकों को सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन कुछ लोग देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये बातें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तराखंड के मार्गदर्शक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहीं। शुक्रवार को देहरादून के टाउन हॉल में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से सीएए को लेकर जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय समेत अन्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि इंद्रेश कुमार ने लोगों को सीएए की बारीकियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए मुस्लिमों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ पढ़े-लिखे लोग भी लोगों में भ्रम फैला रहे हैं जबकि, सरकार ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। अन्य देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और सम्मान देने के उद्देश्य से यह कानून लाया गया है। इंद्रेश कुमार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की पैरवी की है। शुक्रवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य वक्ता इंद्रेश कुमार ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या से देश की अर्थव्यवस्था संकट में घिर सकती है। (जासं)

नागरिकता कानून में सभी धर्मों का खयाल रखा जाए : शिअद

- मुसलमानों समेत किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ न हो पक्षपात : गुजराल
- गठबंधन धर्म निभाने के लिए दिल्ली विस चुनाव में भाजपा का समर्थन करेंगे

नई दिल्ली, प्रेट्र : शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) में किसी खास धर्म को अलग-थलग करने के बजाय सभी धर्मों को समान रूप से देखे जाने के पक्ष में है। पार्टी का पक्ष रखते हुए राज्यसभा सदस्य नरेश गुजराल ने कहा कि संसद में हम लोगों ने इस कानून के पक्ष में मत दिया, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ पक्षपात न हो।

गुजराल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने संसद में कहा भी था कि इस कानून का लाभ मुसलमानों समेत सभी धर्म के मानने वालों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम गठबंधन धर्म से बंधे हैं। इसीलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। इतना ही नहीं भाजपा ने जब हमसे संपर्क किया तो हमने उन्हें अपना समर्थन भी दे दिया।

शिअद के एक अन्य सांसद बलविंदर सिंह भुंदेर ने कहा कि गुरुवार को सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में भी हम लोग अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। हम इस कानून में मुसलमानों समेत सभी धर्मों के मानने वालों का लाभ देने के हिमायती हैं। शिअद के दोनों नेताओं ने कहा कि हमारी पार्टी इस कानून का इसलिए समर्थन करती है क्योंकि इससे पाकिस्तान व अफगानिस्तान के सिखों को फायदा होगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग न लेने वाली शिअद कुछ मुद्दों पर मतभेद के बावजूद उनकी पार्टी को समर्थन देगी।

शिअद के चुनाव न लड़ने के फैसले ने भाजपा नेतृत्व की नींद उड़ा दी थी। माना जा रहा था कि शिअद के रुख से दिल्ली की करीब एक दर्जन सीटों पर सिख मतदाता भाजपा का खेल बिगाड़ सकते थे।

नुकसान की भरपाई के नोटिस रद करने की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार तलब

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए रिकवरी नोटिस को रद करने की मांग पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने रिकवरी नोटिस रद करने की मांग याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ये नोटिस न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और केएम जोसेफ की पीठ ने परवेज आरिफ टीटू की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में याचिका का जवाब देने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने लोगों का मनमाने ढंग से रिकवरी नोटिस भेजा है। प्रदेश में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रशासन ने ऐसे व्यक्ति को रिकवरी नोटिस भेजा है जिसकी छह साल पहले 94 वर्ष की आयु में मृत्यु हो चुकी है। इसी तरह दो ऐसे लोगों को भी नोटिस भेजा गया है जिनकी आयु 92 वर्ष है। याचिका में कहा गया है कि प्रशासन यह नोटिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के आदेश के आधार जारी कर रहा है। जबकि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले में तय किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फिर अपने 2009 के दिशा-निर्देशों पर मुहर लगाई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएए के प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए रिकवरी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया के लिए एडीशनल डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि यह काम सेवानिवृत्त जज देखेंगे। कहा गया है कि हाईकोर्ट की निगरानी का मतलब है, उससे मनमानी प्रक्रिया की आशंका नहीं रहती। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2009 और 2018 के आदेश का अनुपालन करे।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि प्रदेश में सीएए के प्रदर्शनों की घटनाओं की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की इजाजत मांगी जिस पर कोर्ट ने कहा कि वह इस बारे में अर्जी दाखिल करें।

आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बंगाल भाजपा अध्यक्ष पर केस

जागरण संवाददाता, कोलकाता : बंगाल में भाजपा की अभिनंदन यात्रा में छात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी एवं दुर्व्यवहार करने तथा धमकी देने के मामले में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है।

बीते गुरुवार को सीएए के समर्थन में भाजपा के श्रमिक संगठन की ओर से दक्षिण कोलकाता के पाटुली मोड़ पर अभिनंदन यात्रा का आयोजन किया गया था। इसका नेतृत्व दिलीप घोष ने किया था। अभिनंदन यात्रा के दौरान सड़क किनारे संस्कृत विवि की सुदेष्णा दास गुप्ता नामक छात्रा हाथ में 'नो सीएए, नो एनआरसी' का प्लेकार्ड लेकर खड़ी थी। छात्रा का आरोप है कि भाजपा समर्थकों ने उसके हाथ से प्लेकार्ड छीनकर अश्लील कटाक्ष करने के साथ ही दुर्व्यवहार किया। छेड़छाड़ भी की गई। कुछ लोगों ने छात्रा को भाजपा समर्थकों के चंगुल से छुड़ाया था। आरोप है कि अभिनंदन यात्रा के बाद किताब मेले में पहुंचे दिलीप घोष ने छात्रा के साथ घटना को सही ठहराते हुए विवादित बयान दिया था। कहा था कि शुक्र है कि हमारे समर्थकों ने सिर्फ प्लेकार्ड छीनकर छात्रा को जाने दिया। वे भाग्यशाली हैं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे (सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारी) हमेशा विरोध करने के लिए हमारी रैलियों में क्यों आते हैं? वे अन्य घटनाओं में जा सकते हैं। हमने बहुत सहन किया, लेकिन अब ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप है कि दिलीप घोष ने छात्रा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के साथ ही धमकी भी दी। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को पीड़ित छात्रा ने पाटुली थाने में दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीएफआइ के 10 सदस्य गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखनऊ

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआइ) के दस सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से पांच कानपुर, तीन बहराइच और दो सदस्य लखनऊ में गिरफ्तार किए गए हैं।

लखनऊ पुलिस ने जिन दो पीएफआइ कार्यकर्ताओं को पकड़ा, वे गुरुवार देर शाम प्रदर्शनकारियों को भड़काकर कैंडल मार्च के साथ टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध पर ठाकुरगंज थाने में 15 को नामजद कर 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर एक और एफआइआर दर्ज की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में मो. ताहिर, जुगनू, मो. शान, रहबर, दाऊद, सावेज व तुफैल सिद्दीकी हैं। तुफैल और सावेज पीएफआइ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सावेज गत 19 दिसंबर को परिवर्तन चौक पर आगजनी व पथराव की घटना में जेल जा चुका है। हसनगंज पुलिस ने शकीलुर्रहमान, शाबी खान व मो. अरशद को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय ने बताया कि लखनऊ के घंटाघर मामले में पुलिस अब तक 300 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर एफआइआर दर्ज कर चुकी है। दो दर्जन की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सपा नेता पूजा शुक्ला भी हैं। इसके अलावा शुक्रवार को गिरफ्तार अन्य प्रदर्शनकारियों को जेल भेजा गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बहराइच में तीन गिरफ्तार : बहराइच पुलिस ने बौंडी क्षेत्र से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रभारी एसपी रवींद्र सिंह ने बताया कि वे सभी 20 दिसंबर को शहर में हुए जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में पुलिस पर पथराव, वाहनों में तोड़फोड़ व लूटपाट की घटना में शामिल थे। आरोपितों के संबंध पीएफआइ से भी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने चार और संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

कानपुर में पांच सदस्य पकड़े गए : कानपुर में हुई हिंसा के पांच आरोपितों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पांचों पीएफआइ के सदस्य हैं। ये गंगा यात्रा में आए मुख्यमंत्री के विरोध की तैयारी कर रहे थे। कानपुर में 20-21 दिसंबर को सीएए के विरोध में हिंसा हुई थी। बाबूपुरवा में तीन लोग मारे गए जबकि 40 घायल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी थे। केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट से कानपुर बवाल के पीछे पीएफआइ का हाथ होने का पता चला था। शुक्रवार को कानपुर के झकरकटी पुल के पास दबिश देकर पुलिस ने पांच पीएफआइ के सदस्यों को गिरफ्तार किया। सभी 20 दिसंबर की बाबूपुरवा हिंसा में शामिल थे।

पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को माफी नहीं : राजनाथ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी भारतीय की नागरिकता पर सवाल उठाता है तो हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन कोई भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा तो उसे माफ नहीं करेंगे। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ईशाप, न्याय हमारा संकल्प है। इसके पूर्व उन्होंने ग्रेटर नोएडा के अखिल भारतीय गुर्जर संस्कृति शोध संस्थान परिसर में पूर्व भाजपा सांसद हुकुम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया।

इस मौके पर आयोजित सभा में उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना कहा कि निहित स्वार्थ के लिए धर्म की राजनीति की जा रही है। राजनीति शब्द का अर्थ राज्य का सम्मार्ग पर ले जाना है। आज राजनीति शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल चुका है। धर्म की बात कहकर अपने निहित स्वार्थ सिद्ध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग किसी गलतफहमी व बहकावे में न आएं। देश के किसी नागरिक की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है।

बहुत व्यापक है भारतीय संस्कृति : रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है। भारत सभी संस्कृति को साथ लेकर चलने वाला देश है। इस्लाम के 72 फिरके हैं। इस्लामिक देशों में भी सभी फिरके नहीं मिलते, केवल भारत में ही सभी फिरके मिलते हैं। उन्होंने पारसी व यहूदी समाज का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में भटकने के बाद उन्हें केवल भारत में ही सम्मान मिला था। रक्षामंत्री ने कहा कि राष्ट्र का विरोध करने वाले को किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी।

खुल रहे राज

देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार इमाम द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक, जहानाबाद स्थित घर से मिला मुख्य मोबाइल, आतंकी जुड़ाव की भी जांच

'जिन्ना' बनना चाहता था शरजील इमाम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

देशद्रोह का आरोपित शरजील इमाम मुस्लिमों का बड़ा नेता बनना चाहता था। वह मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथकंडों से बहुत प्रभावित है और खुद भी वही करना चाहता था। वह मोहम्मद इकबाल के उन विचारों से भी प्रभावित है, जो उन्होंने मुस्लिम लीग के जरिये देश के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना के संबंध में रखे थे।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने शरजील का मुख्य मोबाइल फोन शुक्रवार को जहानाबाद स्थित उसके घर से बरामद कर लिया है। मोबाइल को दिल्ली लाया जा रहा है, जिसकी जांच के बाद पुलिस को पता चल सकेगा कि शरजील किन-किन लोगों के संपर्क में था। पीएफआइ के नेताओं सहित उसके विदेशी संबंधों का भी पता लगाया जाएगा। क्राइम ब्रांच के साथ पूछताछ कर रही स्पेशल सेल पता लगाने में जुटी है कि उसके भड़काऊ भाषण के लिए विदेश से तो फंडिंग नहीं की गई थी। उसके आतंकी संगठन से जुड़ाव की भी जांच की जा रही है। पूछताछ कर रहे अधिकारी शरजील की बातों से हैरान हैं। वह एक खास कट्टरपंथी विचारधारा का प्रबल समर्थक है। उसके लेख कई अंग्रेजी अखबारों में प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनके वाट्सएप के जरिये भड़काऊ बातें कई मुस्लिम युवाओं को भेजता रहता था। शरजील के पिता और चाचा बिहार में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन आरोपित की मंशा जिन्ना की तरह भारत में मुस्लिमों का बड़ा नेता बनने की थी। सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान उसे बड़ा मौका मिला गया। पुलिस के मुताबिक शरजील तीन मोबाइल फोन रखता था। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को उसके पास से दो मोबाइल मिले थे। लेकिन मुख्य मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ था। वह इस मोबाइल से ही अपने दोस्तों और नजदीकियों को फोन करता था। मालूम हो कि देश विरोधी भाषण का वीडियो वायरल होने के बाद शरजील इमाम पर लोगों की नजर पड़ी और दिल्ली सहित पांच राज्यों में मुकदमा दर्ज किया गया था। बिहार के जहानाबाद स्थित उसके गांव काको से उसे गिरफ्तार किया गया था।

शरजील इमाम फाइल

भाई ने दिल्ली पुलिस को सौंपा शरजील का मोबाइल

जागरण संवाददाता, जहानाबाद : भड़काऊ भाषण दिए जाने के आरोप में गिरफ्तार बिहार के जहानाबाद जिले स्थित काको निवासी शरजील इमाम का मोबाइल फोन भी दिल्ली पुलिस के हाथ लग गया है। छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने दिल्ली पुलिस को उसका मोबाइल सौंप दिया है। हालांकि, पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक मनीष ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि शरजील के भाई द्वारा पुलिस को मोबाइल सौंपे जाने की जानकारी उन्हें नहीं है। दिल्ली पुलिस उसके मोबाइल का सीडीआर निकालकर विस्तृत जांच करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, मुजम्मिल से दिल्ली पुलिस ने फोन कर शरजील के मोबाइल की मांग की थी। दिल्ली पुलिस इस बात की तहकीकात करेगी कि शरजील ने अपने मोबाइल से किन-किन लोगों से बात की है या फिर उन्हें मैसेज किया गया है।

उर्मिला मातोंडकर ने रॉलेट एक्ट से की सीएए की तुलना

पुणे, एएनआइ : अभिनय की दुनिया से राजनीति में आईं उर्मिला मातोंडकर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की तुलना ब्रिटिश कालीन रॉलेट एक्ट, 1919 से की, लेकिन उन्होंने द्वितीय विश्व खत्म होने का वर्ष गलत बताया।

महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मातोंडकर ने कहा, '1919 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश जानते थे कि भारत में अशांति फैल रही है और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यह बढ़ सकती है। इसलिए वे एक कानून लेकर आए, जिसे सामान्य तौर पर रॉलेट एक्ट के तौर पर जाना जाता है।' बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। कुछ महीने पहले कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली मातोंडकर ने आगे कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और रॉलेट एक्ट को इतिहास में काले कानूनों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ज्ञात हो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित रॉलेट एक्ट में ब्रिटिश सरकार को बिना निष्पक्ष सुनवाई किए किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डालने का अधिकार था जिसे वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाला मानती थी।

महात्मा गांधी के बारे में मातोंडकर ने कहा, 'गांधीजी किसी एक देश के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के नेता थे। मैं मानती हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा पालन किया तो वह गांधीजी थे... जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी की हत्या की, वह न तो मुस्लिम था और न सिख। वह एक हिंदू था और इस बारे में मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ और नहीं है।' उल्लेखनीय है कि उर्मिला मातोंडकर ने पिछला लोकसभा चुनाव मुंबई उत्तर सीट से लड़ा था। हारने के बाद पिछले साल सितंबर में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था।

4 फीसद आरक्षण मिलेगा जम्मू-कश्मीर में पहाड़ी भाषी समुदाय के लोगों को। यह फैसला उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में हुई प्रशासकीय परिषद की बैठक में लिया गया। इससे करीब 9.6 लाख लोगों को लाभ होगा।

क्रांति ला सकता है 4डी माइक्रोस्कोप 'एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा'

जागरण विशेष

सौरभ खंडेलवाल, भोपाल

एटोसेकंड स्ट्रीक कैमरा नामक अत्याधुनिक 4डी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की गति को लाइव देखा जा सकता है। एटोसेकंड यानी सेकंड के एक अरब वें हिस्से में आंकी जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का लाइव वीडियो कैप्चर किया जा सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर सॉलिड स्टेट रिसर्च में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. मनीष गर्ग का यह आविष्कार इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल, कंप्यूटिंग, संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति ला सकता है। इसे इस तरह समझें कि इस तकनीकी की मदद से 100 गीगा हट्र्ज के कंप्यूटर को 100 पेटा हट्र्ज का बनाया जा सकता है।

मप्र के शहडोल जिले के मूल निवासी डॉ. मनीष गर्ग कहते हैं, पदार्थ की संरचना में क्रमशः अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन-प्रोटॉन-न्यूट्रॉन इत्यादि सूक्ष्म घटक समाहित होते हैं। पदार्थ की प्रकृति इन्हीं सूक्ष्म घटकों के संयोजन पर निर्भर करती है। इनका अपना द्रव्यमान, आकार, प्रकार, स्वरूप, ऊर्जा, गति इत्यादि होते हैं। इलेक्ट्रॉन सदैव गतिशील बने रहते हैं। अब इस गतिशीलता को लाइव देखा जा सकता है।

मनीष ने नईदुनिया को बताया, पदार्थ की संरचना और क्रियाशीलता को समझना अब पहले से आसान हो जाएगा। ठोस पदार्थ हों या रसायन, इनके उपयोग को पहले से बेहतर बनाया जा सकेगा। दवाएं हों या तमाम विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉन इनका मुख्य घटक है। कंप्यूटर हो या मोबाइल, ऐसे सभी उपकरण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पर आधारित होते हैं। अब इन प्रक्रियाओं को न सिर्फ देखा जा सकेगा, बल्कि हाई डेफिनेशन (एचडी) वीडियो भी बनाया जा सकता है।

प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'साइंस' ने इस शोध, इस उपकरण की तकनीक और इसके भावी इस्तेमाल पर विस्तृत लेख प्रकाशित किया है। डॉ. मनीष शहडोल जिले के बराछ गांव के रहने वाले हैं। इस शोध में जर्मन वैज्ञानिक प्रो. क्लॉस केर्न ने भी उनका साथ दिया। दोनों वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तकनीक से न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को 10 लाख गुना तक दक्ष बनाया जा सकता है, बल्कि जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को और बेहतर समझ कर असाध्य बीमारियों के मूलभूत कारण, निदान और उपचार की भी संभावनाएं इससे खुल गई हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

सुपर माइक्रोस्कोप...

- **इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति को लाइव देखा जा सकता है, कैप्चर किया जा सकता है एचडी वीडियो**
- **इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस, कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्रांति ला सकता है यह आविष्कार**
- **आविष्कार करने वाले डॉ. मनीष मप्र के शहडोल जिले स्थित बराछ गांव के रहने वाले**

परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ सैकड़ा एटोसेकंड (सेकंड का एक अरब वां हिस्सा) पर सक्रिय होता है। अब तक अल्ट्रा फास्ट स्ट्रोबोस्कोप से इलेक्ट्रॉन की गति का तो पता लगाया जा सकता था, लेकिन गति की प्रत्यक्ष तस्वीर नहीं ली जा सकती थी। इसी तरह लाइट माइक्रोस्कोप से इमेज कैप्चर की जा सकती है, लेकिन गति का पता नहीं चल पाता था। अब एचडी वीडियो बना सकते हैं।

-डॉ. मनीष गर्ग, वरिष्ठ वैज्ञानिक,

'मल्टी पेटा हट्र्ज इलेक्ट्रॉनिक मेट्रोलॉजी'

- इस 4डी माइक्रोस्कोप से एक परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की गति को न सिर्फ देखा जा सकता है, बल्कि उसका वीडियो भी बनाया जा सकता है।
- इससे इलेक्ट्रॉन को वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मौजूदा कंपन क्षमता से सौ गुना अधिक कंपन क्षमता पर देखा जा सकेगा।
- कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉन की कंपन की आवृत्ति अधिकतम एक अरब हटर्ज (पेटा हट्र्ज) होती है, अब इसे एक खरब हर्ट्ज तक बढ़ाया जा सकता है।
- इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 10 लाख गुना तक तेज हो सकते हैं, यानी 100 गीगा हर्ट्ज के कंप्यूटर को 100 पेटा हर्ट्ज का बनाया जा सकता है।

पढ़ने के लिए 16 किमी दूर जाना पड़ता था

मनीष गर्ग मप्र के शहडोल जिले के बराछ गांव के मूल निवासी हैं। उनके पिता एक कोल कंपनी में कार्य करते थे। मनीष को पढ़ने के लिए 16 किमी दूर स्थित स्कूल जाना पड़ता था। इस स्कूल से उन्होंने 10वीं पास की। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई उन्होंने किसी स्कूल में जाने की बजाए घर बैठकर की। हां, उनके आग्रह पर इसके लिए पिता ने एक कंप्यूटर का इंतजाम अवश्य कर दिया था। प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में परीक्षा फॉर्म भरकर उन्होंने जेईई परीक्षा पास की और कोलकाता के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने जर्मनी के म्यूनिख स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स से पीएचडी भी की। कंप्यूटर से जुड़ी एक प्रतिष्ठित कंपनी इंटेल ने उन्हें अपना ब्रांड एंबेसेडर भी बनाया।

पीएमटी कांड में सीबीआइ ने 80 को दी क्लीनचिट

नईदुनिया, ग्वालियर

सीबीआइ ने शुक्रवार को विशेष न्यायालय में पीएमटी कांड के 281 आरोपितों में से 201 के खिलाफ चालान पेश किया। जांच के दौरान 80 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में क्लीनचिट दी गई। 201 में से 181 आरोपित पहले से ही जमानत पर हैं। जांच के दौरान 20 नए आरोपितों के नाम जोड़ गए थे, जिनमें से दो को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। सीबीआइ के नोटिस पर 18 में से सिर्फ दो डॉक्टर कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इनमें एक मनोज मौर्य दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में पदस्थ हैं। 16 आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। करीब 800 पेज का चालान होने से सीबीआइ ने सीडी में चालान की कॉपी पेश की।

गौरतलब है कि 2006 से 2010 के बीच फर्जी तरीके से पीएमटी (प्री मेडिकल टेस्ट) पास करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआइटी) ने केस दर्ज किया था। एक एफआइआर में 276 लोगों को आरोपित बनाया था। इस केस में एसआइटी चालान पेश नहीं कर पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यापम कांड की जांच सीबीआइ को सुपुर्द हो गई थी। सीबीआइ ने वर्ष 2015 में इस केस को भी ले लिया था। सीबीआइ ने नई एफआइआर दर्ज की थी। जांच के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 281 तक पहुंच गया। सीबीआइ ने जांच के दौरान परीक्षार्थियों के सॉल्वर, मिडिल मेन को तलाश लिया। उनके नाम एफआइआर में बाद में जोड़े गए। 80 आरोपितों को यह कहते हुए क्लीनचिट है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

इनके नाम जोड़े गए चालान में : चालान में अमित कुमार, उमेश, प्रवीण, तारिक, वीरेंद्र कुमार, अभिमन्यु सिंह, दीपक अहिरवार, आलोक गंगवार, धर्मेंद्र सिंह, संतोष, सुबोध, महेश, आशीष, विनोद, सौराव, राकेश कुमार के नाम जोड़े गए थे।

आशीष कुमार, मनोज मौर्य कोर्ट में उपस्थित हो गए। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया। मनोज मौर्य दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल डॉक्टर हैं। आशीष कुमार उज्जैन के शासकीय अस्पताल में अर्थोपेडिक पद पर कार्यरत हैं।

राजकुमार व सरिता शर्मा को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।

अकाली नेता के घर से 194 किलो हेरोइन बरामद, छह लोग गिरफ्तार

बड़ी बरामदगी ▸ इटली से इंटरपोल और गुजरात पुलिस की सूचना पर हुई कार्रवाई

आरोपितों में अफगान नागरिक और एक महिला भी हैं शामिल

जागरण संवाददाता, अमृतसर

पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने शुक्रवार को अमृतसर में हेरोइन तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश कर छह लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी इटली से इंटरपोल और गुजरात पुलिस की सूचना के बाद हुई। दो चरणों में हुई कार्रवाई में पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के नेता व पंजाब सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (पीएसएसबी) के पूर्व सदस्य अनवर मसीह की कोठी से 194 किलो हेरोइन व अन्य नशीले पदार्थ बरामद किए। पकड़े गए आरोपितों में अफगानिस्तान का अरमान बशअरमल और अमृतसर के बड़े कपड़ा कारोबारी अंकुश कपूर प्रमुख तौर पर शामिल हैं।

एडीजीपी एसटीएफ हरप्रीत सिंह सिद्धू और आइजी डॉ. कौस्तुभ शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस ने 29 जनवरी की रात सुखबीर सिंह उर्फ हैपी और बड़े कारोबारी अंकुश कपूर को ब्रीजा कार सहित गिरफ्तार किया था। उनके पास से छह किलो हेरोइन मिली थी। अंकुश ने स्वीकार किया कि उसने कुछ दिन पहले सुल्तानविंड रोड स्थित आकाश विहार में एक कोठी किराए पर ली थी, जहां अफगान नागरिक अरमान हेरोइन को रसायन से साफ करके अन्य नशीले पाउडर मिलाता था। आइजी कौस्तुभ शर्मा की अगुआई में आकाश विहार स्थित कोठी में छापा मारा गया तो महिला की भूमिका के बारे में कुछ पता नहीं चला। सुखबीर सिंह हैप्पी से रिवॉल्वर बरामद की गई है। इस खेप का 2019 में आइसीपी अटारी पर पकड़ी गई 534 किलो हेरोइन मामले से कोई संबंध नहीं है।

मुझे कुछ मालूम नहीं: अनवर मसीह : अकाली नेता अनवर मसीह ने बताया कि उन्होंने लगभग एक महीना पहले कोठी नौशहरा खुर्द निवासी सुखविंदर सिंह को किराए पर दी थी। इसका किरायानामा भी तैयार कराया है। आरोपितों की पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में वह चुप्पी साध गए।

इटली से संधू के इशारे पर खेप बरामद : इटली पुलिस के हत्थे चढ़े अमृतसर के रंजीत एवेन्यू निवासी सिमरजीत सिंह संधू की सूचना पर ही एसटीएफ ने यह खेप बरामद की है। संधू 300 किलो हेरोइन के मामले में गुजरात पुलिस का वांछित है। वह किसी तरह इटली पहुंच गया। इटली से गुजरात पुलिस को इनपुट मिला था, जो उसने पंजाब पुलिस को दिए। कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शुक्रवार को अमृतसर पहुंच गए।

अरमान ने बनाई थी लैब : अफगान नागरिक अरमान ने कोठी में एक लैबोरेट्री बना रखी थी। वह हेरोइन को केमिकल से साफ कर उसमें दूसरे नशीले पदार्थ मिलाने में माहिर है।

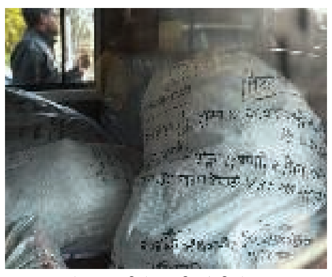

अमृतसर में अकाली नेता की कोठी से बरामद हेरोइन। राघव शिकारपुरिया

इनको किया गिरफ्तार
अंकुश कपूर, कपड़ा कारोबारी (अमृतसर)
अरमान बशअरमल, अफगानिस्तान
सुखबीर सिंह हैप्पी (अमृतसर)
सुखविंदर सिंह, अमृतसर के मॉल रोड स्थित तलवाकर जिम के ट्रेनर (नौशहरा खुर्द, अमृतसर)
मेजर सिंह, (अमृतसर)
तमन्ना गुप्ता, (यासीन रोड, अमृतसर)

क्या-क्या मिला

- **194** किलोग्राम हेरोइन
- **205** लीटर केमिकल
- **38.220** किलोग्राम संदिग्ध पाउडर
- **25.865** किलोग्राम कैफेन पाउडर:
- **01** लाइसेंसी रिवॉल्वर

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की निर्भया के दोषी पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी पवन गुप्ता की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। पवन ने अपराध के समय नाबालिग होने का दावा खारिज करने के आदेश के खिलाफ यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।

पवन ने अपराध के समय दिसंबर 2012 में नाबालिग होने का दावा किया था। हालांकि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसका यह दावा खारिज किया जा चुका है। लेकिन उसने अब सुप्रीम कोर्ट से दावा खारिज होने के आदेश के खिलाफ यह पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। पवन ने शुक्रवार को ही याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में शुक्रवार को ही मामले पर विचार करने के बाद याचिका खारिज कर दी। जस्टिस आर. भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि उन्होंने पुनर्विचार याचिका और उसके साथ दाखिल दस्तावेज ध्यान से देखे और यह पाया कि जिस आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है उसमें ऐसी कोई खामी नहीं है जिस पर पुनर्विचार की जरूरत हो।

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के चार दोषियों में एक पवन गुप्ता भी है। जिसे दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट तक से पवन की फांसी पर मुहर लग चुकी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा को चुनौती देने वाली उसकी पुनर्विचार याचिका पहले ही खारिज कर चुका है। हालांकि पवन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल नहीं की है और न ही उसने फांसी माफी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की है। ऐसे में मौत की सजा से बचने के दो कानूनी विकल्प उसके पास हैं।

दिल्ली के वसंत विहार में 16 दिसंबर, 2012 की रात पैरामेडिकल छात्रा से चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था जिसमें छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक से चारों अभियुक्तों मुकेश, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और विनय कुमार शर्मा को मृत्युदंड दिया गया है।

▸ **अपराध के समय नाबालिग होने का दावा खारिज करने के आदेश के खिलाफ दाखिल की थी याचिका**

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

पवन, विनय और मुकेश की परिजनों से हुई मुलाकात

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : तिहाड़ के जेल संख्या तीन में शुक्रवार को एक ओर जहां फांसी का ट्रायल चल रहा था, वहीं जेल अधीक्षक कार्यालय परिसर में कुछ लोग दोषियों से मुलाकात कर रहे थे। मुलाकात समाप्त होने तक कोर्ट द्वारा फांसी को टालने की बात सामने नहीं आई थी, ऐसे में इस मुलाकात को जेलकर्मी मन ही मन अंतिम मुलाकात मानकर चल रहे थे। लेकिन, अब जबकि दोषियों की फांसी कोर्ट के अगले आदेश तक टल चुकी है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि दोषियों के परिजनों से मुलाकात का सिलसिला अभी कुछ वक्त और चलता रहेगा।

जेल सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को पवन, विनय व मुकेश के स्वजन मुलाकात के लिए जेल आए थे। कड़ी सुरक्षा में तीनों दोषियों को उनके सेल से बाहर निकालकर स्वजनों के सामने लाया गया। करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात के बाद जब वे जेल से बाहर जा रहे थे तब वे रो रहे थे। सूत्रों की मानें तो जेलकर्मियों ने उनसे शांत रहने का अनुरोध किया। कुछ ही दिन पहले अक्षय के स्वजन भी उससे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। जेल सूत्रों का कहना है कि दोषियों ने ही परिजनों को मुलाकात के लिए बुलाया था।

वकीलों की भूमिका पर उठाए सवाल

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर का अब इस केस में कोई भूमिका नहीं है। मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। अदालत ने ग्रोवर को सहायता के लिए नियुक्त किया था, लेकिन वह केस को भटका रही हैं। इस पर ग्रोवर ने कहा कि इस तरह के निजी हमले ठीक नहीं हैं। इसके बाद मुकेश की तरफ से एक अर्जी दायर हुई, जिसमें कहा गया कि उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती, जब तक अन्य दोषियों के कानूनी विकल्प शेष हैं।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र झा ने कहा कि यह सब न्यायिक प्रणाली में हेरफेर कर किया जा रहा है। हाई कोर्ट द्वारा अधिवक्ता एपी सिंह पर अदालत को गुमराह करने के लिए जुर्माना लगाया जा चुका है। इस पर एपी सिंह ने कहा कि उन पर निजी हमला हो रहा है। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आप तय करें कि खुद को बचाने आए हैं या दोषियों को?

किस दोषी के लिए क्या कानूनी विकल्प शेष

मुकेश	सभी विकल्प खत्म
विनय	दया याचिका
अक्षय	दया याचिका
पवन	उपचारात्मक और दया याचिका

इन दोषियों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम लगातार सिस्टम से प्रताड़ित हो रहे हैं। दोषियों के वकील ने मुझे चुनौती दी है कि फांसी कभी नहीं होगी। मेरी लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी और सरकार को फांसी देनी ही होगी।
निर्भया की मां (अदालत के बाहर)

जब तक किसी मामले में एक भी दोषी की कोई याचिका विचाराधीन हो, डेथ वारंट जारी ही नहीं हो सकता। अदालत में इसी तथ्य को रखा गया है।
अधिवक्ता एपी सिंह (अदालत के बाहर)

ये सारे हथकंडे न्याय में देरी के लिए अपनाए जा रहे हैं। पहले किसी ने कोई याचिका दायर नहीं की, लेकिन जब डेथ वारंट जारी हुआ तो एक के बाद एक याचिकाएं दायर हो रही हैं।
सीमा कुशवाहा, पीड़िता की वकील (अदालत के बाहर)

न्यूज गैलरी

नक्सली ब्लास्ट में जवान घायल निशाने पर थे अधिकारी

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के दौरान नक्सलियों की ओर से रची गई साजिश नाकाम हो गई। हालांकि, नक्सलियों ने धनीकरका के पास जो बम लगाया था,उसकी चपेट में आकर एक जवान घायल हो गया। धमाके के कुछ ही देर बाद इसी मार्ग से कलेक्टर- एसपी गुजरने वाले थे। शुक्रवार को जिले के कटेकल्याण ब्लॉक में पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया गया। (नईदुनिया)

बांग्लादेश लौट रहे सात घुसपैठिये सीमा से गिरफ्तार

कोलकाता : बीएसएफ ने बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर अलग-अलग स्थानों से सात घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ के मुताबिक गुरुवार देर रात हुई कार्रवाई में बॉर्डर आउटपोस्ट (बीओपी) चारकुटीबारी क्षेत्र से चार बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उत्तर 24 बीओपी तराली इलाके से दो एवं बीओपी डोबिला इलाके से एक को गिरफ्तार किया गया। (जासं)

डीएचएफएल सीएमडी वधावन भर्ती, स्वाइन फ्लू का शक

मुंबई, प्रेट्र : गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन (डीएचएफएल) के सीएमडी कपिल वधावन को स्वाइन फ्लू के संदेह के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वधावन के वकील ने शुक्रवार को कोर्ट को यह जानकारी दी। वधावन को सांस लेने में परेशानी और तनाव की शिकायत के बाद राज्य सरकार के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि खत्म होने के बाद भी शुक्रवार को विशेष अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सका। केंद्रीय एजेंसी ने वधावन की हिरासत जारी रखने की मांग भी नहीं की। इसके बाद जज प्रशांत राजवैद्य ने वधावन को तीन फरवरी अथवा अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

वधावन के वकील अमित देसाई ने बताया कि उनके मुवक्किल की संदिग्ध स्वाइन फ्लू की जांच की जा रही है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि वधावन को आइसीयू से अन्यत्र नहीं स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। कोर्ट ने कहा कि वह वधावन की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी इकबाल मिर्ची से जुड़े एक मनी लांड्रिंग के मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत वधावन (46) को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि वधावन ने मुखौटा कंपनी बनाकर उसमें पैसे हस्तांतरित किए और उनका इस्तेमाल दक्षिण वर्ली इलाके में स्थित गैंगस्टर मिर्ची की संपत्तियों की खरीद के लिए किया। मिर्ची की वर्ष 2013 में मौत हो चुकी है।

उधर, बांबे हाई कोर्ट ने ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली वधावन की याचिका पर राहत देने से इन्कार कर दिया। वकील ने कहा कि वधावन जांच में मदद कर रहे हैं, इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ईडी के वकील ने विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त मांगा।

जम्मू-कश्मीर पर केंद्रीय मंत्रियों ने पीएमओ को देनी शुरू की रिपोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर दौरे पर गए 37 केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद एक अपना फीड बैक प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को देना शुरू कर दिया है। इस नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विकास योजनाओं को लागू होने के संबंध में जानकारियां दी जानी हैं। हालांकि अब तक केंद्र के 14 मंत्रियों ने कल्याणकारी योजनाओं पर अमल करने का ब्योरा पीएमओ को सौंपा है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अभी भी 23 केंद्रीय मंत्रियों को अपना फीडबैक देना बाकी है। दरअसल, इन केंद्रीय मंत्रियों ने इस पखवाड़े में विभिन्न तिथियों में जम्मू-कश्मीर के बारह जिलों का दौरा किया था जिसमें से नौ जिले जम्मू और श्रीनगर, गांदरबल व बारामूला जिले कश्मीर के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर यह दौरे किए गए। इनका मकसद यह देखना था कि पांच अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां 55 केंद्रीय योजनाओं को समुचित तरीके से लागू कराया गया है अथवा नहीं।

डिफेंस एक्सपो में दुनिया देखेगी अंतरिक्ष के 'योद्धा' भारत को

तैयारी

हथियारों की मंडी में जुटेंगे दुनियाभर के दिग्गज, सेटेलाइट गिराने वाला मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर होगा खास, भारत सहित चीन, अमेरिका, रूस के पास ही है यह तकनीक

निशांत यादव, लखनऊ

डिफेंस एक्सपो-2020 में जमीन, पानी और हवा में मार करने वाले हथियार ही नहीं दिखेंगे बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष युद्ध में कौन देश कितना ताकतवर है...? इससे भी पर्दा उठेगा। होड़ में इस अत्याधुनिक तकनीक से लैस चुनिंदा चार देशों की कतार में खड़ा भारत भी शामिल होगा। मिशन शक्ति के तहत सेटेलाइट मार गिराने वाले डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन) के मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर को पहली बार दुनिया देखेगी। अपने सबसे अचूक अस्त्र को उतारने के पीछे भारत की मंशा हथियारों के बाजार में गहरी पैठ को बढ़ाना है।

पांच फरवरी से प्रस्तावित डिफेंस एक्सपो-2020 की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, लखनऊ में सजने वाली हथियारों की मंडी की पूरी तस्वीर साफ हो गई है। इस दौरान हथियार बनाने वाले अग्रणी देशों की तकनीकी ताकत के बीच भारत की कोशिश सबसे बड़ा आयातक नहीं, मेक इन इंडिया के तहत हथियारों का बड़ा निर्यातक बनने की है। वैसे भी अंतरिक्ष में युद्ध कौशल की तरफ कदम बढ़ा चुके दुनिया के चुनिंदा देश अमेरिका, चीन, रूस के साथ भारत भी पहले ही खड़ा है। चूंकि, इन देशों में अकेला चीन ही एक्सपो में भाग नहीं ले रहा है। ऐसे में उसके हिस्से के बड़े बाजार पर भारत की नजर है। साथ ही दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस समेत अन्य देसी हथियारों को भी आगे बढ़ाने का इरादा है।

डीआरडीओ के हथियारों पर नजर

एंटी सेटेलाइट मिसाइल, ब्रह्मोस के अलावा दुनिया की नजरें डीआरडीओ के बनाए अन्य हथियारों पर भी होगी। रडार के क्षेत्र में इजराइल को भारत कड़ी प्रतिस्पर्धा देता दिखेगा। इसके के लिए इलेक्ट्रानिक्स ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी, मीडियम पावर रडार अरुध्र और मल्टी फंक्शनल रडार उतारे जाएंगे।

पूरी तरह स्वदेशी आर्टीलरी गन धनुष को मार्केट में होवित्जर एम-777 के विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा।

अर्जुन टैंक की बाधाएं दूर करने के बाद इसकी आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश रहेगी।

बीईएमएल अपनी मीडियम बुलेट प्रूफ व्हीकल के लिए भी बाजार तलाशेगा

भारतीय आर्डिनेंस फैक्ट्री की माइन प्रोटेक्टेट व्हीकल भी दक्षिण अफ्रीका के उपकरणों को चुनौती देंगे।

बोइंग नापेगा समुद्र

- **कई कंपनियों के बीच एक्सपो में होगी बोइंग पर सबकी नजर**
- **दुनिया के जंबो जेट बनाने वाली कंपनी पेश करेगी एफए-18 हार्नेट**

भारत के बाजार पर फिदा बोइंग

एक्सपो पर बोइंग जैसी कंपनियों की भी नजर है। चिनूक के बाद बोइंग की कोशिश भारतीय नौसेना के लिए एफए-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान बेचने की है। इस विमान को अभी अमेरिकी नौसेना इस्तेमाल कर रही है।

मेक इन इंडिया पर रहेगी नजर

- एक्सपो में विदेशी कंपनियों की मेक इन इंडिया की प्रतिबद्धता भी नजर आएगी।
- अमेरिका एम-777 होवित्जर आर्टीलरी गन को मेक इन इंडिया थीम पर प्रदर्शित करेगा।
- कोरिया की कंपनी के स्टॉल पर के9-वज्र मेक इन इंडिया का उदाहरण पेश करेगी।

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को नगरोटा के बन इलाके में आतंकियों के खिलाफ अभियान के दौरान सेना के जवान। जागरण

ये हुई बरामदगी

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

पांच एके 47 राइफल, एक पल्सर थर्मल इमेजर युक्त, एम 4 स्नाइपर राइफल के साथ गोलियां, दो अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर, पांच हैंड ग्रेनेड, तीन पाउच, बारूद, दवाइयां, एनर्जी सप्लीमेंट, फैंस कटर, आइकॉम रेडियो सैट, दो मोबाइल फोन व चार बैग। आतंकियों ने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखे थे।

पाक ने फिर तोड़ा संघर्षविराम

लगातार करारा जवाब मिलने के बावजूद पाकिस्तान ने पुंछ जिले के शाहपुर कीरनी और कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के चक चंगा, छन्नटांडा गांवों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ है।

3,762 मर्चेंट नेवी कर्मियों को फर्जी प्रमाणपत्र पर जहाजरानी महानिदेशालय ने नौकरी करते हुए पाया है। इन सभी को कुछ मेरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (एमटीआइ) की मिलीभगत से फर्जी योग्यता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे।

दैनिक जागरण और गूगल लेंस आए साथ, अब अखबार बोलेगा

जेएनएन, नई दिल्ली

- गूगल लेंस लोगो वाली खबर को स्मार्टफोन के कैमरे से क्लिक करके देख सकेंगे सजीव
- यह तकनीक पाठकों को समाचार पत्र के खबरों का डिजिटल अनुभव प्राप्त करने की सुविधा देती है

अपने पाठकों को विश्वसनीय खबरें और बेहतर प्रस्तुति देने के लिए संकल्पित दैनिक जागरण ने इस दिशा में एक और अभिनव कदम उठाया है। अब हम छपे हुए शब्दों को स्वर दे रहे हैं। आप जानते ही हैं कि समाचार पत्र की अपनी सीमाएं होती हैं। खबरों के लिए सीमित जगह और 24 घंटे का निर्धारित समय। इन्हीं चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए जागरण ने गूगल लेंस को साथ जोड़ा है। इससे आपका अखबार अब खास खबरें सुनाएगा और दिखाएगा।

दैनिक जागरण और गूगल लेंस के इस अनूठे प्रयास से अब पाठक समाचार पत्र में छपे गूगल लेंस लोगो वाली खबर को अपने स्मार्टफोन के कैमरे से क्लिक कर उसे सजीव देख सकेंगे। यानी, संबंधित खबर और उसका वीडियो स्मार्टफोन पर लाइव हो जाएगा। इस तरह अब आपका अखबार दैनिक जागरण खास खबरों में आपके लिए बोल उठेगा।

आपको बता दें कि गूगल लेंस आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से लैस तकनीक है जो आपके स्मार्टफोन के कैमरे और 'डीप मशीन लर्निंग' का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ किसी वस्तु की पहचान करती है, बल्कि यह उस चीज को समझती भी है और यह जो देखती है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध कराती है।

गूगल लेंस तकनीक पाठकों को समाचार पत्र के खबरों का डिजिटल अनुभव प्राप्त करने की सुविधा देती है। इनमें वीडियो, इंफोग्राफिक्स, गहन विषय-वस्तु और बहुत कुछ शामिल है।

दैनिक जागरण और गूगल लेंस का एक साथ आना वैश्विक मीडिया जगत में अपनी तरह का एक अनूठा कदम है क्योंकि दैनिक जागरण नवाचारों के साथ आगे बढ़ने में भरोसा रखता है। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके पाठक तेज गति से चल रही जिंदगी के साथ अपडेटेड रहें और इसके समाचार पत्र पाठकों को भी डिजिटल और टेलीविजन कंटेंट का लाभ मिल सके। हम आगे भी आपके अनुभव को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे।

आइबीएम के सीईओ चुने गए भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा

न्यूयार्क, एजेंसियां : दुनिया की जानी-मानी कंपनियों की कमान थामने वाले भारतीयों की फेहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है। दुनिया की दिग्गज आइटी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (आइबीएम) के अरविंद कृष्णा सीईओ नियुक्त हुए हैं।

57 साल के भारतीय मूल के अमेरिकी अरविंद कृष्णा को शुक्रवार को आइबीएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी का सीईओ चुना। वह छह अप्रैल से मौजूदा सीईओ वर्जीनिया रोमैटी की जगह इस पद को संभालेंगे। रोमैटी ने अरविंद कृष्णा को बेहतरीन टेक्नोलॉजिस्ट बताते हुए कहा कि आइबीएम के अगले युग के सही सीईओ हैं। उन्होंने आइबीएम की प्रमुख तकनीकों में जैसे-आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग व ब्लॉक चेन में अहम भूमिका निभाई है।

कृष्णा का जन्म हैदराबाद में हुआ था। वह 1990 से इस कंपनी से जुड़े हैं। अमेरिकी कंपनी आइबीएम का बाजार पूंजीकरण करीब नौ लाख करोड़ रुपये है। कृष्णा ने सीईओ चुने जाने के बाद खुशी जताते हुए कहा कि आइबीएम में इतने प्रतिभाशाली लोग और उच्च तकनीक है कि हम कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान कर लेंगे।

- आइटी कंपनी में छह अप्रैल से वर्जीनिया रोमैटी की जगह लेंगे
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग में निभाई अहम भूमिका

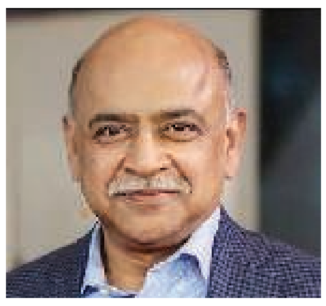

अरविंद कृष्णा की फाइल फोटो। आइबीडॉटकॉम

अभी तक का दायित्व

- वर्तमान में अरविंद आइबीएम में क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के लिए सीनियर वाइस प्रेसीडेंट के पद पर हैं। उन्होंने आइबीएम बिजनेस यूनिट का नेतृत्व किया।
- उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों में आइबीएम क्लाउड, आइबीएम सिक्योरिटी और कॉग्निटिव एप्लिकेशन बिजनेस और आइबीएम रिसर्च भी शामिल हैं।
- अरविंद सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट के अधिग्रहण के प्रणेता थे।

आइआइटी कानपुर से की है पढ़ाई अरविंद कृष्णा ने 1985 में आइआइटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग से स्नातक किया है। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलनोइस से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की है। उनके नाम शोध व तकनीकी से संबंधित 15 पेटेंट हैं।

आइबीएम के बारे में

कंपनी की शुरुआत 16 जून 1911 में कंप्यूटिंग-टैबुलैटिंग-रिकॉर्डिंग कंपनी के नाम से हुई।1924 में इसे बदल कर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किया गया। इसे बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता है।

ये अमेरिकी कंपनी भारत समेत 170 से भी ज्यादा देशों में फैली है।

दुनिया की सबसे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में से एक है। इसमें लगभग 3,80,000 कर्मचारी हैं। अमेरिका के बाहर इसके सर्वाधिक कर्मचारी भारत में हैं।

कंप्यूटर कंपनियों में आइबीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अब तक तीन नोबेल पुरस्कार, चार टूरिंग पुरस्कार, पांच राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक तथा पांच राष्ट्रीय विज्ञान पदक जीते हैं।

कंपनी के नाम दुनिया के सर्वाधिक पेटेंट होने का भी इतिहास है। 1981 में आइबीएम ने पर्सनल कंप्यूटर्स की बिक्री शुरू की।

भारतीयों का परचम

सुंदर पिचाई	सीइओ	गूगल	चेन्नई
सत्य नाडेला	सीइओ	माइक्रोसॉफ्ट	हैदराबाद
राजीव सूरी	सीइओ	नोकिया	भोपाल
शांतनु नारायण	सीइओ	एडोब	हैदराबाद
संजय झा	सीइओ	मोटोरोला	बिहार
अजयपाल सिंह बंगा	सीइओ	मास्टरकार्ड	महाराष्ट्र

आइबीएम ने 26 साल पहले भारत में अपना पहला आफिस खोला था। दो ही दशकों में आज अधिकतम भारतीय कर्मचारियों की मदद से कंपनी ने वह मुकाम हासिल किया है कि बैंकों के बीच होने वाला हरेक लेन-देन आइबीएम के जरिये होता है। भारत में दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियों, दस में से नौ बैंकों, दुग्ध और डेयरी उत्पाद उद्योग के दो-तिहाई उत्पाद, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट (ट्रैफिक) का संचालन और प्रबंधन आइबीएम के जरिये ही हो रहा है।

बच्चों के साथ घर को उड़ा देना चाहता था सिरफिरा

फर्रुखाबाद एनकाउंटर ▶ मुठभेड़ में ढेर सुभाष के घर से 104 बम, देसी राइफल-तमंचा व कारतूस बरामद

घर में पांच किलोग्राम के सिलिंडर व पेंट के डिब्बों में छुपाकर रखे थे बम

विजय प्रताप सिंह, फर्रुखाबाद

फर्रुखाबाद के करथिया गांव में खड़े सुभाष के चंगुल से छूटे बच्चे। जागरण

उप्र के फर्रुखाबाद में बेटी के बर्थडे के बहाने 24 बच्चों को कई घंटे बंधक बनाने वाले सिरफिरे सुभाष बाथम को ढेर करने के बाद तलाशी में उसके घर से बारूद, बम और हथियारों का जखीरा मिला है। उसने बच्चों को छोड़ने के बदले में 20 करोड़ रुपये और हाईवे किनारे जमीन भी मांगी थी। नहीं देने पर पूरा घर उड़ा देने की धमकी तक दी थी। हालांकि, इसके पहले ही पुलिस ने उसे मार गिराया। पुलिस को उसके कमरे से 100 छोटे और चार बड़े बम, एक देसी राइफल व एक तमंचा और कारतूस मिले हैं। एक पेंट बम घर के दरवाजे पर तो पांच किलोग्राम के गैस सिलिंडर में बारूद से बनाया गया बम बेसमेंट में मिला है। शुक्रवार सुबह मुरादाबाद से आए बम निरोधक दस्ते ने इन्हें नष्ट किया।

फर्रुखाबाद की मोहम्मदाबाद कोतवाली इलाके के गांव करथिया के सिरफिरे सुभाष बाथम ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे अपनी एक साल की बेटी कुसुम की बर्थडे पार्टी के बहाने गांव के 24 बच्चे बुलाए और घर के 15 फीट लंबे-चौड़े और 10 फीट गहरे तहखाने में बंधक बना लिया था। मौसा के कत्ल में उम्र कैद की सजा पा चुके सुभाष के इस कृत्य में उसकी बीवी रूबी भी सहयोगी बनी। बच्चों को सकुशल बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद डीजीपी ओपी सिंह व अन्य से पल-पल अपडेट ले रहे थे। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने देर रात मुठभेड़ में सुभाष बाथम को मार गिराने वाली टीम को 10 लाख रुपये इनाम की घोषणा की थी।

पुलिस कार्रवाई से पहले भीड़ ने पथराव कर तोड़ डाला था दरवाजा : आइजी मोहित अग्रवाल सीढ़ी के जरिये छत पर जाने की तैयारी में थे कि बच्चों की कैद से आक्रोशित भीड़ ने सुभाष के घर पथराव करते हुए दरवाजा भी तोड़ डाला। पुलिस भी पीछे से घुस आई। भीड़ सुभाष व उसकी बीवी को बाहर खींच लाई। पुलिस सुभाष को फिर घर में ले गई और वहीं एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मंडलायुक्त सुधीर एम बोबडे की मौजूदगी में हुई तलाशी में पता लगा कि सुभाष ने घर के मुख्य द्वार के पास विस्फोट का पहले से इंतजाम कर रखा था। इसके लिए बम में बल्ब के एलीमेंट का उपयोग किया था। इसे तार से जोड़कर कमरे तक लाया। तार में जैसे ही करंट गया, बम फट गया। उसने पेंट के डिब्बे व गैस सिलिंडर में बारूद भरकर बिजली के एलीमेंट लगाए थे।

भीड़ के हत्थे चढ़ी बीवी, तड़के चार बजे हुई मौत : दरवाजा तोड़कर घर में घुसी भीड़ जिस वक्त सुभाष पर टूट पड़ी तो बीवी रूबी ने बचाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों को जमकर पीटा गया। पुलिस उसे एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल ले गई। शुक्रवार तड़के चार बजे उसे यहां होश तो आया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सफल ऑपरेशन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ व उप्र पुलिस को बधाई दी है। गृहमंत्री ने ट्वीट कर कहा, 'फर्रुखाबाद में बंधक बनाए गए सभी बच्चों को पुलिस द्वारा अपनी कुशल रणनीति व योजना से सुरक्षित छुड़वाना प्रशंसनीय है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप्र पुलिस को बधाई देता हूं।' सीएम ने धन्यवाद देते हुए ट्वीट किया कि प्रदेश सरकार की अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। वहीं, कानपुर में गंगा यात्रा के समापन पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक दरिंदे ने कई बच्चों को कब्जे में ले लिया था। मां गंगा की कृपा से दरिंदा मुठभेड़ में मारा गया और सभी बच्चे सकुशल हैं।

चीख रोकने के लिए एक दूसरे का मुंह दबाते थे बच्चे

जासं, फर्रुखाबाद : शातिर अपराधी सुभाष के तहखाने में कैद एक से लेकर 15 वर्ष तक के 24 बच्चों की सिसकियों तक पर पाबंदी थी। सिरफिरा हल्की सी आवाज पर भी बम से उड़ा देने की धमकी दे रहा था। सामने मौत खड़ी थी, लेकिन किसी की चीख भी निकलती तो दूसरा बच्चा उसके मुंह पर हाथ लगा देता। भूख और प्यास पर खौफ हावी था। करीब 10 घंटे की कैद के बाद छूटे अधिकांश बच्चे दूसरे दिन भी सामान्य नहीं हो पाए। बच्चों को सुरक्षित बचाने वाली 14 साल की अंजलि की छोटी बहन गुड़िया ने बताया कि 'दीदी' लगातार दूसरे बच्चों को हिम्मत बंधाती रहीं। नौ वर्षीय बालिका सोनम ने बताया कि अंजलि दीदी ने ही उसकी एक वर्षीय दुधमुंही बहन शबनम की हालत खराब देखकर सुभाष को इस मासूम को मां के पास भेजने के लिए राजी किया था। आठ वर्षीय बच्ची लक्ष्मी ने बताया कि भूख के मारे बच्चों का बुरा हाल था। चार साल की गौरी तो अब भी दहशत में रोने लगती है। पांच साल की आरवी अपनी तोतली जुबान में कुछ बताने की कोशिश करती है तो उसके चेहरे पर भी खौफ का अहसास साफ दिखता है।

14 साल की बहादुर बिटिया ने तोड़ दिए थे दहशत के 'तार'

संवाद सूत्र, मोहम्मदाबाद

बंधक कांड

- अंजलि ने तहखाने में रखी विस्फोटक भरी बोरी से हटा दिया था तार
- तहखाने का गेट भीतर से बंद कर बच्चों को सिरफिरे की पहुंच से किया दूर

सिरफिरे सुभाष ने बच्चों को तहखाने में बंद कर उसमें विस्फोटक से भरी बोरी में बैटरी का तार डालकर विस्फोट करने की साजिश रची थी। बंधक बच्चों के बीच ही बैठी 14 वर्षीय अंजलि ने हिम्मत दिखाकर तार को बोरी से अलग कर दिया। इसके बाद तहखाने को अंदर से बंद कर लिया था, जिससे सभी 24 बच्चे सुरक्षित बच गए।

सुभाष के चंगुल से छूटने के बाद स्व. नरेंद्र कुमार की 14 वर्षीय पुत्री अंजलि के चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। उसने बताया कि सुभाष चाचा बर्थडे पार्टी के बहाने घर बुलाकर ले गए थे। पहुंचते ही उन्होंने अंदर से गेट बंद कर लिया और जबरदस्ती तहखाने में बंद कर दिया। वहां एक बोरी में बारूद रखा था। उसमें बिजली का तार भी लगा था। सुभाष चाचा कह रहे थे कि 'अगर मुंह से आवाज निकाली तो सबको विस्फोट से उड़ा देंगे'। सभी बच्चे डर गए थे। वह बाहर निकले तो मैंने तार तोड़ दिया और तहखाने का लोहे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उनके कहने पर भी गेट नहीं खोला। चाची (सिरफिरे की पत्नी रूबी) ने दरवाजे के नीचे से बिस्कुट और खाना दिया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खाया और चुप रहे। रात करीब डेढ़ बजे पुलिस गेट तोड़ने लगी तो दरवाजा खोल दिया।

घटना की आपबीती बताती अंजली (मध्य में)। जागरण

बेटी को ग्रामीणों ने दिया इनाम : बहादुर अंजलि को मोहम्मदाबाद निवासी सुभाषचंद्र गुप्ता ने पांच हजार रुपये और बरारिक गांव निवासी फूल सिंह ने दो हजार रुपये देकर पुरस्कृत किया। सभी को इस बेटी पर नाज है।

राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को दंडित करने में बरतें सावधानी : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को पुराने आपराधिक मामलों के लिए सावधानीपूर्वक दंडित किया जाना चाहिए। खासकर जब उन पर देशद्रोह और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हों, चूंकि ऐसे आरोप राजनीतिक कारणों से भी लगाए जा सकते हैं। जस्टिस आरएफ नरिमन और एस.रविंद्र भट की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए कहा। याचिका में राजनीतिक के अपराधीकरण पर सर्वोच्च अदालत के 25 सितंबर, 2018 के फैसले का पालन नहीं करने का दावा किया गया है। लिहाजा, खंडपीठ ने कहा कि हमें ऐसे मामलों में बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चूंकि अब आरोप राजनीति से प्रेरित होकर भी लगाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मौजूदा संसद में 43 फीसद सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील विकास सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग, भाजपा नेता और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वकील गोपाल शंकरनारायणन के इस सुझाव को मानने को तैयार हो गया है कि सभी राजनीतिक दल अनिवार्य रूप से अपने वेबसाइटों पर अपने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को अपलोड कर दें। साथ ही यह भी स्पष्ट करें उन सीटों के लिए बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा सका। इसके बावजूद आयोग का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों को उनका आपराधिक रिकॉर्ड न बताने पर दंडित करने का सुझाव मानने योग्य नहीं है।

मंत्रियों के भ्रष्टाचार से संबंधित याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले नौकरशाह संजीव चतुर्वेदी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। याचिका में उन्होंने वर्ष 2014-17 के दौरान पीएमओ को मंत्रियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों को आरटीआइ कानून के तहत सार्वजनिक करने की मांग की है। जस्टिस हेमंत गुप्ता व एल. नागेश्वर राव की पीठ ने याचिका पर गौर करते हुए केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (सीपीआइओ) और पीएमओ को नोटिस जारी किया है। चतुर्वेदी ने छह सितंबर 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि पीएमओ के सीपीआइओ ने आरटीआइ पर विचार करते हुए कोई गलती नहीं की है। चतुर्वेदी ने पीएमओ में दाखिल अपने आरटीआइ आवेदन में केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ मिलीं भ्रष्टाचार की शिकायतों, उन्हें लेकर हुई पूछताछ और की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी थी।

नेपाल के उपराष्ट्रपति के सलाहकार बन सर्किट हाउस में रुकने आए जालसाज गिरफ्तार

नईदुनिया, उज्जैनः नेपाल के उपराष्ट्रपति नंदकिशोर पून के सांस्कृतिक सलाहकार बनकर मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सर्किट हाउस में ठहरने आए तीन जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपित के खिलाफ जयपुर में धोखाधड़ी, मारपीट और चोरी के डेढ़ दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। आरोपितों के कब्जे से फर्जी दस्तावेज, परिचय पत्र, विजिटिंग कार्ड आदि बरामद किए गए हैं।

एसपी सचिन अतुलकर ने बताया कि गुरुवार रात सर्किट हाउस से सूचना मिली थी कि नेपाल के उपराष्ट्रपति के सांस्कृतिक सलाहकार बताने वाले तीन लोग यहां ठहरने आए हैं। तीनों के पास मौजूद कागजात संदिग्ध हैं। इस पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। सलाहकार बताने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम महावीरप्रसाद पुत्र सत्यनारायण टोरडी निवासी मोतीनगर सोडाला थाना जयपुर बताया। उसके साथ मौजूद व्यक्तियों के नाम कुलदीप व प्रमोद बताए गए। पुलिस अधिकारियों की जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। आरोपित इस प्रकार की धोखाधड़ी मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित कई प्रदेशों में कर चुके हैं। जयपुर में महावीर के खिलाफ 18 केस दर्ज हैं।

मुंबई में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा

महाराष्ट्र के मुंबई के शिवाजी पार्क में शुक्रवार को भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकली। यह पहला मौका था जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की प्रतिमाओं को रथयात्रा के लिए पुरी से मुंबई लाया गया था। हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ के रथ खीचे। एएनआइ

मिसाल

40 साल से हर मकर संक्रांति मेला पर गंगासागर पहुंच कर रहे मानवता की सेवा, शिविर लगाकर बीमार तीर्थयात्रियों का करते हैं नि:शुल्क इलाज

स्वस्थ समाज

हर साल गंगासागर पहुंच 'पुण्य' कमाते हैं यह डॉक्टर भाई-बहन

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

सब तीरथ बार-बार, गंगासागर एक बार! लोग आस्था के महापर्व मकर संक्राति पर एक बार भी गंगासागर पहुंच जाने को सौभाग्य मानते हैं, वहीं यह डॉक्टर भाई-बहन पिछले 40 साल से हर बार यहां पहुंच सेवा कर पुण्य कमाते आ रहे हैं।

मानव सेवा की मिसाल पेश करने वाले भाई-बहन हैं- 73 साल के डॉ. अनंत कुमार चक्रवर्ती और 65 साल की डॉ. अंजलि चक्रवर्ती। दोनों पेशे से होम्योपैथी डॉक्टर हैं। गंगासागर में जो तीर्थयात्री बीमार पड़ जाते हैं, दोनों उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। उनका वेस्ट बंगाल डीएमएस एसोसिएशन गंगासागर में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा प्रदान करने वाला सबसे पुराना संगठन है।

पत्तियों से बनी झोपड़ी में रहकर करते हैं इलाज : गंगासागर में डॉ. भाई-बहन को खुद भी बेहद कठिनाई झेलनी पड़ती है। राज्य सरकार की तरफ से रहने को होगला नामक पत्तियों से झोपड़ी बनाकर दी जाती है। मकर संक्रांति के समय पड़ने वाली कड़ाके की ठंड में दोनों इसी में रहते हैं। उनका चिकित्सा शिविर भी इसी पत्ती का बना होता है। डॉ. अनंत चक्रवर्ती ने कहा- गंगासागर की यात्रा बेहद कठिन है। दुर्गम यात्रा की थकान व वहां चलने वाली सर्द हवाओं के कारण बहुत से तीर्थयात्री बीमार पड़ जाते हैं। उनके निःशुल्क इलाज के लिए हम पिछले 43-44 साल से यहां चिकित्सा शिविर लगाते आ रहे हैं। मरीजों के निःशुल्क इलाज के साथ ही उन्हें मुफ्त में दवाएं भी दी जाती हैं।

डॉक्टर भाई-बहन उस जमाने से गंगासागर जा रहे हैं, जब ज्यादातर डॉक्टर वहां चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने जाने से कतराते थे। डॉ. अंजलि चक्रवर्ती ने कहा- गंगासागर में अभी बहुत सी संस्थाएं मकर संक्रांति पर चिकित्सा शिविर लगाती हैं, लेकिन पहले वहां इतनी सुविधाएं नहीं थीं।

शुरू में हम गंगासागर मेला परिसर में घूम-घूमकर मरीजों को तलाशते थे क्योंकि हर मरीज खुद से चलकर हमारे चिकित्सा शिविर में आने की हालत में नहीं होता था। वहां होने वाली तकलीफ पर दोनों ने कहा- मानव सेवा के आगे ये तकलीफ कुछ भी नहीं। देश के कोने-कोने से गंगासागर आने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा करके अलग ही आनंद मिलता है। ड्यूटी के कारण हम तो पुण्य स्नान भी नहीं कर पाते। हमारा पुण्य तो बीमार लोगों का इलाज करना है।

उम्र के इस पड़ाव में भी अविवाहित भाई-बहन में शुरुआती दिनों जैसा ही उत्साह नजर आता है। उन्होंने कहा, जब तक शरीर साथ देगा, हम गंगासागर जाते रहेंगे।

मकर संक्रांति पर गंगासागर में चिकित्सा शिविर लगाए डॉ. अंजलि और डॉ. अनंत कुमार चक्रवर्ती। बिमल कर्मकार

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चला रहे निःशुल्क क्लीनिक साल्टलेक इलाके के रहने वाले डॉ. भाई-बहन उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार इलाके के देशबंधु पार्क में शेड के नीचे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क क्लीनिक भी चलाते हैं। दोनों ने स्नातक के बाद होम्योपैथी मेडिसीन एंड सर्जरी में डिप्लोमा किया है। डॉ. अनंत कुमार चक्रवर्ती बंगाल सरकार के लिए बतौर मेडिकल अफसर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं।

बीमार भाई की सेवा से जगी प्रेरणा

डॉ. अनंत कुमार चक्रवर्ती ने कहा- जब मैं आठवीं कक्षा में था, उस समय मेरे बड़े भाई बीमार पड़ गए थे। उस वक्त मैंने ही उनकी देखभाल की थी। उसी समय से मन में सेवा की भावना पैदा हुई। उसके बाद मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई शुरू की। अंजलि ने भी भाई का अनुसरण करते हुए मानव सेवा में खुद को समर्पित कर दिया।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बंगाल में मध्यकालीन युग की छह दुर्लभ मूर्तियां बरामद

जासं, कोलकाता : कोलकाता कस्टम विभाग ने मध्यकालीन सेन राजवंशी युग की छह दुर्लभ मूर्तियां जब्त की हैं। गत 29 जनवरी को बंगाल के इस्लामपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर छापामारी अभियान चला कर मूर्तियां जब्त कीं। हालांकि, पुलिस की आंख में धूल झोंक कर तीन तस्कर भागने में सफल रहे। कोलकाता कस्टम विभाग के प्रिवेंटिव शाखा की खुफिया टीम को सैकड़ों साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमाओं के नेपाल तस्करी किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद इस्लामपुर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर 29 जनवरी की रात सिलीगुड़ी की ओर जा रहे चार पहिया वाहन को रोका गया। पुलिस अभी गाड़ी के इधर-उधर ही घूम रही थी कि उसमें सवार चालक और दो अन्य तस्कर मौके का लाभ उठा कर फरार हो गए। तस्करों के भागने के बाद पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली, तो उसमें से एक-एक कर पत्थर की छह दुर्लभ मूर्तियां बरामद हुईं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 1 फरवरी 2020

दैनिक जागरण
संतुलन साधने की कला जीवन में बहुत काम आती है

विपक्ष के तेवर

यह अच्छा नहीं हुआ कि संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर जब यह कहा कि उसके जरिये गांधी जी एवं अन्य राष्ट्र निर्माताओं की आकांक्षा पूरा करने का काम किया गया है तब विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा मचाना जरूरी समझा। विपक्षी सांसद केवल हंगामा करने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने शर्म-शर्म के नारे भी लगाए। वास्तव में उनका मकसद राष्ट्रपति के संबोधन में व्यवधान डालना था। इस दौरान विपक्षी दलों के कई सांसद काली पट्टी से भी लैस दिखे। क्या यह काफी कुछ वैसा ही आचरण नहीं जैसा सीएए के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग कर रहे हैं? दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में तो एक धरना ऐसी सड़क पर काबिज होकर दिया जा रहा है जिसके अवरुद्ध होने से हर दिन लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। इसके बावजूद इस धरने पर बैठे लोग खुद को गांधीवादी और संविधान प्रेमी बता रहे हैं। आखिर यह ढोंग नहीं तो और क्या है? गांधी जी ने तो अपने जीवन में एक भी ऐसा धरना नहीं दिया जिसने दूसरों के लिए कठिनाई पैदा की हो।

राष्ट्रपति की ओर से सीएए के जिक्र मात्र पर विपक्ष ने जैसे तेवर दिखाए उससे तो यही लगता है कि रचनात्मक भूमिका उसके एजेंडे में ही नहीं और उसकी ओर से संसद में शाहीन बाग जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हो सकती है। जो भी हो, यह देखना दयनीय रहा कि विपक्ष ने राष्ट्रपति के इस कथन पर भी गौर करने से इन्कार किया कि वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हैं और विश्व समुदाय से आग्रह करते हैं कि वह इसका संज्ञान ले। सीएए पर विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस जैसा रवैया अपनाए हुए है उससे तो यही लगता है कि वह यह भूलना पसंद कर रहे हैं कि अतीत में उसने क्या कहा और किया? वह संविधान की दुहाई भी दे रही और अपनी राज्य सरकारों के जरिये उसकी धज्जियां भी उड़ा रही है। कल तक जो कांग्रेस सीएए जैसा कानून बनाने की मांग कर रही थी, असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को अपनी पहल बता रही थी और जनसंख्या रजिस्टर को आगे बढ़ा रही थी वह आज इन सब पर सिर के बल खड़ी हो गई है। यह राजनीति के नाम पर की जाने वाली शरारत ही है। इसी शरारत के कारण इस तथ्य की अनदेखी की जा रही है कि नागरिकता कानून में संशोधन के बाद भी किसी भी देश और यहां तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बहुसंख्यक नागरिक भी भारत की नागरिकता पाने के हकदार हैं।

कठघरे में चयन आयोग

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं फिर से सवालों के घेरे में हैं। स्नातक स्तर के कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में शामिल एक महिला अभ्यर्थी की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ होना सामने आया है। जाहिर बात है कि अभ्यर्थी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया। इस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। जांच के बाद क्या कार्रवाई होगी, यह तभी पता चलेगी। सवाल पुलिस रिपोर्ट का नहीं, परीक्षा की शुचिता का है। चिंताजनक यह कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी आयोग के स्तर पर कराई गई परीक्षाओं पर अंगुली उठ चुकी है। चार साल पहले ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भर्ती में परीक्षार्थियों की ओएमआर शीट में सात-सात बार छेड़छाड़ हुई थी। तीन साल पहले ऊर्जा निगम में टेक्नीशियन ग्रेड-टू के पदों की परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ था। जांच के बाद छह परीक्षार्थियों का चयन निरस्त करते हुए उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी। दरअसल मसला, जांच और मुकदमे का है ही नहीं। रिपोर्ट कराना समस्या का समाधान कतई नहीं है। आयोग को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि इससे वह अपनी जवाबदेही से बच जाएगा। ऐसा करके आयोग एक प्रकार से अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है। परीक्षाओं में जालसाजी कैसे और कौन कर रहा है, उसका पता लगाया जाना चाहिए। चूंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास सिर्फ और सिर्फ परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी है। अगर वह उसे भी ठीक से निभा नहीं रही है तो विचारणीय है। आयोग के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि अभी तक जिन भी परीक्षाओं में धांधली पकड़ में आई है, उनमें आयोग ने परीक्षा से जुड़े किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का सीधा सा अर्थ है कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े तंत्र की इसमें मिलीभगत है। गलती एक बार हो सकती है, लेकिन एक के बाद एक गड़बड़ियां पकड़े जाना इस बात का प्रमाण है कि आयोग की व्यवस्थाओं में खोट है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह कि आयोग इसे दूर करने के बजाय पर्देदारी में ज्यादा दिलचस्पी लेता दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि परीक्षाओं की शुचिता बनी रहे, क्यों नहीं इसके लिए गलतियों से सबक लेकर पुख्ता व्यवस्था कर ली जा रही है। साफ है कि आयोग दाल में काले की गुंजाइश बनाए रखना चाहता है।

परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। अन्यथा परीक्षा के मायने के ही खत्म हो जाएंगे

सतही आलोचना का सहारा

तरुण गुप्त

यदि एनआरसी का विचार सैद्धांतिक रूप से सही है तब क्या मात्र उसके क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों के आधार पर ही उसे खारिज करना उचित होगा?

जब कोई विषय ध्रुवीकरण वाला हो तब आप कितनी भी तार्किक बात कहें उससे एक वर्ग निराश नहीं तो असहमत अवश्य होगा। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को लेकर बीते छह हफ्तों से मैं भी लेखकों की ऐसी ही दुविधा से दो-चार हुआ हूं। यह आलेख पाठकों को किसी पक्ष में लामबंद करने का प्रयास नहीं है। अपने विवेक, परिवेश और सुविधा के हिसाब से लोग पहले ही अपना मत बना चुके हैं। बहरहाल इन विषयों से जुड़ी टिप्पणियों में मुख्य रूप से संवैधानिक नैतिकता, मूल ढांचा सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा जैसी तमाम अवधारणाओं पर चर्चा होती रही है। ये भले ही पाठकों को विरक्त न करें, परंतु कानूनी जटिलताओं में जरूर जकड़ती हैं। इस स्थिति में अधिक उपयुक्त यही होगा कि ऐसे विषयों पर विशेषज्ञ ही प्रकाश डालें और संबंधित प्राधिकारी ही इससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर दें।

यहां हम कुछ अपेक्षाकृत आधारभूत मुद्दों की चर्चा करेंगे। एक प्रमुख अखबार में प्रख्यात स्तंभकार ने लिखा कि सीएए-एनआरसी की जुगलबंदी व्यर्थ एवं विध्वंसक किस्म की है। उनके तमाम वैचारिक सहोदरों का भी मानना है कि अवैध प्रवासियों को चिन्हित करने वाले इस उपक्रम से कोई लाभ नहीं होने वाला। इन लोगों को भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि कोई अन्य देश इन्हें नहीं अपनाएगा। मानवाधिकारों को देखते हुए उन्हें डिटेंशन कैंप में भी नहीं रखा जा सकता। वे ये भी मानते हैं कि उनके अवैध विधिक दर्जे के बावजूद वे किसी न किसी कार्य में संलग्न होकर अर्थव्यवस्था में योगदान तो कर ही रहे हैं। आपत्तियों को लेकर कुछ और दलीलें दी गईं जिनमें भारी-भरकम वित्तीय लागत से लेकर भारतीय परिप्रेक्ष्य में एनआरसी से जुड़ी अव्यावहारिकता जैसे पहलुओं की चर्चा है। कई विचारक सरकार की प्राथमिकताओं पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। उनका मानना है कि अप्रत्याशित मंदी के इस दौर में पूरा जोर अर्थव्यवस्था में तेजी लाने वाले उपायों पर होना जाना चाहिए, न कि ध्यान भटकाने वाले उन मसलों पर जो उनकी राय में विशुद्ध रूप से विभाजनकारी एजेंडे से ओतप्रोत हैं।

बहरहाल आप भले ही किसी भी वैचारिक ध्रुव पर खड़े हों, लेकिन आपत्तियों की यह सूची विषय के अति-सरलीकरण का जीता-जागता उदाहरण है। सामान्य समझ के अनुसार हम जानते हैं कि किसी देश में प्रवास के विभिन्न स्तर होते हैं। इसमें कोई पर्यटक, छात्र या कारोबारी के रूप में रह सकता है, लेकिन इसके बावजूद वे नागरिक नहीं माने जाएंगे। दरअसल नागरिक बनना प्रवास का सबसे विकसित स्वरूप है। ऐसे में इसका उत्तर इसी बिंदु में निहित है कि इन अवैध प्रवासियों का क्या किया जाए। उन्हें न तो किसी दूसरे देश में भेजना संभव है और न ही कैद में रखना। संभवतः उन्हें कामकाज की अनुमति दी जाए, परंतु उन्हें मताधिकार से तो वंचित किया ही जा सकता है। हम अपने तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार से तो परिचित हैं कि कैसे तमाम अपात्र लोगों तक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र पहुंच गए। इससे बीते कई वर्षों के दौरान देश के कई हिस्सों में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं जनसांख्यिकीय परिवेश काफी बदल गया है। एनआरसी इस प्रक्रिया को बाधित अवश्य कर सकती है।

अवधेश राजपूत

हम अक्सर इसी उलझन में रहते हैं कि जो संभव है वही किया जाए और इसकी अनदेखी करते हैं कि वास्तव में क्या किया जाना चाहिए? यह रवैया त्रुटिपूर्ण है। अपने नागरिकों की पंजिका तैयार करना प्रत्येक देश का अधिकार है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। कल्याणकारी योजनाओं में रिसाव रुकता है। साथ ही सुनिश्चित होता है कि केवल वही मतदान करेंगे जो वास्तविक नागरिक हों। यदि एनआरसी का विचार सैद्धांतिक रूप से सही है तब क्या मात्र इसके क्रियान्वयन की राह में आने वाली चुनौतियों के आधार पर ही इस अवधारणा को खारिज करना उचित होगा? हमारी वित्तीय, तंत्रीय एवं अन्य चुनौतियों को देखते हुए कारगर एनआरसी के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त होगा, यह तय करने का दायित्व, अधिकार एवं विशेषज्ञता केवल सरकार के पास है।

एनआरसी को लेकर असम के अनुभव से जरूर कुछ सवाल उठते हैं और इसी कारण इसका वह स्वरूप देश के दूसरे हिस्सों में नहीं आजमाया गया। वैसे भी इसका अंतिम प्रारूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है और जब तक सरकार इसे अधिसूचित नहीं करती तब तक इस दिशा में कोई भी अनुमान लगाना निरी अटकल ही होगी। यदि सीएए की बात करें तो किसी अन्य देश की भांति भारत के पास भी नागरिकता को लेकर तमाम कायदे-कानून हैं। इसमें ताजा संशोधन एक विशेष वर्ग के लोगों को शीघ्रता से नागरिकता प्रदान करने का ही प्रावधान करता है। जहां तक इसकी बारीकियों की बात है तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय ही करेगा।

अब सबसे चर्चित मुद्दे यानी अर्थव्यवस्था पर लौटते हैं। यकीनन इसे शीर्ष प्राथमिकता में होना चाहिए, लेकिन क्या यही इकलौती वरीयता होनी चाहिए? क्या अर्थव्यवस्था और एक वैचारिक सामाजिक एजेंडे को समांतर रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता? सरकार सब कुछ भूलकर केवल आर्थिक मोर्चे पर जुट जाए, यह कहना कुछ वैसा ही होगा मानों वह एक वक्त में एक ही कार्य कर सकती है। राज्य सबसे बड़ा निकाय है। क्या उसे एक वक्त में कई कार्यों के संचालन में सिद्धहस्त नहीं होना चाहिए?

विमर्श, आलोचना और विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हालांकि हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे जहां नागरिक ऐसा विरोध करें जिससे दूसरों को कोई परेशानी न हो या सामान्य कामकाज में गतिरोध न उत्पन्न हो। वहीं सरकार भी ऐसे प्रदर्शनों से निपटने के कारगर उपाय नहीं तलाश पाई है जिसमें बलप्रयोग की स्थिति न बने।

लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की दो बड़ी सीख हैं-एक साध्य और साधन की पवित्रता और दूसरा विरोध-प्रदर्शन को अपने मर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। वास्तव में किसी आंदोलन की आत्मा उसके मर्म में ही समाई होती है। समाज को विमर्श की धारा से ही स्वयं को विकसित करना चाहिए। आलोचना का प्रवाह भी मुक्त होना चाहिए, लेकिन वह सही कारणों के आधार पर की जाए। इस बीच कुछ बातें आलोचकों-प्रदर्शनकारियों विशेषकर छात्रों को भी गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले तो उन्हें किसी विषय पर राय बनाने के अति-उत्साह में प्रासंगिक सूचनाओं, जानकारी, शिक्षा, बुद्धिमता, परिपक्वता और अनुभव की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। याद रखें कि किसी मसले पर राय से पहले और कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी सही जानकारी होती है।

response@jagran.com

महिलाओं की जिंदगी संवारता अभियान

स्मृति ईरानी

सामाजिक विकास के एजेंडे के तहत मोदी सरकार महिलाओं को बदलाव का नेतृत्व करने के लिए सशक्त भी बना रही है

महिलाओं की जिन समस्याओं की पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ बात की थी, मोदी सरकार ने उन्हें हल करने का बीड़ा उठाया और सामाजिक विकास का एक नया एजेंडा प्रभावी रूप से लागू कराया। इससे महिलाओं का जीवन न केवल सरल होगा, बल्कि उन्हें सामाजिक विकास की बागडोर अपने हाथ में लेने में भी मदद मिलेगी। मोदी सरकार के लिए सामाजिक विकास का एजेंडा बापू के ग्राम स्वराज के स्वप्न को धरती पर यथार्थ रूप में उतारने का एजेंडा है। मूलभूत सुविधाओं से वंचित भारतीय ग्राम पलायन की चपेट में थे। पुरुष वर्ग का शहरों या कस्बों में पलायन, पहले से ही सुविधाहीन ग्रामों की महिलाओं पर श्रम का असाध्य बोझ डाल रहा था। वर्ष 2014 में, भारत ने तब नया इतिहास रचा जब नीतिगत रूप से महिलाओं और लड़कियों के श्रम को कम करने और उन्हें उनकी सुविधा के लिए लक्षित सेवाएं प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाने पर बल दिया जाने लगा। इस दिशा में पहला बड़ा कदम तब रखा गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवा सौ करोड़ भारतीयों का ध्यान खुले में शौच जैसी कुप्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया ताकि हमारी महिलाओं की गरिमा और उनके स्वास्थ्य को बनाए रखा जा सके। विगत पांच वर्षों में स्वच्छ भारत क्रांति ने दस करोड़ से अधिक घरों में सुरक्षित स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण भारत की महिलाओं के जीवन को बदल दिया। वर्ष 2017 में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक अध्ययन ने अनुमान लगाया था कि भारत के खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) गांवों में महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स अन्य गांवों की तुलना में बेहतर था। अक्टूबर 2019 तक, भारत के सभी गांवों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया।

हाल में अशोका विश्वविद्यालय और वर्जीनिया विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि घर में शौचालय होने से महिलाओं पर यौन अत्याचारों में भी कमी आई है। स्वच्छ भारत के अतिरिक्त भी राजग सरकार द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनमें महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने और उन्हें सम्मान दिलाने पर बल दिया गया। इन कार्यक्रमों में एक बड़ी बात यह थी कि महिलाओं को बदलाव का नेतृत्व करने के लिए सशक्त भी बनाया गया। चूल्हे के जलावन की

लकड़ी या उपलों के जलने से फैलने वाला धुआं ग्रामीण महिलाओं के फेफड़ों और आंखों को रोजाना नुकसान पहुंचाता था। उज्ज्वला योजना से करोड़ों ग्रामीण महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर से उन्हें इस जहरीले धुएं से मुक्ति मिली। पोषण अभियान का बड़ा लक्ष्य ही बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाना है ताकि जन्म के समय बच्चों में कम वजन, उनके विकास में रुकावट, उनके पोषण में कमी और किशोरियों में एनीमिया के मामलों में कमी आए।

स्वच्छ भारत मिशन ने महिला राजमिस्त्रियों की एक फौज खड़ी की है, जिन्हें 'रानी मिस्त्री' के नाम से जाना जाता है। इन रानी मिस्त्रियों ने इस पुरुष-प्रधान कर्मभूमि में भी अपनी छाप छोड़ दी है। सदियों से हमारे देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी महिलाओं ने अपने घरों की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की कठिन जिम्मेदारी उठाई है। राजस्थान की प्रचंड गर्मी में, उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में, पूर्वी महाराष्ट्र की पथरीली जमीनों पर भी, महिलाएं लंबी दूरी तय करती हैं और अपने परिवार के लिए पानी का प्रबंध करती हैं, मगर पिछले कुछ दशकों में जल संकट के गहराने से इन गुमनाम नायिकाओं के जीवन में मुश्किलें और बढ़ी हैं। विशाल और निरंतर बढ़ती आबादी और लगातार प्रदूषित हो रहे जल संसाधन, बदलते मौसम के पैटर्न और लगातार सूखे के साथ भारत के एक तिहाई से अधिक जिले अब जल संकटग्रस्त हैं। ये ऐसे जिले हैं जहां भूजल स्तर 'अति-गंभीर' स्थिति में हैं। इसका अर्थ यह है कि इन जिलों में पानी लाना अब और कठिन हो गया है, क्योंकि जलस्तर बहुत नीचे चला गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में एक ग्रामीण महिला औसतन 2.5 किमी से अधिक की दूरी तय करके किसी जल स्रोत तक पहुंचती है। वास्तव में हमारी ग्रामीण महिलाएं अपने समय का एक बड़ा हिस्सा पानी लाने में खर्च करती हैं।

अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान लालकिले से जल जीवन मिशन की घोषणा करके, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साबित किया कि यह सरकार माताओं-बहनों के जीवन को सरल बनाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जलापूर्ति करना है। फिलहाल केवल 18 फीसद ग्रामीण परिवारों के पास यह सुविधा उपलब्ध है।

इस मिशन का पहला कदम था नए मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उस परंपरा का तोड़ा जाना जिसके माध्यम से जल क्षेत्र में काम किया जा रहा था। अब इसमें केंद्र से लेकर ग्राम स्तर तक सभी मोर्चों पर एक साथ काम किया जाएगा। दूसरा कदम था योजनाओं में स्थानीय स्थितियों के लिए प्रभावी छूट देने की अनुमति ताकि स्थानीय स्थिति के अनुकूल योजना तैयार की जाए। तीसरा कदम था स्रोत के स्थायित्व को योजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना ताकि सुनिश्चित हो सके कि जल की प्रत्येक बूंद का पुनः उपयोग किया जाए।

महिलाएं अपने समुदायों के जल संसाधनों को प्रबंधित करने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। अगर जल जीवन मिशन से परिवार के लिए पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलने की उनकी कड़ी मेहनत को हटा दिया जाए तो इससे महिलाओं का जीवन बहुत आसान हो जाएगा और उन्हें कम मेहनत करनी पडेगी। इसके संकेत प्रत्यक्ष हैं। वास्तविक परिवर्तन के लिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि घरों की वास्तविक मुखिया यानी हमारी माताओं और बहनों को देश के विकास के एजेंडे में भी केंद्र में रखा जाए।

(लेखिका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

परिवार की महत्ता

परिवार प्रत्येक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार की पाठशाला से ही एक व्यक्ति संस्कारों की शिक्षा ग्रहण करता है। परिवार का अपनत्व हमें अकेला महसूस नहीं होने देता है। विषम परिस्थितियों में परिवार हमारे लिए रक्षाकवच बन जाता है। अतः इस दुनिया में वह इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसके पास सुख में हास-परिहास करने के लिए और दुख एवं विपत्ति में साथ में बैठकर गम बांटने के लिए परिवार है।

आज के दौर में कहने को विश्व संकीर्ण हो गया है। इसके हानिकारक प्रभाव के रूप में परिवार के सदस्यों के मध्य की दूरियां कम होने के बजाय और बढ़ गई हैं। संयुक्त परिवार की प्रथा अपने अधोपतन को पा चुकी है। आज एकल परिवार में भी माता-पिता को अपने बच्चों के लिए और बच्चों को अपने माता-पिता के लिए समय नहीं है। आजकल इंसान व्यावहारिक जीवन के रिश्तों के प्रति विमुख होकर सोशल जगत में आभासी मित्रों से रिश्ते बनाने और उनसे संवाद साधने में अधिक व्यस्त होता जा रहा है। सस्ती लोकप्रियता के फेर में आत्ममुग्ध इंसान आज अपने हित और अहित की चिंता भी ठीक से नहीं कर पा रहा है। परिवार में पहले एक साथ मिलकर खाना खाने वाले अब समय के अभाव के चलते न तो एक साथ मिलकर खाना खा पाते हैं और न ही एक घर, एक परिवार में रहने के बाद मिल पाते हैं। साथ रहकर भी उनके बीच एक तरह की दूरी बनी रहती है।

परिवारों का बिखराव हमारे संस्कारों और मूल्यों की परंपरा को ध्वस्त कर रहा है। गूगल हमें हर चीज ढूंढकर दे सकता है, लेकिन वह परिवार, माता-पिता और बुजुर्गों का अनुभव हमें किसी भी कीमत पर लाकर नहीं दे सकता। अतः आभासी दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में परिवार के प्रति हमें अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार के बिना बड़ी से बड़ी कामयाबी और समृद्धि खोखली है।

देवेंद्रराज सुथार

समस्या बढ़ा रही जनसंख्या वृद्धि

रमेश ठाकुर

हिंदुस्तान में जिस तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है उससे यह कुछ ही वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ देगा

पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस बढ़ती जनसंख्या की समस्या पर अपनी चिंता व्यक्त की थी उसे सियासी चश्मे से देखने के बजाय उस पर लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है। आज देश में रेल, सड़क, बाजार, सार्वजनिक स्थान लोगों से खचाखच भरे हैं। घरों के आंगन सिमटते जा रहे हैं। इसके अलावा नौकरियां, मौके, संसाधन घटते जा रहे हैं। नौबत ऐसी भी आ गई है कि चपरासी की भर्ती के लिए पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवा भी आवेदन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण निहायत जरूरी हो जाता है। चिंता करने वाली बात यह है कि आज ऐसी स्थिति है तो आने वाले वक्त में क्या होगा?

ऐसी स्थिति से बचने के लिए दो बच्चा पैदा करने की नीति का हमें अनुपालन करना ही होगा। दुनिया के कई देशों में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून अमल में आ चुके हैं। कई देशों में दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर सरकारी सुविधाओं से वंचित करने के फरमान जारी हो चुके हैं। अगर भारत सरकार भी इस दिशा में कोई कदम उठाती है तो उसका सभी भारतीयों को समर्थन करना चाहिए। देखा जाए तो इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जो कि जनसंख्या विस्फोट की देन है। बेरोजगारी के कारण युवा शक्ति लगातार तनाव की तरफ बढ़ रही है। कुछ गलत रास्तों पर भी चल पड़े हैं। हर तरह के अपराधों में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

आजादी के समय हिंदुस्तान की जनसंख्या मात्र 34 करोड़ थी, लेकिन आज यह बढ़कर 125 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अगले वर्ष नया आंकड़ा आएगा, उससे पता चलेगा हम कहां पहुंच चुके हैं। अभी सर्वाधिक जनसंख्या राज्य उत्तर प्रदेश की है। वहां की कुल आबादी 19.98 करोड़ है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जहां की आबादी छह लाख है। अगर हम बढ़ती जनसंख्या से पनपने वाली समस्याओं पर गंभीरता से गौर करें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस स्थिति में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण पर दिए बयान को अगर सियासी नजरिये से न देखकर सामाजिक समस्या के लिहाज से देखें तो कई बातें साफ हो जाएंगी। इस मसले पर देश के दूसरे वर्ग जितने चिंतित हैं उतने ही अल्पसंख्यक भी। यह दुष्प्रचार मात्र है कि अल्पसंख्यक जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ हैं। उन्हें भी अपनी आने वाली पीढ़ी की उतनी ही चिंता है।

हाल में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हिंदुस्तान में जिस तेज गति से जनसंख्या बढ़ रही है उससे तो यह कुछ ही वर्षों में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। इस लिहाज से अगले पांच वर्ष बाद ही हिंदुस्तान समूची दुनिया में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा। जाहिर है कि आपस में लड़ने के बजाय हमें आज इस समस्या पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

सही चिंता

गांधीवादी मूल्यों की अनदेखी शीर्षक से लिखे अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने गांधी जी के देश में उनके ही नाम का सहारा लेकर फैलाई जा रही अराजकता पर गंभीर टिप्पणी की है। देश के कई शहरों की सड़कों पर कब्जा कर इन दिनों क्या गजब की क्रांति की जा रही है! शाहीन बाग के हंगामेदार मजमे के तो पैंतालीस दिन से अधिक हो गए हैं। आस-पास के लाखों लोग आधे घंटे का रास्ता दो घंटे में तय कर रहे हैं और इधर आंदोलनकारी संविधान के जयकारे के साथ ही जिन्ना वाली आजादी के नारे भी लगा रहे हैं। शाहीन बाग हो या मंसूर अली बाग, पटना का फुलवारी शरीफ हो या मुंबई बाग हर जगह कमोबेश एक सा ही नजारा है। सेक्युलर समाज इनका मजमा देख बाग-बाग है, जबकि आम लोग हैरान और परेशान। कितना अच्छा होता यदि महिलाएं अपने बुर्के से और बहुविवाह एवं हलाला जैसी सामाजिक कुप्रथाओं से आजादी की मांग करतीं। लोकतंत्र, संविधान और समानता की दुहाई देने वाले आंदोलनकारियों के लिए भी उचित यही होता कि वे पहले इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाते।

chandankarn9470@gmail.com

पर्यावरण बचाने की जरूरत

दैनिक जागरण के 30 जनवरी के अंक में प्रकाशित तरुण श्रीधर का लेख, सबके स्वास्थ्य की चिंता करने का समय, में लेखक ने चीन में फैले कोरोना वायरस के संदर्भ में भारत में पशु-पक्षियों की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इस बात को प्रकट किया है कि अभी हमारे यहां पशुओं की आबादी के हिसाब से उनके डॉक्टरों की संख्या बेहद कम है। अतः भारतीय भूमि पर भी कोरोना वायरस जैसे खतरों की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। भारत में पशु-पक्षियों की संख्या दुनिया के अन्य देशों से सर्वाधिक है। हमारे यहां गाय जैसे पशुओं को तो मां का दर्जा दिया गया है और मोर जैसे पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी का। लेकिन जब बात इनके स्वास्थ्य की आती है तो हमारी सरकारें भी इन मासूमों की तरह बेजुबान हो जाती हैं, आखिर क्यों? जो पशुधन देश के सकल घरेलू उत्पाद में चार फीसद की हिस्सेदारी देता है आज उनके साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसा पिछड़ा व्यवहार क्यों है? क्यों नहीं उनकी आबादी के हिसाब से उनकी देखभाल के लिए डॉक्टरों की संख्या संतुलित की जा रही है? पर्यावरण के घटकदल जल, जंगल और जमीन जो हमारी सेहत के साथ-साथ इन बंद जुबानों की सेहत पर भी सीधा असर डालते हैं, बढ़ती आर्थिक प्रतिस्पर्धा और विकास की इस अंधी दौड़ के चलते इन घटकदलों को बढ़ते कार्बन उत्सर्जन अथवा जलवायु परिवर्तनों ने तबाही के कगार पर ला छोड़ा है, जैसा कि चीन के संदर्भ में ये बात खरी उतरती है कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था की बेहतरी में अपने पर्यावरण को तबाह कर दिया है। फलस्वरूप वहां पशु पक्षियों अथवा जलीय जीव जंतुओं का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसका परिणाम आज खतरनाक कोरोना वायरस के रूप में दुनिया के सामने आया है। अतः आज समस्त विश्व को जीव-जंतुओं और पर्यावरण को बचाने की सख्त आवश्यकता है।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

खुल चुकी पोल

दैनिक जागरण के 29 जनवरी के अंक में प्रकाशित ए. सूर्यप्रकाश का लेख, संघीय ढांचे पर हमला करते राज्य, पढ़ा। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से तथ्यों के साथ जो बातें लिखी हैं, वह बिल्कुल सही हैं। लेकिन क्या कारण है कि कुछ चुनिंदा मीडिया वर्ग व नेता इस बात को जो ए. सूर्यप्रकाश जी समझ गए, वे नहीं समझ पा रहे। कहीं इनका एजेंडा कुछ और तो नहीं?

डॉ. सुमनवीर सिंह, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, पलवल

विकास बने चुनावी मुद्दा

दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और सब अपनी -अपनी तरफ से दिल्ली को लंदन-न्यूयॉर्क बनाने की बात कह रहे हैं। कुछ पार्टियां मुफ्त सेवा की बात कर रही हैं, जैसे एक दूसरे से मुफ्त सेवा देने की स्पर्धा चल रही हो। मुफ्त सेवा समस्याओं का समाधान नहीं है। मुफ्त सेवा लेने का मतलब है 1 रुपया लेकर 5 रुपये का नुकसान करना और अपने स्वाभिमान को जीते जी मारना।

ऋषि भारद्वाज, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

24 एप का इस्तेमाल करता है एक आम भारतीय, टेक एआरसी की रिपोर्ट के अनुसार। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म 'एप एनी' की रिपोर्ट के मुताबिक औसत रूप से एक भारतीय 51 एप तक अपने स्मार्टफोन में रखता है।

आजकल

विलुप्त होने से बचाई जाएं छोटी नदियां

आज देश की अधिकांश छोटी नदियां अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। अनेक कारणों से ये नदियां लुप्तप्राय हो रही हैं। छोटी नदियों के समक्ष अस्तित्व का संकट पैदा होने के कारण बड़ी नदियों के लिए भी शुद्ध जल का स्रोत कम होता जा रहा है। देश के एक बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो यहां अनेक छोटी नदियां आज या तो नाले में परिवर्तित हो चुकी हैं या फिर उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। हमें इन नदियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना होगा

रोहित कौशिक
स्वतंत्र टिप्पणीकार

प्रतीकात्मक फोटो।

नदियों के किनारे अनेक सभ्यताएं विकसित हुई हैं। नदियां जहां एक ओर हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी अनेक मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समाज में बचपन से ही नदियों को सम्मान देने और साफ-सुथरा रखने की सीख दी जाती थी। यही कारण था कि नदियां हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान का आधार बनीं। धीरे-धीरे समय बदला और विकास की चकाचौंध में अच्छी परंपराओं को भी तिलांजलि दे दी गई। विकास के नाम पर हुए औद्योगीकरण ने स्थिति को भयावह बना दिया और नदियां अपने अस्तित्व के लिए जूझने लगीं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि स्थिति की भयावहता को देखते हुए हमारा ध्यान बड़ी नदियों पर ही केंद्रित रहा। छोटी नदियों को बचाने के लिए ना तो कोई बड़ा आंदोलन हुआ और ना ही सरकार ने छोटी नदियों के लिए कोई ठोस नीति बनाई। यही कारण है कि आज देश की अनेक छोटी नदियां या तो मर चुकी हैं या फिर मरने के कगार पर हैं।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित पूर्वी काली नदी पिछले कई वर्षों से अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। हालांकि अब 'नीर फाउंडेशन' नामक एक एनजीओ द्वारा काली नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 'दैनिक जागरण' और सरकार भी इस पहल में योगदान कर रही है। दैनिक जागरण इस पहल को समर्थन देकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। इस प्रयास से काली नदी के उद्गम स्थल पर जलधारा पुनः निकलने लगी है। काली नदी को नया जीवन मिलने के बाद इस बात पर विचार-विमर्श किया जा रहा है कि इसमें कैसे साल भर पानी बहता रहे और इसमें औद्योगिक कचरा न फेंका जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

जलाशय से बना रहेगा जल स्तर : जलस्तर बनाए रखने के लिए काली नदी के किनारे 12 जलाशय बनाए जाने की योजना है। यह काम शुरू हो गया है। जलाशयों में खेत और गांव के घरों से निकलने वाले पानी को एकत्र किया जाएगा। इस पानी का शोधन करके नदी में पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में वाटर रिचार्ज पिट खोदे जाएंगे। एक जलाशल में 13 लाख लीटर पानी का भंडारण किए जाने की योजना है। इस तरह कुल 12 जलाशयों में काफी मात्रा में पानी का भंडारण किया जाएगा। इससे नदी का जलस्तर बनाए रखने में काफी मदद मिलेगी। किसानों ने काली नदी को पुनर्जीवित करने के लिए करीब डेढ़ सौ बीघा जमीन खाली कर दी है। इसके साथ ही नदी किनारे की जमीन कब्जा मुक्त कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इससे काफी जमीन सरकार के पास आ सकती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने अपने एक आदेश में काली नदी की जमीन खाली कराकर उसकी सीमाबंदी करने और सीमा पर पिलर गाड़ने के निर्देश दिए हैं। काली नदी को पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए किसान और ग्रामीण भी लगातार श्रमदान कर रहे हैं। काली नदी के उद्गम स्थल को देखने के लिए लोग अंतवाड़ा गांव पहुंच रहे हैं। इस पहल के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में छोटी नदियों को बचाने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए।

काली नाम से दो नदियां : पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 'काली' नाम की दो नदियां हैं। एक है पूर्वी काली नदी और दूसरी है पश्चिमी काली नदी। पूर्वी काली नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के अंतवाड़ा गांव से होता है और यह मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा और फर्रूखाबाद होते हुए कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। कन्नौज में इस नदी का पानी काफी साफ है। इसके उद्गम स्थल पर इसे 'नागिन' और कन्नौज के आस-पास इस नदी को 'कालिंदी' नाम से भी जाना जाता है। आज प्रदूषण के कारण पूर्वी काली नदी की हालत दयनीय है।

पश्चिमी काली नदी : पश्चिमी काली नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में शिवालिक से 25 किमी दक्षिण से निकलकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जनपद में बहती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इन दोनों ही काली नदियों का प्रदूषित जल अंततः गंगा में गिर रहा है। इसलिए गंगा भी प्रदूषित हो रही है।

गौरतलब है कि नमामि नंगे परियोजना के तहत गंगा को स्वच्छ करने का अभियान अभी चल रहा है। सवाल यह है कि छोटी नदियों को स्वच्छ किए बिना गंगा कैसे स्वच्छ हो पाएगी? करीब 30-35 वर्ष पहले पूर्वी काली नदी में स्वच्छ जल बहता था, लेकिन आज इसका प्रदूषित जल किसानों के लिए अभिशाप बन गया है। इस कारण पीने का पानी भी प्रदूषित हो गया है। फलस्वरूप ग्रामीणों को त्वचा और पेट संबंधी बीमारियों ने घेर लिया है।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि काली नदी के पानी में अत्यधिक मात्रा में कॉपर, क्रोमियम, लोहा, जिंक एवं प्रतिबंधित कीटनाशक घुले हुए हैं। हालत यह है कि कुछ जगहों पर धरती के अंदर काफी गहराई तक भारी तत्व अधिक मात्रा में पाए गए हैं। प्रदूषण की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काली नदी के जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। इसी कारण मछलियों एवं अन्य जलीय जीवों के जीवन पर मंडराता खतरा अंततः उनके लिए मौत का सबब बन रहा है। फलस्वरूप इस नदी में जलीय जीवों के अस्तित्व की कोई संभावना दिखाई नहीं देती।

उत्तर प्रदेश की अन्य लुप्तप्राय नदियां : फैजाबाद जिले में गोमती की सहायक नदियों में शामिल तिलोदकी, तमसा, मड़हा, बिसुही और कल्याणी विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से अधिकांश नदियां सूख चुकी हैं जिनमें महज बारिश के दिनों में ही पानी दिखता है। वेदों में उल्लिखित पवित्र कल्याणी नदी जो बाराबंकी जिले में बहती है, उसकी धारा भी सूख गई है। इनके अलावा सहारनपुर की पांवधोई नदी आज गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आज जरूरत इन नदियों को बचाने की है।

प्राकृतिक स्वरूप खोती नदियां

पंकज चतुर्वेदी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

कभी गोमती लखनऊ के बाशिंदों के जीवन-जगत का मुख्य आधार हुआ करती थी। सूर्य की अस्ताचलगामी किरणें इस नदी की जलनिधि से परावर्तित होकर पूरे शहर को सुनहरे लाल रंग से सराबोर कर देती थीं। लखनऊ में गोमती के बहाव की दिशा पूर्व-पश्चिम है सो डूबते सूरज की किरणों का सीधा परावर्तन होता है। लेकिन रिवर फ्रंट के नाम पर जैसे ही नदी को बांधा, गोमती गंदा नाला बन कर रह गई है। नदी में पानी कम और काई अधिक दिखाई देती है। सूरज की रोशनी वही है, उसके अस्त होने की दिशा भी वही है, लेकिन शाम-ए-अवध का सुनहरा सुरूर नदारद है।

पीलीभीत से 32 किमी दूर पूर्व दिशा में ग्राम बैजनाथ की फुल्हर झील गोमती का उद्गम स्थल है। करीब 20 किमी तक इसकी चौड़ाई किसी छोटे से नाले सरीखी संकरी है, जहां गरमियों में अक्सर पानी नाममात्र होता है। फिर इसमें गैहाई नाम की छोटी सी नदी मिलती है और एक छिछला जल-मार्ग बन जाता है। उद्गम से 56 किमी का सफर तय करने के बाद जब इसमें जोकनई नदी मिलती है तब इसका पूरा रूप निखर आता है। शाहजहांपुर और खीरी होकर यह आगे बढ़ती है। मुहमदी से आगे इसका स्वरूप बदल जाता है और इसका पाट 30 से 60 मीटर चौड़ा हो जाता है। जब यह नदी लखनऊ पहुंचती है तो इसके तट 20 मीटर तक ऊंचे हो जाते हैं। फिर यह बाराबंकी, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से गुजरती हुई जौनपुर के करीब सई नदी में मिल जाती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गोमती नदी लखनऊ आने तक काफी हद तक निर्मल रहती है। लेकिन लखनऊ के बाद इसमें 'डी' व 'ई' स्तर का प्रदूषण रहता है। बोर्ड के मानदंडों के मुताबिक 'डी' स्तर का पानी केवल वन्य जीवों और मछली पालन योग्य होता है, जबकि 'ई' स्तर के पानी को मात्र सिंचाई, औद्योगिक शीतकरण व नियंत्रित कचरा डालने लायक माना जाता है। वैसे गोमती नदी में प्रदूषण की शुरुआत लखनऊ से 50 किमी पहले सीतापुर जिले के भट्टपुर घाट से हो जाती है। यहां गोमती की एक प्रमुख सहायक नदी सरिया इसमें आकर मिलती है। सरिया के पानी में सीतापुर जिले में स्थित शक्कर और शराब के कारखानों का प्रदूषित स्त्राव होता है। जैसे-तैसे गोमती लखनऊ तक शुद्ध हो पाती है, लेकिन इस राजधानी शहर में पहुंचते ही यह नाले के स्वरूप में आ जाती है। करीब 28 लाख आबादी वाले इस शहर का लगभग 1,800 टन घरेलू कचरा और 33 करोड़ लीटर गंदा पानी हर रोज गोमती में घुलता है। लखनऊ में बीकेटी से इंदिरा नहर तक कुल 28 नाले नदी में गिरते हैं।

लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च करके महानगर के साढ़े आठ किलोमीटर में गोमती को संवारने की योजना ने गोमती को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। गोमती किसी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी नहीं है, इसका उद्गम व संवर्धन भूजल से ही होता है। रिवर फ्रंट के नाम पर गोमती की धारा को संकरा कर दिया गया। इसके दोनों तरफ कंक्रीट की दीवार बना दी गई। जाहिर है कि इस दीवार को टिकाकर रखने के लिए गहराई में भी दीवार उतारी गई होगी। हर नदी के तट की मिट्टी, उसकी नमी, उसके लिए ऑक्सीजन उपजाती है, उसके पानी को शुद्ध करती है। गोमती को घेर कर खड़ी दीवारों ने नदी के जीवन को ही समाप्त कर दिया। शहर के भीतर स्थित कई कारखाने बगैर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए अपशिष्ट निकास गोमती में कर रहे हैं।

साबरमती : इसी प्रकार गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के दोनों किनारों पर कंक्रीट की दीवार खड़ी करके जिस तरह से रिवर फ्रंट बनाया गया है उससे नदी का प्राकृतिक स्वरूप बिगड़ रहा है। हमें नदियों के प्राकृतिक स्वरूप को बचाए रखना होगा ताकि उसके अस्तित्व को कायम रखा जा सके।

खरी-खरी

उक्तियों की पीठ पर सवार युक्तियां

ब्रजेश कानूनगो

कभी-कभी ऐसा वक्त भी आता है, जब परंपरागत उक्तियां फेल हो जाती हैं और नई युक्तियां पुरानी उक्तियों पर भारी पड़ने लगती हैं। कहा जाता रहा है कि आग लगने से पहले कुआं खोद लिया जाना चाहिए। लेकिन यह वह दौर है जब बस्ती में आग लग जाए, तब भी तुरंत जमीन खोद कर पानी निकाला जा सकता है।

कभी दो नावों में सवारी करना ठीक नहीं माना जाता था। कहा जाता था कि इससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। मगर अब शायद ऐसा नहीं है। एक पांव एक नाव में और दूसरा दूसरी नाव में रखकर नदी पार करना अब कौशल का काम है। एडवेंचर का रोमांच होता है इसमें। इस काम के लिए आदमी में जोखिम उठाने की क्षमता और इच्छा शक्ति भी होना जरूरी है। साधुरामजी बड़े साहसी व्यक्ति हैं और जोखिम लेते रहते हैं। कविता और व्यंग्य लेखन जैसी दो विधाओं पर सवार होकर साहित्य की नदी को पार करने की अभिलाषा में एडवेंचर स्पोर्ट्स करते रहते हैं। मगर इसमें अपवाद स्वरूप कभी-कभार नुकसान भी हो जाता है।

सरकारी फैसलों को लेकर भी कुछ लोग दो नावों की सवारी करते दिखाई देते हैं। निर्णय के साथ भी दिखाई देते हैं और लागू करने के तरीके के विरोध में मंत्रीजी का पुतला भी जला देते हैं। कई बार तो अजीब स्थिति बनती रहती है। भ्रम की ऐसी धुंध में एक दिशा में सोचते हुए दो समूहों के साथ जुड़े होने पर मतिभ्रम भी हो जाता है। लगता है दोनों पक्ष विरोधी हैं। दोनों समझते हैं कि हम दूसरे वाले के गुट में हैं। इसीलिए एक साथ होते हुए भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके बावजूद सबकी ख्वाहिश यही होती है कि किसी तरह नाव और यात्री सुरक्षित किनारे लग जाएं।

सच तो यह है कि यह बदलाव का महत्वपूर्ण समय है। देश, समाज से लेकर नीतियों और व्यवस्थाओं तक में आमूलचूल परिवर्तन हर घड़ी हो रहे हैं। यों कहें सूरज की हर किरण बदलाव की नई रोशनी लेकर आ रही है। ऐसे में 'आग लगने पर कुआं खोदना' या 'दो नावों की सवारी करने' जैसी उक्तियां अप्रासंगिक हो गई हैं। दरअसल, युक्तियां अब उक्तियों की पीठ पर सवार हैं। बहुत कुछ प्रासंगिक और अप्रासंगिक हो रहा है।

ट्वीट-ट्वीट

शाहीन बाग वालों ने और कुछ किया हो या न किया हो, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मुकाबले में जरूर ला दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो यही लोग सबसे ज्यादा पछताएंगे। आयोजक आखिर क्या सोच रहे थे?

मानक गुप्ता@manakgupta

अगर 39,000 रुपये की कीमत वाले फोन को भारत में मिड टीयर या मिड सेगमेंट का फोन कहा जा रहा है तो इसे देखकर यही कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत बहुत अच्छी स्थिति में है।

निमिष दुबे@nimishdubey

आर्थिक समीक्षा के मूल में संपदा सृजन और संपदा सर्जकों को स्थान मिलता देखकर बहुत खुशी हुई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब संपदा पर निशाना साधने के बजाय उसे सराहा जा रहा है।

गौतम चिकरमाने@gchikermane.

बीते 22 दिनों से मैं शांति यात्रा पर रहा। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई और गुरुवार को दिल्ली में राजघाट पर इसका समापन हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय मीडिया द्वारा इसकी पूरी तरह अनदेखी किए जाने पर मैं उनका बहुत आभारी हूं। अगर मैं शांति के बजाय हिंसा भड़काता तब यकीनन सुर्खियों में जगह पाता।

यशवंत सिन्हा@YashwantSinha

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एयरलाइनों की तरह उपद्रवी ट्रेन यात्रियों को भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए?

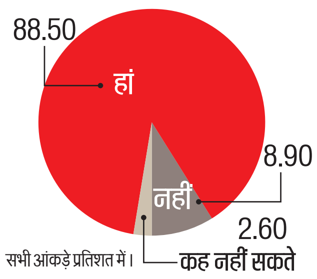

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या आर्थिक समीक्षा में विकास दर को लेकर किए गए दावे से आप सहमत हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जैसे-जैसे पास में आता जाय चुनाव,
रोज सामने आ रहे नए-नए कुछ दांव।
नए-नए कुछ दांव कहीं चलती है गोली,
करती कहीं प्रहार जहर से तीखी बोली।
इसमें मियां 'फवाद' ले रहे इंट्री ऐसे,
बहती दिखे मवाद कहीं फोड़े में जैसे।

– ओमप्रकाश तिवारी

इंसान के डाटा में परिवर्तित हो जाने का दशक

मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

मानव सभ्यता के इतिहास में 21वीं सदी का दूसरा दशक इसलिए याद रखा जाएगा जब इंसान एक डाटा (आंकड़े) में परिवर्तित हो गया और आज इस सदी के तीसरे दशक में यह बहुत मूल्यवान चुका है। डाटा ही वह ईंधन है जो अनगिनत कंपनियों को चलाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह चाहे तमाम एप्स हों या विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सभी उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त हैं। असल में जो चीज हमें मुफ्त दिखाई दे रही है वह सुविधा हमें हमारे संवेदनशील निजी डाटा के बदले मिल रही है। इनमें से अधिकतर कंपनियां उपभोक्ताओं द्वारा उपलब्ध आंकड़ों को संभाल पाने में असफल रहती हैं जिसका परिणाम लागातार आंकड़ों की चोरी और उनके दुरुपयोग के मामले सामने आते रहते हैं। टेक एआरसी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक भारतीय कम से कम 24 एप का इस्तेमाल करता है और यह आंकड़ा वैश्विक औसत से तीन गुना ज्यादा है। मोबाइल एनालिटिक्स फर्म 'एप एनी' की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर किसी फोन में एप रखने का औसत नौ एप प्रयोग करने का है, पर औसत रूप से एक भारतीय 51 एप तक फोन में रखता है। वैसे अधिकतम एप इंस्टॉल करने का आंकड़ा इसी रिपोर्ट के अनुसार 207 का है। यह तथ्य बताता है कि एक आम भारतीय किसी एप को डाउनलोड करने में कितनी कम सावधानी बरत रहे हैं।

सबसे ज्यादा सोशल मीडिया एप का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं से इंसान के डाटा बनने का खेल शुरू हो जाता है। यह सोचने में अच्छा है कि हमारे ऑनलाइन प्रोफाइल पर हमारा नियंत्रण है। हम तय करते हैं कि हमें कौन सी तस्वीरें साझा करनी हैं और कौन सी निजी रहनी चाहिए। हम निमंत्रण स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं, टैग को नियंत्रित करते हैं और पोस्ट या टिप्पणी प्रकाशित करने से पहले दो बार सोचते हैं। बुरी खबर यह है कि जब आपके डिजिटल प्रोफाइल की बात आती है तो आपके द्वारा साझा किया जाने वाला डाटा केवल एक हिमशैल के ऊपरी हिस्से की तरह है। हम बाकी को नहीं देखते हैं जो मोबाइल एप्लिकेशन और ऑनलाइन सेवाओं के अनुकूल इंटरफेस के पानी के नीचे छिपा हुआ है। हमारे बारे में सबसे मूल्यवान डाटा हमारे नियंत्रण से परे है। यह ऐसी गहरी परतें हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। पहली परत वह है जिसे आप नियंत्रित करते हैं। इसमें वह डाटा होता है जो आप सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लिकेशन में फीड करते हैं। इसमें आपकी प्रोफाइल, आपके सार्वजनिक पोस्ट और निजी संदेश, पसंद, खोज, अपलोड की गई फोटो आदि चीजें हैं। दूसरी परत व्यवहार संबंधी टिप्पणियों से बनी है। इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जिन्हें आप शायद हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपका वास्तविक समय, स्थान और आपके अंतरंग और पेशेवर संबंधों की विस्तृत समझ। जैसे एक ही घर में अक्सर एक ही कार्यालय की इमारतों या आपके आराम करने के समय आपके मोबाइल की जगह को दिखाने वाले स्थान पैटर्न को देखकर कंपनियां बहुत कुछ बता सकती हैं कि आप कहां समय बिताते हैं।

तीसरी परत पहले और दूसरे की व्याख्याओं से बनी है। आपके डाटा का विश्लेषण विभिन्न एल्गोरिद्म द्वारा किया जाता है और सार्थक सांख्यिकीय सह-संबंधों के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं के डाटा के साथ तुलना की जाती है। यह परत न केवल हम क्या करते हैं, बल्कि हम अपने व्यवहार और मेटाडाटा (डाटा के विश्लेषण से हासिल किए जाने वाले विविध परिणाम) पर आधारित हैं, उनके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। इस परत को नियंत्रित करना बहुत अधिक कठिन है। इन प्रोफाइल-मैपिंग एल्गोरिद्म का कार्य उन चीजों का अनुमान लगाना है, जिन्हें आप स्वेच्छा से प्रकट करने की संभावना नहीं रखते हैं। इनमें आपकी कमजोरियां, आइक्यू लेवल, पारिवारिक स्थिति, व्यसन, बीमारियां आदि शामिल हैं।

उपभोक्ता अधिकारों के तहत अभी आंकड़े नहीं आए हैं। किसी भी उपभोक्ता को यह नहीं पता चलता है कि उसकी निजी जानकारियों (आंकड़ों) का किस तरह इस्तेमाल होता है। आंकड़ों की दुनिया में भी वर्ग संघर्ष का दौर शुरू हो गया है। लोगों के निजी डाटा सिर्फ कंपनियों के प्रोडक्ट को बेचने में ही मदद नहीं कर रहे, बल्कि यह आंकड़े हमें भविष्य के समाज के लिए तैयार भी कर रहे हैं जिसमें एआइ यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है जो मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता पर कार्य करता है, लेकिन भविष्य का भारतीय समाज कैसा होगा यह इस मुद्दे पर निर्भर करेगा कि अभी हम अपने निजी आंकड़ों के बारे में कितने जागरूक हैं।

यथार्थ

समस्याएं बढ़ाने वाला समाधान

अगर क्षेत्रफल के मामले में आंध्र से बड़े छह राज्यों और आबादी के मामले में उससे बड़े नौ राज्यों का काम एक राजधानी से चल सकता है तो फिर आंध्र को तीन राजधानियों की दरकार क्यों है

प्रणव सिरोही
pranav.sirohi@nda.jagran.com

पूरब की ममता बनर्जी, पश्चिम के शरद पवार और दक्षिण के जगन मोहन रेड्डी भले ही देश के अलग-अलग इलाकों से आते हों, लेकिन एक कड़ी इन तीनों को जरूर जोड़ती है। वह यह कि ये तीनों कांग्रेस से बगावत कर सियासी जमीन पर पनपने वाले विरले नेताओं में से हैं। हालांकि ममता और पवार के उलट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व वाइएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन मूलतः राजनेता नहीं हैं। अप्रत्याशित परिस्थितियां उन्हें सियासत में खींच लाई और अब वह अपनी इसी राजनीतिक जमीन को और उर्वर बनाने के लिए जरूरी खाद-पानी देने में जुटे हैं।

इसके संकेत उन्होंने राज्य की कमान संभालते ही तब दे दिए थे जब उन्होंने अपनी सरकार में पांच उपमुख्यमंत्री बनाकर राजनीतिक पंडितों से लेकर आम लोगों तक सभी को हैरान कर दिया। मानो इतना ही काफी नहीं था। अब उन्होंने राज्य के लिए तीन राजधानियां बनाने का एलान किया है, जो व्यवस्था देश के किसी राज्य में नहीं। उनका यह प्रस्ताव गले उतरता नहीं दिखता। इसके लिए वह राज्य में विधान परिषद व्यवस्था की बलि देने पर भी आमादा हैं। ऐसे में उनके इस दांव की पड़ताल बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे देश में राजनीतिक-आंचलिक तुष्टीकरण की नई परंपरा शुरू हो सकती है।

कितना जरूरी कदम : राज्य सरकार ने नई राजधानी अमरावती के अलावा विशाखापत्तनम में प्रशासनिक राजधानी और कुर्नूल में न्यायिक राजधानी बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में राज्य विधानसभा ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी भौगोलिक क्षेत्रों के समावेशी विकास विधेयक, 2020 और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक, 2020 नाम से दो विधेयक पारित किए हैं। इसके पीछे राज्य सरकार की दलील यही है कि तीन राजधानियां बनने से जन आकांक्षाओं की बेहतर तरीके से पूर्ति हो सकेगी। ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्षेत्रफल के मामले में आंध्र से बड़े देश के छह राज्यों और आबादी के मामले में उससे बड़े नौ राज्यों का काम एक राजधानी से चल सकता है, तो फिर आंध्र को आखिर तीन राजधानियों की दरकार क्यों है? इन विधेयकों के प्रमुख शिल्पकार और राज्य के शहरी विकास मंत्री बोत्सा सत्यनारायण इसके लिए तमाम दलीलें देते हैं। उनका कहना है कि राज्य के पिछड़े दक्षिणी जिलों वाला हिस्सा, जिसे रायलसीमा कहा जाता है, वहां हाईकोर्ट बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है तो इसमें उनकी सरकार कोई नया कदम नहीं उठा रही है। वैसे भी श्रीबाग समझौते में यह फैसला किया गया था कि रायलसीमा और तटीय क्षेत्र में से किसी एक में राजधानी होगी और दूसरे में हाईकोर्ट। कई राज्यों में भी पहले से ऐसी व्यवस्था है। असल में राजधानियों की इस गुत्थी में पूरा पेच अमरावती में विधायी और विशाखापत्तनम में प्रशासनिक राजधानी बनाने को लेकर उलझा हुआ है। इसके पीछे भी सरकार का यह तर्क है कि चूंकि अमरावती को एक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए उसके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं तो वह विशाखापत्तनम के पहले से विकसित बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि यह समाधान भी एक समस्या को सुलझाने के लिए दूसरी परेशानी को आमंत्रण देने जैसा ही होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि अमरावती और विशाखापत्तनम के बीच की दूरी लगभग 360 किमी है। वहीं विशाखापत्तनम एवं कुर्नूल के बीच की दूरी करीब 700 किमी है। इससे सामान्य कामकाज और नीतिगत संचालन दुःस्वप्न बन जाएगा। जो सरकार खर्च बचाने के लिए नई राजधानियां बसा रही है वह एक तरह से सरकारी खजाने पर आवाजाही खर्च का बोझ बढ़ाने की बुनियाद ही रख रही है। सवाल यह भी है कि जिस सरकार के पास एक राजधानी विकसित करने के लिए धनाभाव है, वह तीन राजधानियां भला कैसे विकसित कर पाएगी।

जगन मोहन रेड्डी। फाइल फोटो

मूल में राजनीति : राज्य सरकार की एक और दलील यह है कि पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार द्वारा अमरावती को नई राजधानी बनाने से कई तेदेपा नेताओं ने अमरावती के आसपास बड़े पैमाने पर जमीन खरीदकर वारे-न्यारे किए। यदि ऐसा है तो इसकी उचित रूप से जांच कर दोषियों को दंडित किया जाए। जगन सरकार यह भी कह रही है कि नई राजधानी बनाने को लेकर तेदेपा सरकार ने शिवरामकृष्णन समिति की सिफारिशों को दरकिनार किया और नारायणा समिति गठित कर अपनी मनमाफिक अनुशंसाएं लागू करा लीं। हालांकि तेदेपा इसके पुरजोर विरोध में जुटी है और अब वह वाइएसआर कांग्रेस पर यही आरोप लगा रही है कि विशाखापत्तनम को राजधानी बनाने की आड़ में उसके नेता अपने हित साधना चाह रहे हैं। फिर इसमें तटीय आंध्र की प्रभावशाली कम्मा-नायडू और रायलसीमा में वर्चस्व रखने वाली रेड्डी जातियों की आपसी अदावत का कोण भी देखा जा रहा है।

क्या हो उपाय : यदि सरकार वास्तव में सभी क्षेत्रों की भावनाओं और सहूलियत का ख्याल रखना चाहती है तो बेहतर होगा कि वह कुछ राज्यों में प्रचलित मिनी सचिवालय वाली व्यवस्था को अपना सकती है। इससे इन्कार नहीं कि आंध्र का रायलसीमा प्रतिकूल जलवायु, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और ऐतिहासिक शोषण के कारण पिछड़ा हुआ है, जबकि तटीय इलाके पहले से समृद्ध रहे हैं। ऐसे में यह कहीं अधिक तार्किक होगा कि सरकार रायलसीमा के द्रुत विकास के लिए अलग निकाय का गठन करे। राजधानी के रूप में अमरावती से कन्नी काटने के कारण पहले से चल रही परियोजनाओं पर विराम लगने का खतरा है, जिससे न केवल निवेशक कुपित हो सकते हैं, बल्कि स्थानीय असंतोष की चिंगारी और भड़क सकती है।

ऐसे में बेहतर यही होगा कि जगन सरकार किसानों की दुश्वारियों समेत उन मुद्दों पर काम करे जिनके दम पर पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में उसे प्रचंड से भी कहीं बढ़कर बहुमत मिला था। वरना आंध्र की नियति तेलंगाना के अलग होने के बाद राजधानियों की उलझन में ही फंसकर रह जाएगी।

6

जरूरत के मुताबिक सुधार और सार्वजनिक निवेश के जरिये इकोनॉमिक सर्वे में अनुमानित 6-6.5 परसेंट जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
चंद्रजीत बनर्जी, महानिदेशक, सीआइआइ

अनुमानित जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण है। कोरोना वायरस के चलते ग्लोबल इकोनॉमी पहले से ही दबाव में है। इसके अलावा भारत में मांग अभी जरूरत के मुताबिक नहीं बढ़ी है
रानेन बनर्जी, लीडर इकोनॉमिक एडवाइजरी सर्विसेज, पीडब्ल्यूसी इंडिया

ग्रोथ को प्राथमिकता देनी होगी। एक बार इकोनॉमी गति पकड़ लेती है फिर सरकार अपने खर्चों को कम करके राजकोषीय नियंत्रण की कोशिशें शुरू कर सकती है।
रूमकी मजूमदार, इकोनॉमिस्ट, डेलॉय इंडिया

गति खो चुकी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सरकार को नीतियों और राजकोषीय मोर्चे पर साहसिक कदम उठाने की जरूरत है।
निरंजन हीरानंदानी, प्रेसिडेंट, एसोचैम

इकोनॉमिक ग्रोथ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और ग्रामीण सशक्तीकरण के क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान तो देना होगा। साथ ही भरोसे का माहौल भी बनाने की जरूरत होगी।
इलियास जॉर्ज, नेशनल हेड (इन्फ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एंड हेल्थकेयर) केपीएमजी, इंडिया

शेयर बाजारों को रास नहीं आया इकोनॉमिक सर्वे

मुंबई, प्रेट्र : शेयर बाजारों को इकोनॉमिक सर्वे रास नहीं आया। शुक्रवार को इकोनॉमिक सर्वे सामने आने के बाद देश के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 190.33 अंक फिसलकर 40,723.49 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में भी 73.70 अंक की गिरावट दर्ज की गई। यह 12 हजार के मनोवैज्ञानिक आंकड़े से नीचे आकर 11,962.10 पर स्थिर हुआ। इकोनॉमिक सर्वे में ग्रोथ को बढ़ावा देने और राजकोषीय घाटे में ढील देने की बात कही गई है। सेंसेक्स पैक में ओएनजीसी के शेयरों में सबसे अधिक 5.80 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। पावरग्रिड, एचसीएल टेक, टीसीएस, टाटा स्टील और आरआइएल के शेयर भी लाल निशान पर बंद हुए। वहीं कोटक बैंक, एसबीआइ, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल और टेक महिंद्रा के शेयरों में तेजी देखने को मिली। जानकारों के मुताबिक इकोनॉमिक सर्वे में दिखी राजकोषीय चुनौती से बाजारों के उत्साह में कमी देखने को मिली।

खेती-किसानी को मशीनी बनाने में चुनौतियां अपार

छोटी जोत वाले किसानों के उपयोग वाली मशीनों की जरूरत। माइक्रो सिंचाई में लाभ, पर कटाई की मशीनें उपयुक्त नहीं

जागरण ब्यूरो, दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कृषि क्षेत्र का मशीनीकरण बेहद अहम है। हालांकि अपेक्षित प्रसार न होने से इसका लाभ ज्यादातर किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। बोआई से लेकर फसलों की कटाई की पूरी कड़ी में जिन मशीनों की जरूरत है, वे उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। छोटी जोत वाले किसानों के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी वाली मशीनों की कमी है। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका ब्योरा दिया गया है।

'मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन' के तहत राज्यों में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने की योजना पर सरकार जोर दे रही है। बजट में इन्हें और प्रोत्साहित किया जा सकता है। खेती में जिन उपकरणों की जरूरत होती है, उनमें लेजर लेवलर, हैप्पी सीडर, कंबाइनर हार्वेस्टर व पावर वीडर जैसे नवीनतम उपकरण किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के किसानों को ऐसी मशीनों की ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए 50 फीसद तक की वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इन क्षेत्रों में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना को 80 फीसद तक सब्सिडी दी जा रही है। नतीजतन, 2016-18 के बीच कृषि मशीनीकरण में 7.53 फीसद वृद्धि हुई। ट्रैक्टर और पावर टिलर्स की बिक्री में ज्यादा उछाल आया, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई। हालांकि कृषि मशीनीकरण की स्थिति अन्य देशों की तुलना में कम है।

धान, मक्का व गन्ना कटाई में मशीनों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत: धान, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, दलहन जैसी फसलों की बोआई व कटाई में मशीनों का उपयोग बढ़ाने की जरूरत है। सर्वेक्षण के मुताबिक गन्ना बोआई मात्र 10 फीसद और धान बोआई मात्र 20 फीसद ही मशीनों से होती है। धान की कटाई यूं तो 60 फीसद तक मशीनों से हो रही है, लेकिन उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसी मशीनों से खेतों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। गन्ना व मक्का कटाई के लिए मशीनों का अभाव है। दलहन, ज्वार व बाजरा जैसी फसलों में मशीनों का न्यूनतम उपयोग हो रहा है।

माइक्रो सिंचाई: माइक्रो सिंचाई में आधुनिक मशीनें काफी कारगर साबित हो रही हैं। इस प्रणाली से होने वाली सिंचाई से दोहरा लाभ हो रहा है, जल संरक्षण के साथ ही फसलों की उत्पादकता भी बढ़ी है। उर्वरक व बिजली आदि का उपयोग घटने से खेती की लागत में भी कमी आई है। इस सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से 2019-20 में खेती का क्षेत्रफल 10 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है।

कृषि मशीनीकरण की स्थिति

95% अमेरिका	75% ब्राजील
57% चीन	40% भारत

ट्रैक्टर और पावर टिलर्स की बिक्री में ज्यादा उछाल आया, जिससे कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई

दूसरी हरित क्रांति वाले राज्य पीछे

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

देश में कृषि की स्थिति सुधारने की दिशा में दूसरी हरित क्रांति की अहम भूमिका मानी जा रही है। इस मामले में पूर्वी व पूर्वोत्तर के राज्यों पर बड़ी जिम्मेदारी भी है। सरकार यहां ऑर्गेनिक खेती का हब बनाने की तैयारी में भी है। लेकिन कृषि कर्ज वितरण की विषमता इस तस्वीर को धुंधली कर रही है। कर्ज वितरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व बंगाल हाशिए पर चले गए हैं। पूर्वी राज्यों के साथ पूर्वोत्तर के राज्यों को कुल आवंटित कृषि ऋण का एक फीसद भी नहीं मिल पाया है। स्पष्ट है कि बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय संस्थान जरूरतमंद राज्यों को कृषि ऋण बांटने में फिसड्डी साबित हुए हैं। दरअसल, सूदखोरों से बचाने के लिए केंद्र सरकार साल दर साल संस्थागत कृषि ऋण में बढ़ोतरी करती जा रही है, लेकिन इसका लाभ उन क्षेत्रों को नहीं मिल पा रहा है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए कुल 13.50 लाख करोड़ कृषि ऋण के रूप में बांटने का प्रावधान किया गया। इसमें माना गया है कि कृषि उधारी का क्षेत्रीय वितरण अत्यंत विषम है। रिपोर्ट के साथ आंकड़ा भी भारत के मैप पर दर्शाया गया है। पूर्वी राज्यों के साथ पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बैंक व वित्तीय संस्थान ऋण वितरण में उत्साह नहीं दिखाते हैं। खाद्यान्न उत्पादक राज्यों के बजाय अन्य राज्यों को विशेष तरजीह दी गई है। दक्षिणी राज्यों को कुल आवंटित कृषि ऋण का सात से 15 फीसद तक दिया गया है, जबकि पूर्वी राज्यों में कृषि ऋण वितरण एक फीसद तक सिमट गया है।

महाशक्ति बनाएगी नई शिक्षा नीति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: नई शिक्षा नीति के आने में अभी भले ही वक्त है, लेकिन इसे लेकर सरकार को उम्मीदें बहुत हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने पहली बार इसे लेकर अपना विजन सामने रखा है। इसके तहत देश को कौशल और ज्ञान की एक ऐसी ऊंचाई देना है, ताकि वह इन दोनों ही क्षेत्रों में महाशक्ति बन सके। मौजूदा समय में विज्ञान व प्रौद्योगिकी सहित अकादमिक और उद्योग के क्षेत्र में मैनपावर की भारी कमी है। आर्थिक सर्वेक्षण को देखते हुए आम बजट में इस क्षेत्र को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं।

सरकार ने शिक्षा को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों को आगे भी जारी रखने पर जोर दिया है। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों को वित्तीय मदद देने वाली एजेंसी हेफा (हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी) की क्षमता और दायरे को बढ़ाने की जरूरत जताई है। इसमें 2022 तक हेफा के जरिये उच्च शिक्षण संस्थानों को एक लाख करोड़ रुपये की मदद देने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष (2019-20) में दिसंबर, 2019 तक करीब 75 उच्च शिक्षण संस्थानों को करीब 37 हजार करोड़ की मदद दी गई है। सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरकार ने इसके तहत 'सभी के लिए शिक्षा' की टैगलाइन भी दी है। हालांकि 2017-18 में शिक्षा पर होने वाले औसत व्यय को लेकर आई रिपोर्ट के हवाले से शिक्षा पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता भी जताई है। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाले छात्र आश्चर्यजनक रूप से 10 फीसद से अधिक खर्च करते हैं। इस दौरान उनका सबसे ज्यादा खर्च किताबों, यूनीफॉर्म, ट्रांसपोर्ट और दूसरे खर्चों में होता है। सर्वेक्षण में शिक्षा को मजबूती देने के जिस एक अन्य विषय पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, उनमें स्कूलों को बीच में छोड़ने का औसत है। प्राथमिक स्तर पर यह 10 फीसद है, जबकि माध्यमिक स्तर पर करीब 20 फीसद है।

राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में कुछ ढील मुमकिन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : रेवेन्यू के मोर्चे पर आ रही चुनौतियों और अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार आगामी बजट में राजकोषीय घाटे के टारगेट में ढील दे सकती है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटे के लिए 3.3 परसेंट का टारगेट रखा था। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक सर्वे 2019-20 इस बात के संकेत दे रहा है कि सरकार यह लक्ष्य थोड़ा बढ़ा भी सकती है। हालांकि सर्वे कहता है कि कमजोर वैश्विक विकास के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर कायम है।

सर्वे ने अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय संतुलन के मोर्चे पर आने वाली चुनौतियों का जिक्र भी किया है। सर्वे कहता है पश्चिम एशिया में बने भौगोलिक-राजनीतिक तनाव ने कच्चे तेल की कीमतों को खासा प्रभावित किया है। इसलिए सरकार के सामने पेट्रोलियम उत्पादों की सब्सिडी में वृद्धि का खतरा बना रहने की आशंका जताई गई है। चूंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के चलते निर्यात के मोर्चे पर स्थितियां पहले ही खराब हैं इसलिए यह स्थिति चालू खाता घाटे के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

परोक्ष कर के मोर्चे पर रेवेन्यू की धीमी रफ्तार रही है, लिहाजा जीएसटी के रेवेन्यू संग्रह की रफ्तार बढ़ाना आवश्यक है। व्यय के मोर्चे पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर सर्वे में जोर दिया गया है। खासतौर पर खाद्य सब्सिडी को तार्किक बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। चालू वित्त वर्ष के बजट में 1.84 लाख करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी पर खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। जबकि कुल सब्सिडी 3.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन ने कहा कि साल 2019-20 अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियों भरा वर्ष रहा है। सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 के बजट में पेश की गई मध्यावधि राजकोषीय नीति (एमएफटीपी) के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे का टारगेट बढ़ाकर 3.3 परसेंट किया गया। इसके बावजूद यह उम्मीद जताई गई है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में यह तीन परसेंट पर ही स्थिर रहेगा। एमएफटीपी पर चलते हुए चालू वित्त वर्ष में केंद्र की देनदारियां जीडीपी के 48 परसेंट तक कम हो जाएंगी। केंद्र सरकार के कर्ज में कमी से 2020-21 में इसके जीडीपी के 46.2 परसेंट और 21-22 में 44.4 परसेंट तक पहुंचने की आशा है।

सर्वे के मुताबिक जीडीपी के अनुपात में कर में वृद्धि और प्राइमरी डेफिसिट में कमी होने से पिछले कई वर्षों में सरकार के वित्त प्रबंधन में सुधार हुआ है। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीने में रेवेन्यू प्राप्तियों में 13 परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है।

बात पते की

- जीएसटी के रेवेन्यू संग्रह की रफ्तार बढ़ाना जरूरी
- व्यय के मोर्चे पर सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने पर जोर
- खाद्य सब्सिडी को तार्किक बनाने के लिए कदम उठाने होंगे

₹1.84 लाख करोड़ खाद्य सब्सिडी पर खर्च होने का अनुमान था चालू वित्त वर्ष में

₹3.02 लाख करोड़ कुल सब्सिडी रहने का अनुमान

46.2% रह जाने की संभावना है अगले वित्त वर्ष में केंद्र की देनदारियां जीडीपी के मुकाबले

अब और सुगम होगी कारोबार की राह

बृजेश दुबे • नई दिल्ली

पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए कारोबार के अनुकूल माहौल बेहद जरूरी है। भारत ने पिछले पांच वर्षों के दौरान इसमें काफी प्रगति भी की है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के मुताबिक अब भी हालात ऐसे हैं कि बंदूक का लाइसेंस लेने की कागजी कार्रवाई आसान है, रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस लेने की कागजी कार्रवाई ज्यादा मुश्किल है। शुक्रवार को जारी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इसके संकेत दिए गए। पिछले महज पांच वर्षों में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में 142वें से 63वें स्थान पर आने वाले भारत का सपना शीर्ष 50 में शामिल होना है और आर्थिक सर्वेक्षण में इसकी झलक मिलती है। किसी बिजनेस की शुरुआत, निर्यात और परिवहन से लेकर विवाद निपटान तक, जटिलता और लेटलतीफी दूर करने के उपाय बजट में दिख सकते हैं।

व्यवसाय शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत 136वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारत इस मामले में पाकिस्तान (72), तुर्की (77) व श्रीलंका (85) से भी पीछे है। भारत में प्रक्रियाएं भी जटिल हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने में 10 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, जिन्हें पूरा होने में औसतन 18 दिन लगते हैं। न्यूजीलैंड में यही काम समेकित प्रक्रिया के तहत महज आधे दिन में हो जाता है। चीन में चार दिन, इंडोनेशिया और ब्राजील में 11-11 दिन लगते हैं।

सर्वे में उदाहरण देकर बताया गया है कि कैसे यहां विदेशी मुद्रा उपार्जन करने वाले निर्यातित माल के परिवहन में भी देरी की जाती है। बंदरगाह के जरिये दिल्ली से निर्यात होने वाला माल गंतव्य तक औसतन 49 दिन में पहुंचता है। यहां 19 दिन तो केवल कस्टम क्लीयरेंस, ग्राउंड हैंडलिंग और बंदरगाह पर लदान में लग जाते हैं। राष्ट्रीय औसत भी 7-10 दिन है जबकि चीन, बांग्लादेश, वियतनाम व इंडोनेशिया में ये काम महज एक दिन या उससे भी कम में हो जाते हैं। भारत में 12-16 लाइसेंस, 45 दस्तावेज और राज्य के अनुसार 22-36 अनुमोदन के बाद रेस्तरां खोल सकते हैं, जबकि चीन और सिंगापुर में इसके लिए केवल चार लाइसेंस की जरूरत होती है।

सर्वे में मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर लागू होने वाले 6,796 उपबंधों को भी बेहद थकाऊ और जटिल बताया गया है। इसमें राज्यों के लगने वाले दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के नियम शामिल नहीं हैं। ऐसे में इस दिशा में भी राहत मिलने की संभावना है। भारत में एक कारोबारी विवाद निपटाने में 1,445 दिन लगते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में यह महज 216 दिन में हो जाता है। ऐसे में बजट में प्रक्रियाओं की जटिलता से राहत मिलने की संभावना है।

बात पते की

- व्यवसाय शुरू करने की सुगमता के मामले में भारत का स्थान पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे
- संरचनात्मक सुधार के उपाय के साथ उसके क्रियान्वयन पर भी लगातार निगरानी की जरूरत

8-10% जटिल प्रक्रियाओं और लेटलतीफी को दूर करने से ही पाएंगे इतनी की विकास दर

1,445 दिन लगते हैं भारत में एक कारोबारी विवाद के निपटान में, न्यूजीलैंड में यह महज 216 दिनों में होता है

कारोबारियों को नीतिगत समर्थन की दरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बीते 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने वेल्थ क्रियेटर्स को सम्मान देने का जो आह्वान किया था, सरकार का आर्थिक सर्वे भी उसका समर्थन करता है। सर्वे में कहा गया है कि इकोनॉमी को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने के लिए बाजार के अदृश्य हाथों यानी कारोबारियों को मजबूत करने के साथ साथ भरोसा देने वाले हाथों का साथ भी आवश्यक है।

सर्वे ने इसके लिए 'प्रो-बिजनेस पॉलिसी' तैयार करने की सलाह सरकार को दी है। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने सर्वे के इस पहलू का समर्थन करते हुए कहा कि देश में संपदा का निर्माण करने वालों के लिए इस तरह की नीतियों का निर्धारण बेहद आवश्यक है। सर्वे में कहा गया है कि इसके लिए बिजनेस की शुरुआत करने वाले नए लोगों को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में और आगे बढ़ने की जरूरत बतायी गई है।

इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स में फाइनेंसिंग की चुनौती

₹1.4 लाख करोड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अगले पांच वर्ष में निवेश की जरूरत

30% इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश का हिस्सा पहुंचने का अनुमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में परियोजनाओं की फाइनेंसिंग और लांचिंग की चुनौतियों से निपटने के साथ क्षेत्र में 1.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत बताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओर से शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) रिपोर्ट 2020-25 का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरी तैयारी के साथ लागू करना है, ताकि लोगों को रोजगार देने के साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसके पीछे जीडीपी में बढ़ोतरी का इरादा भी है, क्योंकि बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने में मदद मिलेगी।

पिछले वर्ष 31 दिसंबर को लांच एनआइपी टास्क फोर्स की रिपोर्ट में अगले पांच वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 102 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया था। इसमें ऊर्जा (24 फीसद), सड़क (19 फीसद), शहरी विकास (16 फीसद) तथा रेलवे (13 फीसद) को मिलाकर कुल 72 फीसद निवेश होना है। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में इसे बढ़ाकर 1.4 लाख करोड़ रुपये करने की जरूरत बताई गई है।

एनआइपी की फंडिंग में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 39-39 फीसद, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 22 फीसद रहने की उम्मीद की गई थी। परंतु आर्थिक सर्वेक्षण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 2025 तक बढ़कर 30 फीसद तक हो जाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पांच वर्ष में कुल 102 करोड़ रुपये के प्रस्तावित खर्च में 42.7 लाख करोड़ की परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू हो चुका है। जबकि कुल 32.7 लाख करोड़ की परियोजनाओं का खाका तैयार हो रहा है। बाकी पर अभी विचार होना है। इस प्रकार से दो तिहाई परियोजनाएं पक्की हैं। आने वाले समय में राज्यों की कुछ परियोजनाओं को भी एनआइपी में शामिल किया जा सकता है।

क्षेत्रवार स्थिति

सड़क: आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकार किया गया है कि 2019-20 में सड़क निर्माण की रफ्तार पिछले वर्ष के 29.7 किलोमीटर से घटकर मात्र 12.7 किलोमीटर (30 सितंबर'19 तक) रोजाना रह गई है।

रेलवे: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1253 स्टेशनों के आधुनिकीकरण उच्चीकरण की योजना पर काम चल रहा है। अनेक स्टेशनों का विकास पीपीपी मोड पर करने का प्रस्ताव है।

नागरिक विमानन: उड़ान स्कीम के तहत 43 अप्रयुक्त एयरपोर्ट को चालू करने की योजना के तहत 2019-20 में 4 एयरपोर्ट को चालू किया जा चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से भारत अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन समेत सात प्रमुख देशों में पहले स्थान पर आ गया है। 2023-24 तक सौ और एयरपोर्ट चालू हो जाएंगे। इसके अलावा 46 अप्रयुक्त एयरस्ट्रिप, 16 प्राइवेट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तथा 15 एएआइ के एयरपोर्ट, 31 हेलीपैड और 12 वॉटरड्रोम भी विकसित किए जाएंगे। नवंबर 2019 तक भारतीय एयरलाइंसों में बेड़े में विमानों की संख्या दोगुनी होकर 680 हो गई थी। इनमें करीब 600 विमान उपयोग में हैं।

निशाना रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रही है सरकार

बेरोजगारी खत्म करने का मंत्र साबित हो सकता है निर्यात

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : विपक्ष अक्सर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को इसलिए निशाने पर लेता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार भी परोक्ष तौर पर मान रही है कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाना फिलहाल सबसे बड़ी जरूरत है। शुक्रवार को सरकार की तरफ से पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 बताता है कि रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा करने के लिए सरकार अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों पर काम कर रही है। सिर्फ निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक चार करोड़ और वर्ष 2030 तक आठ करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं।

अगर भारत ग्लोबल ट्रेड में अपनी मौजूदा दो फीसद हिस्सेदारी को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर 3.5 फीसद और वर्ष 2030 तक छह फीसद कर लेता है तो भारत में क्रमशः 3.85 करोड़ और 8.2 करोड़ रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण के ही आंकड़ों पर भरोसा करें तो अगले एक दशक तक हर वर्ष 55 से 60 लाख नए रोजगार के अवसरों की जरूरत होगी। यानी जितनी नौकरियों की जरूरत होगी वह सिर्फ निर्यात से पूरी की जा सकती है। चीन की तरह भारत निर्यात को इतना बढ़ाए कि सभी युवाओं को रोजगार मिल जाए, इसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण ने 'असेंबल इन इंडिया फॉर वर्ल्ड' को 'मेक इन इंडिया' के साथ समाहित करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि कई कंपनियां भारत में पूर्ण निर्माण इकाई स्थापित करने के बजाय सिर्फ असेंबलिंग करती हैं, जबकि सरकार की मंशा यह है कि वे यहां शुरू से लेकर अंत तक निर्माण करें। पड़ोसी चीन ऐसा कर चुका है। वर्ष 2001-2006 तक उसने सात करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए थे। भारत भी वर्ष 1999 से 2011 के बीच निर्यात की वजह से सात लाख श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र से निकालकर संगठित क्षेत्र में लाया था। अब जबकि चीन में इकाई लगाने की लागत बढ़ रही है और अमेरिका-चीन के बीच ट्रेड वार की वजह से कंपनियां दूसरे देशों में निर्माण स्थल की खोज कर रहे हैं तब भारत के पास संभावना है कि वह निर्यात के क्षेत्र में चीन जैसी कहानी दोहरा सके। लेकिन चीन जैसी स्थिति में पहुंचने के लिए भारत को बहुत कुछ करना होगा। डॉलर के मूल्य में चीन का निर्यात भारत से 743 फीसद ज्यादा है।

आर्थिक सर्वेक्षण मानता है कि भारत यह लक्ष्य हासिल कर सकता है। टेक्सटाइल, क्लोदिंग, फुटवियर, खिलौने जैसे सेक्टर में भारत से निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।

टेक्सटाइल, क्लोदिंग, फुटवियर, खिलौने जैसे सेक्टर में निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं मौजूद हैं

सोनी, एपल, सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों की असेंबलिंग लाइन यहां स्थापित हो सकती है और यहां से ये कंपनियां अपने उत्पाद बाहर भेज सकती हैं

743% ज्यादा है डॉलर के मूल्य में भारत के मुकाबले दुनियाभर को चीन का निर्यात

165 दिन कश्मीर में इंटरनेट की सुलभता के बगैर गुजरे, जो लोकतंत्र में अब तक का सबसे बड़ा शटडाउन है। यह जानकारी वॉचडॉग एक्सेस नाऊ ने अपनी एक रिपोर्ट में दी है।

हिमाचल प्रदेश

आम बजट से उम्मीदें

आम बजट को लेकर राजनेता, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र और गृहिणी ही नहीं देश का हर नागरिक उत्साहित होता है। उनके लिए, अगला वित्त वर्ष कैसा रहेगा इसी आम बजट से निर्धारित हो जाता है। दरअसल केंद्र सरकार आम बजट में पूरे देश के लिए कई नई नीतियां और योजनाएं लेकर आती है। आयकर की दर के बारे में बताती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के लिए वह कितनी पूंजी का आवंटन करने जा रही है, इसका भी उसमें जिक्र होता है। इन सबका देश के आम से खास आदमी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी पहली फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि केंद्र सरकार का झोली राज्य के लिए उदारता से खुलेगी। राज्य में अब भी समस्याएं पहाड़ जैसी ही हैं।

समय के साथ प्रदेश ने तरक्की अवश्य की है, लेकिन जिस तेजी से विकास का पहिया घूमना चाहिए था, अभी तक नहीं घूमा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्य में प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं, लेकिन उनका उचित दोहन नहीं हो पाया है। बेरोजगारी गंभीर समस्या है। करीब 70 लाख की आबादी वाले राज्य में इनका आंकड़ा साढ़े आठ लाख के करीब है। औद्योगिक विकास की बात हो या सड़कों, रेललाइन या हवाई यातायात की, कोई भी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। पानी भरपूर है, लेकिन पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए अब भी लोगों को भटकना पड़ता है। सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन अब भी कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। प्रमुख सड़कें खस्ताहाल हैं, जो आए दिन जख्म दे रही हैं। रेललाइन के विस्तार की घोषणाएं होती हैं, लेकिन इनका विस्तार सर्वे से आगे नहीं बढ़ पाया है। यही हाल हवाई सेवाओं का है। सिर्फ कांगड़ा, कुल्लू एवं शिमला से ही उड़ानें हो पा रही हैं, उसमें भी निरंतरता का अभाव है। बागवानी को स्तरोन्नत करने की बातें भी होती हैं, लेकिन विदेशी फलों के मुकाबले अभी और प्रयास किए जाने जरूरी हैं।

> आम बजट से प्रदेश के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। केंद्र की उदार मदद आर्थिक संकट से जूझ रहे प्रदेश के विकास को गति दे सकती है

किसानों को बेसहारा पशुओं और जंगली जानवरों ने परेशान कर रखा है। मजबूरन किसान खेती छोड़ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ओलावृष्टि से अब भी समस्या बनी हुई है। स्वास्थ्य संस्थान हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। यही हाल शिक्षण संस्थानों का है। इसी कारण लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं एवं उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों के लिए जाना पड़ रहा है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन कई पर्यटन स्थल विकसित ही नहीं हो पाए हैं।

राज्य सरकार औद्योगिक निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करती है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं की कमी आड़े आती है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कई उद्योग स्थापित हैं, लेकिन रियायतें न मिलने पर कई उद्योगों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है। ऐसे में राज्य को केंद्र सरकार से उदार सहायता की दरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद है कि प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान करने के साथ ही लंबित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की घोषणा करेंगी। उम्मीद इसलिए अधिक है, क्योंकि केंद्र एवं प्रदेश में भाजपा की सरकारें हैं।

जम्मू-कश्मीर

पहाड़ी भाषियों को आरक्षण देना सही कदम

पहाड़ी भाषी समुदाय (पीएसपी) की लगभग सात दशक पुरानी आरक्षण की मांग जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के छह माह के भीतर ही पूरी हो गई है। अब सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीधी भर्ती, व्यावसायिक संस्थानों और पीजी पाठ्यक्रम की सीटों में पहाड़ी समुदाय को चार फीसद आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी पीजी पाठ्यक्रमों में आरक्षण कोटा बढ़ाया गया है। पहाड़ी भाषा समुदाय को आम बोलचाल में पहाड़ी भी कहा जाता है। इस फैसले से जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ, बारामुला के उड़ी-बोनियार, कुपवाड़ा में केरन-करनाह और अनंतनाग, बड़गाम, बांडीपोरा, गांदरबल, कुलगाम, पुलवामा तथा शोपियां में बसे करीब 9.6 लाख पहाड़ी भाषियों को लाभ होगा।

दरअसल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित किए जाने और जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2004 को लागू किए जाने के बाद मौजूदा आरक्षण कोटे को युक्तिसंगत बनाना अनिवार्य हो गया था। इसलिए पहाड़ी भाषियों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण नियम, 2005 में आवश्यक संशोधन मंजूर किए गए हैं। पीएसपी श्रेणी के लाभ का दावा करने वाले को पहाड़ी कबीले, समुदाय या जनजाति का सदस्य होना चाहिए,

प्रतीकात्मक फोटो

जिसकी विशिष्ट सांस्कृतिक, जातीय और भाषाई पहचान हो। उसकी मातृभाषा पहाड़ी होनी चाहिए। उसके पास एक वैध पहचान प्रमाण होना चाहिए, जो आधार कार्ड या डोमिसाइल प्रमाणपत्र हो सकता है। पीएसपी से संबंधित व्यक्तियों के दावे को प्रमाणित करने के लिए तहसीलदार सक्षम प्राधिकारी होंगे।

इस फैसले से प्रदेश के लोगों में खुशी स्वाभाविक है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि पहाड़ी भाषी लोग अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधा न के बराबर है। स्कूलों में स्टाफ की कमी है, जबकि कॉलेज इक्का-दुक्का जगहों पर ही हैं। यह सही है कि कुछ वर्षों में पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के अलावा अन्य सुविधाओं में विस्तार के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं, परंतु विडंबना है कि अभी भी कर्मचारी और अधिकारी इन क्षेत्रों में नौकरी करने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों विशेषकर महिलाओं में साक्षरता दर कम है।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी, पुंछ, उड़ी, केरन, करनाह, अनंतनाग, बड़गाम, बांडीपोरा जैसे क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश पहाड़ी भाषी क्षेत्रों में मात्र 40 से 50 प्रतिशत के बीच ही साक्षरता दर है। सरकार के इन क्षेत्रों में रहने वालों को आरक्षण देने के फैसले से इनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी और उन्हें उच्च शिक्षा तथा व्यावसायिक कॉलेजों में भी प्रवेश की संभावना बढ़ेगी। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण देने के साथ-साथ वहां पर सुविधाओं में भी विस्तार करे।

अकसर देखा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं न होने के कारण इन क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ है। लोग पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ कर कस्बों और शहरों में आकर बस गए हैं। इससे पहाड़ खाली हो रहे हैं और शहरों में भीड़ बढ़ रही है, जिससे कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अगर सरकार पहाड़ी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करती है तो यह सोने पर सुहागा जैसा होगा। इस पर उपराज्यपाल प्रशासन को गंभीरता से सोच कर उचित फैसला लेना चाहिए।

झारखंड

बेरोजगारी दूर करने के लिए सार्थक पहल

राज्य सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यह वाकई बेहद सकारात्मक है। इसके फलस्वरूप राज्य के बेरोजगारों को शीघ्र ही प्रोत्साहन राशि (भत्ता) के रूप में पांच से सात हजार रुपये मिल सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान झामुमो ने यह कदम उठाने का वादा किया था। शपथ ग्रहण और मंत्रालयों के बंटवारे के बाद सरकार ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। इसके लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक शिविर लगाकर युवाओं का नियोजनालयों में निबंधन कराया जाएगा।

साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी आवश्यक पहल की जाएगी। इसके लिए राज्य के सभी आयुक्तों को नियोजनालयों को अविलंब सक्रिय करने का निर्देश भी दे दिया गया है। यदि सब कुछ सरकार की योजना के अनुसार हुआ तो राज्य भर में 16 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। रोजगार के विकल्प भी मुहैया कराए जाएंगे। यद्यपि

प्रतीकात्मक फोटो

सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने के इस निर्णय का सीधा असर राज्य के सरकारी खजाने की सेहत पर पड़ेगा। जबकि सरकार खजाने की हालत बेहतर न होने की बात भी कह चुकी है। ऐसे में इस जन उपयोगी फैसले पर संपूर्ण रूप से अमल करने के लिए सरकार को खजाने की आर्थिक स्थिति भी बेहतर बनानी होगी। ताकि सरकार का फैसला हवा-हवाई न साबित हो। वहीं सरकारी तंत्र को भी इस काम में पूरी निष्ठा से जुटना होगा। क्योंकि आर्थिक रूप से पिछड़े इस राज्य में निबंधित बेरोजगारों की संख्या ही लाखों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां औसतन हर पांच में से एक युवा बेरोजगार है। राज्य में 45 फीसद से अधिक परास्नातक युवाओं को रोजगार की तलाश है। लगभग 49 फीसद स्नातक युवा भी यहां रोजगार तलाश रहे हैं। युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर राज्य में युवा पुरुषों से लगभग 12 फीसद अधिक है। ऐसे में इन सभी की सही ढंग से पहचान कर इन्हें करियर और स्किल डेवलपमेंट की बेहतर संभावनाओं की न केवल जानकारी उपलब्ध करानी होगी, बल्कि भत्ता मिलने के लिए उनका ईमानदारी से निबंधन हो सके इसे भी सुनिश्चित करना होगा। यद्यपि सरकार से यह आस भी है कि राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने के मामले में वह धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी। इस बार वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य बजट में इस काम के लिए ठोस प्रबंध किए जाएंगे।

बंगाल

संविधान की मर्यादा से खिलवाड़

राज्यपाल जगदीप धनखड़ आहत हैं कि बंगाल में कानून का पालन कोई नहीं कर रहा है। उनकी यह टीस अनायास नहीं है। मौके-बे-मौके उन पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी की तरह हमले हो रहे हैं। खासतौर से सत्ताधारी तृणमूल के नेताओं और संगठन की हर इकाई ने राज्यपाल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जादवपुर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में राज्यपाल के जाने का विरोध करना और उन्हें वापस लौटा देना किसी से छिपा नहीं है। धनखड़ इस पर अपना मर्म बयां कर चुके हैं और वह इस बात से भी दुखी हैं कि ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। खैर, तृणमूल का यह तर्क है कि राज्यपाल अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे हैं। पर इससे भी दुखद पहलू यह कि धनखड़ गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने बैरकपुर गांधी घाट पहुंचे तो एक पुलिस अधिकारी ने उनकी न केवल अनदेखी की, बल्कि वह अखबार पढ़ता रहा। राज्यपाल इससे अपमानित महसूस हुए और पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। राज्यपाल ने आयुक्त से कहा कि उनके सामने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी का अखबार पढ़ना अनुशासनहीनता है। उन्होंने इस पुलिस अधिकारी के बारे में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारी के इस रवैये पर गौर करें तो निःसंदेह उसने अमर्यादित आचरण किया। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अगर विरोध की सीमा लांघ भी जाते हैं तो बात उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का इस तरह का रवैया भविष्य के लिए भी चिंताजनक है। क्या पुलिस अधिकारी अब सरकारों के रुख के हिसाब से आचरण करेंगे? क्या उनकी भूमिका सत्ता की चरण वंदना तक ही है? सत्ता जिसके विरोध में होगी वह चाहे कितने ही महत्वपूर्ण पद पर बैठे हों, लेकिन उनका विरोध करने का कोई न कोई तरीका ढूंढेंगे।

> राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता यदि विरोध की सीमा लांघ भी जाते हैं तो बात उतनी गंभीर नहीं है, पर सरकारी कर्मचारी का इस तरह का रवैया भविष्य के लिए भी चिंताजनक है

राज्यपाल ने यह सवाल भी उठाया कि जिस समय विश्वविद्यालयों में उनका विरोध हो रहा था उस समय पुलिस कहां थी? राज्य के गृह सचिव कहां थे? यानी यह साफ है कि सरकारी तंत्र भी संवैधानिक मर्यादा की अनदेखी कर रहा है। दुख की बात है कि राज्यपाल की नाराजगी पर सरकार ने नोटिस लेने के बजाय पलटवार ही किया। पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि राज्यपाल अगर उनका अपमान करेंगे तो वह चार गुना अपमान करेंगे। मुखर्जी को इस बात पर एतराज था कि राज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को फटकार क्यों लगाई। बिजली मंत्री शोभनदेव चटर्जी तो इसे काल्पनिक करार दे दिया। बहरहाल राज्यपाल भी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं उनके आक्रोश का बांध टूट रहा है। बहरहाल प्रदेश के लोग यह न भूलें कि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। इसकी अपनी एक गरिमा होती है। ऐसे पदों को राजनीतिक नजरिये से नहीं देखना चाहिए। उसका अपमान करने का मतलब कहीं न कहीं संविधान और संघीय ढांचे की अनदेखी है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

2.15 फीसद हिस्सेदारी है भारत की विश्व निर्यात बाजार में, जो बहुत कम है। कृषि उत्पादों का कुल निर्यात 2.7 लाख करोड़ रुपये, जबकि आयात 1.37 लाख करोड़ रुपये का है।

गलाकाट स्पर्धा से बढ़ा टेलीकॉम सेक्टर का संकट

नई दिल्ली, प्रेट्र : टेलीकॉम सेक्टर में मौजूदा संकट की प्रमुख वजह सेक्टर की कंपनियों में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और शुल्क दरों में अधिक कमी है। शुक्रवार को पेश इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वर्ष 2016 के बाद टेलीकॉम सेक्टर में गलाकाट प्रतिस्पर्धा शुरू हुई थी, जिसके चलते शुल्क दरों को लगातार कम किया गया। उदाहरण के लिए 2016-19 के बीच देश में इंटरनेट प्रयोग के लिए मिलने वाले डाटा की कीमत में 99 परसेंट की गिरावट देखी गई है। इसके चलते भारत दुनिया के सबसे कम डाटा शुल्क वाले देशों में शामिल हो गया है।

सर्वे में कहा गया है कि सितंबर, 2016 में रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में उतरने के बाद प्रतिस्पर्धा में तेज इजाफा हुआ। इसका प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र की टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल पर भी देखने को मिला। इस दौरान इन कंपनियों की आर्थिक हालत इस कदर खराब हो गई थी कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने में भी चूक गईं। सर्वे के मुताबिक सरकार इन सार्वजनिक टेलीकॉम कंपनियों को उबारने के लिए प्रयासरत है।

इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि मौजूदा समय में वायरलेस टेलीफोन का बोलबाला है। समूचे टेलीकॉम बाजार में वायरलेस टेलीफोन की हिस्सेदारी 98.27 परसेंट है, जबकि लैंडलाइन टेलीफोन की हिस्सेदारी सिर्फ 1.73 परसेंट है।

सरकारी बैंकों को लेकर बड़े फैसले की दरकार

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

सरकारी बैंकों को लेकर पिछले कुछ वर्षों में कई अहम फैसले करने वाली केंद्र सरकार इनके लिए कुछ और बड़े एलान कर सकती है या नहीं, इसका जवाब तो शनिवार आम बजट पेश हो जाने के बाद ही मिलेगा। लेकिन शुक्रवार को वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है, वह बताता है कि सरकार इनके बारे में कुछ बड़े फैसले लेने पर विचार कर रही है। सरकार की मंशा सर्वेक्षण में दिए गए इस तथ्य से समझी जा सकती है कि वर्ष 2019 में इन बैंकों में आम करदाताओं के लगाए हर एक रुपये पर 23 पैसे की हानि हुई है। दूसरी तरफ वर्ष 1991 के बाद खोले गए नए निजी बैंकों में पिछले वर्ष निवेशकों को हर एक रुपये के निवेश पर 9.6 पैसे का मुनाफा हुआ है। सरकारी बैंकों में इक्विटी के तौर पर आम करदाताओं के कुल 4.30 लाख करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं।

सर्वेक्षण ने बार-बार सरकारी बैंकों के प्रदर्शन को लेकर अपना असंतोष जताया है। शेयर बाजार के आधार पर देश के बैंकिंग सेक्टर की कंपनियों के प्रदर्शन का भी आकलन किया गया है। इसके मुताबिक सरकारी बैंकों में लगाए गए हर एक रुपये की कीमत शेयर बाजार में 71 पैसे है, जबकि निजी सेक्टर के बैंकों के मामले में एक रुपये की बाजार कीमत 3.70 रुपये है। पिछले वर्ष 2019 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल हानि 66,000 करोड़ रुपये की रही है जो एक साल के शिक्षा बजट का दोगुना है। देश में जितने बैंकिंग फ्रॉड होते हैं उसका 85 फीसद सरकारी बैंकों में होता है। इन बैंकों में कुल एनपीए (फंसे कर्जे) की राशि 7.4 लाख करोड़ रुपये की हो चुकी है जो एक वर्ष में ढांचागत क्षेत्र में खर्च की गई राशि का दोगुना है। अक्षमताओं के इन आंकड़ों के साथ ही सरकार ने यह भी जता दिया है कि जैसी स्थिति अभी है, वैसी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। इनकी अक्षमता को बेहतर बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री क्या करती हैं, यह देखने वाली बात होगी। बैंकों के विलय को लेकर कई अहम फैसले कर चुकी सरकार क्या इस बारे में आगे भी नया एलान करेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है उसके मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े 100 बैंकों में कम से कम छह बैंक भारतीय होने चाहिए लेकिन अभी सिर्फ एक ही बैंक (एसबीआइ) इसमें शामिल है। पांच लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने के लिए मजबूत बैंकिंग व्यवस्था चाहिए और यह काम विलय के जरिये किया जा सकता है। सरकार ने इन बैंकों की क्षमता बढ़ाने के लिए फिनटेक और कर्मचारियों के बीच हिस्सेदारी को वितरित करने के विकल्पों पर चर्चा की है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री कुछ ऐसा एलान कर सकती हैं जिससे बैंकिंग सेक्टर में तकनीकी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिले। ऋण देने के बारे में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करने और डाटा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया गया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयार इस सर्वेक्षण के अंत में कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर के बारे में दिए उसके सुझावों को समयबद्ध चरण में लागू करने की नीति बनाई जानी चाहिए।

> **आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकारी बैंकों को दिखाया आईना : मौजूदा प्रदर्शन बेहद लचर**
>
> **बात पते की**
>
> पिछले वर्ष सरकारी बैंकों में आम करदाताओं के हर एक रुपये के निवेश पर 23 पैसे का घाटा
>
> निजी बैंकों में निवेशकों को हर एक रुपये के निवेश पर हुआ 9.6 पैसे का मुनाफा
>
> 66,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ सरकारी बैंकों को पिछले वर्ष, जो एक साल के शिक्षा बजट का दोगुना है
>
> 7.4 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है सरकारी बैंकों का एनपीए, यह ढांचागत क्षेत्र में एक वर्ष में किए गए खर्च का दोगुना है
>
> इकोनॉमी के आकार के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े 100 बैंकों में कम से कम छह बैंक भारतीय होने चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ एसबीआइ इसमें शामिल है

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि निर्यात बढ़ाने पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को मांग आधारित बनाने पर आर्थिक सर्वेक्षण में जोर दिया गया है। विश्व निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 2.15 फीसद है, जो बहुत कम है। कृषि उत्पादों का कुल निर्यात 2.7 लाख करोड़ रुपये, जबकि आयात 1.37 लाख करोड़ रुपये का है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक भारत से खाद्यान्न समेत अन्य कई वस्तुओं की विश्व बाजार में मांग है। इनमें ताजा सब्जियां, ताजे फूल, बासमती चावल, खली व चीनी प्रमुख हैं। बागवानी के ज्यादातर उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की दिशा सफलता मिल सकती है। मसाले, चाय, कॉफी और अरंडी व कच्चे कपास का निर्यात घट गया है। घरेलू किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नए सिरे से निर्यात मांग के मद्देनजर खेती की जरूरत बताई गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय कृषि उपज की धमक बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने को कहा गया है। हाल ही में सरकार ने खाड़ी देशों की जरूरत के हिसाब से खेती करने के समझौते किए हैं।

नसीहत : बाजार में गैरजरूरी हस्तक्षेप ठीक नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह संकल्पना व्यवहार रूप में बजट में दिख सकती है। विभिन्न मंत्रालयों को उपभोक्ता मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने की नसीहत दी गई है। कहा गया है ऐसी कार्य संस्कृति बनाएं, जिससे उपभोक्ता कम खर्च और उत्पादकता अधिक हो।

सर्वेक्षण रिपोर्ट में हवाला दिया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत देशभर में पिछले वर्ष कुल 76,033 छापे मारे गए। महज 3.8 फीसद यानी 2941 ही दोषी ठहराए गए। इससे पता चलता है कि छापे में व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ और बाजार पर प्रतिकूल असर पड़ा। इस अधिनियम ने जमाखोरी पर अंकुश की ताकत तो दी, लेकिन असंगत तरीके से उपभोग भी सीमित कर दिया। बफर स्टॉक नीति से भारत का कृषि बाजार एकीकृत हो गया और फसल विविधीकरण की दिशा में कदम धीमे रहे। एक जैसे खाद्यान्न की अति उपलब्धता से जगह की कमी और सब्सिडी का बोझ बढ़ा। कुल भंडारण के आंकड़े भी नहीं हैं, जो उत्पादकों विपरीत परिस्थितियों की आशंकाओं में उत्पादन और मूल्य आकलन की सुविधा दे सकें। आर्थिक सर्वेक्षण में स्पष्ट किया गया है कि भंडारण की आधुनिक विधि, डिजिटल सूचना तंत्र को बढ़ावा दें, ताकि प्रभावी पूर्वानुमान प्रणाली तैयार हो सके। साथ ही स्थिर व्यापार नीति भी बने। यह ईसीए की अपेक्षा अधिक कारगर होगा।

> **आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में हो सकता है महत्वपूर्ण निर्णय**
>
> **आर्थिक सर्वे में सुझाव - हस्तक्षेप के कई बार मिले उलटे परिणाम**

महंगी हुई डीपीसीओ के दायरे में आई दवाएं : सर्वे रिपोर्ट में राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) से कीमत तय करने को बाजार के प्रतिकूल बताया गया है। जो दवाएं डीपीसीओ, 2013 के अधीन रहीं, उनके अवयव में अब तक 71 रुपये प्रति मिलीग्राम की दर से वृद्धि हुई है, जबकि दायरे से बाहर दवाएं महज 13 रुपये महंगी हुईं।

अस्पतालों में मिलने वाली डीपीसीओ में शामिल दवाओं की कीमत 99 रुपये बढ़ी लेकिन उसकी सूची से बाहर वाली दवाओं में की 25 रुपये। यही नहीं, डीपीसीओ की सूचीबद्ध अपेक्षाकृत सस्ते फार्मूले वाली दवाएं 21 फीसद ही महंगी हुईं लेकिन महंगे फार्मूले वाली करीब ढाई गुना।

हरियाणा को उप्र, तो पंजाब को हिमाचल से जोड़ने की तैयारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

आम बजट 2020-21 में जहां कई नई रेल लाइनों के सर्वे की घोषणा की जा सकती है। वहीं कई नई रेल लाइन बिछाने के लिए भी बजट स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है। हरियाणा को उत्तर प्रदेश के मेरठ से और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने के लिए भी इस बजट में फंड मंजूर किया जा सकता है। पानीपत से मेरठ रेल लाइन बिछाने की कई दशक पुरानी मांग पर इस बजट में फैसला लिया जा सकता है।

रेल मंत्री रहीं ममता बनर्जी ने 2010-11 के रेल बजट पानीपत से मेरठ रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे कराया, जिसकी सर्वे रिपोर्ट एक टेबल से दूसरे टेबल पर घूमती रही। करीब 104 किलोमीटर (किमी) रेल लाइन बिछाने के लिए कितना खर्च होगा, इसका आकलन भी किया जा चुका था, लेकिन लाइन बिछाने के लिए फंड मंजूर नहीं किया गया। 2020-21 के बजट में इस लाइन के लिए फंड घोषित किया जाएगा। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार यह मुनाफे का सौदा बताई जा रही है। इससे हरियाणा व उत्तर प्रदेश का सीधा रेल नेटवर्क बनेगा, वहीं माल ढुलाई का कारोबार भी इस रूट पर बढ़ेगा। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के ऊना से पठानकोट तक रेल नेटवर्क के शेष 25 किमी के टुकड़े को पूरा करने के लिए इस बजट में फंड मंजूर किया जा सकता है। मौजूदा समय दौलतपुर चौक तक रेल लाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि आगे पठानकोट तक बिछाई जानी बाकी है। इसी प्रकार चंडीगढ़ से बद्दी तक रेल लाइन बिछाने के लिए फंडिंग होगी।

> **नई रेल लाइनों का सर्वे और लाइनें बिछाने का किया जा सकता है बजट पास**
>
> **हिमाचल के बद्दी से रेवेन्यू के लिए बिछाई जाएगी नई रेल लाइन**

1600 किमी. अप डाउन हाईस्पीड ट्रेन की हो सकती है घोषणा

दीपक बहल, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाईस्पीड ट्रेन दौड़ाने का सपना साकार करने के लिए रेलवे ने तैयारी कर ली है। 160 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रेन करीब 800 किमी दौड़ेगी और उसी दिन 800 किमी का सफर तय कर लौटेगी। इसकी घोषणा शनिवार को आम बजट में की जा सकती है। इसी प्रकार यात्री और माल ढुलाई के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और निजी कंपनियों के जिम्मे नई ट्रेनें दौड़ने का एलान किया जा सकता है। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आइआरएसडीसी) की जिम्मेदारी बढ़ेगी ताकि एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशनों पर सुविधाएं मिलें।

130 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ रही वंदे भारत एक्सप्रेस के सफल प्रोजेक्ट के चलते अब उसकी रफ्तार 160 किमी प्रतिघंटा की जाएगी। हालांकि वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी की औसत स्पीड सौ किमी प्रतिघंटा भी नहीं है। इसके लिए भी रेलवे के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जा रहा है। मौजूदा समय शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस भी 130 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। लेकिन इनकी औसत स्पीड 90 किमी प्रतिघंटा तक सिमट कर रह जाती है। हाईस्पीड के लिए संरक्षा से जुड़े रेलवे ट्रैक के दोनों ओर कंक्रीट की दीवार, सिग्नल को मॉडिफाइ करने में जुट गया है। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से हावड़ा के बीच बन रहे वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर पूरा होने के बाद यात्री ही नहीं बल्कि सामान की आवाजाही के समय में भी काफी कमी आएगी। ये दोनों रूट काफी व्यस्त माने जाते हैं।

> **आइआरएसडीसी को स्टेशन व निजी कंपनियों को मिल सकती हैं यात्री-गुड्स ट्रेनों के संचालन की जिम्मेदारी**
>
> **रेलवे के आधारभूत ढांचे को और मजबूत कर औसत स्पीड को भी बढ़ाएगा रेलवे**
>
> **वंदे भारत सफल होने के बाद अब हाईस्पीड ट्रेन दौड़ाने की रेलवे ने रूपरेखा की तैयार**

प्रतीकात्मक

व्यस्त रूट पर ट्रेनों की संख्या बढ़ी : रेलवे के सिग्नल लाइन में 24 से 30 रेलगाड़ियां ही दौड़ सकती हैं जबकि डबल लाइन में यह संख्या 60 तक है। ट्रेनों की संख्या में इजाफा होने के कारण एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन दौड़ रही होती है जबकि सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन चालक को कभी गाड़ी बीच में रोकनी पड़ती है तो कभी ट्रेन की रफ्तार कम करनी पड़ती है। अब एक ही पटरी पर मालगाड़ी, शताब्दी, राजधानी सब दौड़ रही हैं जिसका असर भी कहीं न कहीं ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। हालांकि, पंजाब के लुधियाना से कोलकाता तक 22 हजार करोड़ की लागत से रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। इसके बाद एलीवेटेड ट्रैक पर जमीन से करीब 18 फीट ऊंचाई पर मालगाड़ियां दौड़ेंगी। रेलवे ने कॉरिडोर का लक्ष्य 2020 तक रखा है लेकिन 2022 तक उम्मीद है। इस कॉरिडोर के बनने से मालगाड़ियां इस ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी। इससे एक्सप्रेस, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड में करीब दस से पंद्रह घंटे की औसत स्पीड में बढ़ोतरी होगी।

आटोमैटिक ट्रैक न होना भी कारण : रेलवे के हर क्षेत्र में अभी जिस तरह से ताबड़तोड़ ब्लाक का काम चल रहा है। यह भी कहीं न कहीं ट्रेनों की रफ्तार में अड़चन बना हुआ है। हालांकि संरक्षा दृष्टि से पटरी की मरम्मत का काम चलता रहता है। इसके अलावा सिग्नल प्रणाली को भी कई जगहों पर और दुरुस्त किया जा रहा है ताकि ट्रेनों की रफ्तार और बेहतर हो सके।

पशुधन व मत्स्य पालन के सहारे रफ्तार पकड़ेगी खेती

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पशुधन व मत्स्य पालन के सहारे कृषि क्षेत्र की विकास दर रफ्तार पकड़ सकती है। खेती से संबद्ध इन गतिविधियों में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं, जो ग्रामीण बेरोजगारी कम कर सकती हैं। वानिकी, पशुधन व मत्स्य क्षेत्र की संयुक्त रूप से वार्षिक औसत विकास दर सात फीसद को भी पार कर सकती है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच वर्षों के दौरान पशुधन क्षेत्र की औसत विकास दर 7.9 फीसद तक दर्ज की गई है। जबकि मत्स्य क्षेत्र की विकास दर सात फीसद आंकी गई है। इसी तरह डेयरी क्षेत्र की विकास दर 6.5 फीसद रही है। इसके विपरीत कृषि क्षेत्र की विकास दर 2.8 फीसद पर अटक गई है। खाद्यान्न वाली फसलों की विकास दर भी स्थिर है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, वानिकी और मछली पालन की संयुक्त वार्षिक औसत विकास दर 6.58 फीसद है।

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...

नई दिल्ली, शनिवार, 1 फरवरी, 2020

सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

लाइट...कैमरा...एक्शन और ये निकले चिकने चुपड़े नेता जी

अब तो स्मार्ट मोबाइल का हाई पिक्सल कैमरा आपके चेहरे पर चार चांद लगाकर चुटकियों में तस्वीर उतार देता है। लेकिन उन नेताओं के दिन याद करो जब फोटो स्टूडियो ही एक सहारा था। स्टूडियो वाले से पोस्टर, बैनर की तस्वीरों के लिए समय लेना पड़ता था। बड़ी मशक्कत के बाद पोज भी तो निकलता था...दरअसल वो दौर काले बक्से का था। चौक-चौराहों पर तब श्वेत श्याम तस्वीरें दिखती थीं, प्रत्याशियों का गंभीर चेहरा। सबरंग के इस अंक में नेताओं के बदलते चलचित्र स्वरूप से रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

तस्वीर के नीचे चुनावी नारे और आसपास बैनर, झंडों की भरमार होती थी। इन तस्वीरों को देख राहगीरों के कदम रुक जाते थे। भीड़ इन तस्वीरों पर जमकर चुनावी चर्चाएं करती थीं। इन तस्वीरों के पीछे की दिलचस्प कहानियां हैं। जिन फोटो स्टूडियो में नेता अपनी तस्वीरें खिंचाते थे वो दिल्ली के चुनावी सफर की हमसफर हैं। ये स्टूडियो आज भी नेताओं को आकर्षित करते हैं। वरिष्ठ नेता सुभाष आर्या बताते हैं कि आजादी के बाद शुरुआती चुनावों में फोटो का इतना चलन था ही नहीं। तब हम लिथो प्रेस से छपे कागज चस्पा कर प्रचार करते थे। लिथो छपाई दरअसल, पत्थर पर चिकनी वस्तु से लेख लिखकर अथवा डिजाइन बनाकर, उसके द्वारा छाप उतारने की कला है। लिथोग्रैफी शब्द यूनानी भाषा के लिथो (पत्थर) एवं ग्रैफी (लिखना) शब्दों के मिलने से बना है। पत्थर के स्थान पर यदि जस्ता, एल्युमीनियम इत्यादि पर उपयुक्त विधि से लेख लिखकर या डिजाइन बनाकर छापा जाए तो उसे भी लिथोग्रैफी कहेंगे। इस तरह हाथ से लिखकर कागज को पीले रंग का किया जाता है। इसे हाथ से चलने वाली मशीन के जरिए पेपर निकालकर यहां वहां दीवारों पर लगाते थे। रात में कार्यकर्ताओं की टोली निकलती थी और ऊंची जगहों पर पोस्टर लगाते थे। फोटो के लिए प्रत्याशी काला बक्सा पर निर्भर थे। काला बक्सा कपड़े से ढका रहता था। फोटोग्राफर सामने प्रत्याशी को बैठाता था। कपड़ा उठाकर वो कैमरे में अपना चेहरा ढकता था। अंदर फोटो की निगेटिव प्लेट वाले कागज रखे जाते थे। अंदर एक बल्ब भी था जो सिर्फ एक बार में एक फोटो खींचने के लिए ही प्रयुक्त होता था। उसके बाद यह फ्यूज हो जाता था। काला बक्सा चांदनी चौक, भगीरथ पैलेस के सामने आरके स्टूडियो में भी था। जहां प्रत्याशी जाकर अपनी फोटो खिंचवाते थे। वहीं महाबल मिश्रा कहते हैं कि अब तो हर हाथ मोबाइल है। तब स्टूडियो पर ही सब निर्भर होता था। जनकपुरी, विकासपुरी में सब्बरवाल के फोटो स्टूडियो में ही इधर के क्षेत्र के प्रत्याशी अपनी फोटो खिंचवाते थे। फोटोग्राफर विभिन्न एंगल से, प्रणाम करते हुए, खड़ी अवस्था में, हंसते, गंभीर मुद्रा में फोटो खिंचाते थे। ताकि बाद में उसे विभिन्न नारों के साथ प्रयोग किया जा सकें। फोटो भी पैंट शर्ट, पजामा कुर्ता, अलग-अलग परिधानों में उपयोग के आधार पर खिंचवाई जाती थीं। हमारे कार्यकर्ता इन नारे लिखी तस्वीरों, बैनर को लेकर विधानसभा में जाते थे। तब एक क्षेत्र में एक बैठक करते थे। उसी में सभी लोग आते थे एवं आमने सामने बैठकर बातचीत होती थी। हालांकि महाबल यह भी कहने से नहीं चूकते कि पहले के मुकाबले अब चुनाव भी तो बहुत मशक्कत वाला हो गया है। जनता भी पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है।

महानगर परिषद कार्यकाल में कार्यकारी पार्षद रह चुके व वरिष्ठ नेता विजय कुमार मलहोत्रा भी अपने दिनों में चलचित्र से जुड़े दिलचस्प किस्से बताते हैं। कनॉट प्लेस में महत्ता फोटो स्टूडियो समेत कई अन्य स्टूडियो थे। खासकर ओडियन और प्लाजा के सामने। यहां सिर्फ फोटो ही नहीं पोस्टर भी बनते थे, वो भी सस्ते में। उन दिनों 5 रुपये से एक हजार तक में बढ़िया पोस्टर बन जाया करता था। उन दिनों कांग्रेस ज्यादा मजबूत थी। पूरा इलाका उसके बैनर, पोस्टर से अटा पड़ा होता था। बीच में कहीं हमारे पोस्टर दिखते थे। झुग्गी झोपड़ियां तो कांग्रेसी झंडों से भर जाती थीं। हम सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के यहां झंडा लगा पाते थे। हालांकि बाद में चुनाव आयुक्त टीएन शेषन ने काफी कड़ाई की। कनॉट प्लेस में तीन-चार एवं गोल मार्केट में एक स्टूडियो था। फोटो से ही पोस्टर बन जाते थे। कई प्रत्याशी तो दो-दो स्टूडियो में फोटो खिंचवाते थे ताकि एक जगह फोटो ना जमें तो दूसरी जगह का प्रयोग करें। विजय कुमार मल्होत्रा सन् 1958 के चुनाव से जुड़ा संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि तब हर सीट से दो प्रत्याशी चुनाव लड़ते थे। पटेल नगर सीट से मैं और बलराज खन्ना चुनाव लड़ रहे थे। दोनों की ही तस्वीरें खींचकर लगाई गई थीं। कई बार ऐसा होता कि लोग हम दोनों को वोट दे देते, जबकि कम्युनिस्ट और कांग्रेसी प्रचार में ही लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि एक ही वोट दें। दूसरा किसी और को वोट दें। खैर, उस चुनाव में जनता, प्रत्याशी के फोटो पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, वह तो हमारी पदयात्राओं को, हम कितना उनके लिए उपलब्ध हैं इस पर ज्यादा ध्यान देती थी उसी के हिसाब से वोट भी मिलता था। हम प्रचार के लिए भी पदयात्रा पर ज्यादा जोर देते थे। तड़के सुबह घर से निकल जाते थे एवं कार्य कर्ताओं के यहां ही चाय, नाश्ता करते थे। मुझे याद है कि चुनाव में पिताजी ने 500 रुपये दिए थे। और आप हैरान रह जाएंगे कि पूरा पैसा बच गया था। उस समय चुनाव में पैसे बहुत खर्च नहीं होते थे।

हर चेहरे की होती है अपनी खासियत : एक और दिल्ली का खास पुराना स्टूडियो है सब्बरवाल फोटो स्टूडियो, यह गोल मार्केट में है। यही कोई साढ़े तीन दशक पुराना स्टूडियो है। मालिक गगन सब्बरवाल कहते हैं कि मैंने 1973 में फोटोग्राफी करना शुरू किया था। और स्टूडियो 1984 में खोला था। मैंने गृहमंत्री शिवराज पाटिल की फोटो उनके घर पर जाकर खिंची थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, ओम प्रकाश चौटाला, मुलायम सिंह यादव, नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य नेताओं की फोटो खींची हैं। कहते हैं कि हर चेहरे की अपनी खासियत होती है। एक फोटोग्राफर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि उस चेहरे की खासियत को उभारूं ताकि फोटो खूबसूरत दिखे। अब प्रत्याशी विक्ट्री साइन दिखाते फोटो खिंचवाते हैं। वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन, विजय गोयल, प्रकाश जावड़ेकर सरीखे नेताओं की तस्वीर खींचना भी अलग अनुभव था। महिला प्रत्याशी ज्यादातर साड़ी में फोटो पसंद करती हैं। कई तो पहले सिर पर पल्ला रखना नहीं भूलती थीं। उसी के साथ फोटो कराती थीं।

पहले गंभीर लेकिन अब चाहिए मुस्कुराते नेता जी: वक्त के साथ खुदको बदलना बहुत जरूरी होता है। वैसे भी नेताओं की तस्वीर करना कोई आसान काम नहीं है। नेता, जनता का प्रतिनिधि होता है। तस्वीर भी जनता के बीच भरोसा पैदा करती है। जनता के बीच एक धारणा, एक सोच बनती है। इसके लिए सबसे अधिक मायने रखता है कि नेता, चाहे महिला हों या पुरुष वो किस अंदाज में फोटो करा रहे हैं। और दिल्ली के चुनाव में तो हमने बहुत सारे ट्रेंड देखे हैं। कमला नगर स्थित प्रिंस फोटो स्टूडियो के डायरेक्टर उमेश सभरवाल कहते हैं कि दिल्ली के पहले विधानसभा चुनावों में हमारे स्टूडियो में फोटो खिंचवाने वाले 22 जबकि दूसरे चुनाव में 26 प्रत्याशी जीतकर आए थे। जनता की नजरों में पहले एक नेता की पहचान खादी का सफेद कुर्ता पहने ही होती थी। बाद में इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की वजह से बंद गले की अचकन जुड़ गई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ऊपर हाथ उठाए फोटो भी ट्रेंड में था। कुछ समय तक फोटो में संजय गांधी स्टाइल में चलते-चलते कैजुअल पोज वाला फोटो भी ट्रेंड में था। हालांकि इस विधानसभा में एक बार फिर हाथ ऊपर उठाए फोटो देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बाएं हाथ को ऊपर उठाए तस्वीर जारी हुई है। यह कई मायनों में अलग है। पहले के नेता दाएं हाथ को ऊपर उठाकर फोटो खिंचवाते थे। केजरीवाल के एक फोटो में उनके दोनों हाथ ऊपर दिख रहे हैं। वर्तमान चुनाव की बात करें तो नेता कलरफुल ड्रेस में फोटो पसंद करते हैं। खादी का कुर्ता, बंद गले की अचकन अब पुरानी हो गई है। अब तो कैजुअल ड्रेस का जमाना है। मकसद साफ है, नेता आम लोगों की तरह ही दिखना चाहते हैं। इस बदलाव पर उमेश कहते हैं कि पहले के चुनावों में रोटी, कपड़ा, मकान सरीखे गंभीर मसले थे। जनता भी नेता जी को गंभीर भाव में देखना पसंद करती थी अब नेता मुस्कुराते चेहरे में फोटो खिंचवाते हैं। पिछले वर्षों में हुए चुनावों में तो हमनें कई प्रत्याशियों को ग्लैमरस लुक देने के लिए बालों में जेल का अभिनव प्रयोग भी किया था। जो काफी सफल रहा था।

सबसे पुराना स्टूडियो

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ प्रिंस स्टूडियो के निदेशक उमेश सभरवाल

नेताओं के लिए प्रेम फोटो स्टूडियो भी पसंद की जगह रही। कमला नगर स्थित प्रेम फोटो स्टूडियो की शुरुआत 1957 में हुई थी। रेलवे से रिटायर सोहनलाल सभरवाल ने इसे खोला था। वर्तमान में इनके बेटे उमेश इसे संभालते हैं। उमेश कहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना, वर्तमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी चुनाव के दौरान फोटो खिंचवाई हैं। वर्तमान नेताओं की बात करें तो नकुल भारद्वाज, अलका लांबा, रागिनी नायक ने भी यहां फोटो खिंचवाई है। उमेश कहते हैं कि इसी साल हमनें दिल्ली विधानसभा की तस्वीर खिंची हैं। जिसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत सभी विधायक हैं। अगर फोटो की बात करें तो हाल के दशकों में काफी बदलाव आया है। अब फिल्म सेलिब्रिटी की तरह आकर्षक दिखना चाहते हैं। पहले प्रत्याशी गंभीर, इंटलैक्चुअल लुक में फोटो खिंचवाना पसंद करते थे। अब प्रत्याशी फोटो में आत्मविश्वासी और विनम्र दिखना चाहते हैं। यही वजह है कि फोटो खिंचने में कई बार एक से दो घंटे लग जाते हैं।

राजनीतिक पोशाक में सियासत के चटक रंग

एक दौर होता था जब हर नेता एक ही तरह के परिधान में नजर आता था। महिलाएं कॉटन साड़ी और पुरुष सफेद कुर्ता-पायजामा और नेहरु जैकेट। आज बदलते दौर में जहां युवा राजनीति में आगे आ रहे हैं वहीं पहनावे में राजनीतिक परिवर्तन होने स्वाभाविक हैं। इस समय सदाबहार सफेद कुर्ता पायजामा तो चलन में हैं ही और जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह खासकर रंगों का है।

राजनीति की कई पीढ़ियों का नाप ले चुके हैं, नॉर्थ एवेन्यू स्थित सिद्दीकी टेलर्स के संचालक जावेद सिद्दीकी। दरअसल जावेद के पिता अयूब अहमद सिद्दीकी राष्ट्रपति जाकिर हुसैन से लेकर 1999 तक नेताओं के परिधान तैयार करते थे। और तब सफेद कुर्ता और जैकेट का चलन ज्यादा होता था। जावेद कहते हैं कि अब जैसे-जैसे राजनीति की रंगत बदलने लगी है वैसे ही सियासत के चटक रंगों के साथ ही राजनीतिक पोशाक भी चटक हो गई हैं। अब हर रंग के कुर्ते बन रहे हैं और जैकेट्स में खादी से लेकर बनारसी सिल्क तक की बन रही हैं। जावेद के भाई निशात अहमद सिद्दीकी की माने तो यह फैशन नया नहीं है पुराना ही है। अब युवाओं के राजनीति में आने से पहले वाली चीजें फिर चलन में आ रही हैं। चाहे महिला हों या पुरुष, सभी कुर्ता-जैकेट को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। केवल चुनावी मौसम में ही नहीं, अब इन परंपरागत परिधानों का चलन विशेष आयोजन, उत्सवों में भी बढ़ रहा है।

पायजामे की जगह पैंट ने ली : नेता कुर्ते को तो पसंद कर रहे हैं लेकिन पायजामे की जगह अब पैंट को तरजीह दे रहे हैं। जावेद के मुताबिक पैंट्स स्टाइलिश होने के साथ-साथ आरामदायक भी होती हैं। इसके अलावा कुर्तों के कॉलर के स्टाइल में भी बदलाव आया है। जैसे दिल्ली के नेता अजय माकन कॉलर्ड कुर्ता बनवाना पसंद करते हैं। आप नेता राघव चड्ढा रंगों को लेकर काफी चूजी हैं तो हल्के से लेकर फ्लोरोसेंट रंगों में कुर्ता व सफेद पैंट्स बनवाते हैं।

अब पैटर्न और रंगों को लेकर बदली पसंद : जावेद के मुताबिक पुराने से लेकर युवा नेताओं तक के परिधान तैयार कर रहे हैं जिनमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला, राज्य सभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, नितीश कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रस नेता सुबोध कांत सहाय, झारखंड से एमएल कमलेश कुमार सिंह, रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव, दिल्ली के आप प्रत्याशी राघव चड्ढा, पूर्व केंद्री मंत्री व कांग्रेस नेता अजय माकन, संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या शामिल हैं। उनका कहना है कि पहले नेताओं की च्वाइस केवल साइज को लेकर होती थी लेकिन अब रंगों व पैटर्न में भी नेता अपनी पसंद नापसंद रखते हैं और उसी हिसाब से परिधान तैयार किए जाते हैं।

सिल्क के साथ भी हो रहे प्रयोग : फैशन डिजाइनर सिल्की नंदा का कहना है कि राजनीति में ग्लैमर का तड़का लगने के साथ ही कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक पहनावे की परिधियों को तोड़कर सिल्क और कशीदाकारी को अपनाना शुरू कर दिया है। इस समय पठानी पश्मीना शॉल्स, पश्मीना की जैकेट, पुरुषों में पठानी राजपूती शॉल भी सिल्क व प्योर बनारसी जैकेट व बनारसी स्टॉल्स पसंद किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मृति इरानी व सोनिया गांधी से प्रभावित महिला नेता कॉटन और सिल्क साड़ी पर स्टाइलिश डिजाइनर जैकेट की मांग करती हैं। नए नेताओं में महिलाएं भी अब कुर्ते पायजामे को तरजीह दे रही हैं ताकि वह चुनावी फील लाया जा सके। शिवानी चोपड़ा से लेकर आतिशी और प्रियंका सिंह जैसी दिल्ली विधानसभा की प्रत्याशियों को इस तरह के परिधानों में देखा जा सकता है।

प्रियंका दुबे मेहता

दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभआ क्षेत्र से आप प्रत्याशी राघव चड्ढा के साथ जावेद सिद्दीकी।

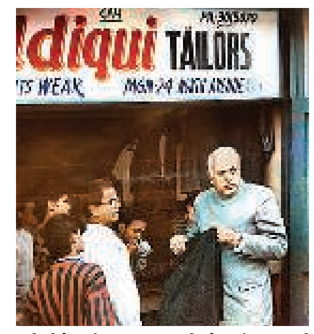

सद्दीकी टेलर्स पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला भी कभी अपने सूट सिलाने आते थे। सिर्फ फारुख ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायण भी यहीं आते थे। सौजन्य : सिद्दीकी टेलर्स

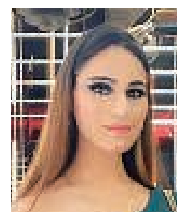

मैं ज्यादा महिला नेताओं के परिधान डिजाइन करती हूं। इसमें साड़ी पर जैकेट, प्लेन कुर्ता और फ्लोरल एंबरॉयड्री वाला दुपट्टा लोगों की पहली पसंद बन रहा है। चुनावी भागदौड़ में लोग आरामदायक ढीले ढाले कुर्ते की मांग कर रहे हैं।

सिल्की नंदा, फैशन डिजाइनर

चुनावी जायका

चाय की चुस्की संग हार जीत पर हो रहा मंथन

दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में पूरी दिल्ली चुनावी रंग में रंग चुकी है। घर, दफ्तर, चौक-चौराहा हो या कॉलेज के कैंपस जिसे देखो पार्टियों के काम-काज और राजनीतिक मुद्दों पर हार-जीत के समीकरण बैठाने में लगा है। इस चुनावी सरगर्मी में युवाओं का जोश भी कुछ कम नहीं है। ऐसा हो भी क्यों न, सरकार बनाने में इनकी भूमिका भी तो अहम है। युवा अपने भविष्य के साथ देशहित के मुद्दों पर कितनी बेबाक राय रखते हैं इसका एहसास दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रवेश करते ही हो जाता है। लॉ फैकल्टी के बाहर मनचंदा स्नैक्स का नजारा राजनीतिक हलचल बताने के लिए काफी है। क्लास खत्म होते ही छात्र तेजी से कैंटीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते कैंटीन में छात्रों का जमावड़ा लग जाता है। कुछ छात्र चाय, कॉफी और स्नैक्स का ऑर्डर देते हैं और उसी के साथ चुनावी चर्चा शुरू हो जाती है। बिजली-पनी की बातें होती हैं तो कुछ महिला सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जता रहे हैं। तभी कुछ छात्र कह उठते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून भी तो है। और फिर प्रदर्शन को लेकर किस पक्ष को कितना नफा और नुकसान होगा, इसकी चर्चा तूल पकड़ लेती है।

नागरिकों की सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा : लॉ फैकल्टी के पांच-छह छात्र नमकीन के साथ चाय की चुस्की लेते हैं। तभी अंकित सुंदरियाल कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान चाय पर चुनावी चर्चा ना हो तो बात बेमानी लगती है। फिर चाय की चुस्की लेते हैं और कहते हैं इस बार तो मैं सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दूंगा। महिलाओं की ही नहीं आज प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा ताक पर है। जो पार्टी अपने नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी हम उसे ही चुनकर लाएंगे। इस पर राजीव कहते हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पांच वर्षों में शिक्षा पर तो अच्छा काम किया है। साथ ही, महिलाओं के लिए बस यात्रा भी फ्री कर दी है, लेकिन बसें तो सड़कों पर दिखती ही नहीं और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। तभी आवाज आती है कि छात्रों के मुद्दे भी चुनावी चर्चा का केंद्र बिंदू होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं। यहां आसपास कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, कमला नगर, वजीराबाद जैसे इलाकों में सफाई पर और ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन नेता सिर्फ हवा हवाई मसलों से चुनाव जीतने में लगे हुए हैं। तभी पास खड़े ऋषभ कहते हैं इस बार सीएए व एनआरसी के विरोध में हो रहा प्रदर्शन भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मोड़ ला सकता है।

बेरोजगारी का मुद्दा कहां है : रामजस कॉलेज की कैंटीन में प्रवेश करते ही समोसे व पकौड़ों की महक छात्रों की भूख बढ़ा देती है। दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठे छात्र अभिषेक कहते हैं कि जब भी दोस्तों के साथ यहां कुछ खाने आते हैं तो ना चाहते हुए भी चर्चा का केंद्र चुनाव हो ही जाता है। दरअसल, सभी राजनीतिक दलों के समर्थक व खिलाफत करने वाले एक ही टेबल पर आकर अपना मत रखने लगते हैं। तभी एक अन्य छात्र की आवाज आती है कि युवाओं के मुद्दे कहां है? रोजगार की बात कौन कर रहा है? कोई पार्टी बिजली, पानी फ्री कर रही है तो कई राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, लेकिन इनमें मुख्य बातें नदारद हैं। इस पर साहिल जोर से कहते हैं कि विगत 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा पहुंच गई है, लेकिन कौन सा राजनीतिक दल इस पर बात कर रहा है? तभी डोसा का स्वाद लेते हुए सुरेंद्र भी बहस में कूद पड़े और बोले कि बेरोजगारी पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। उनकी इस बात से कई छात्र सहमत दिखे। कुछ ने कहा कि रोजगार के नए आयामों पर भी गौर करना होगा। कॉलेज कैंटीन में छात्र कुछ इसी तरह खाने की थाली और चाय संग चुनावी चर्चा जारी रखते हैं।

रितु राणा

बिजली-पानी तो ठीक है, लेकिन बेरोजगार युवाओं की बातें तो किसी के एजेंडे में नहीं है। कैंपस में युवाओं की यही है चिंता। जागरण

एक दूसरे के पूरक थे गांधी और पटेल

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

मेरा दिल भरा हुआ है। क्या कहूं क्या न कहूं? जबान चलती नहीं है। आज का अवसर भारतवर्ष के लिए सबसे बड़े दुख, शोक और शर्म का अवसर है। पिछले चंद दिनों से उनका दिल खट्टा हो गया था और आप जानते हैं कि आखिर उन्होंने उपवास भी किया। उपवास में चले गए होते, तो अच्छा होता। इस समय पर ही उनको जाना था। आज वह भगवान के मंदिर पहुंच गए! देश के पहले उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बात 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में गांधी जी की हत्या के एकदम बाद हुई एक सार्वजनिक सभा में जन साधारण को संबोधित करते हुए कही थी। ऐसी शोक की घड़ी में भी आत्मसंयम का परिचय देते हुए उन्होंने कहा कि यह बड़े दुख का, बड़े दर्द का समय है, लेकिन यह गुस्से का समय नहीं है। क्योंकि अगर हम इस वक्त गुस्सा करें, तो यह सबक जो उन्होंने हमको जिंदगी भर सिखाया, उसे हम भूल जाएंगे! और कहा जाएगा कि उनके जीवन में तो हमने उनकी बात नहीं मानी, उनकी मृत्यु के बाद भी हमने नहीं माना। हम पर यह धब्बा लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि कितना भी दर्द हो, कितना भी दुख हो, कितना भी गुस्सा आए, लेकिन गुस्सा रोककर अपने पर काबू रखिए। अपने जीवन में उन्होंने हमें जो कुछ सिखाया, आज उसी की परीक्षा का समय है। बहुत शांति से, बहुत अदब से, बहुत विनय से एक-दूसरे के साथ मिलकर हमें मजबूती से पैर जमीन पर रखकर खड़ा रहना है।

सरदार पटेल ने हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में गांधी की सर्वव्यापी उपस्थिति के अभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका एक सहारा था और हिंदुस्तान को वह बहुत बड़ा सहारा था। हमको जीवन भर उन्हीं का सहारा था। आज वह चला गया! वह चला तो गया, लेकिन हर रोज, हर मिनट वह हमारी आंखों के सामने रहेगा! हमारे हृदय के सामने रहेगा! क्योंकि जो चीज वह हमको दे गया है, वह तो कभी हमारे पास से जाएगी नहीं! आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो बोझ पड़ रहा है, वह इतना भारी है कि करीब-करीब हमारी कमर टूट जाएगी।

उस दुखद घड़ी में भी एक उत्तम नेता के दुर्लभ गुण का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आशावादिता का दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि कल चार बजे उनकी मिट्टी तो भस्म हो जाएगी, लेकिन उनकी आत्मा तो अब भी हमारे बीच में है। अभी भी वह हमें देख रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वह तो अमर है। मैं उम्मीद करता हूं और हम सब ईश्वर से यह प्रार्थना करेंगे कि जो काम वह हमारे ऊपर बाकी छोड़ गए हैं, उसे पूरा करने में हम कामयाब हों। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस कठिन समय में भी हम पस्त नहीं हो जाएंगे, हम न हिम्मत भी नहीं हो जाएंगे। फिर 2 फरवरी 1948 को रामलीला मैदान में गांधी जी की शोकसभा में सरदार पटेल के मन की पीड़ा फूट पड़ी। उन्होंने गांधी के साथ स्वयं के अभिन्न जुड़ाव और राष्ट्रीय जीवन में उनके अप्रतिम योगदान को बताते हुए कहा कि जब से गांधी जी हिंदुस्तान में आए तब से, या जब मैंने जाहिर जीवन शुरू किया तब से, मैं उनके साथ रहा हूं। अगर वे हिंदुस्तान न आए होते, तो मैं कहां जाता और क्या करता, उसका जब मैं ख्याल करता हूं तो एक हैरानी-सी होती है। महात्मा गांधी ने कारागार से लिखे एक पत्र में सरदार पटेल के बारे में लिखा था कि मेरी कठिनाई यह है कि तुम मेरे साथ नहीं हो इसलिए मैं एकलव्य बनने का प्रयास कर रहा हूं कि जिसने द्रोणाचार्य की अस्वीकृति के बाद अपने समक्ष द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा रखकर तीरंदाजी सीखी थी। मैं उसी तरह, तुम्हारी छवि का स्मरण करते हुए अपने प्रश्न उसके समक्ष रखता हूं। उसी शोकाकुल पटेल ने गांधी स्मृति को लेकर रामलीला मैदान में कहा कि तीन दिन से मैं सोच रहा हूं कि गांधी जी ने मेरे जीवन में कितना पलटा किया और इसी तरह से लाखों आदमियों के जीवन को उन्होंने किस तरह से पलटा? यदि वह हिन्दुस्तान में न आए होते तो राष्ट्र कहां जाता? हिंदुस्तान कहां होता? सदियों से हम गिरे हुए थे। वह हमें उठाकर कहां तक ले आए? उन्होंने हमें आजाद बनाया। उनके हिंदुस्तान आने के बाद क्या-क्या हुआ और किस तरह से उन्होंने हमें उठाया, कितनी दफा किस-किस प्रकार की तकलीफें उन्होंने उठाई, कितनी दफे वह जेलखाने में गए और कितनी दफे उपवास किया, यह सब आज ख्याल आता है। कितने धीरज से वे तकलीफें उठाते रहे और आखिर आजादी के सब दरवाजे पार कर हमें उन्होंने आजादी दिलवाई।

02 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के तट के पास एक तेल टैंकर में आग लगने से, जबकि दो अन्य भारतीय नाविकों की हालत गंभीर है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास हुए इस हादसे के बाद से कुछ नाविक लापता भी बताए जा रहे हैं।

ब्रेक्जिट से भारत को नफा के साथ नुकसान भी

ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलगाव वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाला होगा। यह प्रभाव फिलहाल सैद्धांतिक होगा और इसके व्यावहारिक असर का बड़े पैमाने पर दिखने का अंदेशा कम ही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को यह कई तरह से प्रभावित करेगा। वहीं भारत के संदर्भ में यह अच्छे-बुरे दोनों ही तरह के प्रभावों को लेकर आएगा।

नहीं बदलेंगी ये चीजें

ब्रिटेन या यूरोपीय संघ के नागरिकों को करीब से प्रभावित करने वाली ज्यादातर चीजों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सामान्य रूप से व्यवसायों का संचालन किया जाएगा। इसका अर्थ है कि एक उपभोक्ता के रूप में कोई प्रभावित नहीं होगा। अलगाव की प्रक्रिया के दौरान यूरोप में आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। दोनों जगहों के लोग आराम से आवागमन कर सकेंगे।

सैद्धांतिक ज्यादा, व्यावहारिक कम

ब्रेक्जिट का असर व्यावहारिक कम और सैद्धांतिक ज्यादा है।

बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन

ब्रिटेन यूरोपीय संघ को छोड़ सकता है, लेकिन वह यूरोपीय संघ के सभी कानूनों और यूरोपीय अदालतों के आदेशों का पालन जारी रखेगा। आगामी महीनों में यह यूरोपीय संघ के बजट में अपने योगदान को जारी रखेगा। साथ ही यूरोपीय संघ के कानून में किसी भी बदलाव का पालन भी करेगा। इससे साफ है कि यह बदलाव सैद्धांतिक ज्यादा है और व्यावहारिक कम। ब्रिटेन यूरोपीय संघ के संस्थानों में कोई सार्थक प्रतिनिधित्व नहीं करेगा और अब यूरोपीय संघ के नेताओं की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होगा।

ब्रेक्जिट : यूरोपीय संघ ने क्या गंवाया

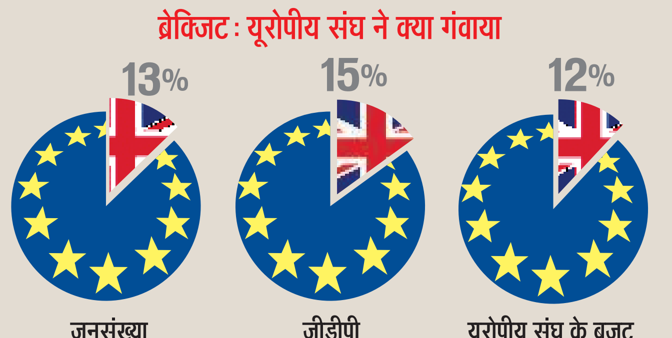

दुनिया पर असर

- निर्यात प्रभुत्व रखने वाले देश प्रभावित हो सकते हैं, चाहे ब्रिटेन को निर्यात हो या न हो। वहीं ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारिक सहयोगी होने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।
- ब्रिटेन का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी होने के कारण अमेरिका को ब्रेक्जिट का सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है।
- ब्रेक्जिट से एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव दीर्घकालिक होने की संभावना नहीं है। हालांकि जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं का व्यापार प्रभावित हो सकता है।

भारत पर नकारात्मक असर

- विदेशी पूंजी निकलने और डॉलर की कीमत बढ़ने से रुपये की कीमत गिर सकती है।
- अल्पावधि में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट आ सकती है।
- पौंड का गिरता मूल्य कई मौजूदा अनुबंधों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है।
- यदि दुनिया यह धारणा बनाती है कि भारत में निवेश जोखिम भरा है तो विदेशी पूंजी के बाहर जाने की आशंका है।
- देश के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर अल्पकाल में नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- कई भारतीय कंपनियां लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और कई का लंदन में यूरोपीय मुख्यालय है। ब्रिटेन इसका फायदा उठाएगा।
- पौंड स्टर्लिंग की कीमतों में गिरावट के कारण ब्रिटेन से होने वाले भारतीय निर्यात को नुकसान होगा।

भारत पर सकारात्मक असर

- कई विशेषज्ञ यह सोचते हैं कि ब्रिटेन की मुद्रा का कमजोर होना अच्छी खबर हो सकती है।
- भारत के एक निर्यातक देश की तुलना में अधिक आयात करने वाला देश होने के चलते इसका प्रभाव भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है।
- पौंड के कम मूल्य के साथ भारतीय कंपनियां कई हाइटेक संपत्ति हासिल करने में सक्षम हो सकती हैं।
- दुनिया भर के निवेशक अशांत समय में सुरक्षित ठिकाने ढूंढते हैं। ऐसे में भारत स्थिरता और विकास दोनों के लिए मुफीद हो सकता है।
- भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंधों को ब्रेक्जिट बढ़ावा दे सकता है।
- अब ब्रिटेन भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए स्वतंत्र होगा।
- पौंड स्टर्लिंग के मूल्य में गिरावट के कारण, यूके से आयात करने वालों को लाभ होगा। ब्रिटेन में सक्रिय भारतीय निर्यात कंपनियों को भी लाभ हो सकता है।

कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित

वायरस का प्रकोप ▶ चीन में जान गंवाने वालों की संख्या 200 के पार, दस हजार संक्रमित

मध्य चीन के वुहान शहर से अब तक 23 देशों में फैल चुकी है यह महामारी

बीजिंग, एजेंसियां : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन से पूरी दुनिया में फैल रहे कोरोना वायरस पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। महामारी का केंद्र माने जा रहे मध्य चीन के वुहान शहर से 23 देशों में वायरस पहुंच चुका है। चीन में इस रहस्यमय वायरस से मरने वालों की संख्या 213 हो गई है। जान गंवाने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग बताए जा रहे हैं। संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर दस हजार के करीब पहुंच गया है।

जेनेवा में गुरुवार को बैठक के बाद डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के प्रकोप को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। इस कदम से वायरस से मुकाबले में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ जाएगा। जबकि चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा, 'सरकार जिम्मेदारी के साथ रोकथाम के व्यापक उपाय अपना रही है। हमें पूरा यकीन है कि हम इस महामारी के खिलाफ जंग जीत लेंगे।'

चार्टर्ड विमानों से निकाले जाएंगे विदेशी : चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'वुहान समेत हुबेई प्रांत में फंसे विदेशी नागरिकों को चार्टर्ड विमानों से उनके देश भेजा जाएगा।' वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में कई विदेशी एयरलाइंस ने चीन की उड़ानें बंद कर दी हैं। इसी के मद्देनजर चीन ने यह एलान किया है।

अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया आगाह : अमेरिका ने चीन की यात्रा करने को लेकर अपने नागरिकों को आगाह किया है। विदेश विभाग ने एक एडवाइजरी में कहा, 'कोरोना वायरस के चलते चीन की यात्रा ना करें।'

चीन के हुबेई प्रांत के सर्वाधिक प्रभावित वुहान शहर में कोरोना वायरस से पीड़ितों का इलाज करने के लिए बनाए जा रहे अस्पताल का काम अंतिम चरण में है। 1000 बेड के इस अस्पताल के निर्माण में हजारों की संख्या में इंजीनियरों और कामगारों की टीमें जुटी हुई हैं। रायटर

इंडोनेशिया में 40 हजार से ज्यादा श्रमिक कैद

जकार्ता, एएफपी : इंडोनेशिया में कोरोना वायरस को लेकर इस कदर भय का माहौल बन गया है कि चीन नियंत्रित एक औद्योगिक परिसर में करीब 43 हजार श्रमिकों को बंद कर दिया गया है। पीटी इंडोनेशिया मोरोवाली इंडस्ट्रियल पार्क ने सुलावेसी द्वीप पर स्थित अपने निकल माइनिंग हब को सील कर दिया है। स्टाफ बगैर अनुमति परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे। वहां करीब पांच हजार चीनी श्रमिक भी हैं। यह परिसर पांच हजार एकड़ में फैला है।

चीन से लोगों को लाने के लिए भारत ने भेजा बोइंग

- एयर इंडिया के 423 सीटर विमान में डॉक्टर और जरूरी दवाइयां भी
- लगभग 400 लोगों को लेकर शनिवार तड़के लौट आएगा विमान

नई दिल्ली, एजेंसियां : कोरोना वायरस की चपेट में आए चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के 423 सीटर बोइंग 747 विमान को भेजा गया है। लगभग 400 भारतीयों को लेकर यह जंबो विमान शनिवार तड़के वापस भी आ जाएगा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से फोन पर बात की और भारतीयों की वापस में सहयोग के लिए उनका आभार जताया।

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट से यह विमान दोपहर एक बजकर 20 मिनट पर उड़ा। पहले इसे साढ़े बारह बजे ही उड़ना था, लेकिन कुछ औपचारिकताओं के पूरा नहीं होने से उड़ान में देरी हो गई।

इस विमान के रवाना होने के बाद एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि वुहान से और भारतीय नागरिकों को लाने के लिए शनिवार को भी एक विमान भेजा जा सकता है। शुक्रवार को भेजे गए विमान के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि इसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पांच डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ भी है। इसके अलावा विमान में जरूरी दवाइयां, मास्क, ओवरकोट, डिब्बा बंद भोजन के पैकेट भी रखे गए हैं। इस विमान में इंजीनियरों और सुरक्षाकर्मियों की टीमें भी हैं। इस पूरे बचाव अभियान का नेतृत्व एयर इंडिया के निदेशक (ऑपरेशन) कैप्टन अमिताभ सिंह कर रहे हैं। विमान में चालक दल के पांच और 15 केबिन क्रू के सदस्य हैं।

एयर इंडिया के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने कहा कि विमान में किसी तरह की सर्विस नहीं प्रदान की जाएगी। खाने के पैकेट सभी सीट के पॉकेट में रख दिए जाएंगे। केबिन क्रू और यात्रियों के बीच किसी तरह की बातचीत भी नहीं होगी। चालक दल और अन्य सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए गए हैं। यह विमान वुहान एयरपोर्ट पर मुश्किल से दो से तीन घंटे ही रहेगा।

केरल की पीड़िता को मेडिकल कॉलेज में भेजा गया : कोरोना वायरस से पीड़ित केरल की छात्रा को त्रिशूर में सरकारी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यह छात्रा वुहान विश्वविद्यालय में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। केरल सरकार ने उन परिवारों से शादी समारोह जैसे आयोजन टालने को कहा है, जिनका कोई सदस्य चीन से लौटा है।

अपने छात्रों को नहीं निकालेगा पाकिस्तान

इस्लामाबाद, आइएएनएस : दुनिया के कई देश जहां चीन के वुहान शहर से अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि वह अपने नागरिकों को नहीं निकालेगा। इनमें ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। वुहान के विश्वविद्यालयों में करीब 500 पाकिस्तानी छात्र पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के अनुसार, प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सहायक जफर मिर्जा ने कहा, 'हमारा मानना है कि यह हमारे सदाबहार मित्र चीन के हित में है। यह दुनिया, क्षेत्र और मुल्क के व्यापक हित में है और हम उन्हें नहीं निकालेंगे।'

हालात पर नियंत्रण के लिए लागू होता है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल (ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी) घोषित कर दी है। आइए जानते हैं कि यह अंतरराष्ट्रीय संगठन किन हालातों में इस स्थिति की घोषणा करती है?

घोषणा की वजह

जब दुनिया में किसी बीमारी के चलते ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके चलते दूसरे देशों के नागरिकों में इसके संक्रमित होने की आशंका बढ़ जाती है तो आपातकाल की घोषणा की जाती है।

पूर्व की घोषणाएं

- **स्वाइन फ्लू, 2009 :** एन1एच1 वायरस 2009 में विश्व भर में फैला। करीब दो लाख की मौत हुई थी।
- **पोलियो, 2014 :** 2012 में पोलियो खत्म होने के करीब था लेकिन अचानक 2013 में इसके पीड़ितों की संख्या में तेज इजाफा हुआ।
- **जीका, 2016 :** अमेरिका में जीका वायरस से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ी।

इबोला 2014, 2019

इबोला वायरस के चलते पहली बार स्वास्थ्य आपातकाल 2014 से 2016 के बीच घोषित किया गया। इस दौरान पश्चिमी अफ्रीका में इससे ग्यारह हजार लोगों की मौत हो गई। दूसरी बार बीते साल भी आपातकाल घोषित किया गया।

घोषणा के मायने

- दुनियाभर के देशों को मिलकर उस बीमारी से बचाव और उसे फैलने से रोकने के उपाय करने होते हैं।
- इसके लिए डब्ल्यूएचओ के पास आकस्मिक फंड होता है, जिसका इस्तेमाल प्रभावित इलाकों में किया जाता है। फिलहाल कोरोना वायरस से निपटने के लिए 18 लाख डॉलर का फंड है।
- मल्टी डायरेक्शनल रिस्पॉन्स के जरिए संक्रामक बीमारियों को फैलने से रोका जाता है।
- डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइन में सफर को लेकर नियम कायदे भी शामिल हैं। हालांकि इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाता।
- प्रभावित इलाकों के बॉर्डर एरिया और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है ताकि वायरस के असर वाले लोगों की पहचान करके उनके अलग रहने की व्यवस्था की जाए।
- डब्ल्यूएचओ के सभी 196 सदस्य देश प्रोटोकॉल और गाइडलाइन को फॉलो करते हैं।

चीन से आने वाले भारतीयों के लिए आइसोलेशन सेंटर तैयार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना से प्रभावित चीन से लाए जाने वाले भारतीयों को कुछ दिनों तक अलग-थलग रखने (आइसोलेशन सेंटर) के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आइटीबीपी ने छावला कैंप में 600 बिस्तरों और सेना ने मानेसर में 300 विस्तरों का आइसोलेशन सेंटर बनाया है। यहां लोगों को 14 दिनों तक विशेषज्ञ डाक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। इसके अलावा सफदरजंग अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट तैयार है।

ब्रिटेन ने आधी रात ईयू को कहा बाय

यूरोपीय यूनियन के साथ खत्म हुई 47 साल पुरानी एकजुटता

लंदन, एजेंसियां : ब्रिटेन आधी रात को औपचारिक तौर पर यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग हो गया। इसके साथ ही ईयू सदस्य देशों के साथ उसकी 47 साल पुरानी आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी एकजुटता खत्म हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन के इस कदम से उसकी किस्मत और समृद्धि नया आकार लेगी। वह विभिन्न देशों से अपने संबंधों को नई दिशा देगा।

ब्रिटेन 1973 में यूरोपीय यूनियन से जुड़ा था। 28 देशों के इस समूह से अलग होने के लिए वर्ष 2016 में ब्रेक्जिट पर जनमत संग्रह कराया गया था। जनमत संग्रह पर जनता की मुहर के बावजूद ब्रिटेन को ईयू से अलग होने में करीब 43 महीने का वक्त लग गया। संसद के गतिरोध के कारण तीन बार ब्रेक्जिट की समय सीमा बढ़ाई गई। संसद से प्रस्ताव पारित नहीं होने पर पिछले साल कंजरवेटिव नेता टेरीजा मे को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए।

ब्रेक्जिट पर संसद में गतिरोध बरकरार रहने पर जॉनसन ने गत 12 दिसंबर को मध्यावधि चुनाव कराया था। इसमें उनकी कंजरवेटिव पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता बचाने में सफल रही। चुनाव जीतने के बाद जॉनसन ने कहा था, हमें नया जनादेश मिल गया है। ब्रिटेन 31 जनवरी को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा।

अलगाव की पूरी प्रक्रिया में लगेगा एक साल : ईयू से ब्रिटेन के अलग होने की पूरी प्रक्रिया में एक साल का वक्त लगेगा। प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वह ईयू का सदस्य बना रहेगा, लेकिन उसे प्रतिनिधित्व और मतदान का अधिकार नहीं होगा। इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष अपने भावी संबंधों की रूपरेखा को अंतिम रुप देंगे। ब्रिटेन ने कहा है कि वह ईयू के साथ एक फरवरी से कारोबारी वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है।

ब्रिटेन के ईयू से आधिकारिक रूप से अलग होने का जश्न लंदन में कुछ यूं मनाया गया। एपी

> यह एक ऐसा पल है, जब नई सुबह हुई और एक कानून से पर्दा उठने जा रहा है। यह क्षण सही मायने में देश के पुन:स्थापना और बदलाव का है। सरकार के तौर पर हमारा काम इस देश को मिलकर आगे ले जाने का है।
> – बोरिस जॉनसन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री

ईयू को आर्थिक नुकसान : ब्रिटेन के अलग होने से ईयू को आर्थिक तौर पर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसकी अर्थव्यवस्था में 15 फीसद की कमी आ जाएगी। इसकी वजह यह है कि लंदन को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक राजधानी माना जाता है।

ब्रिटेन में कहीं खुशी कहीं गम : ईयू से अलगाव पर ब्रिटेन में खुशी और गम, दोनों ही तरह का माहौल दिखा। कई समर्थक ब्रेक्जिट को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर देख रहे हैं तो विरोधी इसे मूर्खता मान रहे हैं। उनकी दलील है कि इससे पश्चिम कमजोर पड़ जाएगा।

भारत-ब्रिटिश संबंधों को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद : ब्रिटेन के प्रमुख कारोबारी संगठन और भारतीय उद्योगपतियों को उम्मीद है कि भारत और ब्रिटेन के कारोबारी और आर्थिक संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। कोबरा बीयर के संस्थापक और कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष लॉर्ड करण बिलिमोरिया ने कहा, 'इसमें कोई साझीदार होगा।' हिंदुजा ग्रुप के सह अध्यक्ष जीपी हिंदुजा ने कहा कि दोनों देशों में मुक्त कारोबार समझौता समेत कई संभावनाएं हैं।

कारोबार समझौते पर आयरलैंड के पीएम ने जताई आशंका : आयरलैंड के प्रधानमंत्री लिओ वाराडकर ने शुक्रवार का यह आशंका जताई, 'आने वाले समय में अगर ब्रिटेन और ईयू के बीच कारोबार समझौता नहीं हो पाया तो यह हमारे लिए खतरा हो सकता है।' आयरलैंड की सीमाएं ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड से लगती हैं। इस साल के आखिर तक होने वाले कारोबार समझौते का उस पर सीधा असर पड़ेगा।

ब्रिटिश अखबारों में छाया रहा ब्रेक्जिट : एएफपी के मुताबिक ब्रिटेन में शुक्रवार को प्रकाशित अखबारों में ब्रेक्जिट पर खबरें छाई रहीं। अखबारों के पहले पेज पर खुशी और मलाल दोनों देखने को मिला। यूरोपीय यूनियन से अलगाव के समर्थक अखबार डेली एक्सप्रेस ने पहले पेज पर 'हां, हमने कर दिखाया' शीर्षक से खबर प्रकाशित की।

ब्रेक्जिट का सफर

- 23 जून, 2016 को कराए गए जनमत संग्रह में 52 फीसद ने इसके पक्ष में वोट दिए
- 27 मार्च, 2017 को ब्रिटिश सरकार ने ईयू से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की
- ईयू से ब्रिटेन के अलग होने की पहली समयसीमा 29 मार्च, 2019 से बढ़ाकर 12 अप्रैल, 2019 की गई
- तीसरी बार समयसीमा 31 अक्टूबर और फिर 31 जनवरी, 2020 की गई
- 23 जनवरी को ब्रिटिश संसद और 29 जनवरी को ईयू संसद ने समझौते पर मुहर लगाई

'हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रमुख रणनीतिक भूमिका'

- अमेरिका ने कहा, क्षेत्र के सकारात्मक विकास के लिए यह जरूरी
- हमारी रणनीति का आधार आजादी और खुलेपन पर आधारित है

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका की हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह रणनीति दोनों देश मिलकर कानून के पालन, समुद्री मार्ग पर बेरोक-टोक आवागमन और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग पर आधारित है। इन बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच कोई मतभेद नहीं है। हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोच को सार्वजनिक करते हुए यह बात अमेरिका के मध्य एशिया मामलों में उप मंत्री जोनाथन हेनिक ने कही।

हेनिक ने कहा, अमेरिका की रणनीति का आधार आजादी और खुलेपन पर आधारित है। इन्हीं बिंदुओं पर चलते हुए वह साझेदारी को मजबूत करता है। भारत के साथ भी इसी आधार पर अमेरिका का सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। अमेरिका क्षेत्र में सुरक्षा, कानून के राज, संप्रभुता के सम्मान, समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता, खुली बाजार नीति, बेहतर शासन, पारदर्शी और लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने में सहयोग देना चाहता है। अमेरिका क्षेत्र में निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले विकास का पक्षधर है। अमेरिका और भारत का सहयोग इन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। नवंबर 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर अपनी सोच जता दी थी। कुछ लोगों में यह भ्रांति है कि अमेरिका क्षेत्र के कुछ देशों को कमजोर करना चाहता है या उन्हें तोड़ना चाहता है। यह सोच पूरी तरह से गलत है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका रणनीतिक रूप से भारत की बड़ी और प्रमुख भूमिका का पक्षधर है।

भारत, अमेरिका और दुनिया के अन्य शक्तिशाली देश बातचीत कर हिंद-प्रशांत महासागर में अबाधित आवागमन को सुनिश्चित करने में लगे हैं। इस सिलसिले में हम अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ आने का आह्वान करते हैं। इससे पूरे क्षेत्र का विकास संभव होगा। चीन की बढ़ती सैन्य ताकत इस मार्ग में बाधा खड़ी करने की कोशिश कर रही है। इसलिए यह एकजुटता जरूरी हो गई है।

आइएसआइ ने सिख आतंकी धड़ों को ड्रग्स तस्करी में झोंका

लाहौर, एएनआइ : आइएसआइ ने पाकिस्तान स्थित सिख आतंकी संगठनों के प्रमुखों को अब मादक पदार्थों की तस्करी के काम में लगा दिया है। हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इन संगठनों के बीच ना केवल प्रतिद्वंद्विता चल रही है बल्कि पाक की खुफिया एजेंसी आइएसआइ का संरक्षण प्राप्त करने के लिए ये संगठन भारत में हेरोइन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में एक-दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लगे हैं।

जून, 2019 में भारत के कस्टम विभाग ने मादक पदार्थों की सबसे बड़ी खेप (532 किलोग्राम हेरोइन) पकड़ी थी। इसे अटारी सीमा से एक ट्रक में पाकिस्तान में तस्करी कर भारत लाया गया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मादक पदार्थों की बरामदगी को नार्को आतंकवाद का मामला करार दिया था। यह पाकिस्तान स्थित सिख आतंकवादी समूहों के बीच प्रतिद्वंद्विता का ही नतीजा था कि 27 जनवरी को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के शीर्ष नेता हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी पीएचडी की लाहौर के डेरा चहल गुरुद्वारा में एक स्थानीय गिरोह ने हत्या कर दी गई थी।

पाकिस्तान ने कहा, गुलाम कश्मीर को मुल्क में मिलाने का प्रस्ताव नहीं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गुलाम कश्मीर को मुल्क में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पाकिस्तान के अखबार 'द डॉन' के मुताबिक पिछले छह सप्ताह से गुलाम कश्मीर के मुल्क में विलय की अटकलें चल रही हैं। इसकी शुरुआत फारुक हैदर खान की उस टिप्पणी के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गुलाम कश्मीर के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे। इन अफवाहों को तब और बल मिला जब गुलाम कश्मीर में मौजूद नौकरशाहों से जुड़े सेवा समूह में एक का नाम बदला गया।

गुलाम कश्मीर के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारुकी ने गुरुवार को कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने उन खबरों को भी खारिज किया, जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, गिलगिट-बाल्टिस्तान की स्थिति को बदलने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रहा है।

पीएम इमरान का वेतन चार गुना करने की खबर का सरकार ने किया खंडन

कराची, प्रेट्र : बदहाल अर्थव्यवस्था से गुजर रहे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान का वेतन चार गुना किए जाने की खबर ने हंगामा मचा दिया है। मीडिया में आ रही ऐसी खबरों का खंडन करते हुए शुक्रवार को सरकार की तरफ से इसे पूरी तरह निराधार बताया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, ऐसी बेबुनियाद खबरों को प्रसारित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इमरान खान का वेतन दो लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा रहा है। इमरान ने हाल में कहा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर मिल रहे वेतन से उनका पूरा खर्च नहीं चल पाता।

बिजनेसमैन पर्नास के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और वीडियो जारी

- फ्लोरिडा स्थित राष्ट्रपति के निजी क्लब मार-ए-लागो का है वीडियो

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की सुनवाई के दौरान उनके और बिजनेसमैन लेव पर्नास की नजदीकी का एक और वीडियो गुरुवार को सामने आया। एक सप्ताह में जारी किया गया यह दूसरा वीडियो है जो ट्रंप के उस दावे के विपरीत है जिसमें उनका कहना था कि वह पर्नास को नहीं जानते हैं। पर्नास का दावा है कि उन्होंने ही ट्रंप के राजनीतिक विरोधियों की जांच के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था। ट्रंप के वकील रूड गुलियानी के पूर्व सहयोगी पर्नास और उनके व्यापारिक साझीदार इगोर फ्रूमैन को पिछले साल साजिश, झूठे बयान और फर्जी रिकॉर्ड बनाने के आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

पर्नास के वकील जोसेफ बांडी ने गुरुवार को यह वीडियो जारी किया। 37 मिनट का यह वीडियो फ्लोरिडा स्थित राष्ट्रपति के निजी क्लब मार-ए-लागो का है। 20 अप्रैल, 2018 के इस वीडियो में रिपब्लिकन पार्टी को चंदा देने वाले लोग शामिल हैं। वीडियो में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के साथ अपनी नजदीकी दिखाने के लिए पर्नास ने यह वीडियो स्वयं बनाया है। नए वीडियो पर फिलहाल व्हाइट हाउस से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पर्नास ने जांच समिति को टैक्सट मैसेज और अन्य दस्तावेज सौंपे हैं, जिसमें 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के संभावित उम्मीदवार जो बिडेन के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच खोलने की बात कही गई है।

चुनावों की रेटिंग के बारे में बात करते दिख रहे ट्रंप : एक सेलफोन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में ट्रंप चुनावों की रेटिंग के बारे में बात करते दिखते हैं। इस दौरान वह यह भी कहते हैं कि सैन्य जनरल उन्हें यह बताने में असमर्थ हैं कि सीरिया और लीबिया में तेल की बिक्री के पैसे कहां जा रहे हैं। पर्नास बुधवार को कैपिटल हिल स्थित संसद पहुंचे थे और महाभियोग सुनवाई में गवाह के रूप में पेश होने की अनुमति मांगी थी। लेकिन कोर्ट के आदेश पर पहनाए गए मॉनीटर के चलते उन्हें प्रवेश देने से इन्कार कर दिया गया।

पिछले शनिवार को भी जारी किया गया था वीडियो : बांडी ने पिछले शनिवार को भी एक वीडियो जारी किया था। 30 अप्रैल, 2018 के उस वीडियो में बिजनेसमैन पर्नास के साथ डिनर के दौरान ट्रंप यूक्रेन पर चर्चा करते दिखते हैं। वह आदेश देते हैं कि यूक्रेन के तत्कालीन राजदूत मैरी योवनोविच को निकाल दिया जाए।

जंगल में आग के कारण ऑस्ट्रेलियाई राजधानी में आपातकाल लागू

ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनबरा के पास दक्षिण में लगी आग के कारण यहां आपातकाल घोषित कर दिया गया है। इस वक्त राजधानी के पास करीब 21500 हेक्टेयर वन क्षेत्र में आग लगी है। एपी

कैनबरा, आइएएनएस : जंगलों में लगी आग के खतरे के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वर्ष 2003 के बाद यह पहला मौका है जब राजधानी में जंगल की आग के कारण आपातकाल लगाया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र (एसीटी) के सीएम एंड्रयू बार ने शुक्रवार को आपातकाल की घोषणा करते हुए बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान और तेज हवाओं के कारण जंगलों की आग से कैनबरा के दक्षिणी उपनगरीय इलाके को खतरा बढ़ गया है। आपातकाल के तहत राजधानी वासियों को आगाह किया गया है कि वे किसी भी संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयार रहें। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में गत सितंबर से आग लगी है। इस आग की चपेट में आकर अब तक 33 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लाखों हेक्टेयर वनक्षेत्र तबाह हो चुका है।

ये भी जानिए

पिछले छह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले जो न्यूजीलैंड की टीम ने खेले हैं, उनमें न्यूजीलैंड की टीम तीन में हारी है, जबकि तीन मैच टाई रहे हैं। टाई हुए तीनों मैचों में उन्हें सुपर ओवर में हार मिली है।

न्यूजीलैंड और सुपर ओवर में 36 का आंकड़ा

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी बार सुपर ओवर में किया पराजित

चौथे टी-20 मुकाबले में टिम सेफर्ट को रन आउट करने के बाद जश्न मनाते शार्दुल ठाकुर और विराट कोहली ● एएफपी

स्कोर बोर्ड

टॉस : न्यूजीलैंड (गेंदबाजी) — मैन ऑफ द मैच : शार्दुल ठाकुर

भारत 165/8 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
लोकेश राहुल का. सेंटनर बो. सोढ़ी	39	26	03	02
सैमसन का. सेंटनर बो. कुगलेइजन	08	05	00	01
विराट कोहली का. सेंटनर बो. बेनेट	11	09	02	00
श्रेयस अय्यर का. सेफर्ट बो. सोढ़ी	01	07	00	00
शिवम दुबे का. ब्रूस बो. सोढ़ी	12	09	02	00
मनीष पांडे नाबाद	50	36	03	00
वाशिंगटन सुंदर बो. सेंटनर	00	03	00	00
शार्दुल ठाकुर का. साउथी बो. बेनेट	20	15	02	00
चहल का. सेफर्ट बो. साउथी	01	02	00	00
नवदीप सैनी नाबाद	11	09	02	00

अतिरिक्त : (बा-2, लेबा-3, नोबॉ-1, वा-6) 12, **कुल :** 20 ओवर में आठ विकेट पर 165 रन, **विकेट पतन :** 1-14 (संजू सैमसन, 1.3), 2-48 (कोहली, 4.3), 3-52 (अय्यर, 6.3), 4-75 (राहुल, 8.4), 5-84 (दुबे, 10.2), 6-88 (सुंदर, 11.3), 7-131 (ठाकुर, 16.3), 8-143 (चहल, 17.5)

गेंदबाजी : साउथी 4-0-28-1, स्कॉट कुगलेइजन 4-0-39-1, मिशेल सेंटनर 4-0-26-1, हैमिश बेनेट 4-0-41-2, ईश सोढ़ी 4-0-26-3

न्यूजीलैंड 165/7 (20 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मार्टिन गुप्टिल का. राहुल बो. बुमराह	04	08	00	00
कोलिन मुनरो रन आउट	64	47	06	03
टिम सेफर्ट रन आउट	57	39	04	03
टॉम ब्रूस बो. चहल	00	03	00	00
रॉस टेलर का. अय्यर बो. ठाकुर	24	18	02	00
डैरेल मिशेल का. दुबे बो. ठाकुर	04	03	01	00
मिशेल सेंटनर रन आउट	02	02	00	00
स्कॉट कुगलेइजन नाबाद	00	00	00	00

अतिरिक्त : (लेबा-7, वा-3) 10, **कुल :** 20 ओवर में सात विकेट पर 165 रन, **विकेट पतन :** 1-22 (गुप्टिल, 4.2), 2-96 (मुनरो, 11.4), 3-97 (ब्रूस, 12.1), 4-159 (टेलर, 19.1), 5-163 (सेफर्ट, 19.3), 6-164 (मिशेल, 19.5), 7-165 (सेंटनर, 19.6)

गेंदबाजी : शार्दुल ठाकुर 4-0-33-2, नवदीप सैनी 4-0-29-0, जसप्रीत बुमराह 4-0-20-1, युजवेंद्र सिंह चहल 4-0-38-1, वाशिंगटन सुंदर 2-0-24-0, शिवम दुबे 2-0-14-0

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : सुपर ओवर में चौकों-छक्कों के आधार पर विश्व कप फाइनल गंवाने वाली न्यूजीलैंड की टीम का सुपर ओवर से 36 का आंकड़ा अभी भी जारी है। इस टीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक आठ बार सुपर ओवर खेला है जिसमें उसे सात बार हार मिली है। एक बार वनडे में ऐसा हुआ है जबकि छह बार टी-20 में उसे सुपर ओवर में पराजय का सामना करना पड़ा है।

लगातार हार : बेचैन न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में शुक्रवार को एक बार फिर हाथ में आया मैच निकाल दिया। लगातार दूसरी बार सुपर ओवर में पहुंचे चौथे मुकाबले को भारतीय टीम ने जीतकर पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 4-0 की बढ़त बना ली। आखिरी मुकाबला रविवार को खेला माउंट मोंगानुई में खेला जाएगा जाएगा। न्यूजीलैंड को आखिरी के दो ओवरों में 11 रनों की दरकार थी और उसके हाथ में सात विकेट बचे थे लेकिन मेजबान टीम ने एक बार फिर खुद को गड्ढे में धकेल दिया और हैमिल्टन के बाद यहां भी मैच सुपर ओवर में पहुंचा दिया। इसके बाद सुपर ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने न्यूजीलैंड छह गेंद में मात्र 13 रन ही बना पाया, जिसे भारतीय टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। केएल राहुल ने पहली दो गेंद पर ही 10 रन बनाकर मैच को भारत के पक्ष में ला दिया था। तीसरी गेंद पर राहुल आउट हुए और इसके बाद विराट कोहली व संजू सैमसन ने भारत को जीत दिलाई।

पांडेय जी का पचासा : यह लगातार चौथा मौका था जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। कंधे की चोट के कारण नियमित कप्तान केन विलियमसन इस मुकाबले में नहीं उतरे। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का फैसला किया था। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन मनीष पांडे ने टीम को खुद की अहमियत बताते हुए 35 गेंद में नाबाद 50 रन बनाए। पांडे की पारी से भारतीय टीम आठ विकेट पर 165 रन बनाने में कामयाब रही। भारतीय टीम ने 12 ओवर तक छह विकेट 88 रनों पर ही खो दिए थे लेकिन मनीष ने उपयोगिता साबित की।

> **18** टी-20 मुकाबलों में मनीष पांडे टीम इंडिया का हिस्सा रहे हैं। इन सभी मुकाबलों में भारतीय टीम एक भी मैच नहीं हारी है

उस बार शमी तो इस बार शार्दुल : बुधवार को तीसरे मुकाबले में मुहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी। इस बार यह कार्य शमी की जगह शार्दुल ठाकुर ने किया, जिन्होंने आखिरी ओवर में मात्र छह रन दिए। भारतीय टीम ने चौथे मुकाबले में रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और शमी को आराम दिया, जिनकी जगह संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को मौका मिला, लेकिन तीनों ही खिलाड़ी छाप छोड़ने में नाकाम रहे। नवदीप ने जरूर 19वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए दो चौके लगाए।

मेजबानों की मुश्किल : भारतीय टीम का यह स्कोर बल्लेबाजी की मददगार पिच पर काफी नहीं था, लेकिन मेजबान टीम ने मैच को खुद ही मुश्किल बना दिया। जहां वह अच्छी स्थिति से दबाव में पहुंच गए। कोलिन मुनरो (64) और टिम सेफर्ट (57) की आकर्षक पारियां पानी में बह गईं। 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने मार्टिन गुप्टिल का विकेट जल्दी खो दिया, लेकिन मुनरो और सेफर्ट ने दूसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी करके मैच को न्यूजीलैंड की पकड़ में ला दिया। मुनरो ने 38 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। मुनरो को कोहली ने बढ़िया तरीके से रन आउट किया। शार्दुल ने बाउंड्री के पास से थ्रो फेंका जो कवर पर खड़े विराट के हाथों में आया। इस बीच न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ चुके थे। विराट ने बल्लेबाज छोर की तरफ सीधा थ्रो फेंककर मुनरो को रनआउट कर दिया। न्यूजीलैंड लगातार अंतराल पर विकेट गंवा रहा था। युजवेंद्र सिंह चहल ने टॉम ब्रूस (00) को चलता किया, लेकिन सेफर्ट को इसके बाद रॉस टेलर के रूप में साथी मिला और दोनों ने टीम को 18 ओवर तक 150 रनों तक पहुंचा दिया।

शार्दुल का कमाल का ओवर : न्यूजीलैंड को अंतिम 18 गेंद में 18 रनों की दरकार थी। जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर में छह रन दिए तो नवदीप सैनी ने 19वें ओवर में चार रन खर्च किए। अब बारी थी शार्दुल की। उन्होंने पहली ही गेंद पर रॉस टेलर को कैच आउट कराया। दो गेंद के बाद सेफर्ट रन आउट हुए। डेरेल मिशेल (04) अगली गेंद पर कैच आउट हुए।

सुपर ओवर में ये हुआ

न्यूजीलैंड 13/1

01 बुमराह ने सेफर्ट को फुल लेंथ गेंद फेंकी। सेफर्ट ने लेग साइड की तरफ शॉट खेला, लेकिन श्रेयस अय्यर मुश्किल कैच को नहीं पकड़ सके। सेफर्ट दो रन बनाने में कामयाब रहे।

02 बुमराह की गेंद पर सेफर्ट ने कवर ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ा।

03 बुमराह ने सेफर्ट को छोटी गेंद फेंकी। गेंद बल्लेबाज का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट के पीछे की तरफ हवा में उछली। विकेटकीपर केएल राहुल पीछे की तरफ दौड़े लेकिन काफी प्रयास के बावजूद यह मुश्किल कैच नहीं पकड़ सके और दो रन आए।

04 बुमराह की छोटी गेंद को सेफर्ट ने लेग साइड बाउंड्री की तरफ उछाला, लेकिन वहां खड़े वाशिंगटन सुंदर ने कैच पकड़ लिया।

05 बुमराह ने एक बार फिर कोलिन मुनरो को छोटी गेंद की। इस बार यह रणनीति काम नही आई और मुनरो ने बैकवर्ड प्वाइंट पर कट के जरिये चार रन हासिल किए।

06 मुनरो स्कूप शॉट को आजमाने में सफल नहीं हुए और गेंद शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े नवदीप सैनी के हाथ में पहुंची। मुनरो एक रन निकालने में कामयाब रहे।

भारत 16/1

01 टिम साउथी ने केएल राहुल को विकेटों में गेंद फेंकी, लेकिन राहुल ने मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया।

02 राहुल ने पुल शॉट के जरिये स्कवायर लेग पर चौका लगा दिया।

03 राहुल ने डीप मिडविकेट की तरफ मारा लेकिन वहां खड़े स्कॉट कुगलेइजन ने कैच पकड़ लिया।

04 एक और छोटी गेंद। कोहली चालाकी से दो रन चुराने में कामयाब रहे।

05 गुड लेंथ गेंद पर विराट ने डीप मिडविकेट और लांग ऑन के बीच से चौका लगाया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सुपर ओवर में न्यूजीलैंड

बनाम	फॉर्मेट	स्थल	वर्ष	टीम-1	टीम-2	नतीजा
इंग्लैंड	वनडे	लॉर्ड्स	2019	इंग्लैंड (15/1)	न्यूजीलैंड (15/1)	बाउंड्री के नियम से इंग्लैंड विश्व चैंपियन
वेस्टइंडीज	टी-20	ऑकलैंड	2008	वेस्टइंडीज (25/1)	न्यूजीलैंड (15/2)	हार
ऑस्ट्रेलिया	टी-20	क्राइस्टचर्च	2008	न्यूजीलैंड (9/0)	ऑस्ट्रेलिया (6/1)	जीत
श्रीलंका	टी-20	पल्लेकल	2012	श्रीलंका (13/1)	न्यूजीलैंड (7/1)	हार
वेस्टइंडीज	टी-20	पल्लेकल	2012	वेस्टइंडीज (19/0)	न्यूजीलैंड (17/0)	हार
इंग्लैंड	टी-20	ऑकलैंड	2019	इंग्लैंड (17/0)	न्यूजीलैंड (8/1)	हार
भारत	टी-20	ऑकलैंड	2020	न्यूजीलैंड (17/0)	भारत (20/0)	हार
भारत	टी-20	वेलिंगटन	2020	न्यूजीलैंड (13/1)	भारत (16/1)	हार

04 मुकाबले इस सीरीज के खेलने से पहले विराट कोहली का टी-20 में बल्लेबाज औसत 52.72 था, लेकिन अब यह घटकर 50.80 का हो गया है

17 टी-20 विकेट सोढ़ी भारत के खिलाफ ले चुके हैं। यह किसी भी कीवी गेंदबाज के किसी टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट हैं

सुपर ओवर में साउथी का संकट

06,06,06

... ये आंकड़ा सुपर ओवर में साउथी का है। पिछले सुपर ओवर की आखिरी दो गेंदों पर साउथी ने दो छक्के खाए थे जबकि शुक्रवार को चौथे टी-20 में सुपर ओवर फेंकने उतरे इस कीवी गेंदबाज की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने छक्का मारा।

भारत के खिलाफ चौथे टी-20 मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज साउथी ● एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : टिम साउथी, सुपर ओवर और हार का चोली-दामन का साथ है। न्यूजीलैंड ने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आठ सुपर ओवर खेले हैं जिसमें उसे सात में हार मिली है। वनडे विश्व कप में सुपर ओवर ट्रेंट बोल्ट ने फेंका था जबकि सात में से छह टी-20 मुकाबलों में साउथी ने सुपर ओवर फेंका। इसमें साउथी एक बार ही अपनी टीम को जीत दिला सके।

अगर वर्तमान टी-20 सीरीज की बात करें तो अब तक हो चुके चार मैचों में से दो मुकाबले सुपर ओवर में गए और दोनों में ही जसप्रीत बुमराह ने भारत की ओर से और साउथी ने न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की। इन दोनों में भारत जीता। हैमिल्टन में सुपर ओवर में मिली हार के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन थे और वेलिंगटन में शुक्रवार को हुए मैच में टिम साउथी ही कप्तान थे। पिछले मैच में आखिरी दो गेंदों पर रोहित शर्मा से दो छक्के खाने के बावजूद उन्होंने इस मैच में भी सुपर ओवर फेंका और पहली दो गेंदों पर एक चौका व एक छक्का खाकर मैच हाथ से निकाल दिया।

सुपर ओवर में टिम साउथी का प्रदर्शन

28 फरवरी 2010
न्यूजीलैंड vs ऑस्ट्रेलिया (क्राइस्टचर्च)
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 214 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने भी चार विकेट पर 214 रन बनाए। सुपर ओवर में साउथी ने सिर्फ छह रन दिए। न्यूजीलैंड ने तीसरी ही गेंद पर मैच जीत लिया।

27 सितंबर 2012
न्यूजीलैंड vs श्रीलंका (पल्लेकल)
विश्व टी-20 के मैच में न्यूजीलैंड को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों ने निर्धारित 20 ओवरों में 174 रन बनाए। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए और न्यूजीलैंड सिर्फ सात रन बना सकी।

01 अक्टूबर 2012
न्यूजीलैंड vs वेस्टइंडीज (पल्लेकल)
श्रीलंका के खिलाफ चार दिन बाद ही न्यूजीलैंड की टीम ने एक बार फिर सुपर ओवर खेला। इस बार सामने थी वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज की टीम 139 रन पर आउट हो गई। वहीं जवाब में न्यूजीलैंड ने सात विकेट पर 139 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 रन बनाए। वहीं जवाब में न्यूजीलैंड की टीम आखिरी गेंद तक मजबूत थी। आखिरी गेंद पर वेस्टइंडीज को जीतने के लिए पांच रन चाहिए थे। साउथी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर सैमुअल ने वेस्टइंडीज को जीत दिलाई।

10 नवंबर 2019
न्यूजीलैंड vs इंग्लैंड (ऑकलैंड)
11 ओवर के मैच में न्यूजीलैंड ने 145 रन बनाए। इंग्लैड ने यही स्कोर बनाया। साउथी के सुपर ओवर में इंग्लैंड ने 17 रन बनाए। मॉर्गन और बेयरस्टो ने उनकी गेंद पर छक्के लगाए। न्यूजीलैंड आठ ही रन बना सका।

29 जनवरी 2020
न्यूजीलैंड vs भारत (हैमिल्टन)
भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने 179 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने बुमराह के सुपर ओवर में 17 रन बनाए और साउथी के ओवर में दो छक्के लगाकर रोहित ने भारत को जीत दिला दी।

31 जनवरी 2020
न्यूजीलैंड vs भारत (वेलिंगटन)
भारत और न्यूजीलैंड हैमिल्टन में सुपर ओवर मुकाबला खेला था। उस मैच में भारत की ओर से रोहित शर्मा ने लगातार दो छक्के लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। शुक्रवार को भारतीय टीम ने 165 का स्कोर बचाया बल्कि सुपर ओवर में मिले 14 रनों के लक्ष्य को भी साउथी की पांच गेंदों में ही हासिल कर लिया।

सुपर ओवर ने मुझे शांतचित रहना सिखाया : कोहली

वेलिंगटन, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शुक्रवार को कहा कि पिछले दो मैचों में मैंने नई सीख ली, जब विरोधी टीम अच्छा खेल रही हो तो आखिर तक शांत बने रहना और वापसी की कोशिश करना।

भारतीय कप्तान ने कहा कि लगातार दो सुपर ओवर में जीत दर्ज करने से टीम के जज्बे का पता चलता है। हम इससे अधिक रोमांचक मैचों की उम्मीद नहीं कर सकते। हमने इससे पहले सुपर ओवर नहीं खेले थे और अब हमने दो में जीत दर्ज की। संजू सैमसन मैच में खास योगदान नहीं दे पाए लेकिन कोहली ने कहा कि एक समय वह केएल राहुल के साथ उन्हें सुपर ओवर के लिए भेजने की सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरू में हम सैमसन और केएल को सुपर ओवर में भेजने की सोच रहे थे, लेकिन तब केएल ने कहा कि मुझे बल्लेबाजी करनी चाहिए। कोहली ने युवा तेज गेंदबाज नवदीप सैनी की भी तारीफ की जो शुक्रवार को विकेट नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि सैनी ने अपनी तेजी से फिर प्रभावित किया। हमने जिस तरह का खेल दिखाया उस पर हमें गर्व है।

मुनरो बोले, भाग्य हमारे साथ नहीं था : न्यूजीलैंड ने फिर से जीत की स्थिति में होने के बावजूद मैच गंवाया लेकिन सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने भारत को जीत का श्रेय दिया और कहा कि भारत हमेशा वापसी का मौका बना लेता है। मुनरो ने कहा कि यही क्रिकेट है। हमने दोनों मैचों में खुद को जीत की स्थिति में रखा था लेकिन भारतीय टीम इस समय बेहतरीन फॉर्म में है और जिस तरह का क्रिकेट वह खेल रही है वह हमेशा वापसी का रास्ता निकाल लेती है। सुपर ओवर में भाग्य की भी बात होती है। यह किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। हमने दो मैच अपने हाथों से गंवा दिए। कुछ खिलाड़ी वास्तव में आहत हैं लेकिन हमारी टीम मजबूत है और हम वापसी करेंगे। उम्मीद है कि रविवार को हम जीत दर्ज करेंगे। मुनरो ने कहा कि उन्हें जो लक्ष्य मिला था उससे वह खुश थे।

पांडे बोले, हमारी कोशिश 5-0 से सीरीज जीतने की होगी

रन लेते मनीष पांडेय ● एएफपी

वेलिंगटन : मध्यक्रम के बल्लेबाज मनीष पांडे ने कहा कि हम सिर्फ इन दो मैचों में नहीं किसी भी मैच में आखिरी गेंद तक हार नहीं मानेंगे। अगर आप इस मानसिकता से खेलेंगे तो आपको इस तरह के सुपर ओवर वाले मैच मिलेंगे और आपके पास वहां से जीतने का मौका होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास सीरीज को 5-0 से जीतने का मौका है और ऐसा करना बेहद ही शानदार होगा। पांचवें मैच में हमारी कोशिश यही होगी। किसी भी टीम ने इससे पहले ऐसा नहीं किया है। मुझे लगता है इसकी शुरुआत करना शानदार होगा। पांडे से जब पूछा गया कि क्या खिलाड़ियों को इस बात का भरोसा था कि वे एक बार फिर सुपर ओवर में जीतेंगे तो उन्होंने कहा कि बीच के ओवरों में लगा कि मैच हमारे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन पिछले मैच में हम ऐसा करने में सफल रहे थे जिससे हमारा विश्वास और बढ़ा कि हम मैच को सुपर ओवर तक लेकर जा सकते हैं।

मेंडिस ने श्रीलंका को हार से बचाया

हरारे, आइएएनएस : श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने नाबाद 116 रनों की पारी खेलते हुए यहां हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जिंबाब्वे को ड्रॉ खेलने पर मजबूर कर दिया। जिंबाब्वे ने श्रीलंका के सामने 361 रनों का लक्ष्य रखा। जिंबाब्वे ने जिस तरह से श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पहली पारी में 293 रनों पर ही रोका था, उससे लगा था कि मेजबान टीम मैच अपने नाम कर सकती है लेकिन मेंडिस ने इस पर पानी फेर दिया। श्रीलंका ने मैच के आखिरी दिन शुक्रवार को तीन विकेट के नुकसान पर 204 रनों बनाकर मैच को ड्रॉ पर समाप्त किया।

जिंबाब्वे ने दिन की शुरुआत सात विकेट के नुकसान पर 241 रनों के साथ की थी। छह रन बनाकर ही उसने अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। पहली पारी में मेजबान टीम ने 406 रन बनाए थे और श्रीलंका को पहली पारी में बड़ा स्कोर न कर दे पाने के कारण वह दूसरी पारी में 113 रनों की बढ़त के साथ उतरी थी और इसी कारण श्रीलंका के सामने उसने बड़ा स्कोर किया। विशाल लक्ष्य के सामने श्रीलंका की कोशिश अपने विकेट बचाए रखते हुए मैच ड्रॉ कराने की थी। 26 रनों पर दिमुथ करुणारत्ने (12) का विकेट खोने के बाद टीम दबाव में थी, लेकिन विश्वा फर्नांडो और मेंडिस ने उसे बचा लिया। एंजेलो मैथ्यूज 13 रन बनाकर आउट हुए।

इकबाल कासिम पीसीबी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने

कराची, प्रेट्र : बायें हाथ के पूर्व स्पिनर इकबाल कासिम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की प्रभावशाली क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कासिम ने 50 टेस्ट खेले है और वह पहले टीम के मुख्य चयनकर्ता भी रह चुके है। इस समिति में पूर्व कप्तान वसीम अकरम, पूर्व टेस्ट खिलाड़ी उमर गुल, अली नकवी और महिला टीम की पूर्व कप्तान एवं मौजूदा मुख्य चयनकर्ता उरूज मुमताज शामिल है। पीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) वसीम खान और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संचालन के निदेशक जाकिर खान इस समिति के सह-सदस्य हैं। पीसीबी ने कहा कि समिति बोर्ड के अध्यक्ष अहसान मनी को क्रिकेट से जुड़े मामलों पर सलाह देगी, जिसमें राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के प्रदर्शन और उनके प्रबंधन, घरेलू क्रिकेट संरचना, उच्च प्रदर्शन केंद्र और खेल की स्थिति शामिल हैं। सीईओ वसीम खान ने कहा कि ये सदस्य खेल के प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधि हैं। वे हमारी नीति के अनुरूप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जो पीसीबी प्रबंधन को पाकिस्तान में खेल में सुधार करने में मदद करेंगे।

हमने अंत तक उम्मीद बनाए रखना सीखा है : ठाकुर

वेलिंगटन, प्रेट्र : भारत की चौथे टी-20 में जीत में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की अहम भूमिका रही। उन्होंने 20वें ओवर में न्यूजीलैंड को दो सेट बल्लेबाजों के रहने के बाद भी उसे जरूरी सात रन नहीं बनाने दिए।

ठाकुर को इसी कारण मैन ऑफ द मैच चुना गया। ठाकुर ने कहा कि उनकी टीम ने पिछले मैच से सीखा था कि उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और यही चौथे मैच में किया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के बाद ठाकुर ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। हम इसी तरह के रोचक मुकाबलों के लिए खेलते हैं। पिछले दो मैचों में हम इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते थे। पिछले मैच से हमने सीखा था कि उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिलने से काफी फायदा हुआ क्योंकि इससे वो दबाव में बिखर गए।

ठाकुर ने अहम समय पर बल्ले से भी योगदान दिया और 15 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए। इस पर ठाकुर ने कहा कि मैंने बल्ले से अच्छा योगदान दिया जिससे टीम को मदद मिली, लेकिन मुझे और खेलना चाहिए था। उम्मीद है कि अगले मैच में ऐसा कर सकूं।

मेसी के 500

फुटबॉल
- कोपा डे रे में लेगानेस को 5-0 से दी शिकस्त
- ग्रीजमैन, लेंगलेट और मेलो ने भी दागे गोल

मैड्रिड, एएफपी : लियोन मेसी (59वें व 89वें मिनट) के दो गोल की बदौलत बार्सिलोना ने लेगानेस को 5-0 से हराकर कोपा डे रे के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। यह लियोन मेसी की मौजूदगी में बार्सिलोना की 500वीं जीत है। स्पेनिश फुटबॉल के इतिहास में 500 जीत दर्ज करने वाले मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 32 साल के मेसी ने जीत का यह आंकड़ा 710वें मैच में हासिल किया।

कैंप नाउ स्टेडियम में मिली इस जीत में मेसी के दो गोल के अलावा एंटोनी ग्रीजमैन (चौथे मिनट), क्लेमेंट लेंगलेट (27वें मिनट) और आर्थर मेलो (77वें मिनट) ने भी बार्सिलोना के लिए गोल दागे। वेलेंसिया के खिलाफ शनिवार को ला लीगा में मिली हार के बाद बार्सिलोना ने इस जीत के साथ शानदार वापसी की। बार्सिलोना की यह जीत उसके नए मैनेजर क्विकी सेतियान के आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी। सेतियान ने कहा, 'हमने बहुत सारी चीजें अच्छी कीं, लेकिन मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूं, क्योंकि हमने पहले हाफ के अंतिम चरण में खेल पर से नियंत्रण खो दिया।' मेस्टाला में वेलेंसिया के खिलाफ मिली हार की वजह से बार्सिलोना और रीयल मैड्रिड के बीच तीन अंकों का अंतर हो गया था, जिससे रीयल मैड्रिड लीग में शीर्ष पर पहुंच गया था। इस वजह से सेतियान पर भी दबाव था, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में अर्नेस्टो वलवेरदे की जगह बार्सिलोना के मैनेजर का कार्यभार संभाला था। उनकी नियुक्ति का आकलन इस सत्र में लीग और चैंपियंस लीग में में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, लेकिन बार्सिलोना का कोपा डे रे में हाल का इतिहास काफी शानदार रहा है, जहां उसने पिछले पांच साल में चार बार खिताब जीता है। तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद बार्सिलोना अब अंतिम-आठ में पहुंचने में सफल रहा है, जहां रीयल मैड्रिड, वेलेंसिया, रीयल सोसिएयाद, ग्रेनाडा, विलारीयल और एथलेटिक बिल्बाओ पहले ही जगह बना चुके हैं।

मैच के दौरान गेंद पर काबू पाने का प्रयास करते लियोन मेसी। रायटर

ग्रीजमैन ने खेल शुरू होने के चार मिनट बाद ही पहला गोल कर बार्सिलोना का खाता खोला। 27वें मिनट में मेसी के कॉर्नर पर लेंगलेट ने गोल कर बार्सिलोना को 2-0 से आगे कर दिया। 59वें मिनट में मेसी ने अपना पहला और बार्सिलोना की ओर से तीसरा गोल किया और फिर मेलो ने भी गोल दागकर मैच में अपना खाता खोला। हालांकि, लेगानेस की हार तय हो चुकी थी, लेकिन मैच खत्म होने से पहले मेसी ने इस मैच में अपना दूसरा, सत्र का अपना 19वां और सेतियान के बार्सिलोना से जुड़ने के बाद तीसरा गोल किया।

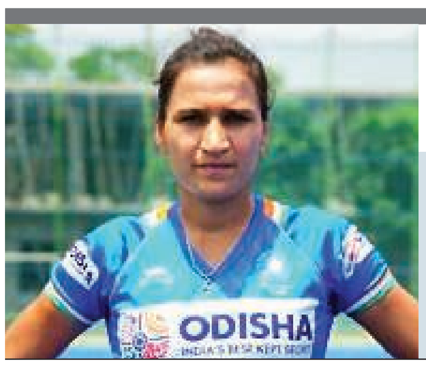

साई ने दी रानी रामपाल को पदोन्नति

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को विश्व गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुने जाने के सम्मान में उन्हें समय से पहले प्रोन्नति देने की घोषणा की। साई के साथ 2015 में सहायक कोच के तौर पर जुड़ने वाली रानी को तत्काल प्रभाव से कोच (लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति दी गई है।

मुझे लगता है कि भारतीय तेज गेंदबाज मुहम्मद शमी इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज हैं।
– **शोएब अख्तर, पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज**

थिएम पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में

टेनिस ▶ डोमिनिक ने चार सेटों तक चले मुकाबले में एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया

अब खिताबी मुकाबले में होगा जोकोविक से सामना

मेलबर्न, रायटर : नई पीढ़ी के बीच के मुकाबले में डोमिनिक थिएम ने शुक्रवार को एलेक्जेंडर ज्वेरेव को 3-6, 6-4, 7-6, 7-6 से हराकर पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बनाई, जहां उनका सामना मेलबर्न पार्क के जादूगर नोवाक जोकोविक से होगा। रोड लेवर एरिना में यह एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबला था जिसमें बारिश ने भी बाधा डाली, लाइट भी गुल हुई और कई नाटकीय घटनाएं हुईं, लेकिन पांचवीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के थिएम ने सुस्त शुरुआत की, लेकिन अहम मौकों पर उन्होंने बहादुरी भरा प्रदर्शन किया।

उन्होंने निर्णायक मुकाबले में तीन मैच प्वाइंट जुटाने और फिर क्रॉस कोर्ट वॉली के साथ अपने तीसरे ग्रैंडस्लैम फाइनल में प्रवेश किया। वह अपने पिछले दो फ्रेंच ओपन के फाइनल में राफेल नडाल से हार गए थे। हालांकि, यहां उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नडाल को बाहर का रास्ता दिखाया था।

थिएम ने कहा, 'आज हम दोनों ही जीत सकते थे। शायद मेरे पास थोड़ा अनुभव है, थोड़ा सा कुछ और। वह सिर्फ 22 साल का है और वह अपने पहले ग्रैंडस्लैम फाइनल में जगह बनाने से ज्यादा दूर नहीं है। यह एक आश्चर्यजनक मैच था, एक बार फिर से दो टाईब्रेक, दोनों काफी मुश्किल और काफी करीबी। उसे हराना लगभग असंभव सा था।' पुरुषों के ग्रैंडस्लैम में कई वर्षों से बिग थ्री का दबदबा रहा है, जिसमें जोकोविक, नडाल और रोजर फेडरर शामिल हैं। अब थिएम इस खिताब को जीतकर ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले ऐसे पहले व्यक्ति बनना चाहेंगे, जिसका जन्म पिछली सदी के अंतिम दशक में हुआ।

ये दोनों खिलाड़ी मेलबर्न में अपने पहले फाइनल में पहुंचने के लिए उत्सुक थे और दोनों ही शुरुआत में कुछ नर्वस थे और बारिश के खेल में कुछ देर की बाधा डालने से पहले दोनों ने मैच में अपनी शुरुआती सर्विस गंवा दी। खेल दोबारा शुरू हुआ तो ज्वेरेव ने पहला सेट अपने नाम कर लिया। हालांकि, थिएम ने वापसी की और दूसरे सेट के तीसरे गेम को लगातार डबल फाल्ट के साथ जीता। इसके बाद थिएम अपनी सर्विस गंवा बैठे और फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी रैलियां देखने को मिलीं। आखिरकार थिएम ने 5-3 की बढ़त बनाई और फिर दूसरा सेट थिएम ने अपने नाम कर लिया।

तीसरे सेट में जब ज्वेरेव 1-0 से आगे थे तो मैच को लाइट गुल होने की वजह से दूसरी बार रोका गया और करीब सात मिनट तक खेल रुका रहा। खेल जब दोबारा शुरू हुआ तो थिएम ने बैकहैंड के जरिये ज्वेरेव को जाल में फंसाया और अपनी सर्विस वापस हासिल की। उन्होंने इस ज्वेरेव को कोर्ट पर चारों ओर दौड़ाया, लेकिन इस जर्मन खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। थिएम को अपनी सर्विस गंवानी पड़ी, जिसके बाद ज्वेरेव ने कुछ बेहतरीन खेल दिखाया और सेट ट्राइब्रेक में चला गया।

एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराने के बाद जश्न मनाते डोमिनिक थिएम। एपी

म्लादेनोविक-बाबोस की जोड़ी ने जीता महिला डबल्स खिताब

मेलबर्न, एएफपी : फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक और हंगरी की टिमिया बाबोस ने शीर्ष वरीयता प्राप्त सियेह सू वेइ और बारबरा स्ट्राइकोवा को हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स खिताब जीत लिया। दोनों ने विंबलडन चैंपियन जोड़ी को एक घंटे 12 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-1 से मात दी। यह उनका साथ में तीसरा ग्रैंडस्लैम खिताब और ओवरऑल 10वां खिताब है। पिछले साल इन दोनों की जोड़ी फाइनल में सैम स्टोसुर और झांग शुआइ से हार गई थीं।

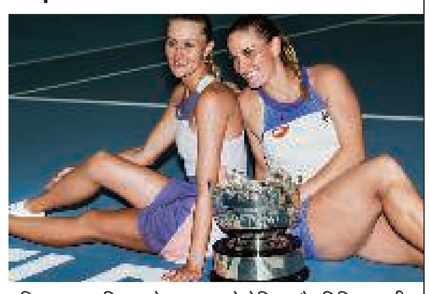

महिला डबल्स खिताब के साथ म्लादेनोविक और टिमिया। एपी

मुगुरुजा को हराकर केनिन बन सकती हैं जाइंट किलर

मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स फाइनल में गैरवरीय गार्बाइन मुगुरुजा का सामना सोफिया केनिन से होगा और टूर्नामेंट से पहले सेरेना विलियम्स को प्रबल दावेदार मान रहे टेनिस प्रेमियों ने इस फाइनल की कल्पना भी नहीं की होगी। उलटफेरों से भरे टूर्नामेंट में 21 वर्ष की केनिन अगर स्पेन की मुगुरुजा को हरा देती हैं तो 'जाइंट किलर' साबित होंगी। ऐसा करने पर वह सेरेना को पछाड़कर अमेरिका की नंबर एक खिलाड़ी भी बन जाएंगी। अमेरिका की 38 साल की सेरेना ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंडस्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी से एक खिताब दूर हैं। उन्हें तीसरे दौर में चीन की वांग कियांग ने हराया। गत चैंपियन नाओमी ओसाका भी तीसरे चरण में 15 साल की कोको गॉफ से हार गई थीं। गॉफ को अमेरिका की केनिन ने मात दी। शीर्ष-10 में से छह खिलाड़ी तीसरे दौर में ही हार गए, जिससे लग रहा था कि दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी एश्ले बार्टी की राह आसान हो गई है। मास्को में जन्मी 14वीं वरीयता प्राप्त केनिन ने सेमीफाइनल में उसे हराया। वह हार भी जाती हैं तो भी विश्व रैंकिंग में नौवें स्थान पर पहुंच जाएंगी। मुगुरुजा को हराने पर वह सेरेना को पछाड़कर रैंकिंग में सातवें स्थान पर आ जाएंगी। दोनों के बीच चाइना ओपन में पिछला मुकाबला केनिन ने जीता था।

आग पीड़ितों की मदद के लिए मैच में खेलेंगे दिग्गज ब्रायन लारा

सिडनी, प्रेट्र : वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के पीड़ितों की मदद के लिए खेले जाने वाले चैरिटी मैच में भाग लेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट डाट कॉम डाट एयू के मुताबिक वेस्टइंडीज के लिए 131 टेस्ट में 52.89 की औसत से 11953 रन बनाने वाले इस खिलाडी ने मैच में भाग लेने की पुष्टि की है। इससे पहले 2011 में भारत को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले युवराज सिंह और पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी इस मैच में खेलने की पुष्टि कर चुके हैं।

मैच को 'बुशफायर क्रिकेट बैश' का नाम दिया गया है जो आठ फरवरी को खेला जाएगा। दान के लिए इसी दिन कॉमनवेल्थ बैंक महिला त्रिकोणीय सीरीज का टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा, जबकि बिग बैश लीग का फाइनल की राशि भी आग पीड़ितों को दी जाएगी। भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के महान गेंदबाज कर्टनी वॉल्श स्टार से सुसज्जित रिकी पोंटिंग एकादश और शेन वार्न एकादश के कोच होंगे। ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के पूर्व खिलाड़ी एंड्रयू साइमंड्स, ब्रैंड हैडिन और माइक हसी भी इस मुहिम में जुड़ गए हैं जिसमें पूर्व सितारे पोंटिंग, वार्न, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेट ली, लैंगर, माइकल क्लार्क, शेन वॉटसन और एलेक्स ब्लैकवेल शामिल हैं। स्टीव वॉ और मेल जोंस भी इस मुहिम में शामिल होंगे।

अंडर-19 विश्व कप सेमीफाइनल में भारत के सामने होगा पाकिस्तान

बेनोनी, प्रेट्र : मुहम्मद हुरेरा के अर्धशतक और गेंदबाजों के मिश्रित योगदान की बदौलत पाकिस्तान ने यहां शुक्रवार को अफगानिस्तान को छह विकेट से हराकर अंडर-19 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। पाक का अब सेमीफाइनल में सामना भारतीय टीम से होगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। दोनों टीमों के बीच यह कांटे का मुकाबला चार फरवरी को खेला जाएगा। अफगानिस्तान ने 189 का स्कोर खड़ा करने के बाद भी चुनौती पेश की, लेकिन बोर्ड पर ज्यादा स्कोर नहीं होने और हुरेरा की जबरदस्त पारी की वजह से वे यह मैच जीत नहीं सके। हुरेरा के अलावा कासिम अकरम के नाबाद 25 और मुहम्मद हैरिस के नाबाद 29 रनों की बदौलत पाक ने 41.1 ओवर में ही जीत दर्ज कर ली।

रोमांचक जंग

पाकिस्तान के कप्तान रोहेल नजीर ने कहा कि हमने दो-तीन कैच शुरुआत में टपका दिए थे। हम अफगानिस्तान को जल्द समेटना चाहते थे। स्पिनरों ने हमारे लिए काफी अच्छा काम किया, जिसकी वजह हम अफगानिस्तान को 190 के अंदर सिमटने में सफल रहे।

डोप परीक्षण में नाकाम पहलवान रविंदर प्रतिबंधित

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले साल अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहलवान रविंदर कुमार को प्रतिबंधित दवाई के सेवन का दोषी पाया गया है जिसके लिए उन पर चार साल का प्रतिबंध लगाया गया है। उनका विश्व चैंपियनशिप में जीता गया पदक भी छीना जा सकता है क्योंकि नाडा के डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल ने उन सभी प्रतियोगिताओं में रविंदर के परिणाम हटाने के निर्देश दिए हैं जिनमें नमूना एकत्रित किए जाने के बाद इस पहलवान ने हिस्सा लिया था। रविंदर का नमूना पिछले साल फरवरी मार्च में जयपुर में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान लिया गया था। नाडा ने उन्हें पिछले साल 14 मई से अस्थायी निलंबित किया था।

आरपी, मदन और सुलक्षणा की सीएसी चुनेगी चयनकर्ता

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▶ एक साल का होगा क्रिकेट सलाहकार समिति का कार्यकाल

▶ दो चयनकर्ताओं को चुनने की होगी सबसे पहली जिम्मेदारी

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज रुद्र प्रताप सिंह, 1983 विश्व कप टीम के सदस्य मदन लाल और महिला क्रिकेटर सुलक्षणा नायक को बीसीसीआइ ने शुक्रवार को क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का सदस्य घोषित किया। सीएसी का सबसे पहला काम मौजूदा चयनकर्ता एमएसके प्रसाद और गगन खोड़ा का स्थानापन्न चुनना होगा।

बीसीसीआइ सचिव जय शाह के अनुसार सीएसी सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। सीएसी राष्ट्रीय टीमों के कोच को भी नियुक्त करेगी। पिछले वर्ष अक्टूबर में हितों के टकराव के आरोप लगने के बाद कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। पहले गौतम गंभीर का सीएसी सदस्य बनना तय माना जा रहा था, लेकिन गंभीर संसद के सदस्य हैं जिसकी वजह से आरपी के लिए रास्ता खुल गया। उत्तर प्रदेश के 34 वर्षीय गेंदबाज सबसे युवा सीएसी सदस्य हैं। उनके अलावा मदनलाल 68 और नायक 41 वर्षीय हैं। पिछले ही सप्ताह बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गंभीर के स्थानापन्न की बात कही थी, जबकि लाल और नायक का चुना जाना तय था। नए सदस्यों के 23 अक्टूबर को पद संभालने के बाद बीसीसीआइ को सीएसी सदस्य चुनने में तीन महीने का वक्त लग गया। सीएसी का सदस्य बनना एक बड़ा पद है, लेकिन उनका काम सीमित है। हालांकि मदनलाल इस चुनौती के लिए तैयार हैं।

मदनलाल ने कहा कि जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है। आपको अपना काम पूरी गंभीरता के साथ करना होगा। हालांकि उन्होंने अभी साफ नहीं किया कि सीएसी चयनकर्ताओं को चुनने के लिए जोनल पॉलिसी अपनाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं पता है कि जोनल सिस्टम बना रहेगा या नहीं। शुक्रवार को ही मुझे अपने पद की आधिकारिक जानकारी मिली। अगले कुछ दिनों में हमें ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। देव, अंशुमन और रंगास्वामी के इस्तीफा देने से पहले सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर भी सीएसी का हिस्सा थे, लेकिन इन तीनों ने भी हितों के टकराव के आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बीसीसीआइ के मौजूदा संविधान के तहत कोई इंसान एक से ज्यादा पद नहीं संभाल सकता है। पूर्व तेज गेंदबाज मदनलाल ने भारत का 39 टेस्ट और 67 वनडे में प्रतिनिधित्व किया है। 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी लाल हिस्सा रहे हैं। इसके बाद वह भारतीय टीम के कोच बने और सीनियर चयन समिति के सदस्य भी रहे।

विविध

सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित लेखिका डॉ. दलीप का निधन

जासं, पटियाला : देश की दूसरी सरस्वती पुरस्कार प्राप्त लेखिका डॉ. दलीप कौर टीवाणा का मोहाली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। 81 वर्षीय डॉ. टीवाणा 20 दिनों से बीमार चल रही थीं। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पटियाला में होगा। डॉ. टीवाणा के परिवार में पति डॉ. भूपिंदर सिंह और पुत्र इंजीनियर सिरमनजीत सिंह हैं।

लेखिका डॉ. दलीप कौर टीवाणा की फाइल फोटो।

डॉ. टीवाणा के 45 उपन्यास व पांच कहानी संग्रह के अलावा बहुत सी रचनाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई हैं। 1971 में उन्हें उपन्यास 'एहो हमारा जीवन' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह पंजाब साहित्य अकादमी चंडीगढ़ व लुधियाना की अध्यक्ष भी रहीं। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पंजाबी विभाग के प्रोफेसर व भाषा विभाग में डीन रहीं डॉ. टीवाणा को शिक्षा व साहित्य क्षेत्र में अहम योगदान के लिए 2004 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। 2015 में देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल के विरोध में उन्होंने पद्मश्री लौटा दिया था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं के दर्द को दुनिया के सामने रखा।

हस्तशिल्पियों के महाकुंभ के लिए सज गया मेला

सुशील भाटिया, फरीदाबाद

सूरजकुंड मेला प्रांगण एक बार फिर देशी-विदेशी हस्तशिल्पियों की कारीगारी और पर्यटकों के अवलोकन का गवाह बनने को तैयार है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ड्रेस डिजाइनर रितु बेरी के मार्गदर्शन में सजाए गए मेला प्रांगण में शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक से 16 फरवरी तक चलने वाले सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्री और हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट के रूप में मेले का मुख्य आकर्षण होंगे। एक और खास आकर्षण पहली बार किसी यूरोपियन देश का मेले का हिस्सा बनने का है और यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इंग्लैंड को। इंग्लैंड सहित कुल 40 देशों के शिल्पी मेले में भाग ले रहे हैं। पिछली बार यह संख्या 30 थी।

मेला शुभारंभ की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव योगेंद्र त्रिपाठी, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन, हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान और उज्बेकिस्तान के राजदूत फरहाद अरजेव ने मेले की विशेषताओं के बारे में मुख्य चौपाल पर विस्तृत जानकारी दी।

सुबह 11 बजे होगा शुभारंभ : योगेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 1987 में पहली बार शुरू हुए मेले के 34वें संस्करण का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे शुभारंभ करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर, मेजबान हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा व हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर गोलन और विधायक सीमा त्रिखा उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनेंगे।

40 देश बनेंगे हिस्सा : योगेंद्र त्रिपाठी व विजयवर्धन के अनुसार शिल्पमेला पूरे भारत के हजारों शिल्पकारों को अपनी कला और उत्पादों को व्यापक दर्शकों को दिखाने में मदद करता है। मेले के जरिये देश की कभी समृद्ध रही शिल्पकला को पुनर्जीवित करने में भी मदद मिलती है। विजयवर्धन के अनुसार पिछले वर्ष अफ्रीका और एशिया के 30 से अधिक देशों ने मेले में भाग लिया था। इस बार इंग्लैंड के पांच शिल्पी भी भाग लेंगी। इसके लिए सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और ब्रिटिश काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इंग्लैंड सहित 40 देश मेले का हिस्सा होंगे। इसमें पार्टनर कंट्री-उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, मिस्र, इथियोपिया, घाना, कजाकिस्तान, मलावी, नामीबिया, नेपाल, रूस, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, तजाकिस्तान, थाईलैंड, ट्यूनीशिया, तुर्की, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, जिम्बाब्वे आदि हैं।

महकेगा हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत का गुलदस्ता : हिमाचल प्रदेश इस बार थीम राज्य है। इस राज्य के विभिन्न जिलों से कलाकार शिल्प और हस्तशिल्प के माध्यम से अपनी अनूठी संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों कलाकार विभिन्न लोक कलाओं और नृत्यों का प्रदर्शन करेंगे। पारंपरिक नृत्यों और कला रूपों से लेकर व्यंजनों तक, दर्शकों को लुभाने के लिए हिमाचल के कलाकार सांस्कृतिक विरासत का गुलदस्ता लेकर आए हैं। मेले की मानद सलाहकार प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रितु बेरी के सानिध्य में इस बार तीन फैशन शो होंगे, जबकि आम तौर पर एक ही होता है। इसके अलावा पूरे पखवाड़े सांस्कृतिक संध्याओं का शानदार प्रदर्शन दर्शकों को मनोरंजन के लिए आकर्षित करेगा।

सूरजकुंड मेला परिसर में बनाए गए हिंदू आस्था के प्रतीक बनारस के अस्सी घाट की अलौकिक प्रतिकृति का वीडियो बनाता विदेशी पर्यटक। ओम प्रकाश पांचाल

बम धमाकों से थर्राया पटना का अशोक राजपथ

जागरण संवाददाता, पटना

▶ पटना विवि के छात्रों और लालबाग मोहल्ले के लोगों के बीच बमबारी में दारोगा और सिपाही घायल

सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान शुक्रवार देर शाम पटना स्थित अशोक राजपथ गोलियों की तड़तड़ाहट और बम धमाकों से थर्रा उठा। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों और लालबाग मोहल्ले के लोगों के बीच जमकर गोलीबारी व बमबारी हुई। बम धमाके में पीरबहोर थाने के दारोगा मनोज कुमार और पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। उपद्रवियों ने दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ करने के साथ दो कारों को आग के हवाले कर दिया।

बवाल शांत कराने पहुंची पुलिस को भी उपद्रवियों ने खदेड़ दिया। इसके बाद एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ पहुंचे और लाठियां भांजने लगे। भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर उपद्रवियों में भगदड़ मच गई। तीन घंटे बाद बवाल पर काबू पाया गया। हालांकि, तनाव की स्थिति देर रात तक बनी हुई थी। पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी इलाके में कैंप कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, पटना विश्वविद्यालय के मिंटो, नूतन और जैक्सन हॉस्टल के लड़के शुक्रवार की शाम मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए जुलूस की शक्ल में निकले थे। जैसे ही वे विश्वविद्यालय कैंपस से बाहर निकलकर थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि लालबाग मोहल्ले के शरारती तत्वों ने बमबारी और पथराव शुरू कर दिया। जवाब में हॉस्टल के लड़कों ने भी फायरिंग की। इस बीच सैदपुर हॉस्टल के लड़के भी जुलूस लेकर पहुंच गए। सभी लड़के एकजुट होकर स्थानीय लोगों पर टूट पड़े। दोनों ओर से जमकर बमबारी और फायरिंग होने लगी। इस दौरान विसर्जन जुलूस के साथ जा रहे पीरबहोर थाने के दारोगा मनोज कुमार के पास एक धमाका हो गया। बम के छर्रे उनके पैर में लग गए। पथराव में सिपाही का सिर फट गया।

कई थानों की पुलिस पर हमला : वायरलेस पर सूचना पाकर कदमकुआं, सुल्तानगंज और गांधी मैदान की पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने उस पर भी हमला बोल दिया। पुलिस उल्टे पांव लौट गई। आधे घंटे बाद पूरी रणनीति तैयार कर अशोक राजपथ पर फिर पुलिस पहुंची। स्टेट आरएएफ और सैकड़ों जवान गाड़ी से उतरते ही लाठियां भांजने लगे। इसके बाद बवाल शांत हुआ। एक दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है।

उपद्रवियों ने कार में आग लगा दी। प्रेट्र

नए कानून के भय से सूनी किराये की कोख

संदीप पांडेय, लखनऊ

▶ ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलोजी 2020 का तीसरा दिन

▶ नए सरोगेसी बिल को लेकर घबराहट, महिला से करार से कतराए दंपती

देश में नया सेरोगेसी बिल अभी अधर में है, मगर इसका भय साल भर बना रहा। ऐसे में देश-विदेश के दंपतियों ने सरोगेट मदर से किनारा कर लिया। लिहाजा, हजारों किराए की कोख सूनी रह गईं।

लखनऊ में चल रही ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलोजी (एआइसीओजी) 2020 के तीसरे दिन शुक्रवार को सरोगेसी बिल-2019 पर मंथन के दौरान ये बातें सामने आईं। देशभर से आए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) एक्सपर्ट ने केंद्र से बिल में नियमों को शिथिल करने की मांग की। इंडियन सोसाइटी ऑफ थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन की सचिव डॉ. शिवानी सचदेवा गौर ने कहा कि बिल लोकसभा में गत वर्ष पास हुआ। राज्यसभा में पास होकर कानून में तब्दील हो जाएगा। वहीं, सिर्फ लोकसभा से पास होने पर ही देश में गत वर्ष सेरोगेसी मदर-चाइल्ड का ग्राफ काफी घट गया। देशभर के तीन हजार आइवीएफ सेंटरों पर सेरोगेसी मदर-चाइल्ड केयर की सुविधा है। 2018 में इन सेंटरों पर किराए की कोख से वर्षभर में करीब पांच हजार बच्चों का जन्म हुआ। वहीं 2019 में दंपतियों ने सरोगेसी मदर से मुंह फेर लिया। ऐसे में गत वर्ष सिर्फ दो हजार शिशुओं ने ही सरोगेसी मदर से जन्म दिया।

खून के रिश्ते की कोख होगी मान्य

डॉ. शिवानी के मुताबिक नए कानून के मुताबिक जेनेटिक रिलेटिव की ही कोख ली जा सकती है। ऐसे में खून के रिश्ते में कोख मिलना मुश्किल है। परिवार की महिला की घर के सदस्यों के बीच रिश्ते अलग-अलग हैं। ऐसे में मां बनने को तैयार नहीं हो रही हैं। लिहाजा, नियम शिथिल किए जाएं। साथ ही सरोगेसी मदर का शुल्क व केयर को लेकर स्पष्ट कानून बने। इस संबंध में सोसाइटी के सदस्य लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी से वार्ता भी कर चुके हैं।

लोकतंत्र की जीत, 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद किया मतदान

नईदुनिया, रायपुर

छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण में शुक्रवार को मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण के बाद मतदान किया, जोकि लोकतंत्र की जीत को दर्शाता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुरराम सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 75 फीसद मतदान हुआ। अंतिम आंकड़ा शनिवार को जारी किया जाएगा। प्रदेश के नक्सल हिंसा प्रभावित कई इलाकों में वर्ष 2015 में हुए चुनाव की तुलना में इस बार दो गुना से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ पाटन के कुदडीह प्राथमिक शाला स्थित मतदान केंद्र में वोट डाला। उनके साथ बेटी स्मिता बघेल, दिव्या बघेल, दिप्ती बघेल और बेटे चैतन्य बघेल भी वोट डालने पहुंचे।

प्रदेश के दक्षिणी बस्तर के सुरनार क्षेत्र में पिछले चुनाव के 26 प्रतिशत मतदान की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़कर 54 हुआ है। चिकपाल और तुमकपाल में कैंप खोलने के बाद मतदान के प्रतिशत में काफी वृद्धि हुई है। अति संवेदनशील मतदान केंद्र सुरनार में अधिकारियों के समक्ष एक लाख रुपये के इनामी नक्सली सहित 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

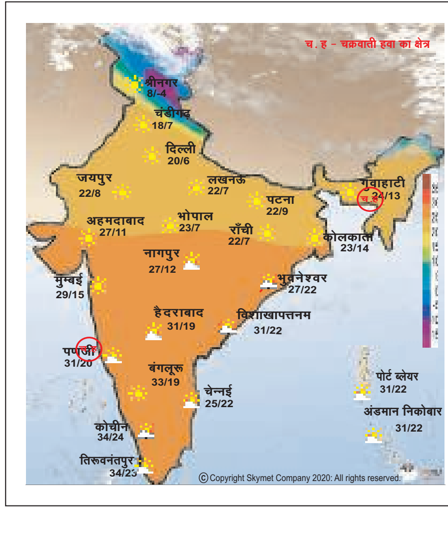

मौसम विशेष

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में आंशिक बादलों के साथ शुष्क मौसम जारी रहेगा। रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन के तापमान में हल्की वृद्धि होगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। ठंडी सुबह में कोहरा व कुहासा रहेगा। दिन चमकीली धुप के साथ सुहावना रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/16/आंबा	अहमदाबाद	29/05/व
कोलकाता	23/13/सा	बड़ौदा	31/09/सा
चेन्नई	33/23/व	नागपुर	28/13/आंबा
हैदराबाद	30/19/सा	इन्दौर	23/11/सा
बंगलूरु	33/19/सा	राँची	23/08/सा
त्रिवेन्द्रम	34/24/सा	पटना	22/08/सा
गुवाहाटी	25/14/आंबा	जमशेदपुर	26/14/आंबा
गंगटोक	14/03/सा	पुणे	32/16/आंबा

देश की सबसे पुरानी जीवन बीमा योजना 1884 में लागू

आज ही के दिन 1884 में डाककर्मियों के लिए डाक जीवन बीमा योजना अस्तित्व में आई। 1888 में टेलीग्राफ कर्मियों को भी शामिल किया गया। 1894 में इसके दायरे में महिलाओं को भी शामिल किया गया। यह देश की सबसे पुरानी जीवन बीमा है।

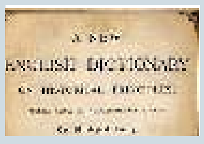

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला संस्करण प्रकाशित

आज ही 1884 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पहले संस्करण का प्रकाशन हुआ। इसमें 352 पेज थे और इसकी 4 हजार कॉपियां प्रकाशित की गई थी। उसी समय से यह विश्व की सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी शब्दकोशों में से एक है। एक बड़ी पुस्तक का यह एक भाग था।

बॉलीवुड के 'हीरो' जैकी श्रॉफ का जन्म

आज ही 1957 में जयकिशन काकूभाई श्रॉफ यानी जैकी श्रॉफ का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्हें स्कूल के एक दोस्त ने जैकी नाम दिया। मॉडलिंग से करियर शुरू करने वाले जैकी ने 1982 में फिल्म स्वामी दादा से आगाज किया। उन्हें वर्ष 1983 में फिल्म हीरो से पहचान मिली। वह अब तक 13 भाषाओं की करीब सवा दो सौ फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। पत्नी के साथ मिलकर जैकी श्रॉफ एंटरटेनमेंट कंपनी शुरू की। उन्हें चार बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ वे अब भी फिल्मों में सक्रिय हैं।

इधर-उधर की

मिनी माउस का गुस्सा

न्यूयॉर्क, एजेंसी : डिज्नी के चरित्र मिकी, मिनी माउस और गूफी की चुहलबाजियों से किसी के चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, ऐसे में इनके द्वारा सड़क पर किसी को पीटते देखना काफी चौंकाने वाला था। यह घटना लास वेगास की है। जहां मिनी माउस के पहनावे में एक महिला ने महिला सुरक्षाकर्मी की पिटाई कर दी। लड़ाई के दौरान मिनी माउस का मास्क गिर जाता है और फिर वह सुरक्षाकर्मी पर ताबड़तोड़ हमला बोल देती है। उन्हें देखकर अच्छे-अच्छे बॉक्सर भी शर्म से पानी-पानी हो जाएं। दो महिलाओं के बीच जारी लड़ाई के दौरान मिकी और गूफी के पहनावे में आए लोग भी उन्हें रोकने में असफल रहे। मिकी को मिनी के शक्तिशाली मुक्कों का शिकार होना पड़ा। बाद में काफी देर बाद मिनी ने महिला सुरक्षाकर्मी को छोड़ा। इसका वीडियो सामने आया है, जिसे सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। जहां पर करीब 36 लाख लोग इस लड़ाई को देख चुके हैं।

शॉर्टवेब रेडियो प्रसारण की आखिरी हिंदी सेवा भी बंद

बीबीसी के शॉर्टवेब रेडियो का प्रसारण 31 जनवरी (शुक्रवार) को बंद कर दिया गया। इसके आखिरी हिंदी कार्यक्रम दिनभर का अंतिम प्रसारण शाम साढ़े सात बजे हुआ। दिनभर कार्यक्रम की शुरुआत और उससे जुड़ी यादों को लेकर सोशल मीडिया और ब्लॉग पर संदेश चलते रहे। किसी ने इसके शुरुआत होने का वो दौर याद किया तो किसी ने कार्यक्रम की प्रमाणिकता के शेर पढ़े। इसके सफर पर एक नजर :

पहला प्रसारण

बीबीसी हिंदुस्तानी सेवा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष बताने के लिए शुरू की गई। 11 मई 1940 को दस मिनट के समाचार बुलेटिन के साथ इस सेवा का पहला प्रसारण हुआ था। जून 1941 में इसको आधा घंटा का स्पेस मिला। जुल्फिकार अली बुखारी इसके पहले संचालक बने जो 1945 तक साथ निभाते रहे। 1947 में विभाजन के बाद, यही बुखारी पाकिस्तान रेडियो के पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए।

लोकप्रियता का चरम था आपातकाल

बीबीसी रेडियो की विश्व सेवा, हिंदी सेवा और उर्दू सेवा का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक तरह से इस पर उसका एकाधिकार रहा है। आपातकाल में इसकी लोकप्रियता चरम पर थी और यही प्रमाणिक खबरों का तमगा हासिल करने की घड़ी थी। इसके सबसे ज्यादा श्रोता भारत और खाड़ी के देशों में रहे हैं।

... इसलिए बंद की गई सेवा

पिछले साल भारत में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस की पहुंच तीन करोड़ से बढ़कर पांच करोड़ हो गई। इस दौरान बीबीसी के श्रोता बड़ी संख्या में शॉर्टवेव रेडियो से डिजिटल और टीवी की ओर चले गए। रेडियो श्रोताओं की लगातार गिरती संख्या को देखते हुए बीबीसी ने हिंदी में शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण समाप्त करने का फैसला किया है।

डिजिटल माध्यम पर रहेंगे ये कार्यक्रम

शॉर्टवेव प्रसारण बंद होने के बावजूद बीबीसी डिजिटल माध्यमों पर अपने कुछ नियमित कार्यक्रम जैसे, विवेचना और दुनिया-जहां डिजिटल ऑडियो के रूप में प्रसारित करता रहेगा।

यहां अब भी बाकी है

बीबीसी रेडियो जापान व चाइना रेडियो इंटरनेशनल से हिंदी व बांग्ला का प्रसारण हो रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत खराब है। ड्यूचे विले व वॉयस ऑफ अमेरिका भी अपना रेडियो प्रसारण बंद कर चुका है।

फोटो न्यूज

पर्यावरण के लिए खतरनाक लेमिनेटिड पोस्टर

बांग्लादेश में होने वाले चुनावों में प्लास्टिक लेमिनेटिड चुनावी पोस्टरों का इस्तेमाल किए जाने से यहां पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा है। यह तस्वीर राजधानी ढाका की है, जहां पूरी सड़क लेमिनेटिड पोस्टरों से अटी पड़ी है। अधिकांश राजनीतिक दल बारिश और धूप से बचाने के लिए पोस्टरों में प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। पर्यावरणविदों का दावा है कि चुनाव के दौरान करीब 306 मिलियन लेमिनेटिड पोस्टरों का इस्तेमाल हुआ, जो खतरनाक स्थिति को दर्शाने के लिए काफी है। इसके खिलाफ देश में आवाज मुखर होने लगी है। एएफपी

'स्किन सेंसर' को बढ़ावा देगी नई बैट्री

तकनीक ▶ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने विकसित की नरम और लचीली बैट्री

अब दिल की धड़कनों की निगरानी करने वाले सेंसर बनाना होगा आसान

नई बैट्री के इस्तेमाल से उपकरणों की उम्र बढ़ सकती है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : वैज्ञानिकों ने एक नरम और लचीली बैट्री विकसित की है, जो पारंपरिक बैटरी में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील घटकों की तुलना में पावर यानी बिजली को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकती है और एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक पर निर्भर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मदद से ऐसे सेंसर विकसित किए जा सकते हैं जो मनुष्य की त्वचा से चिपक कर उनके हृदय की धड़कनों की निगरानी कर सकते हैं।

नेचर कम्युनिकेशन नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, स्मार्टवॉच जैसे पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनाना अब सीमित हो चला है क्योंकि ऐसे ज्यादातर उपकरण अक्सर भारी और ठोस बैट्रियों से चलते हैं। अध्ययन में कहा गया है कि ठोस बैट्रियों के कारण कई बार लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और रासायनिक रिसाव या आग लगने के कारण सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है।

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियर और इस अध्ययन के सह-लेखक जिनान बाव ने कहा, 'अब तक हमारे पास ऐसा कोई स्रोत नहीं था, जिससे ऐसे उपकरण बनाए जा सकें, जो हमारे शरीर में चिपकने के साथ-साथ आसानी से मुड़ सकता हो और जरूरत के हिसाब से खिंच भी सके।'

मोड़ने के बाद भी होता है बिजली का प्रवाह : वर्तमान अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पॉलीमर विकसित किया है जो ठोस होने के साथ-साथ नरम और लचीला है और आसानी से सतह के आकार के मुताबिक मुड़ भी सकता है। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि प्रायोगिक बैट्री की मूल लंबाई को लगभग दो बार मोड़ा (फोल्ड) और आवश्यकता से अधिक खींचा भी जाता है तो भी इसमें निरंतर बिजली का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा कि अगूंठे के नाखून के आकार की इस प्रोटोटाइप बैट्री में ऊर्जा स्टोर करने की क्षमता उतनी ही होती है जितनी एक पारंपरिक बैट्री में होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस डिवाइस के जरिये भविष्य में हम इंसानों के हृदय की धड़कनों को मापने के लिए कर सकते हैं क्योंकि इसे आसानी से किसी भी सतह पर चिपकाया जा सकता है।

ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स

शोधकर्ताओं ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैट्री पॉलीमर का इस्तेमाल इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में करती है। दरअसल, इलेक्ट्रोलाइट्स ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करते हैं और नकारात्मक आयनों को बैटरी के सकारात्मक ध्रुव तक पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स तरल जेल है, जो कुछ मामलों में रिसने के साथ-साथ फट भी सकते हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट बैट्री के ध्रुवों के बीच विद्युत आवेश को वहन करता है।

सस्ता सेटेलाइट लांच व्हीकल बना रहा इसरो

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) देश में 30 से 35 करोड़ रुपये की लागत वाला सस्ता सेटेलाइट लांच व्हीकल तैयार करने के करीब है। इस व्हीकल से 500 किलोग्राम तक का सेटेलाइट कक्षा में भेजा जा सकेगा। इस व्हीकल से पहला सेटेलाइट आगामी मई तक लांच होने की संभावना है।

कम लागत वाले लांच व्हीकल के तैयार होने से इसरो को बड़ा व्यावसायिक फायदा होने की उम्मीद है। इससे वह माइक्रो, मिनी और मीडियम साइज के सेटेलाइट लांच करने वाले व्हीकल के बाजार में काफी आगे निकल जाएगा। यह बात एक समूह चर्चा के दौरान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के उप निदेशक टीवी हरिदास ने कही है।

इसरो की उपलब्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस व्हीकल के उत्पादन का कार्य तीन हफ्तों में शुरू हो जाएगा और उसके बाद के कुछ हफ्तों में यह कार्य करने के लिए प्राप्त हो जाएगा। इसरो की योजना अगले पांच साल में 50 लांच व्हीकल बनाने की है। सरकारी उपक्रम का ठेके पर काम करने का तरीका आश्चर्यजनक रूप से सफल है।

शाकाहार से कम होगा यूटीआइ का खतरा

शोध अनुसंधान

शोधकर्ताओं का कहना है कि शाकाहारी आहार से मूत्रमार्ग में संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआइ) आमतौर पर ई. कोलाई जैसे गट (आंत) बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया मूत्रमार्ग के जरिये शरीर में प्रवेश कर किडनी और मूत्राशय को प्रभावित करता है। पूर्व के अध्ययन से यह जाहिर हो चुका है कि ई. कोलाई का मुख्य स्रोत मीट होता है। लेकिन अभी यह ज्ञात नहीं कि मीट के सेवन में कमी लाने से यूटीआइ का खतरा कम होता है या नहीं। ताइवान के त्यू चाई मेडिकल फाउंडेशन के शोधकर्ताओं ने शाकाहारी खानपान को लेकर नया अध्ययन किया है। मांसाहारी की तुलना में शाकाहारी लोगों में यूटीआइ का खतरा 16 फीसद तक कम पाया गया। यह निष्कर्ष करीब दस हजार प्रतिभागियों पर किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इस दौरान शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि शाकाहारी भोजन करने वालों की तुलना में मांसाहारी लोगों का इम्यून सिस्टम दुरुस्त नहीं था। -आइएएनएस

मीठे भोजन से हो सकता है मसूड़ों में संक्रमण

बहुत ज्यादा मीठा खाने वाले लोग सचेत हो जाएं। इस तरह का खानपान दांतों और मसूड़ों के लिए खतरनाक हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मीठे खाद्य पदार्थों और सॉफ्ट ड्रिंक से दांतों में कैविटी और मसूड़ों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस तरह का खानपान दांत और मसूड़े से संबंधित समस्याओं का कारण बन सकता है। मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन में कमी लाने के साथ ही नियमित तौर पर दांतों की सफाई करने से इन खतरों से बचाव हो सकता है। इसके साथ ही पौष्टिक खानपान की आदत को भी बढ़ावा देना चाहिए। डेनमार्क की आरहूस यूनिवर्सिटी के प्रमुख शोधकर्ता बेंट न्यावाद ने कहा, 'आज के दौर में यह आम सहमति बनती जा रही है कि चीनी के ज्यादा सेवन का संबंध इन समस्याओं से होता है।' -आइएएनएस

★★★

जवानी जानेमन

प्रमुख कलाकार : सैफ अली खान, अलाया एफ, कुमुद मिश्रा, चंकी पांडे
निर्देशक : नितिन कक्कड़
अवधि : दो घंटे

इंसान ताउम्र जवान ही रहना चाहता है। यह संभव नहीं, लिहाजा वह अपनी सोच से खुद को युवा रखता है। वह उम्र को खुद पर हावी नहीं होने देता, मगर आसपास के लोग कड़वी सच्चाई का एहसास करा ही देते हैं। फिल्म में रोमांटिक, आजाद ख्याल और रंगीले मिजाज के जसविंदर सिंह उर्फ जैज की भी यही कहानी है।

जैज पब में डांस करने, लड़कियों के साथ रात बिताने और अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीने में यकीन रखता है। वह अपने बाल भी अलग-अलग रंग में डाई कराता रहता है। हफ्ते में एक बार अपने माता-पिता और भाई के साथ समय व्यतीत करने घर जाता है। बड़े भाई के साथ उसके बिजनेस में हाथ बंटाता है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी 21 साल की बेटी टिया है। यही नहीं, वह अपने ब्वॉयफ्रेंड से गर्भवती भी है। टिया जैज को अपना पिता होने के संबंध में बताती है कि इसके तीन विकल्प हैं। 33.33 प्रतिशत संभावना है कि आप मेरे पिता है। एक का निधन हो चुका है। एक और शख्स के भी उसके पिता होने की संभावना है। यह सुनते ही लगता है जैज पर आसमान टूट पड़ा हो। उसकी जिंदगी में भूचाल आ गया हो। डीएनए टेस्ट से दोनों के पिता-पुत्री होने की पुष्टि होती है। जैज के लिए यह भी चौंकाने वाली बात होती है कि वह पिता के साथ नाना भी बनने वाला है। जिम्मेदारियों से दूर रहने वाले जैज के लिए यह स्वीकारना मुश्किल होता है।

पिता-पुत्री के संबंधों को एक्सप्लोर करती इस फिल्म की कहानी लंदन की है। पिता-पुत्री के संबंधों के साथ अकेले इंसान की जिंदगी की दुश्वारियां, परिवार की अहमियत, रिश्तों में स्थायित्व जैसे मुद्दों को भी समेटने की कोशिश की गई है। फिल्म टुकड़ों में मनोरंजन करती है। कई दृश्य प्रभावित करते हैं। चुटीले डायलॉग हंसाते भी हैं। हालांकि जैज का अपनी बेटी को लेकर हृदय परिवर्तन किन वजहों से होता है, उसे स्पष्ट नहीं किया है। फिल्म में कई ऐसे प्रसंग हैं, जिन्हें लेखन स्तर पर बेहतर किया जा सकता था। मसलन, जब जैज के बड़े भाई को लेकर उसके माता-पिता को गलतफहमी होती है कि टिया के साथ उसके संबंध हैं। इसी तरह जैज का टिया की मां से मिलने पर कोई खास प्रतिक्रिया न देना।

'फिल्मिस्तान', 'नोटबुक' जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले नितिन कक्कड़ ने कलाकारों से उम्दा काम लिया है। जैज बने सैफ अली खान पहले भी स्वच्छंद, खिलंदड़, आजाद ख्याल जैसे शख्स का किरदार निभा चुके हैं। अपनी उम्र के किरदारों को निभाते हुए वह जंचते हैं। उन्होंने जैज के मनोभावों, रंगीले मिजाज के सुर को कायम रखा है। अभिनेत्री पूजा बेदी की बेटी अलाया एफ की यह पहली फिल्म है। उनकी मासूमियत टिया के किरदार को विश्वसनीय बनाती है। हेयर ड्रेसर की भूमिका में कुबरा सेठ जंचती हैं। अस्पताल में बिस्तर पर बीमारी की अवस्था में चंकी पांडे का अभिनय बेहतरीन है। बड़े भाई बने कुमुद मिश्रा चंद दृश्यों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। तब्बू कैमियो में भी अपनी दमदार परफॉर्मेंस से याद रह जाती हैं। -स्मिता श्रीवास्तव

रंगीन जिंदगी के साइड इफेक्ट्स

★★★★★ उत्कृष्ट ★★★★ बहुत अच्छी ★★★ अच्छी ★★ औसत ★ औसत से कम

स्क्रीन शॉट

मां का नाम जोड़ने पर बोले अनुभव सिन्हा

'मुल्क', 'आर्टिकल 15' के बाद अनुभव सिन्हा ने एक बार फिर सामाजिक विषय पर फिल्म 'थप्पड़' का निर्देशन किया है। यह फिल्म पत्नी को सरेआम पति द्वारा थप्पड़ मारने के आधार पर तलाक लेने पर है। हमारे समाज में थप्पड़ खाने पर मां अपनी बेटी को उसे भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देती है। फिल्म में तापसी का किरदार उसके खिलाफ आवाज उठाता है। फिल्म में तापसी पन्नू के अपोजिट पावैल गुलाटी हैं। पावैल ने धारावाहिक 'युद्ध' में अमिताभ बच्चन के बेटे की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को लेकर खास बात यह है कि अनुभव सिन्हा, निर्माता भूषण कुमार और कृष्ण कुमार तीनों ने ही अपने नाम के साथ अपनी मां के नाम को बीच में जोड़ा है। इस बाबत अनुभव सिन्हा का कहना है कि उनकी मां को उनकी बनाई कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई है। अब वह इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उन्हें यकीन है कि अगर वह जीवित होतीं तो उन्हें यह फिल्म जरूर पसंद आती। लिहाजा उन्हें अपने नाम के साथ मां का नाम जोड़ने का विचार आया। उन्होंने इस विचार को भूषण कुमार के साथ साझा किया तो उन्हें भी आइडिया रोचक लगा। उन्होंने भी अपनी मां का नाम जोड़ा। यही वजह है कि ट्रेलर में अनुभव सुशीला सिन्हा, भूषण सुदेश कुमार और कृष्ण कृष्णा कुमार नजर आ रहा है।

...इसलिए राम जेठमलानी की बायोपिक में हो रहा विलंब

अभिनेता कुणाल खेमू और उनकी पत्नी सोहा अली खान ने प्रख्यात वकील राम जेठमलानी की जिंदगी पर फिल्म बनाने की घोषणा की थी। हालांकि अभी फिल्म के बनने में काफी समय है। फिल्म के विलंब के संबंध में कुणाल का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम जेठमलानी जी हमारे बीच नहीं रहे। हम हमेशा से चाहते थे कि वह फिल्म देखें। उनका 70 साल का करियर रहा है। इतने बड़े करियर में निजी और प्रोफेशनल स्तर पर चीजों को दो घंटे की फिल्म में समेट पाना आसान नहीं है। दरअसल, फिल्म में उनकी निजी और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी को दिखाया जाएगा। यही वजह है कि उनकी स्क्रिप्ट तैयार करने में काफी समय लग गया। स्क्रिप्ट अब फाइनल स्टेज पर है। हंसल मेहता फिल्म का निर्देशन करेंगे। इस साल के मध्य तक यह भी तय हो जाएगा कि उनकी भूमिका कौन निभाएगा। अभी हमें यह देखना है कि फिल्म में उनका कौन-सी आयु का हिस्सा ज्यादा दिखाया जाना है। उसके मुताबिक ही हम कास्टिंग करेंगे।'

बाइक चलाकर करीना के शो में पहुंचीं सोनाक्षी

सलमान खान को कई बार मुंबई की सड़कों पर साइकिल की सवारी करते देखा गया है। कई बार सितारों को भी ऑटो रिक्शा में घूमते देखा गया है, लेकिन किसी अभिनेत्री को बाइक चलाकर किसी इवेंट पर पहुंचते शायद ही किसी ने देखा हो। ऐसा नहीं है कि अभिनेत्रियां बाइक नहीं चला सकती हैं, लेकिन कॉस्ट्यूम्स और मेकअप के चलते ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। बात की जाए अगर सोनाक्षी सिन्हा की तो उन्होंने यह संभव कर दिखाया है। सोनाक्षी पूरे टशन में हेलमेट पहनकर बाइक चलाकर पहुंच गई मुंबई के महबूब स्टूडियो में करीना कपूर खान के रेडियो शो 'व्हाट वुमन वान्ट' के लिए शूट करने। इस पूरे सफर के दौरान पैपराजी के कैमरे उनका पीछा करते रहे। वैसे सोनाक्षी के लिए बाइक चलाना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले वह फिल्म 'सन ऑफ सरदार' में बाइक दौड़ातीं और उस पर स्टंट करती नजर आई थीं। इस साल सोनाक्षी 'भुज : द प्राइड ऑफ इंडिया' फिल्म में नजर आएंगी। साथ ही उनके वेबसीरीज पर डेब्यू करने की खबरें भी आ रही हैं। सुनने में आया है कि सोनाक्षी रीमा कागती की वेबसीरीज कर सकती हैं।

'जयललिता' में पूरे चेहरे पर नहीं हुआ है प्रॉस्थेटिक का इस्तेमाल : कंगना

कंगना रनोट की फिल्म 'पंगा' को दर्शकों और समीक्षकों की काफी सराहना मिली है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 21.36 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इसके बाद कंगना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'थलाइवी' में नजर आएंगी। प्रख्यात हस्तियों की जिंदगी पर फिल्म बनाते समय फिल्ममेकर उनके चेहरे को हूबहू मिलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए प्रास्थेटिक मेकअप की मदद ली जाती है। बीते दिनों 'थलाइवी' को लेकर कंगना का लुक सामने आया था। उसमें जयललिता से उनका चेहरा मिलाने का प्रयास साफ नजर आ रहा था। हालांकि कंगना का कहना है कि उनके पचास प्रतिशत चेहरे पर ही प्रॉस्थेटिक का इस्तेमाल हुआ है। जिसमें गाल, गर्दन और ठोड़ी शामिल है। माथे और नाक पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। कंगना के मुताबिक, उतने मेकअप से ही उनके चेहरे का मिलान जयललिता से हो गया था। वह कहती हैं, 'मेकअप देखकर लगा कि यह तकनीक कितनी विकसित हो गई है। लिहाजा जब पहली बार मैंने खुद को देखा तो अच्छा लगा था।' 'थलाइवी' के अतिरिक्त कंगना एक्शन फिल्म 'धाकड़' कर रही है।

'कामयाब' फिल्म को मिला शाह रुख खान का साथ

छोटी बजट में अलहदा विषयों पर बनी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छी सफलता मिल रही है। लिहाजा बड़े निर्माता इन फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ अब इसमें शाह रुख खान भी शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निर्देशक हार्दिक मेहता की फिल्म 'कामयाब' को शाह रुख प्रेजेंट करेंगे। शाह रुख खान की प्रोडक्शन कपंनी ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने लिखा कि किस्से के हिस्से...कामयाब, इस प्रेरणात्मक कहानी को प्रेजेंट करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। शाह रुख खान ने आदे लिखा- 'चरित्र किरदारों की यह एक मार्मिक कहानी है। उसका खुद के साथ संघर्ष, फिल्में और जिंदगी... कड़वी मीठी... और शानदार अभिनय। उम्मीद है कि इस छोटी फिल्म को बड़े दिल से अपनाया जाएगा।' 'कामयाब' फिल्म में संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म छह मार्च को रिलीज होगी। इससे पहले पिछले साल अक्षय कुमार ने मराठी फिल्म 'चुंबक' को प्रजेंट किया था। सलमान खान ने भी सतीश कौशिक की फिल्म 'कागज' को अपना सपोर्ट दिया है। फिल्म बनकर तैयार है, जिसमें पंकज त्रिपाठी मुख्य भूमिका में हैं। उसकी रिलीज तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

'हैप्पी भाग जाएगी 3' की कहानी अपने आप पकेगी : मुदस्सर अजीज

फ्रेंचाइज फिल्मों के दौर में 'मर्दानी' के अलावा 'हैप्पी भाग जाएगी' भी ऐसी फिल्म है, जो महिला प्रधान है। 2016 में 'हैप्पी भाग जाएगी' और 2018 में 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' रिलीज हुई थी। अब दो साल बाद इसकी तीसरी फिल्म के बारे में निर्देशक मुदस्सर अजीज का कहना है कि उन्हें फिल्म के निर्माता आनंद एल राय के साथ एक ऐसी शाम या महफिल का इंतजार है, जहां से तीसरी फिल्म बनाने का ख्याल आए। मुदस्सर इस फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि 'हैप्पी भाग जाएगी 3' को लेकर वह आनंद से अक्सर बात किया करते हैं। वह कहते हैं, 'हैप्पी भाग जाएगी' हो या 'हैप्पी फिर भाग जाएगी', दोनों ही फिल्मों का विचार किसी शाम का नतीजा था। हमने किसी योजना के तहत इन फिल्मों को नहीं बनाया था। हम एक महफिल में साथ थे, जहां कहानी का आइडिया आया था। 'हैप्पी भाग जाएगी 3' के लिए वैसी ही किसी महफिल का इंतजार है।' पहली फिल्म में डायना पेंटी अकेली हैप्पी थीं। दूसरी में उनका साथ एक और हैप्पी सोनाक्षी सिन्हा ने दिया। तो क्या तीसरी फिल्म में तीन हैप्पी होंगी? इसके जवाब में मुद्दसर ने कहा, 'यह कहानी पर निर्भर करेगा। कहानी अपने आप पकेगी।